



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 280]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 19, 2010/आश्विन 27, 1932

No. 280]

NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 19, 2010/ASVINA 27, 1932

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अक्टूबर, 2010

अंतिम जांच परिणाम

विषय : चीन जन.गण. तथा इजराइल के मूल के या वहां से निर्यातित एस डी एच उपकरण के आयात के बारे में पाटनरोधी जांच ।

सं. 14/2/2009-डीजीएडी.—वर्ष 1995 में यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 और सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं का अभिज्ञान, पाटनरोधी शुल्क का निर्धारण एवं वसूली तथा क्षति निर्धारण) नियम, 1995 (जिसे आगे नियम कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए ;

### प्रक्रिया

2. निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई गई है ।

क. निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे आगे प्राधिकारी कहा गया है) को घरेलू उद्योग की ओर से मै. तेजस नेटवर्क्स लि. (जिसे आगे आवेदक कहा गया है) चीन जन.गण. एवं इजरायल (जिन्हें आगे संबद्ध देश कहा गया है) के मूल के या वहां से निर्यातित सिंक्रोनस डिजीटल हाइआर्की ट्रांसमिशन उपकरण (जिसे आगे एस डी एच या संबद्ध वस्तु कहा गया है) के पाटन का आरोप लगाते हुए एक आवेदन प्राप्त हुआ और जांच शुरू करने तथा संबद्ध वस्तु पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया है।

ख. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग की ओर से आवेदक द्वारा प्रस्तुत पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर चीन जन.गण. और इजराइल के मूल की या वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों के बारे में जांच शुरू करना उचित समझा । प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 5 के अनुसार जांच शुरू करने से पूर्व पाटन के आरोप की प्राप्ति के बारे में नई दिल्ली स्थित संबद्ध देशों के दूतावास को अधिसूचित किया ।

ग. प्राधिकारी ने आरोपित पाटन की मौजूदगी, उसकी मात्रा एवं प्रभाव का निर्धारण करने तथा पाटनरोधी शुल्क की उस राशि की सिफारिश करने, जिसे यदि लागू किया जाएगा तो के घरेलू उद्योग को हुई क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी, के लिए उप नियम 6(2) अनुसार 5 के अनुसार संबद्ध देशों के मूल की या वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आवासी द्वारा जांच शुरू करते हुए दिनांक 21 अप्रैल, 2009 को एक सार्वजनिक सूचना जारी कर, जिस भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया ।

घ. प्राधिकारी ने ज्ञात निर्यातकों (जिनके नाम और पते आवेदक द्वारा प्राधिकारी द्वारा उपलब्ध कराए गए थे) को सार्वजनिक सूचना की एक प्रति भेजी और उन्हें नियम 6 के अनुसार पत्र की तारीख से चालीस दिनों के भीतर लिखित में अपने विचारों से अलगाव उत्पन्न का अवसर प्रदान किया और उनसे जांच शुरूआत संबंधी अधिसूचना द्वारा 40 दिन के अन्तराल के अन्दर दायर करने एवं लिखित में अपने विचारों से अलगाव करने का लाभ दिया गया ।

इ. उपर्युक्त नियम 6 के अनुसार घरेलू उद्योग द्वारा दायर की जानी वाली रूपांतरण की प्रतियां ज्ञात निर्यातकों एवं संबद्ध देशों के दूतावासों/उच्चायोगों द्वारा दिया गया कराई ।

च. प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध वस्तु के समस्त ज्ञात आवासकों (जिनके नाम और आवेदक द्वारा प्राधिकारी को उपलब्ध कराए गए थे) को सार्वजनिक सूचना की जानी वाली रूपांतरण के अनुसार पत्र की तारीख से चालीस दिनों के अन्तराल में अपने विचारों से अलगाव उत्पन्न कराई ।

छ. नियम 6(2) के अनुसार नई दिल्ली स्थित संबद्ध देशों के दूतावासों/उत्पादकों की शुरूआत के बारे में इस अनुरोध के साथ सूचित किया गया था कि ने निर्धारित उत्पादकों के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने के लिए अपने देशों/क्षेत्रों के निर्यातकों/उत्पादकों द्वारा दिया गया अनुसार पत्र, निर्यातक को भेजी गई याचिका तथा निर्यातक प्रश्नावली के द्वारा दिया गया अनुसार याचिकाकर्ताओं द्वारा ज्ञात निर्यातकों/उत्पादकों की उपलब्ध कराई गई सूची के साथ उत्पादक स्थित संबद्ध देशों के दूतावासों/उच्चायोगों को भेजी गई थी ।

ज. जहां कहीं अनुरोध किया गया, अन्य हितबद्ध पार्टियों को अपनी विधि आवेदन की जाकर प्रति भी उपलब्ध कराई गई थी ।

झ. प्राधिकारी ने नियम 6 के अनुसार संगत सूचना मांगने के लिए संबद्ध देशों में उत्पादक उत्पाद के निम्नलिखित ज्ञात निर्यातकों/उत्पादकों, संबद्ध देशों के ज्ञात वित्तीयों वर्गे प्रतिवेदन भेजी थी ।

- I. हुआवी टेक्नोलॉजीज कंपनी लि.
- II. वुहान रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ पोर्ट एंड ट्रैटी कांग्जुनकिंग
- III. जैडटीई कार्पोरेशन

## IV. अल्काटेल-लूसेन्ट

ज. उपर्युक्त अधिसूचना के उत्तर में संबद्ध देशों के निम्नलिखित नियातकों/विदेशी उत्पादकों/विदेशी उत्पादकों की एसोसिएशन ने प्रश्नावली के अपने उत्तर दायर किए:

- I. जैडटीई कार्पोरेशन लि.
- II. हुआवी टेक्नोलॉजीज कंपनी लि.
- III. शेनजेन हुआवी टेक्नोलॉजीज कंपनी लि.
- IV. हीसिलिकॉन टेक्नोलॉजीज लि.
- V. फाइबर होम टेलीकम्युनिकेशन्स टेक्नोलॉजीज कंपनी लि.
- VI. वुहान फाइबर होम इंटरनेशन टेक्नोलॉजीज कंपनी लि.
- VII. हेंगज्ञाऊ ई सी आई टेलीकम्युनिकेशन्स कंपनी लि.
- VIII. ई सी आई टेलीकम्युनिकेशन्स कंपनी लि.
- IX. अल्काटेल लूसेंट शंघाई बैल कंपनी लि.
- X. सी सी सी एम ई
- XI. अल्काटेल-लूसेंट शंघाई बैल कंपनी
- XII. यू टी स्टारकॉम
- XIII. सीएना, यू एस ए

ट. निम्नलिखित आयातकों को प्रश्नावलियां भेजी गई थीं ।

- I. एअरसेल लिमिटेड
- II. पृथ्वी इनफॉरमेशन लि.
- III. डिसनैट वायरलैस लिमिटेड
- IV. पंजाब कम्यूनिकेशन्स लि.
- V. भारती एयरटैल लिमिटेड
- VI. एचटीएल जीएचटी
- VII. भारत संचार निगम लिमिटेड
- VIII. हुवाई इंडिया
- IX. टाटा टेली सर्विसेज लिमिटेड
- X. जैट टी ई इंडिया
- XI. टाटा टेली सर्विसेज (महाराष्ट्र) लिमिटेड
- XII. ई सी आई इंडिया
- XIII. आइडिया सेल्युलर लिमिटेड
- XIV. अल्काटेल लूसेंट
- XV. वोडाफोन एस्सार लिमिटेड
- XVI. नोकिया सीमेस नेटवर्क
- XVII. रेलटेल कार्पो. ऑफ इंडिया लिमिटेड

---

XVIII. एरीक्शन  
 XIX. टाटा कम्यूनिकेशन्स  
 XX. हिमाचल फ्यूचरिस्टिक कम्यूनिकेशन्स  
 XXI. रिलायंस कम्यूनिकेशन्स लिमिटेड  
 XXII. आई सी ओ एम एम  
 XXIII. श्यान टेलीलिंक्स

ठ. निम्नलिखित आयातकों/उपभोक्ताओं/उनकी एसोसिएशन ने प्रश्नावली का उत्तर दिया है और सूचना/अनुरोध प्रस्तुत किए हैं:

- i. ईसीआई इंडिया प्रा. कं. लि.
- ii. हुआवी इंडिया टेलीकम्यूनिकेशन प्रा.लि.
- iii. वोडाफोन एस्सार लि.
- iv. बुकपालामृता मैग्नेटिक कंपोनेट्स लि.
- v. पृथ्वी इनफॉरमेशन्स साल्युशंस लि.
- vi. हुआवी टैक्नॉलॉजीज इंडिया प्रा.लि.
- vii. मै. एम आर ओ - टैक लि., बंगलौर
- viii. मै. जूनीपर नेटवर्क प्रा. लि., इंडिया
- ix. एअरसैल लिमिटेड
- x. वोडाफोन एस्सार लि.
- xi. भारती एअरटैल लिमिटेड
- xii. ईसीआई टेलीकॉम इंडिया प्रा.लि.
- xiii. अरएडी डाटा कम्यूनिकेशन्स लि.
- xiv. टाटा टेली सर्विस
- xv. बी एस एन एल
- xvi. तिरुमाला सेवन हिल्स

ड. जांच अधिकारी सहित पिछले तीन वर्षों के लिए संबद्ध वस्तु के आयातों के व्यौरों की व्यवस्था करने हेतु वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएंडएस) तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमाशुल्क बोर्ड (सी बी ई सी) से अनुरोध किया गया था।

ढ. प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पार्टियों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का अगोपनीय रूपांतरण एक सार्वजनिक फाइल के रूप में उपलब्ध रखा और उसे हितबद्ध पार्टियों के निरीक्षणार्थ खुला रखा।

ण. घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों (जीएएपी) के आधार पर भारत में संबद्ध वस्तु की इष्टतम उत्पादन लागत तथा उसे बनाने और बेचने की लागत अनंतिम रूप से निकाली गई थी ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या

पाटन मार्जिन से कमतर पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा।

त. विभिन्न हितबद्ध पार्टियों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के संबंध में प्राधिकारी ने उनके गोपनीयता के दावों की जांच की और उन पर विधिवत विचार किया। जहां प्राधिकारी गोपनीयता के दावों के बारे में संतुष्ट हो गए और जहां संबंधित हितबद्ध पार्टी ने पर्याप्त अगोपनीय रूपांतरण उपलब्ध कराया है, वहां प्राधिकारी ने हितबद्ध पार्टियों द्वारा प्रदत्त ऐसी सूचना को गोपनीयता प्रदान की है।

थ. जो सूचना गोपनीय प्रकृति की है अथवा जिसे किसी हितबद्ध पार्टी ने गोपनीय आधार पर प्रदान किया है, उसे इस विवरण में गोपनीय माना गया है और उसका खुलासा अन्य हितबद्ध पार्टियों को नहीं किया गया है। तथापि, ऐसी गोपनीय सूचना के अगोपनीय रूपांतरण का प्रकटन उस सीमा तक वर्तमान प्रकटन विवरण में किया गया है, जिस सीमा तक उससे गोपनीय आधार पर प्रदत्त सूचना के सारांश को उचित ढंग से समझा जा सके।

द. समस्त ज्ञात निर्यातकों और चीन जन.गण के दूतावास को बाजार अर्थव्यवस्था के व्यवहार (एम ई टी) संबंधी प्रश्नावली भेजी गई थी। निर्यातकों को सूचित किया गया था कि प्राधिकारी का प्रस्ताव यथासंशोधित पाटनरोधी नियमावली के अनबंध 1 के पैरा 7 और पैरा 8 के मध्येनजर आवेदक के दावे की जांच करने का है। अतः चीन जन.गण. से संबद्ध वस्तु के निर्यातकों/उत्पादकों से अनुरोध किया गया था कि वे इस बात पर विचार करने के लिए कि क्या प्राधिकारी द्वारा सहयोगी निर्यातकों/उत्पादकों को बाजार अर्थव्यवस्था का व्यवहार प्रदान किया जाए। पैरा 8 के उप पैरा (3) में यथाउल्लिखित आवश्यक सूचना/पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करें।

ध. यह जांच 1 अप्रैल- 31 दिसंबर, 2008 (9 माह-जांच अवधि) तक की अवधि के लिए की गई है। घरेलू उद्योग को हुई क्षति के निर्धारण हेतु 2005-06, 2006-07, 2007-08 की अवधि तथा जांच अवधि पर विचार किया गया है।

न. प्राधिकारी ने 7 सितंबर, 2009 को प्रारंभिक जांच परिणाम दर्ज किए जिसकी प्रति भारत स्थित संबद्ध देशों के दूतावासों सहित समस्त हितबद्ध पार्टियों को भेजी गई थी। समस्त हितबद्ध पार्टियों से प्रारंभिक जांच परिणामों पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करने के लिए कहा गा था।

प. प्राधिकारी ने हितबद्ध पार्टियों की मौखिक सुनवाई करने के लिए दिनांक 21-12-09 को एक सार्वजनिक सुनवाई आयोजित की जिसमें हितबद्ध पार्टियों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। हितबद्ध पार्टियों को लिखित अनुरोध दायर करने की सलाह दी गई थी औश्र उन्हें विरोधी हितबद्ध पार्टियों द्वारा किए गए अनुरोधों के उत्तर प्रस्तुत करने की अनुमति दी गई थी। हितबद्ध पार्टियों से प्राप्त लिखित अनुरोधों और उत्तरों पर संगत समझी गई सीमा तक इस विवरण में विचार किया जा रहा है। इस प्रयोजनार्थ समस्त हितबद्ध पार्टियों को यह सलाह दी

गई थी कि वे दिनांक 4 जनवरी, 2010 तक हर हालत में अपने लिखित अनुरोध प्रस्तुत कर दें और उन्हें हर हालत में 17 जनवरी, 2010 तक उत्तर संबंधी अनुरोध दायर करने की अनुमति दी गई थी ।

ब. यह जांच माननीय हैदराबाद उच्च न्यायालय में चल रहे मामले से संबंधित न्यायलयीय कार्यवाही के कारण एक वर्ष की निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरी नहीं की जा सकी और इसीलिए जांच पूरी करने के लिए 20.10.2010 तक का समय विस्तार मांगा गया था, जिसकी अनुमति केन्द्र सरकार ने प्रदान कर दी है ।

भ. जिन प्रतिवादी निर्यातकों ने अपने अनुरोध दायर किए थे और जिन्हें प्राधिकारी ने सत्यापन के लिए बुलाया था उनके आंकड़ों का मौके पर सत्यापन आवश्यक सीमा तक किया गया था ।

म. बड़ी संख्या में भागीदार पार्टियों और इन हितबद्ध पार्टियों द्वारा उठाए गए तमाम पुढ़े को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी ने सर्वप्रथम इन हितबद्ध पार्टियों द्वारा किए गए अनुरोध प्रकाशित किए । इसके अलावा, पुनरावृत्ति से बचने के लिए प्राधिकारी ने इन हितबद्ध पार्टियों के तर्कों को सामूहिक रूप से प्रकाशित किया ।

य. उपर्युक्त नियमावली के नियम 16 के अनुसार आवश्यक तथ्यों/आधार का प्रकटन ज्ञात हितबद्ध पार्टियों को किया जा रहा है और उन पर प्राप्त टिप्पणियों पर अंतिम जांच परिणामों में विचार किया जाएगा ।

र. \*\*\* यह चिन्ह इस अधिसूचना में किसी हितबद्ध पार्टी द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना का द्योतक है और प्राधिकारी ने नियमानुसार उसे गोपनीय ही माना है ।

ल. इस अंतिम जांच परिणाम संबंधी दस्तावेज में प्रयुक्त संक्षिप्ताक्षर का तात्पर्य निम्नानुसार है -

क्र.सं	संक्षिप्ताक्षर	व्याख्या/अर्थ
1.	प्राधिकारी	निर्दिष्ट प्राधिकारी
2.	अधिनियम	वर्ष 1995 में यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं का अभिज्ञान, पाटनरोधी शुल्क का निर्धारण एवं वसूली तथा क्षति निर्धारण) नियम,
3.	नियमावली	1995 विचाराधीन उत्पाद अर्थात् इस प्रकटन विवरण के संगत पैरा में
4.	उत्पाद	यथापरिभाषित एस डी एच ट्रांसमिशन उपकरण

5.	सीकेडी	पूर्णतः नॉकड डाउन स्थिति
6.	एसकेडी	अर्ध नॉकड स्थिति
7.	नि.प्रा.	निर्दिष्ट प्राधिकारी
8.	घ.उ.	घरेलू उद्योग
9.	पा.रो.करार	डब्ल्यू टी ओ पाटनरोधी करार
10.	एस डी एच	सिंक्रोनस डिजिटल हाइआर्की ट्रांसमिशन उपकरण
11.	तेजस	तेजस नेटवर्क्स लि.
12.	वी एम सी एल	वुप्पालाकृता मैग्नेटिक कंपोनेट्स लि.
13.	पृथ्वी	पृथ्वी इन्फॉरमेशन सॉल्यूशंस लि.
14.	बी एस एन एल	भारत संचान निगम लि.

### विचाराधीन उत्पाद तथा समान वस्तु

#### घरेलू उद्योग (तेजस अथा अन्य भारतीय उत्पादकों के अनुरोध)

3. विचाराधीन उत्पाद के बारे में घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं :-

क. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद "संयोजित रूप में, सी के डी, एस के डी रूप में या आकस्मिक ब्रॉड बैंड/सेल्युलर उपकरण से फिट किए गए सिंक्रोनस डिजीटल हाइआर्की ट्रांसमिशन उपकरण, उसके पुर्जे, संबद्ध सॉफ्टवेयर तथा उसके आवश्यक पुर्जे एवं संघटक" हैं।

ख. एस डी एच ट्रांसमिशन उपकरणों को मल्टीप्लेक्सर, एड ड्रॉप मल्टीप्लेक्सर (ए डी एम), मल्टीप्ल, एड ड्रॉप मल्टीप्लेक्सर, (एम ए डी एम), डिजीटल क्रॉस-कनेक्ट, पापुलेटेड पी सी वी, विद्युत आपूर्ति, लेजर, चेसेज तथा एस डी एच ट्रांसमिशन उपकरण के लिए निर्दिष्ट साफ्टवेयर आदि जैसे नामों से भी जाना जाता है, जिसमें एस डी एच ट्रामिशन उपकरणों के आवश्यक पुर्जे शामिल होते हैं और ये विचाराधीन उत्पाद के दायरे में हैं बशर्ते उक्त संघटक केवल एच डी एस ट्रांसमिशन उपकरण के लिए निर्दिष्ट हों।

ग. एच डी एस ट्रांसमिशन उपकरणों की खरीद ट्रांसमिशन उपकरणों के रूप में या अन्य उपकरण के भाग के रूप में अर्थात ब्रॉड बैंड और/अथवा सेल्युलर (जीएसएम एवं सी डी एम ए दोनों) उपकरणों के रूप में की जा सकती है। ब्रॉड बैंड और/अथवा सेल्युलर उपकरण के भाग स्वरूप एच डी एस ट्रांसमिशन उपकरण भी विचाराधीन उत्पाद के दायरे में आते हैं।

घ. विचाराधीन उत्पाद अनेक इलेक्ट्रॉनिक संघटकों और/अथवा इलेक्ट्रॉनिक प्रिटेट सर्किट बोर्डों का संयोजन है जिसे संयुक्त कम गति के सिग्नलों को (अल्प या लंबी) दूरी में

ऑप्टिकल फाइबर के जरिए पारेषण हेतु उच्च गति के सिंगलों में मल्टीफ्लेक्सिंग हेतु विशिष्ट नियत कार्यों के निष्पादन हेतु तैयार किया जाता है। चूंकि अन्य अनुप्रयोगों में इन्हें बेश ट्रांसमिशन केन्द्रों, स्थिर एक्सचेंजों तथा मौजूदगी के अन्य केन्द्रों पर स्थापित किया जाता है, इसलिए अलग-अलग स्थानों पर स्थापित एस डी एच उपकरण संबद्ध गुणधर्मों के संबंध में अलग-अलग हो सकते हैं।

ड. अलग-अलग एस डी एच उपकरण भौतिक एवं ऑप्टिकल, उत्पादन प्रौद्योगिकी, विनिर्माण प्रक्रिया, आर एंड डी विकास, सॉफ्टवेयर क्षमताओं, कार्य एवं उपयोग आदि सहित उत्पाद की अनिवार्य विशेषताओं के संबंध में तुलनीय हैं। तदनुसार विभिन्न एस डी एच उपकरणों को वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ एक समान उत्पाद माना गया है।

च. विचाराधीन उत्पाद का आयात पूर्ण उपकरण के रूप में या सी के डी, एस के डी रूप में या संघटक रूप में भी किया जा सकता है। इसके अलावा, नेटवर्क में जोड़ने/एस डी एच ट्रांसमिशन उपकरण की स्थापना करने के लिए कई सहायक उपकरणों की जरूरत होती है (ई-1 केबल, पी सी एम केबल, पॉवर केबल, रैक, वर्क स्टेशन आदि)। सॉफ्टवेयर इन उपकरणों का अभिन्न अंग होता है जिसे उपकरण के भाग के रूप में या अलग से खरीदा जा सकता है। ये सभी विचाराधीन उत्पाद के दायरे में आते हैं।

छ. विचाराधीन उत्पाद सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 85 के अंतर्गत वर्गीकृत है।

ज. संबद्ध वस्तु के उत्पादन में शामिल प्रमुख प्रयास प्रौद्योगिकी विकास में निहित होता है। संबद्ध वस्तु के डिजायन और विकास में विश्वभर के उत्पादकों द्वारा अत्यधिक अनुसंधान एवं विकास संबंधी प्रयास किए जाते हैं, जिसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि लगभग 60% जनशक्ति विचाराधीन उत्पाद के डिजायन एवं विकास में लगाई गई है।

झ. उत्पादन का केन्द्र बिन्दु प्रौद्योगिकी, जानकारी, उत्पाद डिजायन एवं विकास होता है। विनिर्माण की वार्तविक प्रक्रिया वस्तुतः संबद्ध वस्तु के उत्पादन एवं आपूर्ति में शामिल कुल कार्यकलाप का अत्यंत छोटा भाग होती है और इसमें पी सी वी (पॉपूलेटेड पीरीवी) पर कई संघटकों का जटिल संयोजन शामिल होता है और तत्पश्चात तैयार उत्पाद के रूप में इसका संयोजन और जांच की जाती है।

ज. वर्तमान उत्पाद का उत्पादन एक ऐसा कार्यकलाप होता है जिसमें जटिल हार्डवेयर की डिजायन एवं विकास, खचित साफ्टवेयर एवं नेटवर्क प्रबंधन साफ्टवेयर तथा तैयार उत्पाद का अंतिम संयोजन एवं उसकी जांच शामिल होती है। याचिकार्कर्ता, संबद्ध देशों के उत्पादकों और विश्व के अन्य प्रतिरप्तियों द्वारा ये सभी कार्यकलाप संयुक्त रूप से किए जाते हैं।

ट. उत्पादन प्रक्रिया को निम्नलिखित में विभाजित किया जा सकता है :-

- अनुसंधान
- उत्पाद परिकल्पना
- डिजाइन एवं ड्राइंग
- उत्पाद के प्रोटोटाइप का विकास
- प्रौद्योगिकी विकास
- कार्यचालनात्मकता की परिकल्पना और उसकी समझ
- संबद्ध साफ्टवेयर का विकास
- उत्पाद का ब्लू प्रिंट और प्रोटोटाइप का विकास
- संभावित एकीकरण
- परीक्षण
- संयोजन
- साफ्टवेयर प्रोग्रामिंग
- जिग परीक्षण

ठ. उत्पाद के किसी उपभोक्ता द्वारा किसी पार्टी को ऑर्डर देने से पूर्व उपरोक्त सभी घटकों के संयोजन पर जोर दिया जाता है। इसके अलावा, भारत में कुछेक उपभोक्ताओं द्वारा भारत से किसी के द्वारा की गई बिक्री तथा प्रदान की जा रही सहायता पर जोर दिया जाता है। अतः संबद्ध देशों के उत्पादकों ने बिक्री एवं सहायता सेवाएं प्रदान करने के लिए भारत में अपने खुद के/संबद्ध उद्यम स्थापित कर दिए हैं।

ड. संबद्ध वस्तु की डिजायन और विकास में अनुसंधान एवं विकास से संबंधित पर्याप्त संसाधन शामिल होते हैं। याचिकाकर्ता ने इन वर्षों के दौरान अत्यधिक बौद्धिक संपदा विकसित कर दी है। इसी तरह विदेशी उत्पादकों ने भी इन वर्षों में अत्यधिक बौद्धिक संपदा विकसित कर ली है।

ढ. याचिकाकर्ता और इस उद्योग में प्रमुख वैश्विक प्रतिस्पर्धियों द्वारा संघटक विनिर्माण के एक बड़े भाग का निष्पादन विशिष्टकृत उत्पादकों (इलेक्ट्रोनिक संविदा विनिर्माता) से कराया जाता है। संघटक विनिर्माण कार्यकलाप के एक बड़े भाग का निष्पादन करने वाली ये कंपनियां केवल उजरती कार्य के प्रसंस्कर्ता होती हैं जिनके पास प्रौद्योगिकी एवं उत्पाद में शामिल डिजाइन एवं विकास की कोई जानकारी नहीं होती है। इन उजरती कार्य प्रसंस्कर्ताओं के पास संबद्ध वस्तु के उत्पादन में अपेक्षित बौद्धिक संपदा की जानकारी नहीं होती है।

ण. भारतीय नियमावली और डब्ल्यू टी ओ पाटनरोधी करार में विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र के बारे में कोई उल्लेख नहीं है और न ही इसमें ऐसे मापदंडों का उल्लेख है जिन पर विचाराधीन उत्पाद के वर्णन/विनिर्देशन हेतु विचार करना चाहिए।

त. याचिकाकर्ता ने विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र के अपने दावे के समर्थन में भारत, ई सी और अमरीका द्वारा जांच किए गए कई मामलों पर अनुसंधान किया। इनमें चीन जन.गण. से कुछेक टो बिहाइंड लॉन ग्रूमर्स और उसके भाग, चीन जन.गण. और कोरिया से डायमंड सॉब्लेड्स और उसके भाग, जापान से ग्रे पोटलैंड सीमेंट तथा सीमेंट किंलकर, चीन जन.गण. से हैंड ट्रक एवं उसके कुछेक पुर्जों, जापान से संयोजित या विसंयोजित अखबारों की बड़ी मुद्रण प्रेसों और उनके संघटकों, जापान से मकेनिकल ट्रांसफर प्रेसों के मामलों में अमरीकी आई पी सी के निर्णय शामिल हैं। इसके अलावा, याचिकाकर्ता ने ऑयल बोर्डों, स्टील ट्यूब एवं पाईप फिटिंग, कम्पैक्ट डिस्क प्लेयर्स (सी डी पी) में मामलों में ई सी के निर्णयों का हवाला दिया।

थ. घरेलू उद्योग "किसी वस्तु" के संबंध में कानून के अंतर्गत राहत की मांग करने का हकदार है और ऐसी वस्तु का तात्पर्य उसके समस्त ज्ञात रूपों/प्रजातियों/प्रकारों से है।

द. "एस डी एच उपकरण" में विभिन्न रूपों में, अलग-अलग नामों में, अलग-अलग रूप में आपूर्त उत्पाद शामिल हैं। मल्टीप्लैक्सर, एड ड्राप मल्टी प्लैक्सर (ए डी एम), मल्टीप्ल एड ड्राप मल्टीलेक्सर (एम ए डी एम), डिजिटल क्रास कनेक्ट्स एक ही उत्पाद के अलग-अलग नाम हैं। एस डी एच ट्रांसमिशन उपकरण के लिए नियम पापुलेटिड पी सी बी, विद्युत आपूर्ति, लेजर, चेसेज तथा साफ्टवेयर इस उत्पाद के विभिन्न उप घटक हैं।

ध. उत्पाद की आपूर्ति संयोजित रूप में अथवा उत्पाद के इन विभिन्न उप घटकों में विभाजित रूप में की जा सकती है। कोई निर्यातक उपयोग के लिए तैयार माल के रूप में अथवा उप संयोजित, कार्डों, सी के डी/एस के डी स्थितियों में निर्यात कर सकता है और भारत में शेष प्रचालन (नगण्य मूल्यवर्धन सहित) कर सकता है। इसके अलावा, इस उत्पाद का उत्पादन और आपूर्ति विशिष्ट ग्राहक की जरूरत के अनुसार विभिन्न आकारों में की जा सकती है।

न. एस डी एच उपकरण के उत्पादन के तरीके और उपयोग किया जाता है तथा विभिन्न जांचकर्ता प्राधिकारियों द्वारा जांच किए गए विभिन्न मामलों से उत्पन्न हुई स्थिति से यह सिद्ध होता है कि विचाराधीन उत्पाद का क्षेत्र वर्तमान मामले में व्यापक नहीं है। इसके अलावा, विचाराधीन उत्पाद से संबंधित उत्पादन कार्यकलापों पर विचार करते हुए पुर्जों/संघटकों को शामिल करना पूर्णतः न्यायोचित है।।।

प. याचिकाकर्ता ने एस डी एच अनुप्रयोग हेतु पुर्जों/संघटकों पर ही पाटनरोधी शुल्क लगाने की मांग की है।

फ. विभिन्न प्रकारों को शामिल करने हेतु हितबद्ध पार्टियों के दावे निम्नलिखित कारणों से विश्वसनीय हैं।

।. मल्टलप्लैक्सर-याचिकाकर्ता एस डी एच मल्टीप्लैक्स की भारी मात्रा में बिक्री करता है।

ii. डी डब्ल्यू डी एम मल्टीप्लैक्सर वर्तमान याचिका और जांच के भाग नहीं हैं ।

ब. जहां तक विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र का संबंध है, कानून में एकमात्र यह अपेक्षा की गई है कि क्या (क) विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में शामिल विभिन्न प्रकार एक ही वस्तु है; (ख) तेजस ऐसी किसी वस्तु का विनिर्माण करती है जो विचाराधीन उत्पाद की समान वस्तु है ।

भ. याचिकाकर्ता ने फासनर के मामले में ई सी के निर्णय का उल्लेख किया है और यह तर्क दिया है कि किसी उत्पाद के कुछेक खास संघटक/पुर्जे का उत्पादन न किए जाने से कोई कंपनी उत्पाद के बारे में संरक्षण प्राप्त करने की पात्र नहीं बन जाती है । घरेलू उद्योग को उत्पाद के उत्पादन में संलग्न होना चाहिए और उसके लिए बाजार में उत्पाद के पुर्जे को उतारना अपेक्षित नहीं है ।

म. याचिकाकर्ता ने पुर्जे और संघटकों को शामिल करने की मांग इसलिए की है क्योंकि (क) इन्हें ऐस डी एच उपकरणों के उत्पादन हेतु विशिष्ट रूप से डिजाइन किया जाता है (ख) इनका उत्पाद के उत्पादन के अलावा, कोई अन्य अनुप्रयोग नहीं है । (ग) पुर्जे/संघटकों/संयोजन/उप संयोजन के चरण से लेकर उत्पाद के उत्पादन में एकमात्र स्क्रू ड्राइवर प्रौद्योगिकी अंतर्गत होती है और इसलिए उत्पाद क्षेत्र से इन्हें अलग किए जाने का तात्पर्य इनका पाटित कीमतों पर आयातों की अनुमति देने से होगा, जिससे पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बावजूद सतत पाटन होगा और क्षति होगी । यह बात अविवादित रही है कि घरेलू उद्योग का इस संबंध में तर्क गलत है । घरेलू उद्योग ने यह प्रश्न भी उठाया है कि यदि विचाराधीन उत्पाद पर पाटनरोधी शुल्क अनुचित है तो ऐसी मदों के आयात की अनुमति क्यों दी जानी चाहिए और ऐसे आयातों से घरेलू उद्योग को क्षति क्यों होनी चाहिए । घरेलू उद्योग ने यह भी तर्क दिया है कि प्राधिकारी यह विनिर्दिष्ट कर सकते हैं कि पुर्जे, संघटकों, उपसंयोजनों पर ऐसा शुल्क घोषणा के आधार पर लगाया जा सकता है और इसे संगत सीमाशुल्क अधिसूचना में भी विनिर्दिष्ट किया जा सकता है ।

य. डी डब्ल्यू डी एम मल्टीप्लैक्सर और पी डी एच मल्टीप्लैक्सर अलग-अलग उत्पाद हैं । प्राधिकारी इनका विशिष्ट स्पष्टीकरण दे सकते हैं ताकि कुछेक हितबद्ध पार्टियों द्वारा अनावश्यक रूप से उत्पन्न की गई शंकाओं का निवारण किया जा सके । इसके अलावा, प्राधिकारी उचित वर्णन के संबंध में विरोधी पार्टियों के ऐसे अन्य तर्कों पर विचार कर सकते हैं और शुल्क लागू होने के समय स्पष्टता सुनिश्चित करने हेतु अंतिम जांच परिणामों में इसे स्पष्ट कर सकते हैं ।

4. यह दावा किया गया है कि यह एक सुस्थापित कानून है कि उत्पाद विवरण निस्तारणीय रहता है और सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सुविधा के लिए प्रदान किए जाते हैं । केवल इस वजह से कि किसी उत्पाद की सूचना किसी पाटनरोधी शुल्क की अधिसूचना के

अंतर्गत विनिर्दिष्ट किसी वर्गीकरण के अंतर्गत प्रदान की गई है, इसका तात्पर्य यह नहीं है कि उस पर पाटनरोधी शुल्क वसूल किया जाएगा ।

5. कुछेक उत्पादों को विशिष्ट रूप से शामिल किए जाने के बारे में हितबद्ध पार्टियों के दावों के संबंध में घरेलू उद्योग ने निम्नानुसार दावा किया है :-

- i. एस टी एम-1, 4, 16-इन प्रकारों को शामिल करने के बारे में कोई विवाद नहीं है ।
- ii. एस टी एम-64-घरेलू उद्योग ने इनका उत्पादन और आपूर्ति की है । यह दावा निराधार है । दौरे के दौरान अधिकारियों को यह प्रदर्शित किया गया है कि कंपनी एस टी एम-64 का उत्पादन करती है जो डी एक्स सी भी है । यह तथ्य कि तेजस ने किसी विशिष्ट ग्राहक हेतु किसी विशिष्ट उत्पाद प्रकार के लिए किसी विशिष्ट निविदा में बोली नहीं लगाई थी, का तात्पर्य यह नहीं है कि उक्त कंपनी उस उत्पाद विशेष का उत्पादन नहीं करती है । किसी विशेष निविदा में भाग लेने का तात्पर्य यह नहीं है कि वह कंपनी उस उत्पाद विशेष का उत्पादन नहीं कर रही है ।
- iii. एसटीएम-256-जहां तक भारत में एस टी एम 256 का संबंध है, इसकी कोई जरूरत नहीं है । एस टी एम 256 एस डी एच उपकरण से भिन्न कोई चीज नहीं है । किसी भी ग्राहक ने एस टी एम 256 की मांग नहीं की है और एस टी एम-256 प्रणाली के लिए कोई अनुमोदित विनिर्देशन (टी ई सी जी आर) नहीं है, ये प्रणालियां टेलीकॉम ऑपरेटरों द्वारा नहीं लगाई गई हैं । किसी उत्पाद का उत्पादन तभी किया जा सकता है यदि उसकी मांग/जरूरत विद्यमान हो । यह माना जाता है कि भारत में किसी टेलीकॉम ऑपरेटर ने कोई एस टी एम 256 प्रणाली स्थापित नहीं की है और यहां तक कि विश्व भर में बहुत ही कम टेलीकॉम ऑपरेटरों ने अपने नेटवर्क में एस टी एम-256 प्रणाली स्थापित की है । तेजस ने एस टी एम-256 प्रौद्योगिकी के विकास में भारी आर एंड डी निवेश किया है और तेजस अपेक्षानुसार अपनी प्रणालियों पर एस टी एम-256 क्षमताएं उपलब्ध करा सकती है ।
- iv. मल्टीप्लैक्सर-मल्टीप्लैक्सर एक व्यापक पद है । एस डी एच उपकरण में भी मल्टीप्लैक्सर होते हैं । घरेलू उद्योग ने इनका उत्पादन और आपूर्ति की है । इनका भारत में आयात किया गया है । तथापि, प्राधिकारी यह स्पष्ट करें कि केवल एस डी एच मल्टीप्लैक्सर भी विचाराधीन उत्पाद के दायरे में आते हैं ।
- v. डी डब्ल्यू डी एम - ये एस डी एच उपकरण नहीं हैं और विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर हैं । हितबद्ध पार्टियों ने यह अपवर्जन केवल प्राधिकारी को गुमराह करने के लिए मांगा है ।
- vi. एस डी एच उपकरणों के पुर्जे और संघटक - इन्हें अलग रखा जा सकता है । घरेलू उद्योग के तर्क को अलग से प्रकाशित किया गया है ।

6. यह दावा किया गया है कि आकस्मिक उपभोक्ताओं द्वारा घरेलू एवं विदेशी उत्पादकों द्वारा आपूर्त वस्तु का इस्तेमाल अदल-बदल कर किया जा रहा है । भारत में बी एस एन एल, भारती, एअरसैल जैसे समस्त प्रमुख दूर संचार सेवा प्रदाता हुआबी उत्पाद एवं तेजस उत्पाद की खरीद कर रहे हैं और वह भी उसी नेटवर्क के लिए, उसी अनुप्रयोग के लिए और उसी विनिर्देशन पर ।

7. आगे यह दावा किया गया है कि डी डब्ल्यू डी एम प्रौद्योगिकी पर प्रचालनरत मल्टीप्लैक्सर अथवा अन्य उपकरण विचाराधीन उत्पाद में शामिल नहीं हैं । आपूर्तिकर्ता एस डी एच मल्टीप्लैक्सर या डी एच सी की आपूर्ति करते हैं और इनका प्रदर्शन अधिकारियों के दौरे के दौरान किया गया था ।

8. तेजस एस डी एच उत्पादों तथा कैरियर अर्थ नैट उत्पादों, दोनों का उत्पादन करती है । तेजस द्वारा उस स्थिति में लागू शुल्क का भुगतान किया जाएगा यदि वह एस डी एच के उपयोग हेतु दोहरे उपयोग के संघटकों की प्राप्ति करेगी और यदि वह उत्पाद के दायरे में आएगी । यह याचिका केवल एक ऐसे उत्पाद के बारे में है, जो भले ही विभिन्न रूपों में है । नियमों में कहीं भी विचाराधीन उत्पाद के दायरे के भीतर किसी उत्पाद के विभिन्न रूपों को शामिल करने से वंचित करने का प्रावधान नहीं है । अब तक की गई किसी भी जांच में बमुश्किल ऐसा पाया गया है जिसमें विचाराधीन उत्पाद के विविध रूप न रहे हों ।

9. एस डी एच, उसकी सहायक सामग्री, संबद्ध साफ्टवेयर, पुर्जे और संघटक, पॉपुलेटेड पी सी बी, विद्युत आपूर्ति, लेजर, चेसेज, ई आई केबल, पी सी एम केबल, पावर केबल, रैक सामूहिक रूप से एस डी एच उपकरण (वर्क स्टेशन को छोड़कर) है । अलग-अलग रूप में इनका कोई अंतिम उपयोग नहीं है । उदाहरणार्थ किसी ट्यूबलाइट के लिए एक ट्यूब, एक चॉक, एक स्टार्टर और एक आधार अपेक्षित होता है । ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ये चारों मर्दे अलग-अलग वस्तुएं हैं क्योंकि उनकी अलग-अलग विशेषता है ।

10. नियम 5 की अपेक्षाओं की पूर्ति विचाराधीन उत्पाद के संबंध में करनी होती है न कि विचाराधीन उत्पाद के अलग-अलग रूपों के संबंध में । विचाराधीन उत्पाद एस डी एच ट्रांसमिशन उपकरण है । जब "एस डी एच 5-1 इंटरफेश" से युक्त "अलग-अलग प्रौद्योगिकी उपकरण" का आयात किया जाएगा तो शुल्क "अलग-अलग प्रौद्योगिकी उपकरण" के संपूर्ण मूल्य पर नहीं लगाया जाएगा, अपितु केवल एस डी एच-1 प्रौद्योगिकी से संबंधित पुर्जों पर लगाया जाएगा ।

11. यह सुझाव दिया गया है कि प्राधिकारी सिएना के इस दावे की जांच कर सकते हैं कि उसके द्वारा उत्पादित वस्तु का मूल स्थान अमरीका है और बौद्धिक संपदा अधिकार अमरीका में है । यदि वस्तु का उद्गत चीन जन.गण. में होता है तो पाटनरोधी शुल्क लागू होना चाहिए । यदि वस्तु चीन के मूल की नहीं है तो पाटनरोधी शुल्क लागू नहीं होना चाहिए ।

### फिबकॉम के अनुरोध

12. उन्होंने विचाराधीन उत्पाद का घरेलू विनिर्माता होने का दावा किया है । तथापि, लिखित दस्तावेज के अलावा, अपने तर्क के समर्थन में उन्होंने कार्यकलाप के अपने क्षेत्र की पुष्टि करने के लिए कोई अन्य सूचना प्रस्तुत नहीं की है । अपने लिखित अनुरोध में उन्होंने यह बताया है कि इससे "पूर्ण एस डी एच उपकरण" तथा "एस डी एच में प्रयोग हेतु पापुलेटेड माड्यूल" पर पाटनरोधी शुल्क लगाने को समर्थन मिलता है परंतु उन्होंने संघटकों पर संस्तुत और उद्ग्रहीत होने वाले शुल्क का विरोध किया है ।

### निर्यातकों/आयातकों तथा अन्य हितबद्ध पार्टियों के अनुरोध

13. निम्नलिखित विरोधी पार्टियों ने विचाराधीन उत्पाद तथा समान वस्तु के बारे में अपने तर्क दिए हैं :-

- (क) हुआवी टैक्नोलॉजीज कंपनी लि., चीन जन.गण.
- (ख) हुआवी टैक्नोलाजीज इंडिया प्रा.लि.
- (ग) हुआवी टेलीकम्युनिकेशन (इंडिया) प्रा.लि.
- (घ) एम आर ओ - टैक लि., बंगलौर
- (ङ) जूनीपर नेटवर्क प्रा. लि., इंडिया, एअरसैल लि.
- (च) वोडाफोन एस्सार लि.
- (छ) भारती एअरटैल लिमिटेड
- (ज) सीसीसीएमई
- (झ) पृथ्यी इनफॉरमेशन्स साल्युशंस लि.
- (अ) बुप्पालामृता मैग्नेटिक कंपोनेट्स लि.
- (ट) ईसीआई टेलीकॉम लि.
- (ठ) हैंगजाऊ ई सी आई टेलीकम्युनिकेशन कंपनी लि., चीन जन.गण.
- (ड) ईसीआई टेलीकॉम इंडिया प्रा. लि.
- (ढ) आरएडी डाटा कम्युनिकेशन्स लि.
- (ण) अल्काटेल-लूसेंट शंधाई बैल कंपनी
- (त) टाटा टेली सर्विस
- (थ) फाइबर होम टेलीकम्युनिकेशन टैक्नोलाजीज कंपनी लि.
- (द) जैड टी ई कार्पोरेशन लि., चीन जन.गण.
- (ध) यू टी स्टॉरकॉम
- (न) फिबकॉम
- (प) सिएना, यू एस ए
- (फ) बी एस एन एल
- (ब) तिरुमाला सेवन हिल्स

14. इन हितबद्ध पार्टियों के अनुरोधों का सारांश सामूहिक रूप से निम्नानुसार है :-

### i. उत्पाद का दायरा अति विस्तृत है

क. वर्तमान मामले में विचाराधीन उत्पाद का दायरा अति विस्तृत है ।

ख. डी डब्ल्यू डी एम, सी डब्ल्यू डी एम, माइक्रोवेब रेडियो, बेश केन्द्र, रूटर आदि जैसे उत्पाद पर स्पष्टता के अभाव में सीमाशुल्क विभाग एवं डी आर आई द्वारा पाटनरोधी शुल्क हेतु विचार किया जा रहा है जिसकी वजह से दूरसंचार उपभोक्ताओं के लिए विलंब और उत्पीड़न का मामला बना है । विलंब और उत्पीड़न से बचने के लिए प्राधिकारी को इस संबंध में आवश्यक स्पष्टीकरण जारी करने चाहिए ।

ग. उत्पाद को याचिका में किए गए उल्लेखानुसार टी ई सी दिशानिर्देश, जी आर सं. जी आर/एस डी एच-13/01 जुलाई, 2003, जी आर - एस डी एच-04/03 मार्च, 2005, जी आर/एस डी एच-10/02 मार्च, 2005, जी आर/एस डी एच-08/02 मार्च, 2005 तथा जी आर/एस डी एच-07/01 मार्च, 2005 के अनुसार तैयार किया जाता है । इस आशय का स्पष्टीकरण जारी किया जाए कि पाटनरोधी शुल्क टी ई सी के इन मानकों के अंतर्गत विनिर्मित उत्पादों पर ही लागू होता है ।

घ. जांच शुरूआत संबंधी अधिसूचना में परिभाषित उत्पाद क्षेत्र अति व्यापक है । विशिष्ट रूप से पृथक उत्पाद यथा मल्टीप्लैक्सर को उत्पाद के दायरे में लाना तर्क सम्मत नहीं है ।

ड. डिजिटल क्रास कनेक्ट तथा एड ड्राइड क्रास मल्टीप्लैक्सर एस डी एच उपकरण की विशेषताएं हैं न कि एस डी एच उपकरण की । एस डी एच ट्रांसमिशन उपकरण विशिष्ट प्रौद्योगिकी के होते हैं जिनमें ये विशेषताएं होती हैं ।

च. बेस स्टेशन, माइक्रोवेब, रूटर एवं स्विच, डी डब्ल्यू डी एम तथा सी डब्ल्यू डी एम जैसे कुछ उत्पादों का एस डी एच उत्पादों से ताल्लुक होता है और ये एस डी एच ट्रांसमिशन उपकरण नहीं हैं ।

छ. डी एच सी प्रौद्योगिकियां जांच अवधि के दौरान तेजस द्वारा विनिर्मित अनुषंगी एस डी एच ट्रांसमिशन उपकरणों में उपलब्ध नहीं होती हैं और डी एच सी के लिए जी आर का उल्लेख भी याचिका के पैरा-छ में तेजस द्वारा प्रदत्त जी आर की सूची में नहीं किया गया है ।

ज. विश्व भर में एक वस्तु/उत्पाद के संबंध में ही जांच को सीमित करने की परंपरा रही है । सीमाशुल्क अधिनियम और पाटनरोधी नियमावली में "किसी वस्तु", "कोई वस्तु", "वस्तु", "उत्पाद", "कोई उत्पाद", "उत्पाद", "समान उत्पाद" शब्दों का उपयोग किया गया है । कहीं भी बहुवचनों का उपयोग नहीं किया गया है । इस प्रकार, जिस जांच में एक से अधिक "समान वस्तुएं" शामिल हों, वह आदितः अवैध है ।

झ. उत्पाद को भौतिक विशेषताओं, वाणिज्यिक प्रतिस्थापनीयता की मात्रा, कार्य एवं अंतिम उपयोग, उद्योग विनिर्देशन, कीमत, गुणवत्ता आदि जैसे संकेतकों पर विचार किए बिना व्यापक रूप में परिभाषित किया गया है ।

ज. दोहा दौर के अंतर्गत गठित कार्यदल ने "विचाराधीन उत्पाद" की व्याख्या की है और इसलिए डी जी ए डी को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र का निर्धारण करते समय समस्त संगत तथ्यों की जांच करनी चाहिए ।

ट. प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त पी सी एन के आधार पर इस बात का मजबूत अनुमान लगाया जा सकता है कि आपूर्तिकर्ताओं के साथ तेजस की सीमा एस टी एम-1 से लेकर एस टी एम-64 तक के उत्पादों तक सीमित है ।

ठ. विचाराधीन उत्पाद के अधिकतम संभावित दायरे की वजह से पार्टियां इस जांच द्वारा प्रतिकूलतः प्रभावित हो रही हैं ।

## ii. सीमाशुल्क वर्गीकरण

क. 851762 में प्रदत्त वर्तमान सीमाशुल्क टैरिफ शीर्ष के स्थान पर सही सीमाशुल्क टैरिफ शीर्ष 85176260 को विर्दिष्ट किया जाए ।

ख. उत्पाद का वर्गीकरण गलत और भ्रामक है ।

ग. प्रारंभिक जांच परिणाम के पैरा 5 में एस डी एच ट्रांसमिशन उपकरण का उल्लेख है जबकि शुल्क तालिका में "पूर्ण एस डी एच उपकरणों" का उल्लेख है । लुप्त "ट्रांसमिशन" शब्द ने भ्रम पैदा किया है जो कि सी.शु. अधिसूचना से भी स्पष्ट हो जाता है ।

घ. अस्पष्ट परिभाषा से अनावश्यक उत्पीड़न हुआ है और सी. शु. विभाग ने पाटनरोधी शुल्क की मांग की है जिससे नेटवर्क निर्गम में विलंब हुआ है और दूरसंचार ग्राहकों को असुविधा हुई है ।

ङ. यद्यपि, एस डी एच मल्टीप्लैक्सर 8517.62.60 के अंतर्गत वर्गीकृत हैं, तथापि, तेजस ने केवल 6 अंक (8517.62) का उल्लेख कर नि प्रा को जानबूझकर भ्रमित किया है ।

च. सामान्य सीमाशुल्क नियम के अनुसार असंयोजित अथवा विसंयोजित रूप में प्रस्तुत किसी उत्पाद को पूर्ण अथवा तैयार उत्पाद के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा । एस डी एच उपकरणों के पुर्जों तथा संघटकों पर किसी भी हालत में अर्थनिरूपण के सामान्य नियमों के नियम 2(क) के अनुसार अपूर्ण या तैयार न किए गए उपकरणों के रूप में विचार नहीं

किया जा सकता । इस आशय के उल्लेख के अभाव में भी भारतीय सीमाशुल्क नियम 2(क) को लागू करेगा कि "इसमें सीकेडी/एसकेडी शामिल हैं" ।

छ. शुल्क तालिका में 6 अंकीय कोड से भ्रम पैदा हुआ है क्योंकि आर ए डी उत्पाद 8 अंकीय वर्गीकरण में आते हैं जो 8517.6270/90 हैं ।

iii. उत्पाद के दायरे में एस डी एच ट्रांसमिशन उपकरण के लिए नियम सहायक सामग्री, पुर्जों तथा संघटकों, संबद्ध साफ्टवेयर, पापुलेटिड पी सी पी, विद्युत आपूर्ति, लेजर, चेजेज तथा साफ्टवेयर का अनुचित समावेशन

क. "सहायक सामग्री, संबद्ध साफ्टवेयर और उसके अनिवार्य पुर्जों और संघटकों" के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है । वस्तु क्षेत्र में शामिल किसी भी सहायक सामग्री को विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है ।

ख. संबद्ध साफ्टवेयर का कोई स्पष्ट अर्थ नहीं दिया गया है ।

ग. यह स्पष्ट नहीं है कि क्या पुर्जे या संघटक एक शब्द हैं या दो शब्द । पुर्जे और संघटक क्या हैं और ये सहायक सामग्री से किस प्रकार भिन्न हैं ।

घ. जांच शुरूआत संबंधी अधिसूचना में "एस डी एच ट्रांसमिशन उपकरण आदि के लिए लिए नियत पापुलेटिड पी सी बी, विद्युत आपूर्ति, लेजर, चेसिज और साफ्टवेयर" का उल्लेख है । वस्तु क्षेत्र को सूची के अंत में "आदि" शब्द का उपयोग कर अंतहीन बना दिया गया है ।

ड. विचाराधीन उत्पाद में साफ्टवेयर को शामिल करने के बारे में विरोधाभाष है यदि एस डी एच उपकरण का आयात जी एस एम नेटवर्क जैसे अन्य उपकरण के भाग के रूप में किया जाता है तो एस डी एच कीमत का निर्धारण किस प्रकार किया जाएगा ।

च. तेजस के लिए यह सिद्ध करना जरूरी है कि वह ऐसे पुर्जों और संघटकों का उत्पादन करती है जिन्हें विचाराधीन उत्पाद में शामिल करने की मांग की गई है ।

छ. एस डी एच, उसकी सहायक सामग्री, संबद्ध साफ्टवेयर, पुर्जे एवं संघटक, पापुलेटिड पी सी बी, विद्युत आपूर्ति, लेजर, चेसिज, ई आई केबल, पी सी एम केबल, पावर केवल, रैक, वर्क स्टेशन आदि नाम, विशेषता और उपयोगिता के रूप में विशिष्ट तथा अलग वस्तुएं हैं और इन्हें उत्पाद के क्षेत्र में शामिल नहीं किया जा सकता ।

ज. नियम 5(2) की अपेक्षाएं पूरी नहीं की गई हैं क्योंकि याचिका में सहायक सामग्री, संबद्ध साफ्टवेयर, पुर्जों और संघटकों, पापुलेटिड पी सी बी, विद्युत आपूर्ति, लेजर, चेसिज,

ई आई केबल्स, पी सी एम केबल, पावर केबल, रैक, वर्क स्टेशन आदि के बारे में कोई आंकड़ा और साक्ष्य निहित नहीं है ।

झ. तेजस द्वारा सहायक सामग्री, संबद्ध साफ्टवेयर, पुर्जों तथा संघटकों का पण्य व्यापार नहीं किया जाता है ।

ज. लेजर और रिसीवरों सहित पुर्जों तथा संघटकों का कोई घरेलू उद्योग नहीं है । अतः इन्हें विचाराधीन उत्पाद में शामिल नहीं किया जा सकता ।

ट. एस डी एच ट्रांसमिशन प्रौद्योगिकी में प्रयुक्त पुर्जों, संघटकों और उपकरणों पर भी शुल्क को सीमित रखने के बारे में स्पष्टीकरण जारी किया जाना चाहिए ।

**iv. उपकरण/परियोजना के भाग के रूप में आयातित आयात पर शुल्क नहीं लगाया जा सकता**

क. विचाराधीन उत्पाद में ऐसे कुछेक उत्पाद शामिल हैं, जिनका विनिर्माण याचिकाकर्ता नहीं करता है । यह एक सुविरस्थापित सिद्धांत है कि जब तक घरेलू बाजार में किसी रामान उत्पाद का विनिर्माण नहीं किया जाता है तब तक घरेलू उद्योग को क्षति होने का प्रश्न नहीं उठत है ।

ख. प्रारंभिक जांच परिणाम के अनुसार यद्यपि विचाराधीन उत्पाद में "आकस्मिक सेल्युलर/ब्राउड बैंड उपकरणों के भाग रूप एस डी एच उपकरण" शामिल हैं तथापि, उन्हें शुल्क तालिका में शामिल नहीं किया गया है । चूंकि तेजस केवल अनुषंगी पारंपरिक एस डी एच उपकरणों का संयोजन करती है, इसलिए उसके पास सेल्युलर/ब्राउड बैंड उपकरणों पर शुल्क की मांग करने का कोई अधिकार नहीं है ।

**v. याचिकाकर्ता द्वारा जिस उत्पाद का उत्पादन नहीं किया जाता है, उसे उत्पाद के क्षेत्र में शामिल नहीं किया जा सकता ।**

क. याचिकाकर्ता केवल सीमित प्रौद्योगिकी की क्षमता के ही उत्पाद का उत्पादन करने में सक्षम है परंतु उसने क्षति के बारे में अपुष्टिकृत दावे के बावजूद अंतिम उच्च उपकरण को शामिल करने की मांग की है ।

ख. याचिकाकर्ता के पास एस टी एम 64 का कोई वाणिज्यिक स्थापन नहीं है । अतः याचिकाकर्ता के एस टी एम 64 के साथ बाजार में आयातित वस्तु की प्रतिस्पर्धा का प्रश्न नहीं उठता है ।

ग. विचाराधीन उत्पाद की परिभाषा में समुचित सुधार किया जाना चाहिए ताकि मल्टीप्लैक्सर का उल्लेख करते हुए प्रारंभिक जांच परिणाम के खासकर पैरा 6 में तेजस द्वारा उत्पादित उपकरणों को ही शामिल किया जा सके ।

घ. इस क्षेत्र के सबसे बड़े पी एस यू ने भी यह उल्लेख किया है कि तेजस ने एस टी एम 64 तथा डी एक्स सी उत्पादों की संविदाओं हेतु बोली नहीं लगाई है । इस प्रकार बी एस एन एल के अनुसार भी तेजस एस टी एम 64, एस टी एम 256 तथा डी एक्स सी उत्पादों को विनिर्माण नहीं करती है ।

ङ. प्राधिकारी को विचाराधीन उत्पाद को अधिक यथार्थ रूप में तथा चयनात्मक रूप में परिभाषित करना चाहिए और वास्तविक उत्पादों के बारे में तेजस से विशिष्ट घोषणा की मांग करनी चाहिए ।

च. विचाराधीन उत्पाद को गलत ढंग से परिभाषित किया गया है ताकि उसमें तेजस द्वारा विनिर्मित न किए गए उन एस डी एच ट्रांसमिशन उपकरणों को शामिल किया जा सके जो तेजस द्वारा विनिर्मित उपकरणों के "समान वस्तु" नहीं हैं ।

छ. प्रारंभिक जांच परिणामों के पैरा 97 में बी एस एन एल प्रमाण पत्रों, बी एस एन एल के आपूर्ति प्रमाण पत्रों तथा आई टी आई लि. के प्रमाण पत्रों और भारत इलैक्ट्रोमिक्स के प्रमाण पत्रों से यह सिद्ध होता है कि तेजस केवल एस टी एम-1, एस टी एम-4 और एस टी एम-16 का विनिर्माण करता है न कि एस टी एम 64 और एस टी एम 256 का । । । । ।

ज. चूंकि तेजस ने स्वयं यह स्वीकार किया है कि एस टी एम-1, एस टी एम-4 और एस टी एम-16 से भिन्न उपकरणों को विचाराधीन उत्पाद से अलग रखा जाए, इसलिए विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र को पुनः निर्धारित करने की जरूरत है ।

झ. जिन एस डी एच उपकरणों तथा पुर्जों तथा संघटकों का विनिर्माण तेजस नहीं करती है, उन्हें विचाराधीन उत्पादों से अलग रखा जाना चाहिए ।

ञ. जिन ग्रेडों का तेजस उत्पादन नहीं करती है उन्हें जांच के दायरे से अलग रखा जाना चाहिए । अतः इसी आई के आधारित उपकरणों को अलग रखा जाना चाहिए क्योंकि तेजस ऐसे उत्पादों की पेशकश नहीं करती है ।

ट. बी एस एन एल ने इस बात की पुष्टि की है कि तेजस ने कभी भी एस टी एम-4, ओ-ई-ओ आधारित डी एक्स सी उपकरणों की निविदाओं में भाग नहीं लिया है । तदनुसार एस डी एच की इस श्रेणी और उसके विनिर्माण में प्रयुक्त पुर्जों तथा संघटकों को विचाराधीन उत्पाद के दायरे से अलग रखा जाना चाहिए ।

vi. ऐसे पुर्जों/संघटकों का दोहरा उपयोग, जिन्हें परिभाषित करना कठिन है

क. तेजस के लिए यह स्पष्ट करना अपेक्षित है कि किन संघटकों का आयात किया गया है और किस वजह से उन्हें दोहरे उपयोग वाला माना गया है ।

ख. पी सी बी में निहित आई सी को विशिष्ट रूप से एस डी एच उपकरणों के लिए तैयार किया जाता है और इसलिए यह समझना कठिन है कि उनका दोहरा उपयोग किस प्रकार हो सकता है ।

ग. इस बात का भेद करना कठिन है कि किस पुर्जे का अनन्य उपयोग होता है और किस पुर्जे का दोहरा उपयोग होता है, अतः ऐसा कोई वर्गीकरण द्विअर्थी एवं अस्पष्ट है ।

घ. यदि संघटकों के आयात की गणना तब की जाती है जब उनका उक्त उत्पाद के लिए अनन्य उपयोग होता हो तो तेजस द्वारा उपबंध का दुरुपयोग करने की संभावना बनती है क्योंकि दोहरे उपयोग के उत्पादों की गणना नहीं की जाएगी ।

च. जैसा कि स्वीकार किया गया है, कि कुछेक संघटकों और पुर्जों का वैकल्पिक उपयोग (एस डी एच से इतर) होता है, शुल्क लगाए जाने का गंभीर प्रचालनात्मक प्रभाव पड़ेगा जिससे मुकदमेबाजी शुरू होगी तथा अनावश्यक लागत आएगी और भारत में आयातकों तथा प्रयोक्ताओं के लिए प्रतिकूल परिणाम होंगे ।

च. लेजरों और रिसीवरों का बहुविद उपयोग (एस डी एच से पृथक) होता है और भारतीय प्रयोक्ता 100% आयात पर निर्भर होते हैं । लेजरों और रिसीवरों को विकल्प नहीं है ।

छ. डी जी ए डी को वैकल्पिक उपयोग वाले संघटकों को अलग रखना चाहिए और ऐसे संघटकों को शामिल करना चाहिए जिनका एस डी एच उपकरणों के उत्पादन में अनन्य रूप से उपयोग होता हो ।

### vii. अन्य मुद्दे

क. उपभोक्ता परिकल्पना को भी विचाराधीन उत्पाद के निर्धारण में महत्व दिया जाना चाहिए ।

ख. हुआबी एस टी एच उत्पादों और तेजस के उत्पादों के बीच काफी अंतर हैं । हुआबी अपने खुद के ए एस आई सी का उत्पादन करती है जबकि तेजस ऐसी नहीं करती है । आई/पी के लिए तेजस ई पी जी ए वैंडर पर आश्रित हैं । उनके उत्पाद डीजल लोकोमोटिव और स्टीम लोकोमोटिव इंजनों के समान हैं अर्थात् दोनों का उपयोग रेल गाड़ी को खीचने के लिए किया जाता है । परंतु ये समान वस्तुएं नहीं हैं क्योंकि इनमें अंतर समानताओं से काफी दूर है ।

ग. तेजस ने विरोधाभाषी तर्क दिए हैं। एक ओर वह कहती है कि विदेशी उत्पादक अपने देश में आर एंड डी करते हैं और उनके वृद्धिकारी कार्यकलाप करने के लिए ही भारत में कार्यालय हैं। दूसरी ओर वह यह दावा करती है कि विदेशी उत्पादकों ने भारत में कम श्रम लागत का लाभ उठाने के लिए यहां विकास केन्द्र खोले हैं और इन कंपनियों द्वारा सृजित आई पी विदेशों में वास करती है।

घ. सार्वजनिक सुनवाई के दौरान तेजस के खुद की स्वीकारोक्ति के अनुसार (कि कुछेक उत्पाद विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से अलग रखे जाने की पात्रता रखते हैं), अब पूरी कार्यवाही को घ. उ. के क्षेत्र, विचाराधीन उत्पाद जैसे पहलुओं के संबंध में निर्धारित करने की जरूरत है। पाटन मार्जिन, क्षति विश्लेषण का पुनः निर्धारण विचाराधीन उत्पाद के नए निर्धारण के अनुसार पुनः किया जाना चाहिए।

ड. प्रौद्योगिकी एवं कार्यचालनत्मकता में अंतर के कारण एस डी एच उपकरणों के अलग-अलग प्रकारों पर एक-दूसरे के स्थान पर तकनीकी या वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय होने पर विचार नहीं किया जा सकता। न ही ये उत्पाद दो अलग-अलग विनिर्माताओं के हैं।

च. नि. प्रा. इस बात का पता लगाने में विफल रहे हैं कि क्या संबद्ध देशों से हुए आयात तेजस वस्तुओं के समान हैं और क्या प्रतिस्पर्धा की स्थितियां क्षति निर्धारण हेतु संचयन को न्यायोचित ठहराने के लिए भी एक समान हैं। वास्तविक प्रयोक्ताओं ने भी रिकॉर्ड में ऐसी सामग्री प्रस्तुत की है कि तेजस के पास ऐसी प्रौद्योगिकी नहीं है जो आयातित संबद्ध वस्तु के लिए उपलब्ध है।

छ. विचाराधीन उत्पाद एस डी एच ट्रांसमिशन उपकरण है। यदि कंपनी ने अन्य उत्पादों की बिक्री की है तो उसे विचाराधीन उत्पाद के दायरे में किसी भी हालत में शामिल नहीं किया जाना चाहिए।

ज. जब आर ए डी द्वारा "एस डी एच-1 इंटरफेस" से युक्त "अलग प्रौद्योगिकी उपकरण" का आयात किया जा रहा है तो "अलग प्रौद्योगिकी उपकरण" के संपूर्ण मूल्य पर शुल्क नहीं लगाया जाएगा अपितु एस डी एच-1 प्रौद्योगिकी से जुड़े पुर्जों पर ही लगाया जाएगा।

झ. आर ए डी द्वारा एस टी एम-1 इंटरफेस के कुछेक उत्पादों का निर्यात किया जाता है जिनमें एक्सिस प्रौद्योगिकी का उपयोग होता है न कि एस डी एच प्रौद्योगिकी का। इन उत्पादों का एस डी एच उपकरणों के समान उपयोग नहीं होता है। एस टी एम-1 इंटरफेस वाले अधिकांश उत्पाद एस डी एच वातावरण में कार्य नहीं करते हैं क्योंकि उनका उपयोग एस डी एच नेटवर्क (एक्सिस टर्मिनल) को आंकड़े एवं ध्वनि संप्रेषण हेतु किया जाता है और ये एस डी एच ट्रांसमिशन नहीं होते हैं। अतः उत्पाद क्षेत्र में संशोधन किया जाना चाहिए ताकि उसमें एस टी एम-1 इंटरफेस वाले उत्पादों सहित आर ए डी उत्पादों को अलग रखा जा सके।

ज. कोर डायरेक्टर निर्विवाद रूप से क्षमता, कार्यचालनात्मकता, तकनीकी विनिर्देशन और अंतिम उपयोग के संबंध में विशिष्ट उत्पाद है। कोर डायरेटक्टर हेतु तकनीकी विनिर्देशनों को तेजस की याचिका में प्रदत्त विनिर्देशनों में शामिल नहीं किया गया है। कोर डायरेक्टर को उच्चतम रूप से रखा जाता है जो मल्टीपिल स्रोतों से इनपुट आंकड़ों को संयोजित करता है और उन्हें विशेष युक्ति द्वारा संचार माध्यम के आधार पर नेटवर्क पर प्रेषित करता है जबकि संबद्ध वस्तु का रूपरेखा निम्न होता है।

ट. सिएना द्वारा यू एस ए से कोर डायरेक्टर का निर्यात किया जा रहा है। इसके उत्पाद का संयोजन सिएना के विनिर्देशनों और अपेक्षाओं के अनुसार और यू एस ए तथा भारत में सिएना द्वारा किए गए आर एंड डी के अनुसरण में चीन जन.गण. के एक संविदा विनिर्माता द्वारा किया जाता है।

ठ. कोर डायरेक्टर में अधिकांश मूल्यवर्धन डिजायन एवं विकास के रूप में होता है जो अमरीका या भारत में किया जाता है और ऐसा चीन जन.गण. में नहीं होता है। सिएना को दूर संचार उत्पादों का एक ज्ञात अमरीकी उत्पादक माना गया है। चूंकि संबद्ध देशों से इतर एक देश अमरीका में सिएना का आर एंड डी कार्य होता है, इसलिए कोर डायरेक्टर को जांच के दायरे से अलग रखा जाना चाहिए।

ड. लगभग 99% सहायक सामग्री तथा पुर्जे एवं संघटकों का या तो आयात किया जाता है या तेजस द्वारा उसकी स्थानीय खरीद की जाती है और इसलिए तेजस को विचाराधीन उत्पाद के एक समूह का उत्पादक नहीं माना जा सकता।

ढ. विचाराधीन उत्पाद को सर्वप्रथम श्रेणीबद्ध किया जाना चाहिए और इन श्रेणियों के आधार पर पाटन मार्जिन तथा पाटनरोधी शुल्क का निर्धारण एवं संस्तुति कीजानी चाहिए क्योंकि नि प्रा ने स्टेनलैस इसपात के कोल्ड रोल्ड फ्लैड उत्पादों तथा लैड एसिड बैटरियों के मामले में ऐसा किया है।

#### याचिका का आधार और घरेलू उद्योग का क्षेत्र विस्तार याचिकाकर्ता के अनुरोध

14 क. याचिकाकर्ता ने निम्नलिखित तर्क दिए हैं:-

क. याचिकाकर्ता ने वह सूचना प्रदान की है जो पर्याप्त और सही है जिससे स्पष्टतः यह सिद्ध होता है कि याचिकाकर्ता का उत्पादन भारतीय उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा बनता है।

ख. वी एम सी एल, पृथ्वी जैसी अन्य पार्टियों को नियमानुसार घरेलू उद्योग नहीं माना जा सकता।

ग. वायस एंड डाटा, कम्युनिकेशन्स टुडे जैसी समस्त प्रकाशित सूचना से इस बात की पुष्टि होती है कि याचिकाकर्ता देश में इस उत्पाद का एक बड़ा उत्पादक है और घरेलू विनिर्माता का दावा करने वाली वी एम सी एल तथा पृथ्वी जैसी अन्य पार्टियां घरेलू विनिर्माता ही नहीं हैं ।

घ. सी एम ए आई, टी ई एम ए जैसी प्रमुख औद्योगिक एसोसिएशनों की सूचना से भी यह सिद्ध होता है कि याचिकाकर्ता एक प्रमुख उत्पादक है ।

ड. यद्यपि, पृथ्वी, वी एम सी एल, हुआवी जैसी कंपनियां उत्पादक मानी जाती हैं, तथापि उन्हें इस तथ्य के मद्देनजर कि वे विचाराधीन उत्पाद का बड़ी मात्रा में आयात कर रहे हैं, नियम 2(ख) के अंतर्गत पात्र उत्पादक के रूप में स्वीकार नहीं की जा सकती ।

च. इस याचिका का समर्थन मै. मेजरमेंट एंड कंट्रोल्स लि. तथा कोरल ने किया है ।

छ. वर्तमान विचाराधीन उत्पाद के प्रयोजनार्थ उत्पादन में अनुसंधान, उत्पाद परिकल्पना, डिजाइन एवं ड्राइंग, प्रौद्योगिकी विकास, कार्यचालनात्मकता की परिकल्पना एवं समझ, उत्पाद का ब्लू प्रिंट तैयार करने, संबद्ध साफ्टवेयर के विकास, उत्पाद के प्रोटोटाइप के विकास(हार्डवेयर व साफ्टवेयर), संघटक खरीद, सोल्डरिंग तथा ई एम एस कार्यकलाप, एकीकरण, टेस्ट जिग की तैयारी, संयोजन, परीक्षण तथा उत्पाद सहायता एवं बग फिक्सेज जैसे कार्यकलाप शामिल होते हैं । जब तक कोई कंपनी ये समस्त कार्यकलाप नहीं करती है तब तक उसे उत्पाद के घरेलू उत्पादक के रूप में मान्यता नहीं दी जा सकती ।

ज. जहां तक तेजस द्वारा आयातों का संबंध है, याचिकाकर्ता ने निम्नलिखित तर्क दिए हैं:-

(i) याचिकाकर्ता को इस बात के होते हुए भी कि उनके द्वारा संघटकों अथवा उप संयोजनों का पूरक आयात किया जा रहा है, वर्तमान याचिका दायर करने हेतु एक पात्र घरेलू विनिर्माता माना जाना चाहिए ।

(ii) याचिकाकर्ता ने नियम 2(ख) के अंतर्गत घरेलू उद्योग माने जाने को न्यायोचित ठहराने हेतु पर्याप्त व्यौरे उपलब्ध कराए हैं । इनमें शामिल हैं (क) तेजस द्वारा खपत की गई सामग्री का चीन जन.गण., इजराइल और तीसरे देशों से आयातित संघटकों में विभाजन (तेजस द्वारा किए गए प्रत्यक्ष आयात अथवा तेजस द्वारा आयातित उप संयोजन दोनों), (ख) उत्पादन के विभिन्न चरणों में तेजस द्वारा व्यय की गई अनुसंधान एवं विकास लागत, (ग) घरेलू एवं आयातों में कुल खरीदों का विभाजन (घ) संघटकों एवं संयोजनों की देशवार खरीद (घ) दोहरे उपयोग के संघटकों और एस डी एच आवेदन में उल्लिखित संघटकों के संबंध में विभिन्न मदों

के बारे में चीन जन.गण. से आयातित पुर्जे/संघटकों का ब्यौरा (जिससे यह पता चलता है कि प्रिंटेट सर्किट बोर्डों को छोड़कर चीन जन.गण. से आयातित पुर्जे/संघटक ऐसे पुर्जे और संघटक हैं जिनका विचाराधीन उत्पाद में अनन्य उपयोग नहीं होता है । याचिकाकर्ता ने यह भी दावा किया है कि प्रिंटेट सर्किट बोर्डों का उत्पादन भी याचिकाकर्ता द्वारा प्रदत्त डिजाइन के अनुसार किया जाता है) ।

(iii) सत्यापित आंकड़ों के आधार पर यह देखा जाता है कि याचिकाकर्ता द्वारा आयातित चीन के पुर्जे/संघटकों का मूल्य नगण्य है ।

झ. तेजस द्वारा उजरती कार्य संविदा आधार पर ई एस एस की सेवाएं ली जाती हैं । ई एम एस सेवाओं के इस उपयोग की तुलना उस ढंग से नहीं की जा सकती जिस ढंग से वी एम सी एल/पृथ्वी जैसी कंपनियां प्रचालन कर रही हैं । विशिष्टीकृत एजेंसियों (ई एम एस) के लिए विनिर्भित उप संविदा संघटक अथवा कार्ड किसी अन्य एस डी एच विनिर्माता से खरीदे गए ऐसे संघटकों या कार्डों से काफी अलग होते हैं और तत्पश्चात उत्पाद का संयोजन किया जाता है । याचिकाकर्ता ने कंपनियों के प्रमुख व्यापार कारोबार, आयातित मद की प्रकृति, आयातों के कारण, आयातों का प्रयोजन और क्या कंपनी का मुख्य ध्यान उत्पाद के आयात अथवा उस देश में विनिर्माण पर केन्द्रित है, जैसे मापदंडों के संदर्भ में अपने विनिर्माण कार्यकलापों की तुलना वी एम सी एल, पृथ्वी जैसी कंपनियां हुआवी के एक एजेंट के रूप में वस्तुतः कार्य कर रही हैं- सीकेडी/एसकेडी स्थितियों में उत्पाद की खरीद करने, उत्पाद के संयोजन एवं परीक्षण हेतु हुआवी प्रौद्योगिकी का उपयोग करना तथा बग फिक्स करना । वी एम सी एल/पृथ्वी के पास एस डी एच उपकरण के उत्पादन हेतु अपेक्षित तकनीकी विशेषज्ञता का अभाव है और ये उत्पाद की बड़ी आयातक रही हैं ।

ट. भारत में केवल वृद्धिकारी कार्यकलाप करने वाली किसी कंपनी को तब तक अपात्र धरेलू विनिर्माता माना जाना चाहिए जब तक कि ऐसी कंपनी (i) निविष्टि को उत्पादन में पर्याप्ततः रूपांतरित करने के लिए भारत में उत्पादन कार्यकलाप कर रही है (ii) विचाराधीन उत्पाद का पर्याप्त मात्रा में आयात कर रही है और/अथवा वे संबद्ध देशों के संबद्ध वस्तु की विदेशी उत्पादकों से संबंधित नहीं हैं । (iii) मुख्य ध्यान पूरक संयोजन वाले आयातों अथवा भारत में परीक्षण प्रचालनों पर केन्द्रित नहीं है । भारतीय बाजार में एस डी एच उपकरण के विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं को दो श्रेणियों में बाटा जा सकता है - (क) ऐसी कंपनियां जो पूर्ण उत्पाद जीवन चक्र से संबंधित व्यय करती हैं, जिसमें प्रौद्योगिकी विकास, अनुसंधान एवं विकास तथा भारत में विनिर्माण शामिल हैं, और (ख) ऐसी कंपनियां जो प्रमुख उत्पाद संबंधी व्यय करती हैं, जिसमें प्रौद्योगिकी विकास, अनुसंधान व विकास व भारत से बाजर विनिर्माण शामिल हैं और तेयार उत्पाद का भारत को निर्यात अंतिम संयोजन/जांच संबंधी अनुदेशों के साथ संयोजित अथवा सी के डी/एस के डी स्थिति में करती हैं ।

ठ. अनुसंधान एवं विकास कार्यकलाप तथा उत्पादन - याचिकाकर्ता ने जोरदार ढंग से यह तर्क दिया है कि किसी कंपनी को उत्पादक तभी माना जा सकता है जब वह देश के भीतर पर्याप्त अनुसंधान एवं विकास करती हो । अनुसंधान एवं विकास से संबंधित अन्य हितबद्ध पार्टियों के तर्कों का खंडन करते हुए याचिकाकर्ता ने यह तर्क दिया है कि इस देश में अनुसंधान एवं विकास को कई उप श्रेणियों में बांटा जा सकता है जिनमें शामिल हैं (क) एस टी एच प्रौद्योगिकी वाले किसी उपकरण के उत्पादन हेतु अपेक्षित मूलभूत अनुसंधान, (ख) उत्पाद की किसी नई श्रृंखला (अर्थात् एस टी एम 4, एस टी एम 16, एस टी एम 64, एस टी एम 256 के उत्पादन के लिए अपेक्षित अनुसंधान), (ग) इन श्रृंखलाओं में किसी विशेष मॉडल (अर्थात् एस टी एम 4 या एस टी एम 16 के विभिन्न प्रकार) के विकास के लिए अपेक्षित अनुसंधान, (घ) प्रत्येक मॉडल के बड़े पैमाने पर उत्पादन हेतु अपेक्षित अनुसंधान एवं विकास । याचिकाकर्ता ने आगे यह तर्क दिया है कि यहां तक कि लेखा मानकों और आयकर प्राधिकारियों द्वारा किसी अनुसंधान या विकास संबंधी व्यय को राजस्व या पूँजी खाते में प्रभारित करने की अनुमति नहीं दी जाती है । क्या अनुसंधान एवं विकास पर किया गया कोई व्यय राजस्व खाते में प्रभावित किया जाएगा अथवा क्या पूँजीकरण कंपनी द्वारा किए गए अनुसंधान के स्वरूप पर निर्भर होगा । कंपनी ने यह प्रदर्शित करते हुए अपनी बहियों से सूचना प्रदान की है कि (क) कुल व्यय को अनुसंधान डिजाइन एवं विकास संबंधी व्यय तथा परीक्षण एवं संयोजन सहित विनिर्माण व्यय में विभाजित करना (ख) कुल अनुसंधान एवं विकास व्यय को राजस्व खाते एवं पूँजीकृत राशि में प्रभारित राशियों में विभाजित करना । (ग) ऐसे अनुसंधान का स्वरूप जिसमें व्यय का पूँजीकरण नहीं किया गया है और जहां व्यय को राजस्व खाते में प्रभारित किया गया है । इसके अलावा, याचिकाकर्ता ने तेजस, पृथ्वी, वी एम सी एल तथा हुआबी द्वारा किए गए विभिन्न अनुसंधान एवं विकास कार्यकलापों की तुलना (क) भारत में आई पी आर निवासी के साथ भारत में अनुसंधान (ख) भारत में डिजाइन एवं विकास (ग) भारत एवं अन्य देशों में ई एम एस संविदा विनिर्माण (घ) संयोजन एवं परीक्षण प्रक्रिया (ड) भारत में "विनिर्देशन विकास" (च) भारत में अंतिम संयोजन एवं परीक्षण (छ) भारत में की गई बिक्री पश्चात "बग फिक्स/संवर्धन/उन्नयन" (ज) बिक्री पश्चात - भारत में पुर्जों की आपूर्ति/प्रौद्योगिकी सहायता के संबंध में की है और यह दावा किया है कि पृथ्वी और वी एम सी एल द्वारा भारत में केवल संयोजन प्रचालन किए जाते हैं और हुआबी भारत से बाहर अपने अधिकांश प्रचालन करती है ।

### उत्पादन का तात्पर्य

15. याचिकाकर्ता ने तर्क दिया है कि कंपनी द्वारा किए गए कार्यकलाप पृथ्वी, हुआबी जैसी अन्य कंपनियों द्वारा किए गए उत्पादन एवं कार्यकलाप हैं और वी एम सी एल का उत्पादन मान्य नहीं है । याचिकाकर्ता ने कई तर्क दिए हैं जो संक्षेप में निम्नानुसार हैं :-

i. उत्पादन का तात्पर्य सभी उत्पादों में एक समान नहीं हो सकता । वर्तमान जांच में जांच के प्रयोजनार्थ उत्पादन का तात्पर्य ऐसे उत्पादन कार्यकलाप से होगा जिसके परिणामस्वरूप "विचाराधीन उत्पाद" का "उत्पादन" होता हो । इसके अलावा

उत्पाद की पहचान उत्पाद विशेषताओं, उत्पादन प्रौद्योगिकी, उत्पादन प्रक्रिया, कार्य एवं उपयोग, कीमत एवं सीमाशुल्क वर्गीकरण जैसे कई मापदंडों के संबंध में की जाती है। एस डी एच उपकरण के उत्पादन में अंतर्गत कई कदम/चरण होते हैं जिनमें परिकल्पना, विस्तृत ड्राइंग तथा डिजाइन (ब्लू प्रिंट) को तैयार करना शामिल है।

- ii. प्रचालनात्मक अपेक्षाओं के आधार पर तेजस अपेक्षित विशिष्ट संघटकों की पहचान करती है और विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर घटकों का विकास करती है, जिससे अपेक्षित प्रचालन के संबंध में ऐसा हार्डवेयर कार्य करता है। हार्डवेयर के ब्लू प्रिंट और विकसित किए गए साफ्टवेयर के आधार पर एक पूर्णतः प्रचालनात्मक प्रोटोटाइप तैयार किया जाता है। इस "प्रोटोटाइप" में हार्डवेयर एवं उपकरण के प्रचालन हेतु आवश्यक खचित साफ्टवेयर तथा नेटवर्क में अन्य उपकरण के साथ उसकी उपयुक्तता निहित होती है जैसा कि नेटवर्क प्रबंधन प्रणाली के जरिए देखा जाता है। तेजस द्वारा विकसित प्रोटोटाइप की जांच परीक्षण विनिर्देशनों और परीक्षण साफ्टवेयर के उपयोग द्वारा की जाती है। एक पूर्ण प्रचालनात्मक पोटोटाइप में चेसिज, रैक, पी सी बी, केबल साफ्टवेयर आदि शामिल होते हैं। एस डी एच प्रोटोटाइप की जांच के बाद तेजस की जरूरत के अनुसार पी सी बी पर संघटकों की सोल्डरिंग हेतु ई एम एस को निर्देश दिए जाते हैं। मुख्यतः सोल्डरिंग कार्यकलापों के लिए कुछेक संयोजन प्रचालनों के निष्पादन हेतु कैरियर मीडिया पर ई एम एस को विभिन्न साफ्टवेयर भी मुहैया कराए जाते हैं। ई एम एस द्वारा सोल्डर्ड अकार्यचालनात्मक पी सी बी की आपूति एस डी एच उपकरण के रूप में भारत में तेजस विनिर्माण सुविधा को की जाती है जब तक कि उसे समेकित न किया गया हो और उसकी जांच चेसिज, रैक, केबल, साफ्टवेयर घटकों जैसे तेजस के ग्राहकोनुकूल संघटकों के साथ न की गई हो। एकीकरण कार्यकलाप के बाद कड़ी जांच, डीबिंग तथा गुणवत्ता नियंत्रण का कार्य किया जाता है। जांच, डीबिंग एवं रिवर्किंग कार्यकलाप में विशेष टैस्ट जिग, जांच विनिर्देशन तथा साफ्टवेयर की जांच शामिल होती है जो एस डी एच उपकरण की विनिर्माण प्रक्रिया में महत्वपूर्ण है।
- iii. पाटनरोधी कानून में यह परिभाषित नहीं है कि "उत्पादन" अथवा "विनिर्माण" किसे माना जाएगा। "घरेलू उत्पादक" के दायरे का तात्पर्य अधिनियम की धारा 9क और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों की विषयवस्तु के प्रयोजनार्थ निकाला जाएगा। इसके अलावा नियमों में घरेलू उद्योग एवं घरेलू विनिर्माता के बीच भेद किया गया है। सभी घरेलू उत्पादक घरेलू उद्योग नहीं होते हैं।
- iv. पाटन कानून के अंतर्गत घरेलू उद्योग के क्षेत्र को समझने के प्रयोजनार्थ अन्य विधानों के अंतर्गत "विनिर्माण" की परिभाषा को नहीं लिया जा सकता। इस सिद्धांत को काजी नुरुल एचएच पैट्रोल पंप बनाम उप निदेशक, ई एस आई कार्पोरेशन, 2009 (240) ई एल टी 481 (एस सी) में सूचित के मामले में मार्गनीय उच्चतम न्यायालय के हाल के निर्णय में विधिवत निर्धारित किया गया है। ऐसी कई संविधियां हैं, जिनमें "विनिर्माण", "विनिर्माण प्रक्रिया" अथवा "विनिर्माता" एवं को परिभाषित किया गया है। उदाहरणार्थ इनमें जागील हैं- फैक्टरी
- v.

अधिनियम, 1948, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986, बीड़ी एवं सिगार कामगार अधिनियम, 1966 तथा भारत माप मानक अधिनियम, 1976, विदेश व्यापार नीति । इन संविधियों में उत्पादन की परिभाषा काफी अलग-अलग है जिससे यह सिद्ध होता है कि किसी कंपनी को केवल उत्पाद शुल्क का भुगतान करने और इसीलिए उत्पाद शुल्क कानून के अंतर्गत एक उत्पादक के रूप में माने जाने पर वर्तमान कानून के प्रयोजनार्थी भी उत्पादक माना जाना चाहिए ।

- vi. पाटनरोधी कानून के अंतर्गत उत्पादक के निर्धारण हेतु संगत विचार होंगे- भारत में निवेश का स्तर किए गए कार्यकलापों में शामिल तकनीकी विशेषज्ञता, भारत में मूल्यवर्धन की सीमा, रोजगार के स्तर और अन्य लागत तथा भारत में किए गए कार्यकलाप, जिसके परिणामस्वरूप वस्तु का उत्पादन होता है ।
- vii. उत्पाद के मूल्य का अत्यंत महत्वपूर्ण भाग भारत में विकसित साफ्टवेयर होता है, जिसे आंशिक रूप से ई एम एस द्वारा संयोजन के स्तर पर लोड किया जाता है और आंशिक रूप से इसका उपयोग भारत में जांच, डिब्जिंग एवं रिवर्किंग के लिए किया जाता है और इसे एस डी एच नेटवर्क के कार्यचालन हेतु प्रयोक्ताओं को भी मुहैया कराया जाता है । साफ्टवेयर के विकास में वस्तु का उत्पादन भी निहित होता है ।
- viii. माननीय उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने इस बात पर विचार किया कि क्या "वस्तु" शब्द में साफ्टवेयर शामिल होगा और इसलिए क्या साफ्टवेयर विकास को वस्तु का उत्पादन मना जाएगा ।
- ix. तेजस द्वारा भारत में साफ्टवेयर विकसित किया जाता है जिसका एक भाग कैरियर मीडिया पर ई एम एस को उपलब्ध कराया जाता है और ऐसे कार्यकलाप को तेजस द्वारा "वस्तु" का उत्पादन मना जाता है ।
- x. तेजस द्वारा ई एम एस से वापस प्राप्त वस्तु के पश्चात पर्याप्त कार्यकलाप भी किए जाते हैं । इस चरण पर वह उत्पाद एस डी एच उपकरण के रूप में कार्य करने योग्य नहीं होता है और वह उत्पादन के मध्यम चरण में होता है । तेजस द्वारा "इन हाउस" विकसित साफ्टवेयर, जांच विनिर्देशनों एवं जांच प्रक्रिया द्वारा संयोजन एवं जांच कार्यकलाप किए जाते हैं । तेजस द्वारा "नेटवर्क प्रबंधन साफ्टवेयर, घटक प्रबंधन साफ्टवेयर, अनुप्रयोग साफ्टवेयर आदि" जैसे अन्य एस डी एच साफ्टवेयर घटकों का विकास भी किया जाता है जो एस डी एच नेटवर्क के कार्यचालन के लिए आवश्यक होते हैं ।
- xi. जहां तक इस तर्क का संबंध है, कि उजरती कामगार भी एक विनिर्माता होता है, तेजस ने यह तर्क दिया है कि जहां समूची प्रक्रिया उजरती कामगार द्वारा की जाती है, वहां उसके लिए विनिर्माता का दर्जा हासिल किया जा सकता है । तथापि, जहां उत्पादन कार्यकलाप के एक भाग को ही आउटसोर्स किया जाता है और पर्याप्त कार्यकलाप विनिर्माता द्वारा किए जाते हैं, वहां यह नहीं कहा जा सकता कि तैयार वस्तु के विनिर्माता के रूप में कुछेक प्रक्रियाओं की आउटसोर्सिंग के कारण उसकी पहचान खो गई है ।

xii. माननीय उच्चतम न्यायालय ने श्रीराम विनायल एंड कैमिकल इंड बनाम सी सी, मुंबई, 2001 (129) ई एल टी 278 (एस सी) में सूचित, के मामले में यह निर्णय दिया है कि संयोजन को बाह्य विनिर्माण के बराबर नहीं माना जा सकता । यूनाइटेड टेलीकॉम्स लि. बनाम सी सी, बंगलौर, 2009 (241) ई एल टी 380 (टी) के मामले में यह निर्णय दिया गया है कि मोबाइल फोन तब तक नहीं बनते हैं जब तक कि विनिर्माता द्वारा उनमें साफ्टवेयर लोड न कर दिया गया हो । अतः क्या मात्र संयोजन विनिर्माण होगा, यह प्रत्येक मामले के तथ्यों पर आधारित होगा । मात्र इस वजह से कि एस डी एच उपकरण के उत्पादन में शामिल प्रक्रियाओं में से एक या दो प्रक्रियाओं को आउटसोर्स किया गया है, यह नहीं कहा जा सकता कि तेजस एस डी एच उपकरण का उत्पादक नहीं है ।

xiii. विनिर्माण की सामान्य परिभाषा के अंतर्गत वी एम सी एल तथा पृथ्वी द्वारा किए गए कार्यकलाप विनिर्माण कार्यकलाप नहीं होंगे, यदि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम में ऐसा मान्य प्रावधान न किया गया होता । किसी मान्य प्रावधान का तात्पर्य कढाई से और उस अधिनियम में अधिनियमित प्रयोजन के लिए ही निकालना होता है ।

xiv. याचिकाकर्ता ने तेजस और आयातकों द्वारा किए गए विभिन्न कार्यकलापों की तुलना उपलब्ध कराई है । याचिकाकर्ता ने तर्क दिया है कि वर्तमान उत्पाद के प्रयोजनार्थ उत्पादन का तात्पर्य विनिर्देशन विकास तथा किए गए अनुसंधान एवं विकास के आधार पर हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर की डिजाइनिंग आपूर्तिकर्ताओं के साथ सहयोगात्मक संघटक विकास, प्रोटोटाइप उत्पाद विकास, भारत में नेटवर्क प्रबंधन साफ्टवेयर का विकास, जांच प्रक्रियाओं का विकास, भारत में जांच विनिर्देशनों एवं जांच साफ्टवेयर का विकास, भारत में हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर के विनिर्देशन एवं गुणवत्ता के संदर्भ में उत्पाद सत्यापन, पूर्ण एस डी एच प्रोटोटाइप (संयुक्त रूप से हार्डवेयर + साफ्टवेयर) के विनिर्देशन एवं गुणवत्ता के संदर्भ में संपूर्ण सत्यापन, बोर्ड विनिर्माण, एस डी एच साफ्टवेयर में साफ्टवेयर की स्थापना, पूर्ण एस डी एच बॉक्स (हार्डवेयर + साफ्टवेयर) का अंतिम संयोजन एवं जांच, बिक्री पश्चात बगफिक्स, बिक्री पश्चात "उत्पाद विशेषता संवर्धन/उन्नयन", बिक्री पश्चात - पुर्जों की आपूर्ति/प्रौद्योगिकी सहायता जैसे कार्यकलापों से है और यह दावा किया गया है कि तेजस उत्पादक के रूप में माने जाने के लिए आवश्यक ये समरत प्रचालन करती है जबकि पृथ्वी, बीएमसीएल द्वारा केवल भारत में संयोजन प्रचालन किए जाते हैं । हुआबी द्वारा भारत से बाहर उसके अधिकांश प्रचालन किए जाते हैं । इसके अलावा, तेजस के भारत में उत्पाद डिजाइन दल द्वारा विकसित "जांच प्रक्रियाओं एवं विनिर्देशनों" के आधार पर कठिन संयोजन एवं जांच भी की जाती है । पृथ्वी तथा वी एम सी एल जैसे अन्य आयातकों द्वारा संबद्ध उत्पादों के लिए कोई प्रौद्योगिकी विकास अथवा आर एंड डी कार्यकलाप नहीं किया जाता है । यहां तक कि अंतिम संयोजन और आयातित उत्पाद की जांच संबद्ध देशों के उनके विदेशी प्रौद्योगिकी प्रदाताओं/विनिर्माता द्वारा प्रदत्त विनिर्देशनों के अनुसार की जाती है ।

xvi. तेजस ने भारत में ग्राहक सहायता एवं सेवा केन्द्र स्थापित करने के लिए भारी निवेश किया है। तेजस भारत के भीतर अपने उत्पादों के लिए "स्थापना सेवाएं, संवर्धन, बगफिक्स" करने में सक्षम है। इसके विपरीत पृथ्वी, वी एम सी एल जैसे आयातकों के पास भारत के भीतर "संवर्धन", "बगफिक्स", क्षमताओं के लिए प्रौद्योगिकी क्षमता नहीं है और वे "संवर्धन" तथा "बगफिक्स", की व्यवस्था करने के लिए अपने विदेशी प्रौद्योगिकी प्रदाताओं/विनिर्माताओं पर निर्भर हैं। उनके पास अपना "उत्पाद प्रलेखन" भी नहीं है (वे केवल हुआबी कॉपीराइट सहित हुआबी द्वारा प्रदत्त दस्तावेज की फोटोकॉपी करते हैं), जिससे यह सिद्ध होता है कि वे एस डी एच के घरेलू उत्पादक की अपेक्षा केवल आयातक तथा व्यापारी हैं।

xvii. तेजस ने भारत में या उसके बाहर विभिन्न संघटकों तथा उनकी खरीद एवं विकास को अभिज्ञात किया और यह तर्क दिया कि ई एम एस की सहायता लेना स्वयं की डिजायन एवं विकास में सहायता लेने की तुलना में अत्यंत भिन्न है। वी एम सी एल तथा पृथ्वी के मामले में वस्तुतः हुआबी ही ऐसी कंपनी है जो संबद्ध उत्पाद की उत्पादक है और संयोजन प्रचालन (यदि कोई हो) वी एम सी एल तथा पृथ्वी के लिए छोड़ दिए जाते हैं। तेजस के मामले में कंपनी उत्पादक है और सोल्डरिंग प्रचालन ई एम एस संविदाकारों से कराए जाते हैं।

xviii. जहां तक ई एम एस के कार्यकलापों का संबंध है, याचिकाकर्ता ने अनुरोध किया है कि वैश्विक रूप से इसे विधिवत स्वीकार किया गया है कि ई एम एस कंपनियां केवल संविदा विनिर्माता हैं जिनके पास उत्पाद अधिकार का कोई स्वामित्व नहीं है, आई पी आर अथवा जानकारी नहीं है और वे केवल उजरती कामगार हैं जो अलग-अलग उद्योगों से इलेक्ट्रोनिक उत्पादों को सोल्डरिंग/जांच सेवाएं प्रदान करती हैं।

xix. याचिकाकर्ता ने यह निर्धारित करने के लिए कि क्या कोई कंपनी संबंधित उत्पाद की उत्पादक है अथवा नहीं, यू एस आई टी सी के 6 कारकों पर भी भरोसा किया है। ये हैं:

- किसी फर्म के पूंजी निवेश की मात्रा और स्रोत;
- अमरीकी उत्पादन कार्यकलाप में शामिल तकनीकी विशेषज्ञता
- अमरीका में उत्पाद का मूल्यवर्धन
- रोजगार के स्तर
- अमरीका में प्राप्त पुर्जों की मात्रा और प्रकार; तथा
- अमरीका में ऐसी कोई अन्य लागत तथा कार्यकलाप जिससे समान उत्पाद का उत्पादन होता है जिसमें उत्पादन संबंधी निर्णय भी शामिल हैं।

xx. याचिकाकर्ता ने विभिन्न पुस्तकों में उभरते हुए न्यायशास्त्र का भी हवाला दिया है-स्ट्रानबुक एवं हुपर द्वारा लिखित पाटन एवं सब्सिडी, मै. क्लायब स्टानबुक एवं फिलिप बैंटले द्वारा लिखित यूरोपीय समुदाय में पाटनरोधी एवं प्रतिसंतुलनकारी शुल्क के अधिरोपण को शासित करने वाला कानून एवं प्रक्रियाएं, जूडिथ जैको, जोहान ह्यूमन एवं जार्ज मिरांडा, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस की पाटनरोधी जांच संबंधी पुस्तिका, अमरीकी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आयोग की पाटनरोधी एवं

प्रतिसंतुलनकारी शुल्क संबंधी पुस्तिका । याचिकाकर्ता ने ई सी, भारत एवं अमरीकी प्राधिकारियों के कई निर्णयों का भी हवाला दिया ।

### निर्णातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पार्टियों के अनुरोध

16. विचाराधीन उत्पाद तथा समान वस्तु के बारे में निम्नलिखित विरोधी पार्टियों ने अपने तर्क दिए हैं :-

- (i) हुआवी टैक्नॉलॉजीज कं.लि., चीन जन.गण.
- (ii) हुआवी टैक्नॉलॉजीज इंडिया प्रा. लि.,
- (iii) हुआवी टेलीकम्युनिकेशन (इंडिया) प्रा.लि.
- (iv) एम आर ओ - टैक लि., बंगलौर (आयातक)
- (v) जूनीपर नेटवर्क प्रा. लि., इंडिया, एअरसैल लिमिटेड
- (vi) वोडाफोन एस्सार लि.
- (vii) भारती एअरटैल लिमिटेड
- (viii) सीसीसीएमई
- (ix) पृथ्वी इनफॉरमेशन्स साल्युशंस लि.
- (x) बुप्पालामृता मैगनेटिक कंपोनेट्स लि.
- (xi) ईसीआई टेलीकॉम.लि.
- (xii) हैंगजाऊ ई सी आई टेलीकम्युनिकेशन्स कं. लि., चीन जन.गण.
- (xiii) ईसीआई टेलीकॉम इंडिया प्रा. लि.
- (xiv) आरएडी डाटा कम्युनिकेशन्स लि.
- (xv) अल्काटेल-लूसेंट, शंघाई बैल कंपनी
- (xvi) डाटा टेली सर्विस
- (xvii) फाइबर होम टेलीकम्युनिकेशन्स टैक्नोलॉजीज कंपनी लि.
- (xviii) जैड टी ई कार्पो. लि., चीन जन.गण.
- (xix) यू टी स्टारकॉम
- (xx) फिब कॉम
- (xxi) सिएना, यू एस ए
- (xxii) बी एस एन एल
- (xxiii) तिरुमाला सेवन हिल्स

17. इन हितबद्ध पार्टियों के अनुरोधों का सामूहिक सारांश निम्नानुसार है :-

- i. आवेदक रवयं संबद्ध वस्तु का आयातक है और उसके पास वर्तमान याचिका दायर करने का अधिकार नहीं है । क्योंकि आवेदक ई एम एस जैसे विशिष्टीकृत उत्पादकों से संघटकों के अधिकांश पुर्जों को आउटसोर्स करता है ।
- ii. आवेदक द्वारा एक ई एस एस सेलेस्टिका से संबद्ध वस्तु का आयात किया जा रहा है जो चीन जन.गण. में कई कार्यालयों के जरिए प्रचालन करती है । चूंकि

आवेदक ने संबद्ध देशों से वस्तु का स्वयं आयात किया है, इसलिए वह इस मामले में "घरेलू उद्योग" का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता ।

iii. आर एंड डी के मापदंड के आधार पर "घरेलू उद्योग" की पात्रता के बारे में आवेदक का दावा दोषपूर्ण है क्योंकि आर एंड डी इस संबंध में प्रयोग किया जाने वाला एकमात्र कारक नहीं है । डब्ल्यू टी ओ पैनल रिपोर्ट डब्ल्यू टी/डीएस/337/आर के पैरा 7.112, 7.114 और 7.124 का संदर्भ दिया गया है । ये पैरा पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 4.1 की व्याख्या से संबंधित है । अतः यह तर्क दिया गया है कि उत्पादकों की समस्त श्रेणियों और समूह को घरेलू उद्योग का भाग माना जाएगा ।

iv. बी एस एन एल भी आयातक के रूप में आवेदक को वर्गीकृत करता है ।

v. याचिका कुछेक उत्पादकों एस टी एम 256, एस टी एम 64 और डिजिटल क्रास कनेक्ट्स से संबंधित है । ये ऐसे उत्पाद हैं, जिनका आवेदक न तो विनिर्माण करता है और न ही बिक्री । अतः याचिकाकर्ता के पास भी कोई अधिकार नहीं है ।

vi. याचिकाकर्ता का यह दावा भ्रामक और गलत है कि उसके पास जांच अवधि के दौरान भारतीय उत्पादन का 84.7% हिस्सा रहा है ।

vii. याचिकाकर्ता ने अपने इस दावे के लिए कोई साक्ष्य नहीं दिया है कि मै. मेजरमेंट एंड कंट्रोल्स लि. ने याचिका का समर्थन किया है ।

viii. "अधोषित एसो. के पत्र" में एम सी आई, बी ई एल और आई टी आई को गलत ढंग से भारतीय उत्पादकों के रूप में वर्गीकृत किया गया है । एम सी आई ने आज की तारीख तक संबद्ध वस्तु की एक भी इकाई की बिक्री नहीं की है । बी ई एल और आई टी आई एच एफ सी एल तथा पृथ्यी की तर्ज पर कार्य करती है ।

ix. समाज वस्तु का उत्पादन करने वाले घरेलू उद्योग को समुचित ढंग से अभिज्ञात नहीं किया गया है और याचिका दायर करने के आधार की पुष्टि नहीं की गई है ।

x. याचिकाकर्ता ने स्वयं और अन्य भारतीय उत्पादकों के बीच कृत्रिम भेद किया है । अन्य उत्पादकों ने एम टी एन एल तथा बी एस एन एल द्वारा जारी निविदाओं में भाग लिया और निविदाएं भी हासिल कीं । तथापि, तेजस द्वारा दिए गए तर्क के आधार पर उन्हें मात्र उत्पादक और एम टी एन एल, बी एस एन एल की निविदाओं में मात्र भागीदार कंपनी होनी चाहिए ।

xi. किसी उत्पादक द्वारा स्वयं एम टी एन एल, बी एस एन एल की निविदा हासिल करने सह यह पता चलता है कि वे संबद्ध उत्पाद के उत्पादक हैं । यह निर्धारण कि क्या किए गए आर एंड डी के आधार पर कोई कंपनी कोई उत्पादक है अथवा नहीं । नियम 2(ख) के प्रयोजनार्थ निर्धारण हेतु बेतुका और अप्रासंगिक है ।

xii. नियम 2(ख) में घरेलू उद्योग को "समाज उत्पाद के विनिर्माण और उससे जुड़े कार्यकलाप में संलग्न समूचे घरेलू उत्पादकों" के रूप में परिभाषित किया गया है । तेजस इस जांच पर खरी नहीं उत्तरती है ।

xiii. भारतीय पाटनरोधी नियमावली में "विनिर्माण" की कोई परिभाषा नहीं है । विनिर्माण पद के दायरे के बारे में कुछ दिशा-निर्देश एक्साइड टैरिफ अधिनियम, 1944 की धारा 2(च) के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा किए गए अर्थ निरूपरण से प्राप्त किए जा सकते हैं ।

xiv. उच्चतम न्यायालय ने यह उल्लेख किया कि जहां तक विनिर्माण कार्यकलाप के परिणामस्वरूप किसी नए विपणनीय वस्तु तैयार होने का संबंध है, ऐसा माना जाता है कि कोई विनिर्माण हुआ है ।

xv. याचिकाकर्ता और याचिकाकर्ता द्वारा आयातक के रूप में वर्गीकृत घरेलू उद्योग के कुछेक अन्य सदस्यों द्वारा किए गए कार्यकलापों के बीच अत्यंत सूक्ष्म अंतर है । याचिकाकर्ता को इस तथ्य की वजह से घरेलू उद्योग के रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता कि वह बाहर से अपने संघटक प्राप्त करता है और अपने उत्पादन के लिए संविदा विनिर्माण सेवाओं का उपयोग करता है ।

xvi. यह दावा करना गलत है कि उन्हीं को घरेलू उद्योग माना जाना चाहिए जो पर्याप्त आर एंड डी कार्यकलाप करते हैं । विधिक अपेक्षा उत्पादन की है न कि आर एंड डी की सीमा की ।

xvii. याचिका में इस आशय का कोई जिक्र नहीं है कि याचिकाकर्ता किन पुर्जों और संघटकों का भारत में उत्पादन करता है, जिसके अभाव में प्राधिकारी यह जांच नहीं कर सके कि क्या याचिकाकर्ता उन सभी उत्पादों का उत्पादन करता है जो घरेलू उद्योग के दायरे में आते हैं ।

xviii. प्राधिकारी को याचिकाकर्ता द्वारा आयातित पुर्जों और संघटकों से संबंधित सूचना मांगनी चाहिए थी ।

xix. तेजस ने अपनी याचिका में भारतीय उत्पादकों की चुनिंदा सूची दी है और उसने जानबूझकर कई उत्पादकों (फिबकॉम आदि) को छोड़ दिया है ।

xx. "वृद्धिकारी कार्यकलापों" में संलग्न कंपनियों की अनदेखी करने की निप्रा की नीति अस्वीकार्य है क्योंकि "विनिर्माता ऐसे कई कार्यकलाप करता है जिससे विचाराधीन उत्पाद को आकार मिलता है" । (बी पी एल इंडिया), (उच्चतम न्यायालय) और मैजेस्टिक ऑटो (सोर्स्टेट) के मामलों पर भरोसा किया गया)

xxi. नियम 2(ख) में किसी आर एंड डी आधारित वर्गीकरण की अपेक्षा नहीं की गई है । इसमें केवल "समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न घरेलू उत्पादकों" का उपयोग किया गया है ।

xxii. हुआवी द्वारा भारत में बड़े पैमाने पर आर एंड डी कार्यकलाप किए जाते हैं ।

xxiii. तेजस द्वारा किए गए भारी मात्रा में आयातों को ध्यान में रखते हुए तेजस द्वारा किए गए उत्पादन कार्यकलाप की प्रकृति पर याचिकाकर्ता ने विचार नहीं किया है ।

xxiv. तेजस के लिए यह सिद्ध करना अपेक्षित है कि वह ऐसे पुर्जों और संघटकों का उत्पादन करती है जिन्हें विचाराधीन उत्पाद में शामिल करने की मांग की गई है जबकि उसने इसके विपरीत स्वीकार किया है ।

xxv. तेजस की याचिका के पैरा ३ जिसमें संयंत्र एवं मशीनरी में कम निवेश होने की बात कही गई है, के प्रतिकूल पी एफ के पैरा ६८ में यह उल्लेख है कि याचिकाकर्ता ने जनशक्ति एवं संयंत्र तथा उपकरणों में भारी निवेश किया है ।

xxvi. तेजस के लिए यह स्पष्ट करना अपेक्षित है कि कौन से संघटकों का आयात किया गया है और उन्हें दोहरे उपयोग वाला क्यों माना गया है ।

xxvii. पी सी बी में लगाए गए आई सी को विशेष रूप से एस डी एच उपकरणों के लिए तैयार किया जाता है इसलिए यह समझना कठिन है कि वे दोहरे उपयोग वाले किस प्रकार हो सकते हैं ।

xxviii. तेजस की फैक्ट्री में जाए बिना (जैसा कि सार्वजनिक सुनवाई के दौरान स्वीकार किया गया है) प्राधिकारी यह निष्कर्ष नहीं निकाल सकते कि तेजस के पास अपेक्षित समझत क्षमताएं हैं । यद्यपि पी एफ के पैरा 43 के अनुसार उक्त निष्कर्ष याचिकाकर्ता के परिसरों में की गई विस्तृत जांच के बाद निकाला गया है ।

xxix. याचिकाकर्ता की उत्पादन प्रक्रिया मुख्यतः थाइलैंड में होती है । तेजस की 2007-08 की वार्षिक रिपोर्ट में भी इस तथ्य को स्वीकार किया गया है ।

xxx. तेजस ने कई एस डी एच उपकरणों का आयात किया है । यह निष्कर्ष भी निकाला जा सकता है कि तेजस के पास "आयातित वस्तु" की मरम्मत करने की सुविधा ही नहीं है क्योंकि इस सूची में की गई कुछेक प्रविष्टियों में "मरम्मत वाली वस्तु" का उल्लेख किया गया है ।

xxxi. पुर्जे और संघटकों को अंततः चीन जन.गण. से प्राप्त किया जाता है । थाइलैंड से हुए निर्यातों को उनके अंकित मूल्य पर स्वीकार नहीं किया जाएगा । (डी जी एडी रबड रसायन मामले का हवाला दिया गया) ।

xxxii. सी एम ए आई के पत्र के अंतिम भाग में यह पुष्टि की गई है कि इस पत्र का साक्ष्य के तौर पर अत्यंत कम महत्व है ।

xxxiii. एक अन्य प्रमुख उद्योग एसोसिएशन टीमा ने अपने 3 दिसंबर, 09 के पत्र में भी इस आशय की परिभाषा के बारे में याचिकाकर्ता के दृष्टिकोण का भी पुरजोर समर्थन किया है कि घरेलू उद्योग कौन है और उन्होंने प्राधिकारी के अंतरिम निर्णय का समर्थन किया है । स्पष्ट तौर पर व्यापरियों और संयोजकों को घरेलू उद्योग नहीं माना जा सकता ।

xxxiv. जांच अवधि के दौरान भारतीय उत्पादन में 84.7% हिस्सा रखने का तेजस का दावा अत्यंत संदेहास्पद है क्योंकि तेजस ने खबर यह स्वीकार किया है कि उसका 16% बाजार हिस्सा है और वायस एंड डाटा के अनुसार ई सी आई का 30% और एल्काटेल का 18% है ।

xxxv. तेजस ने यह स्वीकार किया है कि वह अन्य देशों से कुछेक संघटकों/उप संयोजनों का आयात कर रही है अतः वह इस बात से इंकार नहीं कर सकती कि उसने आरोपित पाटित उत्पाद का आयात किया है और इस प्रकार वह घरेलू उद्योग नहीं है ।

xxxvi. कंपनियों में विदेशी शेयरधारिता का उपयोग घरेलू उत्पादकों को अलग रखने के आधार के रूप में नहीं किया जा सकता ।

xxxvii. डब्ल्यू टी ओ पैनल रिपोर्ट डी एस 337 की पाद टिप्पणी 289 पर भरोसा करते समय निप्रा ने स्पष्ट तौर पर यह नहीं माना है कि अन्य भारतीय उत्पादकों को उत्पादक नहीं माना जा सकता ।

xxxviii. यू एस आई टी सी का कलर टेलीविजन रिसीवरों के बारे में निर्णय किसी देश विशेष के कानून के विशिष्ट उपबंधों पर आधारित है जो भारत के लिए अनुषंगी मानक है । उक्त मामले में उल्लिखित 6 मानकों के अनुसार भी हुआबी तथा वी

एम सी एल बेहतर स्थार पर हैं। इसके अलावा आर एंड डी भरोसा की गई सामग्री के अंतर्गत कोई मानदंड नहीं है और न ही यह भारतीय कानून के अंतर्गत है।

xxxix. यदि कलर टेलीविजन रिसीवरों के मामले में यू एस आई टी सी के निर्णय के निष्कर्ष पर भरोसा किया जाए तो अन्य भारतीय उत्पादकों को भी घरेलू उद्योग माना जाना चाहिए।

xli. जब "घरेलू उद्योग" के बारे में भारतीय कानून पहले से मौजूद है तो अनुषंगी मानकों को लागू करना अनावश्यक है और वह भी जो पाटनरोधी कानून से संबंधित ही नहीं है। तेजस द्वारा भरोसा की गई आई पी एल सामग्री अमरीका में एक निजी निकाय की महज राय है और उसका कानूनन कोई महत्व नहीं है।

xlii. तेजस की पेपर बुक में "हुआबाई इंडिया फुट प्रिंट: माइल स्टोन" वस्तु का उल्लेख किया गया है जिससे याचिकाकर्ता के मामले को समर्थन नहीं मिलता है क्योंकि इससे यह स्पष्ट होता है कि हुआबी इंडिया 2000 से अधिक आर एंड डी इंजीनियरों को नियोजित करती है और उराने 200 मिलियन अम.डॉ. का निवेश किया है जिसके भारत में 7 कार्यालय हैं।

xlii. तेजस ने यह तर्क दिया है कि बी एस एन एल द्वारा किसी पार्टी को निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति तब तक नहीं दी जाती है जब तक कि वास्तविक विनिर्माता (ओ ई एम) भाग न लें। तथापि, इस दस्तावेज से यह पता चलता है कि प्रौद्योगिकी हरतांतरण किसी बाजार का एक विधिवत मान्यता प्राप्त भाग है। इसके अलावा, ओ ई एम की परिभाषा में कहीं भी यह परिकल्पना नहीं की गई है कि केवल ओ ई एम ही समूचे उत्पाद का विनिर्माण करता है।

xliii. दिल्ली कलॉथ एंड जनरल मिल्स तथा उजागर प्रिंट्स के उच्चतम न्यायालय के मामलों के अनुसार-उत्पाद शुल्क के भुगतान का तात्पर्य यह है कि संबंधित कंपनी विनिर्माण/उत्पादन करती है और इसलिए सार्वजनिक सुनवाई में याचिकाकर्ता के इस तर्क की अनदेखी की जाए कि उत्पाद शुल्क का भुगतान संगत नहीं है। इसका स्पष्ट तात्पर्य मुद्दे को घुमाना है।

xliv. तेजस की 60% जनशक्ति आर एंड डी में नियोजित है जिसका तात्पर्य यह है कि 40% तेजस के संयोजन कार्यकलाप में संलग्न है अतः संयोजन को उत्पाद के विनिर्माण हेतु "प्रासंगिक कार्यकलाप" नहीं माना जा सकता।

xlv. तेजस ने इस आशय के विरोधाभाशी तर्क दिए हैं कि एक ओर वह यह कहती है कि विदेशी उत्पादन अपने देश में आर एंड डी करते हैं और उनके केवल वृद्धिकारी कार्यकलाप करने के लिए भारतीय कार्यालय हैं। दूसरी ओर वह यह दावा करती है कि विदेशी उत्पादकों ने भारत में कम लागत के श्रमिकों का लाभ उठाना लेए भारत में विकास केन्द्र खोले हैं और इन कंपनियों द्वारा सृजित आई पी विदेश में निहित है।

xlvi. कोरल टेलीकॉम तथा टीमा का उल्लेख पी एफ में नहीं किया गया है और इस प्रकार अब अनुरोध करने का अवसर प्रदान नहीं किया जाना चाहिए।

xlvii. "विनिर्माण" को परिभाषित करने के लिए भारत संघ बनाम दिल्ली क्लॉथ एंड जनरल मिल्स (1963) के उल्लिखित मामले पर भरोसा किया गया है जिसमें यह पुष्टि की गई है कि प्राधिकारी द्वारा घरेलू उत्पादक को प्रदत्त अर्थ गलत है ।

xlviii. तेजस द्वारा एस टी एम 1,4,16 में प्रयुक्त 27.66% संघटक आयात किए जाते हैं और उनका दोहरा उपयोग नहीं होता है । तेजस के पास एस डी एच में प्रयोग करने के अलावा कोई अन्य प्रत्यादन कार्यकलाप नहीं है ।

xlix. समान वस्तु के भारतीय उत्पादन का 86% उत्पादन करने का तेजस का दावा आधारहीन है । तेजस ने रिपोर्ट किया है कि कार्डों का संयोजन भारत से बाहर होता है और किसी विनिर्माण ट्रॉन का दौरा करने से यह स्पष्ट हो जाएगा कि आर एंड डी तथा जांच प्रासंगिक कार्यकलाप मानते समय कार्डों का संयोजन विनिर्माण का केन्द्र बिन्दु है ।

i. तेजस ने खुद के बनाए रखे उत्पादक के आधार पर अन्य सभी कंपनियों को अविनिर्माता घर्गीकृत किया है । यदि तेजस के आई पी आर स्वामी को वास्तविक विनिर्माता मानने के तर्क लो स्वीकार किया जाता है तो रायल्टी का भुगतान कर विनिर्माण करने वाले सभी उत्पादक विनिर्माता नहीं रह जाएंगे ।

ii. तेजस ने यह स्वीकार किया है कि वह संघटकों का आयात करती है और तत्पश्चात उसके आयातों को केवल इस वजह से वी एम सी एल/पृथ्वी द्वारा किए गए आयातों से भिन्न नहीं देखा जा सकता कि तेजस आर एंड डी जैसे अनुषंगी एकीकरण कार्यकलाप करती है । रिलायंस मामले के अनुसार यह स्पष्ट है कि आर एंड डी जैसे अनुषंगी एकीकरण कार्यकलापों को किसी कंपनी को विनिर्माता कहने के लिए आवश्यक नहीं माना जा सकता ।

iii. केवल आर एंड डी करने और अपने खुद की उत्पादन सूची रखने को विनिर्माता नहीं कहा जा सकता । इसके अलावा, जिन उत्पादकों के पास केवल पूर्ण अनुषंगी एकीकरण है, उन्हें रिलायंस उद्योग के मामले के अनुसार भारत में उत्पादक नहीं माना जा सकता ।

iv. पाटनरोधी जांच के अनुसार उत्पादन क्या है, इससे संबंधित उद्धरण और निर्णीत मामले भ्रामक हैं और उल्लिखित कोई भी मामला लागू नहीं होगा ।

v. अमरीकी कानून में निहित प्रावधान भारतीय कानून में नहीं है ।

vi. ई एम एस सेवाएं मात्र सोल्डरिंग सेवाएं नहीं हैं । चूंकि आवेदक थाइलैंड में ई एम एस पर पूर्ण नियंत्रण रखता है अतः वह यह नहीं कह सकता कि उनकी थाइलैंड में कोई संबद्ध पार्टी नहीं है ।

vii. तेजस यह सिद्ध करने में विफल रही है कि उत्पाद शुल्क के भुगतान को विनिर्माण क्यों नहीं माना जाता है ।

viii. निर्दिष्ट प्राधिकारी को तेजस को घरेलू उद्योग का दर्जा प्रदान करने के लिए मतदान कराना चाहिए ।

ix. चूंकि उत्पाद पारंपरिक हैं, इसलिए तेजस भारत में समूची मांग को पूरा करने में समर्थ नहीं होगी ।

l ix. तेजस ने जानबूझकर घरेलू उद्योग की सूची में से कुछेक भारतीय उत्पादकों को छोड़ दिया है। प्राधिकारी समान मामले में चुनिन्दा आधार पर विवेकाधिकार का उपयोग नहीं कर सकते।

l x. तेजस ने अपनी याचिका में भारतीय उत्पादकों की चुनिन्दा सूची उपलब्ध कराई है और जानबूझकर कई उत्पादकों (फिबकॉम आदि) को छोड़ दिया है।

l xi. "वृद्धिकारी कार्यकलाप" में संलग्न कंपनियों की अनदेखी करने की निप्रा की नीति अस्वीकार्य है क्योंकि "विनिर्माण में कई कार्यकलाप शामिल होते हैं जिससे विचाराधीन उत्पाद तैयार होता है"। (बी पी एल (उच्चतम न्यायालय) तथा मेजेस्टिक आटो (सेस्टेट) के मामलों पर भरोसा किया गया)।

l xii. नियम 2(ख) में कोई आर एंड डी आधारित वर्गीकरण अपेक्षित नहीं है। इसमें मात्र "समान वस्तु के विनिर्माण अथवा उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न घरेलू उत्पादकों" का उपयोग किया गया है।

l xiii. तेजस उस स्थिति में घरेलू उद्योग होने का दावा कर रही है जब यह तीसरे देश के ऐसे शेयरधारकों के स्वामित्व वाली कंपनी है जो ई एम एस से बाहर उत्पादन कार्यकलाप करती है। इसलिए यह घरेलू उद्योग की पात्र नहीं है और जो वास्तव में संबद्ध वस्तु का आयात करती है।

l xiv. अमरीका प्राधिकारियों द्वारा प्रदत्त उत्पादन की परिभाषा/अर्थ पर तेजस के विश्वास पर टिप्पणियां करते हुए हितबद्ध पार्टियों ने यह तर्क दिया है कि जब "घरेलू उद्योग" के बारे में भारतीय कानून पहले से मौजूद है तो अनुषंगी मानकों को लागू करना अनावश्यक है और वह भी जो पाटनरोधी कानून से संबंधित ही नहीं है। तेजस द्वारा भरोसा की गई आई पी आर सामग्री अमरीका के एक निजी निकाय की मात्र राय है और उसका कानूनन महत्व नहीं है।

l xv. तेजस द्वारा "हुआबी इंडिया फंट प्रिंट: माइलस्टोन" नामक एक लेख पर भरोसा किए जाने से याचिकाकर्ता के मामले को समर्थन नहीं मिलता है; क्योंकि इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि हुआबी इंडिया 2000 से अधिक आर एंड डी इंजीनियर नियोजित करती है और उसने 200 मिलियन अम.डॉ. का निवेश किया है और भारत में उसके 7 कार्यालय हैं।

l xvi. दिल्ली कलॉथ एंड जनरल मिल्स तथा उजागर प्रिंट्स के उच्चतम न्यायालय के मामलों के अनुसार उत्पाद शुल्क के भुगतान का तात्पर्य यह है कि संबंधित कंपनी विनिर्माण/उत्पादन करती है और इसलिए सार्वजनिक सुनवाई में याचिकाकर्ता के इस तर्क की अनदेखी की जाए कि उत्पाद शुल्क का भुगतान संगत नहीं है। इसका स्पष्ट तात्पर्य मुद्दे को घुमाना है।

l xvii. तेजस की 60% जनशक्ति आर एंड डी में नियोजित है जिसका तात्पर्य यह है कि 40% तेजस के संयोजन कार्यकलाप में संलग्न है अतः संयोजन को उत्पाद के विनिर्माण हेतु "प्रासंगिक कार्यकलाप" नहीं माना जा सकता।

l xviii. यद्यपि, निप्रा ने यह स्वीकार किया है कि तेजस चीन जन.गण. से आयात कर रही है, फिर भी उसने तेजस को घरेलू उद्योग मानने का विकल्प चुना है। उत्पादन की कुल लागत की तुलना में ऐसे आयातों के प्रतिशत का प्रश्न पाटनरोधी नियमों के अनुसार नहीं है।

Ixix. तेजस ने यह तर्क दिया है कि समावेशन भूलवश हुआ है और अपवर्जन की पुष्टि की जानी है। इस तर्क को मानते हुए आयात करने वाले अन्य घरेलू उत्पादक के साथ भी तेजस के समान लोचशीलता प्रदान की जा सकती है।

Ixx. तेजस सहित समस्त भारतीय विनिर्माता पुर्जों और संघटकों के संबंध में आयात पर निर्भर हैं और इन पुर्जों और संघटकों का कोई घरेलू उद्योग नहीं है।

Ixxi. इस आशय का कोई निर्धारण नहीं है कि क्या विचाराधीन उत्पाद में शामिल प्रत्येक वस्तु के संबंध में तेजस घरेलू उद्योग है।

Ixxii. जहां तक "आधार" के मुद्दे का संबंध है, वी एम सी एल तथा अन्य हितबद्ध पार्टियों को पूर्ण अवसर देने से इंकार किया गया है।

Ixxiii. उच्चतम न्यायालय ने रिलायंस इंड. बनाम निप्रा के मामले में यह निर्णय लिया है कि विनिर्माण प्रक्रिया का अनुषंगी एकीकरण "घरेलू उद्योग" के निर्धारण के प्रयोजनार्थ संगत नहीं है। अतः अनुसंधान तथा आर एंड आई इस संबंध में असंगत है।

Ixxiv. पुर्जों, संघटकों, सहायक सामग्री आदि को शामिल किए जाने के परिणामस्वरूप पृथ्वी और अन्य ऐसे ही घरेलू उत्पादकों को अवैध रूप से घरेलू उद्योग से अलग रखा गया है।

Ixxv. यह निर्धारण हेतु कि क्या कोई कंपनी घरेलू उद्योग मानी जा सकती है, भारतीय नियमों में "पर्याप्त रूपांतरण" की शर्त निर्धारित नहीं की गई है। सी के डी/एच के डी रूप में आयातित पुर्जों और संघटकों का पूर्णतः निर्मित उपकरण में संयोजन विनिर्माण है। इसके अलावा, उत्पाद शुल्क का भुगतान एक अखंडनीय तथ्य है और इस आशय का निश्चयात्मक साक्ष्य है कि विनिर्माण किया गया है। (बी पी एल इंडिया, नरेन तुलामन मामलों पर भरोसा किया गया।)

Ixxvi. आर एंड टी से संबंधित लागत, भारत में आई पी आर स्वामित्व आदि उत्पाद शुल्क के भुगतान तथा घरेलू उद्योग के निर्धारण के प्रयोजनार्थ असंगत है। आई सी ए आई द्वारा ए एस 26 के अनुसार विकास एवं डिजाइन व्यय को परिसंपत्तियों के रूप में पूँजीगत किया जाना चाहिए और ये लागत का भाग नहीं है।

Ixxvii. तेजस पेपर बुक की पेपर बुक के पृष्ठ 17 व 18 पर तेजस द्वारा की गई प्रक्रिया की सूची से यह स्पष्ट होता है कि यह वास्तविक निर्माता नहीं है।

Ixxviii. यदि विनिर्माण पूर्व लागत को अलग रखा जाता है तो तेजस द्वारा किए गए आयात उसकी लागत में अत्यंत अधिक अनुपात में होंगे जिससे स्पष्ट होता है कि तेजस स्वयं एक प्रमुख आयातक है।

Ixxix. प्रत्येक सहायक सामग्री, संबद्ध साफ्टवेयर, पुर्जों तथा संघटकों आदि के लिए स्वतः कोई आयात न करने अथवा निर्यातकों/आयातकों से कोई संबंध न होने का अनिवार्य प्रमाणन भी उपलब्ध नहीं कराया गया था।

Ixxx. चूंकि वित्त मंत्रालय द्वारा इस समय ऐसे सभी उत्पादकों को एस डी एच के उत्पादक माना जा रहा है, इसलिए जांच शाखा अर्थात् वाणिज्य मंत्रालय द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय और केन्द्र सरकार द्वारा सुनिर्धारित सिद्धांतों को कृत्रिम रूप से परिवर्तित नहीं किया जा सकता।

Ixxxi. तेजस सहायक सामग्री, संबद्ध साफ्टवेयर, पुर्जों तथा संघटकों के व्यापारी बाजार में नहीं है।

Ixxxii. निप्रा को घरेलू उद्योग से अलग रखने हेतु अन्य घरेलू विनिर्माताओं के साथ किए गए पत्रव्यवहार, यदि कोई हो, और अपने निर्णय के आधार का खुलासा करना चाहिए ।

Ixxxiii. निप्रा ने आवेदक को आयातक पाए जाने की स्थिति में उसके पक्ष में नियम 2(ख) के अंतर्गत विवेकाधिकार का प्रयोग करने के समर्थन में कोई कारण भी दर्ज नहीं किया है ।

Ixxxiv. सी एम ए आई का पत्र तारीख रहित, अहस्तांक्षरित है और यह पत्र शीर्ष पर भी नहीं है । यह पता करना आश्चर्यजनक है कि प्राधिकारी का निष्कर्ष केवल सी एम ए आई पत्र पर आधारित है और रिकॉर्ड में ऐसी कोई सामग्री नहीं है कि क्या निप्रा ने आगे और पूछताछ की थी । सुनवाई में कोई भी समर्थक उपस्थित नहीं था और उन्होंने अब तक कोई सूचना दायर नहीं की है ।

Ixxxv. निप्रा का यह निष्कर्ष कि तेजस ने पूर्ण एस डी एच उपकरणों का कोई आयात नहीं किया है, उस सीमा तक नियम 2(ख) लागू नहीं होता है और याचिकाकर्ता को आयातक नहीं माना जा सकता, मोटे तौर पर विशेषतः इसलिए गलत है कि तेजस रवयं चीन जन.गण. सहित भारत से बाहर प्राप्त पुर्जों और संघटकों का संयोजन करती है ।

Ixxxvi. निप्रा द्वारा घरेलू उद्योग के क्षेत्र और परिभाषा का पुनर्निर्धारण करना अपेक्षित है क्योंकि अन्य भारतीय उत्पादक भी तेजस के कार्यकलापों के समान भारत में संयोजन प्रचालनों, जांच और बिक्री कर रहे हैं ।

### हैदराबाद स्थित आंध्र प्रदेश के माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष कार्रवाई

18. मै. बुप्पालामृता मैग्नेटिक कंपोनेट्स लि. ने दिनांक 21.4.2009 की जांच शुरूआत संबंधी अधिसूचना और 7.9.2009 के अंतिम जांच परिणामों को अवैध मनमाना तथा गैर-कानूनी घोषित करने और परिणामतः कई आधारों पर उन्हें निरस्त करने की घोषणा करते हुए निर्देश देने अथवा परमादेश रिट के रूप में आदेश देने की मांग करते हुए आंध्र प्रदेश स्थित माननीय आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका संख्या 22155/09 के रूप में एक याचिका दायर की । मै. पृथ्वी इनफारमेशन साल्यूशंस लि. तथा मै. टाटा टेली सर्विसेज लि. ने अभियोजन आवेदन दायर किया और अधिसूचना को चुनौती दी । तेजस ने माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के खिलाफ दो एस एल पी दायर की । प्राधिकारी ने भी माननीय उच्चतम न्यायालय में एक एस एल पी दायर की । प्राधिकारी ने रिट याचिकाकर्ता और अन्य पार्टियों द्वारा इन रिट याचिकाओं में दिए गए विभिन्न तर्कों पर सावधानीपूर्वक विचार किया और विधिक एवं वारतविक रिथति को देखते हुए इन हितबद्ध पार्टियों द्वारा उठाए गए मुद्दों की जांच की है । मामलों और हितबद्ध पार्टियों द्वारा दिए गए तर्कों का सारांश निम्नानुसार है:—

19. इन रिट याचिकाओं में निम्नलिखित मुद्दे उठाए गए हैं:—

- पृथ्वी और वी एम सी एल ने यह तर्क दिया कि डी जी ए डी ने न्याय के अनुरोध की अनुदेखी की है, इसलिए कार्यवाही आक्षेपित है । यद्यपि पृथ्वी और वी एम सी एल आप्टिकल ट्रांसमिशन उपकरणों के सबसे बड़े विनिर्माता हैं परंतु उन्हें घरेलू उद्योग नहीं माना गया है ।

- ii. विचाराधीन उत्पाद और समापन वर्तु की परिभाषाएं सही नहीं हैं। । उत्पाद की परिभाषा काफी व्यापक है । जांच अवधि के दौरान ऐसे कई उत्पादों का तेजस ने विनिर्माण नहीं किया था । उन्हें विचाराधीन उत्पाद में शामिल किया गया है । एस टी एम 64, एस टी एम 256, डी डब्ल्यू डी एम, डी एक्स सी, कोर डायरेक्टर आदि जैसे उत्पादों को शामिल किए जाने का उल्लेख किया गया है ।
- iii. तेजस द्वारा आपूर्त एस टी एम 1/4/16/64 वही उत्पाद नहीं हैं जिनका आयात किया गया है और इन दोनों में भारी अंतर है ।
- iv. शुल्क एवं एस कोड 851762 पर लगाया जाता है जिसमें डी डब्ल्यू डी एम शामिल है ।
- v. विचाराधीन उत्पाद में अनेक संघटक तथा सी के डी/एस के डी सैट शामिल हैं। जिनका विनिर्माण तेजस नहीं करती है ।
- vi. तेजस ने उत्पाद को इस तरह से परिभाषित किया है ताकि अन्य आप्टिकल ट्रांसमिशन उत्पाद का विनिर्माण करने वाली पृथ्वी को जानबूझकर छोड़ा जा सके ।
- vii. पृथ्वी और वी एम सी एल उत्पाद शुल्क तथा सीमाशुल्क आंकड़ों के अनुसार विनिर्माता हैं ।
- viii. वी एस एन एल ने डी जी ए डी से कहा है कि वह जांच को समाप्त कर दें क्योंकि इससे बाजार में तेजस का एकाधिकार स्थापित होता है । बी एस एन एल ने यह भी कहा है कि तेजस ने कभी भी एस टी एम 64 निविदा में भाग नहीं लिया है ।
- ix. तेजस का यह आरोप गलत है कि हुआवी ने एक वर्ष में कीमतों में 50 प्रतिशत से अधिक की कमी की है ।
- x. तेजस का दृष्टिकोण एकाधिकारवादी है ।
- xi. भारत में समस्त विनिर्माता रंगटकों का आयात करते हैं। और भारत में संयोजन करते हैं। अतः पुर्जों को उत्पाद के दायरे में शामिल कर तेजस ने पृथ्वी और वी एम सी एल को पात्र घरेलू उत्पादक के रूप में विचार किए जाने से वंचित किया है ।
- xii. तेजस ने प्रमुख उत्पादक होने की बात सिद्ध करने के लिए कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया है । सी एम ए आई का पत्र गलत है । सी एम ए आई का पूर्ववृत्त संदिग्ध है ।
- xiii. तेजस एक प्रमुख विनिर्माता नहीं है और आई सी आर ए, गार्टनर तथा वायस एंड डाटा के अनुसार उसका बाजार हिस्सा मात्र 20 प्रतिशत है ।
- xiv. तेजस संघटक का आयात भी करती है परंतु उसे पात्र घरेलू उद्योग माना जाता है जबकि पृथ्वी और वी एम सी एल को घरेलू उद्योग नहीं माना गया था । डी जी ए डी ने यह कहते हुए नियमों में ढील दी कि तेजस ने दोहरे उपयोग के संघटकों का आयात किया जिसमें इस बात पर विचार नहीं किया गया कि तेजस संघटकों का अनन्य उपयोग करती है अर्थात् एस डी एच टेलीकॉम उपकरणों के विनिर्माण हेतु ।
- xv. तेजस मलेशिया और थाईलैंड से आयात करती है । तीसरे देश (चीन जन.गण. / इजरायल से भिन्न) से आयात की वजह से भी पार्टी को आयातक माना जाना चाहिए क्योंकि नियम 2(ख) के अंतर्गत आयात का देश विनिर्दिष्ट नहीं है । यदि तेजस ने तीसरे देशों से आयात किया है तो तेजस घरेलू विनिर्माता माने जाने की पात्र नहीं है ।

**xvi.** तेजस ई एम एस की सेवाएं उपयोग करती हैं। प्राधिकारी को यह जांच करनी चाहिए कि इन ई एम एस कंपनियों ने संघटकों का आयात कहां से किया है। इस बात की प्रबल संभावना है कि ई एम एस कंपनियां चीन जन.गण. से संघटकों का आयात करती हैं।

**xvii.** जो पार्टी संघटकों का विनिर्माण नहीं कर रही है और ची जन.गण. सहित अन्य देशों से उनका आयात कर रही है वह संघटकों पर शुल्क की मांग नहीं कर सकती।

**xviii.** दोहरे उपयोग के संघटकों पर शुल्क लगाए जाने से प्रचालनात्मक समर्थाएं और भ्रांति उत्पन्न होती हैं।

**xix.** डी जी ए डी ने पृथ्वी तथा वी एम री एल को पात्र विनिर्माता नहीं माना है क्योंकि वे निविष्टियों का कोई "पर्याप्त रूपांतरण" नहीं करती है। पाटनरोधी नियम में "पर्याप्त रूपांतरण" की कोई अवधारणा नहीं है।

**xx.** डी जी ए डी ने गलत ढंग से आर एंड डी, ई एम एस संविदा विनिर्माण, बिक्री पश्चात एवं बग फिक्स को विनिर्माण कार्यकलाप का भाग माना है। ये कार्यकलाप पात्र विनिर्माता का निर्धारण करने के लिए संगत नहीं हैं।

**xxi.** बी एस एन एल ने डी जी ए डी को लिखे अपने पत्रों में यह उल्लेख किया है कि तेजस घरेलू उद्योग की पात्र नहीं हैं और तेजस एस टी एम 64 का विनिर्माण नहीं करती है।

**xxii.** टेलीफॉम उद्योग आयात पर आश्रित है क्योंकि उच्च गुणवत्ता वाले संघटक भारत में उपलब्ध नहीं हैं। आयात पर नियंत्रण से उद्योग के लिए लागत बढ़ेगी। सी के डी तथा एस के डी आयात भी उद्योग को प्रभावित करेंगे।

**xxiii.** डी जी ए डी ने गोपनीयता के बहाने प्रारंभिक जांच परिणामों में सूचना को दबाया है जिससे प्रारंभिक जांच परिणामों के दौरान अस्पष्टता उत्पन्न हुई है और उनकी नीति में स्पष्टता का अभाव है।

**xxiv.** संविदाएं निविदा प्रक्रिया द्वारा प्रदान की जाती हैं और दरें आयातों से पूर्व उद्धृत की जाती हैं। इस प्रकार आयातों के पहुंच मूल्य और उद्योग को हुई क्षति के बीच कोई कारणात्मक संबंध मौजूद नहीं है।

**xxv.** 9 माह की जांच अवधि पाटनरोधी पद्धति के दिशानिर्देशों के खिलाफ है।

**xxvi.** प्राधिकारी ने पुर्जों के बारे में क्षति का कोई पृथक निर्धारण नहीं किया है और एस डी एच बक्सों पर शुल्क पुर्जों पर लागू की गई है। ऐसा नियम 4 (ख) और 17 (घ) के अंतर्गत अनुमत्य नहीं है।

**xxvii.** उत्पाद के मानकी करण हेतु पी सी एन पद्धति गलत है क्योंकि उत्पाद की प्रकृति के अनुसार इसका मानकीकरण नहीं किया जा सकता।

20. माननीय उच्च न्यायालय ने रिट याचिका सं. 22155/2009 में दिनांक 21.10.2009, 11.11.2009 तथा 18.11.2009 के तीन अंतरित आदेशों द्वारा प्रारंभिक घरण में पाटनरोधी कार्रवाइ को स्थगित किया। तेजस ने माननीय उच्च न्यायालय के उपर्युक्त आदेशों को विवादित बताते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष एस एल पी सं. 32870-32875/2009 दायर की। माननीय उच्चतम

न्यायालय ने उपर्युक्त विवादित आदेश को स्थगित कर दिया और माननीय उच्च न्यायालय ने शीघ्र सुनवाई करने और लंबित रिट याचिका का निस्तारण करने का निर्देश दिया ।

21. माननीय उच्च न्यायालय ने रिट याचिका 22155/2009 में 22.1.2010 के आदेश द्वारा 21.4.2009 की जांच शुरूआत संबंधी अधिसूचना और 7.9.2009 के प्रारंभिक जांच परिणामों को अन्य बारों के साथ-साथ इन आधारों पर रद्द कर दिया ।

क. निर्दिष्ट प्राधिकारी के क्षेत्राधिकार का अनुमान आवेदक की इस संतुष्टि पर निर्भर करता है कि वह नियमावली के नियम 2(ख) में यथापरिभाषित घरेलू उद्योग है और इस निष्कर्ष पर निर्भर करता है कि घरेलू उद्योग की योग्यता के अभाव में निर्दिष्ट प्राधिकारी के क्षेत्राधिकार का अनुमान, जांच की शुरूआत, प्रारंभिक जांच परिणाम तथा अंतिम जांच परिणाम क्षेत्राधिकार रहित हैं और कोई जांच क्षेत्राधिकार के प्रयोग में त्रुटि उत्पन्न करेगी ।

ख. नियमावली के नियम 2(ख), 5 (1), 6, 8, 12 और अनुबंध 1 तथा 2 में सिद्धांधिकार वी एम सी एल अथवा हितबद्ध पार्टियों पर है और आरंभिक सिद्धांधिकार यह सिद्ध करने के लिए तेजस पर रहता है कि वह घरेलू उद्योग है भले ही वह स्वयं आयातक है और वह आयातक नहीं है और यह कि वस्तु के पाटन के कारण से उन्हें क्षति हुई है और निर्दिष्ट प्राधिकारी उस वस्तु के विनिर्माताओं/आपूर्तिकर्ताओं/व्यारियों से नकारात्मक सिद्ध करने की आशा नहीं कर सकते हैं ।

ग. नि प्रा. ने त्रुटिपूर्ण ढंग से क्षेत्राधिकार का अनुमान लगाया है क्योंकि तेजस घरेलू उद्योग की परिभाषा में नहीं आता है और वह वस्तुतः आयातक है इसके अलावा, पृथकी तथा वी एम सी एल चीन जन.गण. की हुआवी से सी के डी/एस के डी रूप में एस डी एच उपकरण के आयातक हैं इसलिए वे एस डी एच उपकरण के "विनिर्माता" भी नहीं हैं क्योंकि उन्होंने उपकरण का कथित रूप से "संयोजन" किया है और उत्पाद शुल्क का भुगतान किया है ।

घ. याचिकाकर्ता तेजस पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के प्रयोजनार्थ एस डी एच उपकरण का "घरेलू उत्पादक" नहीं है और इसलिए वह इस आधार पर पाटनरोधी याचिका दायर करने का पात्र नहीं है कि उसने जांच शुरूआत संबंधी अधिसूचना में यथापरिभाषित विचाराधीन उत्पाद के भाग रूपरूप कुछेक संघटकों का आयात किया है । "घरेलू उद्योग" के रूप में पात्रता हेतु घरेलू उत्पादक को "प्रमुख अनुपात" अर्थात उत्पादक की हैसियत से विनिर्माण में संलग्न होना चाहिए और उसे यह प्रदर्शित करना चाहिए कि वह समस्त विचाराधीन उत्पाद के पुर्जों, सहायक सामग्री और संघटकों का विनिर्माण करता है ।

ड. वी एम सी सी एल इन आधारों पर एक विनिर्माता है कि (क) वी एम सी एम केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम के अंतर्गत एक निर्धारिती है (ख) कोई उद्योग पाटनरोधी कानून के प्रयोजनार्थ केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के उदग्रहण हेतु विनिर्माता नहीं हो सकता और वह विनिर्माता के रूप में वंचित नहीं रह सकता (ग) मुख्यतः इस कारण से कि वह हुआवी से साफ्टवेयर की जांच कराती है और उसकी पुस्तिकाओं का उपयोग करती है, विनिर्माता बनने से वंचित नहीं रह जाती है । (घ) शामिल

प्रक्रिया निश्चित तौर पर विर्निर्माण है (ड.) ऐसी किसी हालत में जब आक्षेपित प्रारंभिक जांच परिणाम और अनंतिम शुल्क से सीधे तौर पर वे प्रभावित होते हैं वी एम सी एल को विनिर्माता न होने के आधार पर आधार से वंचित नहीं किया जा सकता ।

च. सीमाशुल्क टेरिफ अधिनियम के अध्याय 85 के अंतर्गत टैरिफ वर्गीकरण एक उप शीर्ष के अंतर्गत एस डी एच तथा अलग-अलग उपशीर्षों के अंतर्गत अन्य मल्टीप्लैक्सरों, ऑप्टीकल मल्टीप्लैक्सर साफ्टवेयर से संबंधित है और कांउसिल ने यह अनुरोध किया है कि विनिर्देशन के आधार पर एस डी एच उपकरण की क्षमता अलग-अलग होती है । यह एस टी एम-1 हेतु 155 एम वी पी एस से लेकर एस टी एम 256 के लिए 40 जी वी पी एस के बीच हो सकती है । अतः निप्रा ने हितबद्ध पार्टियों/निर्यातकों, आयातकों/घरेलू एजेंसियों को आमंत्रित करते समय समस्त क्षमताओं के उपकरणों तथा अन्य उपकरणों के लिए एस डी एच उपकरण का पी सी एन तैयार करने हेतु कोड तालिका निर्दिष्ट की है । यह केवल एस टी एम-1, एस टी एम-4, एस टी एम-16 और एस टी एम 64 से संबंधित है । अतः उपलब्ध समस्त सामग्री से यह स्पष्ट नहीं होता है कि क्या वी एम सी एल द्वारा विनिर्मित एस डी एच उपकरण तेजस द्वारा विनिर्मित उत्पादों के समान या समनुरूप हैं ।

छ. नि प्रा ने हितबद्ध पार्टियों के बहुमूल्य अधिकारों से इंकार किया है और उसने याचिकाकर्ता तेजस की कुछेक कारोबारी स्वामित्वाधीन सूचना को गोपनीय रखने में उसकी मदद करके गैर-कानूनी कार्य किया है ।

22. नि प्रा ने विशेष अनुमति याचिका सं. 2010 की 7675 (और पृथकतः विशेष अनुमति याचिका सं. 2010 की 7254 तथा कोरल टेलीकॉम लि. की विशेष अनुमति याचिका सं. 2010 की 4589) के तहत हैदराबाद स्थित माननीय आंध्रप्रदेश उच्च न्यायालय के 22.1.2010 के आक्षेपित आदेशों को भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी । पार्टियों को सुनने के बाद माननीय उच्चतम न्यायालय ने 19.3.2010 के आदेश द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित किए :

"चूंकि इन मामलों में आर्थिक परिणाम शामिल हैं इसलिए हमारे लिए इस दृष्टि से इन मामलों का त्वरित निपटान करना अपेक्षित है क्योंकि इनमें पाटनरोधी कानूनों की व्याख्या शामिल है । पार्टियों को संविधान पीठ द्वारा सिविल अपील सं. 2002 की 3453 (जिंदल स्टेनलैस लि. एवं अन्य बनाम हरियाणा राज्य एवं अन्य) की सुनवाई के बाद सुनवाई की निर्धारित तारीख हेतु इन मामलों का उल्लेख करने की स्वतंत्रता दी जाती है । इस बीच हम आयातक कंपनियों को यह निर्देश देते हैं कि वे निम्नलिखित उपकरणों पर अंतरिम शुल्क का भुगतान करें :

1. एस टी एम - 1
2. एस टी एम - 4 (एस के डी/सी के डी में उप संयोजन और/पुर्जा तथा संघटकों का उपसंयोजन
3. एस टी एम -16
4. एस टी एम-64 तथा

## 5. एस टी एम – 256

तथापि, यह स्पष्ट किया जाता है कि डी डब्ल्यू डी एम उपर्युक्त सूची से अलग है । उपर्युक्त के अधीन उच्च न्यायालय के आक्षेपित निर्णयों को स्थगित किया जाता है ।

तथापि, निर्दिष्ट प्राधिकारी को यह निर्देश दिया जाता है कि वह सुनवाई करें और मामले का न्याय निर्णय करें तथा अंतिम आदेश पारित करें जो इन विशेष अनुमति याचिकाओं में निर्णयों के अधीन होंगे । ”

23. प्राधिकारी नोट करते हैं कि अन्य पार्टियों के साथ-साथ वी एम सी एल, पृथ्वी तथा हुआबी टैक्नोलॉजीज इंडिया सहित पाटनरोधी शुल्क लगाने का विरोध करने वाली हितबद्ध पार्टियों ने अपनी विनिर्माण क्षमताओं अथवा उनके द्वारा किए गए आयातों के बारे में प्राधिकारी को किसी भी समय कोई सूचना प्रदान नहीं की है । यद्यपि, दावों और प्रतिदावों के बारे में सत्यापनीय सूचना प्रदान करने का दायित्व हमेशा हितबद्ध पार्टी पर होता है तथापि, प्राधिकारी ने स्पष्टता की वजह से निर्धारित तारीख का उल्लेख करते हुए 20 जुलाई, 2010 के पत्र द्वारा इन हितबद्ध पार्टियों से सूचना मांगी । इसके उत्तर में मांगी गई सूचना का कड़ा विरोध करते हुए वी एम सी एल तथा पृथ्वी ने अपेक्षित सूचना प्रदान करने के लिए समय बढ़ाने की मांग की । प्राधिकारी ने मामले की जटिलता को देखते हुए संगत सूचना प्रस्तुत करने हेतु इन दोनों पार्टियों को समय विस्तार प्रदान किया । तथापि, हुआबी इंडिया ने समय विस्तार तो नहीं मांगा, अपितु विलंब से सूचना प्रस्तुत की ।

24. इन तीनों हितबद्ध पार्टियों से प्राधिकारी द्वारा मांगी गई सूचना का सारांश निम्नानुसार है :—

क. भारत में उन कंपनियों के नाम, पते और उत्पादन जो इन पार्टियों के अनुसार एस डी एच उपकारणों की उत्पादक है ।

ख. इन तर्कों के लिए सत्यापनीय साक्ष्य के साथ औचित्याधार की (i) अलग-अलग पार्टियों द्वारा उत्पादित और आपूर्त एस डी एच उपकरण अलग-अलग उत्पाद अथवा अन्यथा अतुलनीय हैं, (ii) एस टी एम 64, एस टी एम 256 तथा डी एक्स सी अलग-अलग उत्पाद हैं और उन्हें अलग रखा जाना चाहिए (iii) याचिकाकर्ता द्वारा भरोसेमंद अनुसंधान एवं विकास कार्यकलापों को विनिर्माण पूर्व कार्यकलाप माना जाना चाहिए और ये उत्पादन को परिभाषित करने के आधार नहीं होने चाहिए ।

ग. विचाराधीन उत्पाद तथा अन्य उत्पादों को विभाजित करते हुए इन कंपनियों द्वारा किए गए अनुसंधान एवं विकास कार्यकलापों के साथ उनकी प्रकृति का व्यौरा ।

घ. इन कंपनियों द्वारा किए गए व्यापारिक कार्यकलापों का स्वरूप ।

ड. वार्षिक रिपोर्टों की प्रतियां ।

च. जहां तक विचाराधीन उत्पाद का संबंध है, ऐसे कार्यकलाप जिनहें कंपनी द्वारा विनिर्माता के रूप में अर्ह बनने में लिए किया जाना चाहिए ।

छ. घरेलू विनिर्माता के रूप में उसकी अपात्रता के आरोपों के विशेष संदर्भ में भारत से बाहर तेजस द्वारा किए जा रहे कार्यकलापों की सूचना

ज. डी डब्ल्यू डी एम और एस बी एच मल्टीप्लैक्सर के बीच अंतर और समानता

झ. उत्पाद के पुर्जों और संघटकों तथा विसंयोजित अथवा असंयोजित रूप में उत्पाद को बाहर रखने का औचित्य ।

25. पृथ्वी/बी एम सी एल तथा हुआवी द्वारा प्रदत्त सूचना/अनुरोधों पर वर्तमान अंतिम जांच परिणाम संबंधी दस्तावेज में विचार किया गया है ।

26. इन अनुरोधों के अलावा इन हितबद्ध पार्टियों ने इस आधार पर नए सिरे से सार्वजनिक सुनवाई की मांग की कि प्राधिकारी बदल गए हैं । कुछ अन्य पार्टियों ने भी सार्वजनिक या व्यक्तिगत सुनवाई की मांग की । अतः प्राधिकारी ने इन हितबद्ध पार्टियों के दावों की जांच की ।

27. प्राधिकारी ने जांच की कार्रवाई के दौरान माननीय उच्च न्यायालय में इन हितबद्ध पार्टियों द्वारा किए गए अनुरोधों और प्राधिकारी के समक्ष किए गए अनुरोधों पर सावधानीपूर्वक विचार किया है । इन पर इस प्रकटन विवरण और इस अंतिम जांच परिणाम संबंधी दस्तावेज में समुचित कार्रवाई की गई है ।

### प्राधिकारी द्वारा जांच

28. जिन विभिन्न अनुरोधों पर प्राधिकारी द्वारा कार्रवाई अपेक्षित है उन्हें मोटे तौर निम्नलिखित में श्रेणीबद्ध किया जा सकता है :

- क. विचाराधीन उत्पाद तथा इससे संबंधित मुद्दे ।
- ख. घरेलू उद्योग तथा इसके आधार से संबंधित मुद्दे, घरेलू उद्योग द्वारा आयात आदि ।
- ग. क्या कुछ हितबद्ध पार्टियों द्वारा मांग की गई नए सिरे से सार्वजनिक सुनवाई अनिवार्य है ।

### विचाराधीन उत्पाद तथा समान वस्तु

29. प्राधिकारी ने प्रारंभिक जांच परिणाम में विचाराधीन उत्पाद के अनुपालन में निम्नानुसार उल्लेख किया है ।

"5. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद "संयोजित रूप में, सी के डी, एस के डी रूप में या आकस्मिक ब्रॉड बैंड/सेल्युलर उपकरण से फिट किए गए सिंक्रोनस डिजीटल हाइआर्की ट्रांसमिशन उपकरण, उसके पुर्जे, संबद्ध सॉफ्टवेयर तथा उसके आवश्यक पुर्जे एवं संघटक" हैं।"

6. एस डी एच ट्रांसमिशन उपकरणों को मल्टीप्लेक्सर, एड ड्रॉप मल्टीप्लेक्सर (ए डी एम), मल्टीप्ल, एड ड्रॉप मल्टीप्लेक्सर, (एम ए डी एम), डिजीटल क्रॉस-कनेक्ट, पापुलेटेड पी सी बी, विद्युत आपूर्ति, लेजर, चेसेज तथा एस डी एच ट्रांसमिशन उपकरण के लिए निर्दिष्ट साफ्टवेयर आदि जैसे नामों से भी जाना जाता है, जिसमें एस डी एच ट्रांसमिशन उपकरणों के आवश्यक पुर्जे शामिल होते हैं और ये विचाराधीन उत्पाद के दायरे में हैं बशर्ते उक्त संघटक केबल एच डी एस ट्रांसमिशन उपकरण के लिए निर्दिष्ट हों।

7. एच डी एस ट्रांसमिशन उपकरणों की खरीद ट्रांसमिशन उपकरणों के रूप में या अन्य उपकरण के भाग के रूप में अर्थात ब्रॉड बैंड और/अथवा सेल्युलर (जीएसएम एवं सी डी एम ए दोनों) उपकरणों के रूप में की जा सकती है। ब्रॉड बैंड और/अथवा सेल्युलर उपकरण के भाग स्वरूप एच डी एस ट्रांसमिशन उपकरण भी विचाराधीन उत्पाद के दायरे में आते हैं।

8. विचाराधीन उत्पाद अनिवार्य अनेक इलेक्ट्रॉनिक संघटकों और/अथवा इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटेट सर्किट बोर्डों का संयोजन है जिसे संयुक्त कम गति के सिंगलों को अल्प या लंबी दूरी में ऑप्टिकल फाइबर के जरिए पारेषण हेतु उच्च गति के सिंगलों में मल्टीफ्लेक्सिंग हेतु नियम कार्यों के निष्पादन हेतु तैयार किया जाता है। चूंकि अन्य अनुप्रयोगों में इन्हें बेश ट्रांसमिशन केन्द्रों, स्थिर एक्सचेंजों तथा मौजूदगी के अन्य केन्द्रों पर स्थापित किया जाता है, इसलिए अलग-अलग स्थानों पर स्थापित एस डी एच उपकरण संबद्ध गुणधर्मों के संबंध में अलग-अलग हो सकते हैं। अलग-अलग एस डी एच उपकरण भौतिक एवं ऑप्टिकल, उत्पादन प्रौद्योगिकी, विनिर्माण प्रक्रिया, आर एंड डी विकास, सॉफ्टवेयर क्षमताओं, कार्य एवं उपयोग आदि सहित उत्पाद की अनिवार्य विशेषताओं के संबंध में तुलनीय हैं। तदनुसार विभिन्न एस डी एच उपकरणों को वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ एक समान उत्पाद माना गया है।

9. विचाराधीन उत्पाद का आयात पूर्ण उपकरण के रूप में या सी के डी, एस के डी रूप में किया जा सकता है। इसके अलावा, नेटवर्क में जोड़ने/एस डी एच ट्रांसमिशन उपकरण की स्थापना करने के लिए कई सहायक उपकरणों की जरूरत होती है (ई-1 केबल, पी सी एम केबल, पॉवर केबल, रैक, वर्क स्टेशन आदि)। सॉफ्टवेयर इन उपकरणों का अभिन्न अंग होता है जिसे उपकरण के भाग के रूप में या अलग से खरीदा जा सकता है। ये सभी विचाराधीन उत्पाद के दायरे में आते हैं।

10. यह नोट किया जाता है कि विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन हेतु अनंक संघटकों की जरूरत होती है जिनके बहु-विकल्पीय उपयोग होते हैं । अतः यह स्पष्ट किया जाता है कि संघटकों के संबंध में विचाराधीन उत्पाद का क्षेत्र केवल ऐसे संघटकों और पुर्जों तक सीमित है, जिनका विचाराधीन उत्पाद के बारे में ही अनन्य रूप से उपयोग होता है । दूसरे शब्दों में विचाराधीन उत्पाद का क्षेत्र केवल उन संघटकों/पुर्जों पर लागू होता है, यदि उनका अनन्य रूप से उपयोग एच डी एच उपकरण के उत्पादन में होता हो ।

11. विचाराधीन उत्पाद सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 85 के अंतर्गत वर्गीकृत है । भारतीय व्यापार वर्गीकरण के अनुसार इसे सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की अनुसूची-1 के शीर्ष 851762 के अंतर्गत पुनः वर्गीकृत किया जाता है । तथापि, यह वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वर्तमान जांच के दायरे पर किसी भी रूप में बाध्यकारी नहीं है ।"

30. कई हितबद्ध पार्टियों ने अनेक आधार पर विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र पर विवाद उत्पन्न किया है । प्राधिकारी ने पाटनरोधी शुल्क का समर्थन या विरोध करने वाली विभिन्न हितबद्ध पार्टियों द्वारा दिए गए तर्कों पर सावधानीपूर्वक विचार किया है और निम्नलिखित निष्कर्ष पर पहुंचे हैं । वर्तमान मामले में विचारार्थ जो मुख्य मुद्दा उठा है वह उत्पादन के अर्थ से संबंधित है । यह मुद्दा उत्पाद की विशिष्टताओं, अपनाई गई उत्पादन प्रक्रिया, भारत, चीन जन.गण और तीसरे देशों में विचाराधीन उत्पाद के विनिर्माण/संयोजन में संलग्न कंपनियों द्वारा किए गए कार्यकलापों के स्वरूप को देखते हुए उठाया गया है । विभिन्न हितबद्ध पार्टियों द्वारा दिए गए तर्कों की सावधानीपूर्वक जांच के बाद प्राधिकारी निम्नलिखित निष्कर्ष पर पहुंचे हैं ।

- i. मामला दर मामला आधार पर उत्पादन के अर्थ पर विचार करना उचित होगा । उत्पादन की सार्वभौमिक परिभाषा उचित नहीं होगी । वस्तुतः अलग-अलग कानूनों और विनियमों में उत्पादन को अलग-अलग अर्थ में परिभाषित किया गया है/माना गया है, जैसा कि अलग-अलग कानूनों में उत्पाद के अलग-अलग अर्थ/व्याख्या से स्पष्ट होता है । प्राधिकारी का मानना है कि विशिष्ट कानून और विनियम, विशिष्ट परिभाषाओं और अर्थ निरूपण तथा उस उद्देश्य और प्रयोजन, जिसके लिए कानून बनाया गया है, को ध्यान में रखते हुए उत्पादन के अर्थ पर विचार करना अपेक्षित है । उदाहरण के तौर पर वर्तमान मामले में पाटनरोधी शुल्क के प्रयोजनार्थ यह मानना अत्यंत अनुचित होगा कि कोई कंपनी केवल इसलिए घरेलू उत्पादक है कि वह कुछेक वृद्धिकारी उत्पादन कार्यकलाप कर रही है । वस्तुतः ऐसी किसी व्याख्या से कानून अप्रचालनीय बन जाएगा । अतः प्राधिकारी यह मानते हैं कि कोई कंपनी केवल उत्पाद शुल्क अदा करने के आधार पर घरेलू उत्पादक नहीं मानी जा सकती । प्राधिकारी नोट करते हैं कि

उत्पाद शुल्क कानून के अंतर्गत वस्तु को उस स्थिति में उत्पादित किया हुआ माना जाता है यदि खुदरा बिक्री कीमत की धोषणा अथवा परिवर्तन अथवा उपभोक्ता के लिए उत्पाद को बेचने योग्य बनाने के लिए वस्तु पर किए गए किसी अन्य कार्य सहित किसी इकाई कन्टेनर में पैकिंग या पुनर्पैकिंग अथवा कन्टेनरों की लेवलिंग या पुनः लेवलिंग सहित वस्तु को पूर्णता प्रदान करने के लिए प्रासंगिक अथवा अनुषंगी कार्यकलाप किए गए हों । तथापि, पाटनरोधी कानून के प्रयोजनार्थ यह नहीं कहा जा सकता कि उत्पादन बनने के लिए ऐसे उत्पादन कार्यकलाप पर्याप्त हैं । इसके लिए आयात या घरेलू उत्पादन में विविध कार्यकलाप और दोहरा लेखांकन अपेक्षित होगा ।

- ii. पाटनरोधी कानून के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी यह मानते हैं कि वस्तु को तभी उत्पादित किया गया माना जाना चाहिए यदि निविष्टि को उत्पादन में "पर्याप्ततः रूपांतरित" किया गया हो । जांच प्राधिकारियों की व्यापक स्वीकृत परंपरा भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्मों, उत्पादन प्रौद्योगिकी, विनिर्माण प्रक्रिया, संयंत्र एवं उपकरण, कार्य व उपयोग, कीमत, उपभोक्ता अवधारणा तथा सीमाशुल्क वर्गीकरण जैसे मापदंडों पर विचार करने की रही है ताकि इस बात पर विचार किया जा सके कि क्या दोनों वस्तुएं समान हैं अथवा भिन्न हैं । इसके अलावा, वस्तु का अंततः उत्पादन छोटी या बड़ी प्रक्रिया को अपनाकर किया जा सकता है और इसे उस रूप में अंततः रूपांतरित करने से पूर्व एक या अधिक चरणों में उत्पादित किया जा सकता है जिस रूप में वह निर्दिष्ट प्रयोजन के लिए उत्पादित वस्तु बन सकती है । केवल यदि कुछ निविष्टियों को मध्यवर्ती चरण में प्रसंस्कृत किया गया है, जहां पर उनका कोई उपयोग नहीं है (और वे कोई कार्य नहीं कर सकती हैं) परंतु अंतिम उत्पाद में खपत न होने के कारण मध्यवर्ती चरण को एक वस्तु माना जा सकता है यद्यपि वह उच्च चरण पर बिक्री योग्य है । इस दृष्टिकोण से प्राधिकारी यह मानते हैं कि एस डी एच उपकरण अथवा संयोजनों, उप संयोजनों, जिनका उत्पादन एस डी एच उपकरण बनाने की उत्पादन प्रक्रिया के दौरान किया गया है, के उत्पादन और बिक्री पर वर्तमान के प्रयोजनार्थ एक अलग उत्पाद के रूप में विचार नहीं किया जा सकता ।
- iii. प्राधिकारी ने याचिकाकर्ता और विदेशी उत्पादकों द्वारा किए गए उत्पादन कार्यकलापों के स्वरूप की विस्तार से जांच की । मौके पर सत्यापन अन्य बातों के साथ-साथ विशेष रूप से इस पहलू पर केनिद्रत रहा । प्राधिकारी ने इस संबंध में विभिन्न हितबद्ध पार्टियों के तर्क पर विचार किया है । इस बारे में प्राधिकारी निम्नलिखित निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि उत्पादन क्या है और एस डी एच उपकरण के विनिर्माण में किस प्रकार के उत्पादन कार्यकलापों को शामिल करना अपेक्षित है । एस डी एच उपकरण के निर्माण में शामिल विभिन्न चरण निम्नानुसार हैं ।

अनुसंधान >> उत्पाद परिकल्पना >> डिजाइन एवं ड्राइंग >> प्रौद्योगिकी विकास >> कार्यचालनात्मकता की परिकल्पना और उसकी समझ >> उत्पाद का ब्लू प्रिंट तैयार करना >> संबद्ध साफ्टवेयर का विकास >> उत्पाद के प्रोटोटाइप का विकास-हार्डवेयर तथा साफ्टवेयर >> संघटक की खरीद >> डिजाइन के अनुसार बोर्ड/कार्ड की पापुलेटिंग >> सोल्डरिंग तथा ई एम एस कार्यकलाप >> एकीकरण >> टैस्ट जिग तैयार करना >> संयोजन >> परीक्षण >> उत्पाद सहायता एवं बग फिक्स ।

iv. यह संभव है कि इन चरणों में से कुछेक चरणों में एक या अधिक उप प्रक्रिया शामिल हो जिसे स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है अथवा इनमें से कुछ प्रक्रिया को किसी कंपनी द्वारा एकीकृत किया जा सकता है ।

31. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी ने प्रारंभिक जांच परिणामों में यथापरिभाषित विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र की समीक्षा की । विभिन्न हितबद्ध पार्टियों की रिश्तति के बारे में प्राधिकारी निम्नानुसार मानते हैं -

(क) तेजस- तेजस द्वारा किए गए उत्पादन कार्यकलाप निम्नलिखित तालिका में दिए गए हैं

- क. अनुसंधान
- ख. उत्पाद परिकल्पना
- ग. डिजाइन एवं ड्राइंग
- घ. प्रौद्योगिकी विकास
- ड. कार्यचालनात्मकता की परिकल्पना और उसकी समझ
- च. उत्पाद का ब्लू प्रिंट तैयार करना
- छ. संबद्ध साफ्टवेयर का विकास
- ज. उत्पाद के प्रोटोटाइप का विकास-हार्डवेयर तथा साफ्टवेयर
- झ. संघटक की खरीद
- ट. सोल्डरिंग तथा ई एम एस कार्यकलाप
- ठ. एकीकरण
- ड. टैस्ट जिग तैयार करना
- ढ. संयोजन
- ण. परीक्षण
- त. उत्पाद सहायता एवं बग फिक्स ।

32. तेजस द्वारा किए गए उत्पादन कार्यकलाप की प्रकृति पर विचार करते हुए प्राधिकारी यह मानते हैं कि तेजस घरेलू विनिर्माता है ।

33. जहां तक पृथकी और वी एम सी एल का संबंध है, प्राधिकारी को स्रोत सूचना के आधार पर उपलब्ध तथ्यों के अनुसार भारत में पृथकी एवं वी एम सी एल द्वारा किए गए उत्पादन कार्यकलाप हैं- संयोजन, परीक्षण, तथा उत्पाद सहायता एवं बग फिक्स। जाहिर तौर पर ये कंपनियां भारत में केवल संयोजन प्रचालन करती हैं जो अति व्यापक कार्यकलाप है। निविष्टि का उत्पादन में "पर्याप्त" रूपांतरण नहीं होता है। कंपनी द्वारा खपत की गई निविष्टियों का विशिष्ट स्वरूप, कार्य/उपयोग नहीं होता है और उन्हें विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन हेतु उपयोग में लाया जाता है।

34. प्राधिकारी नोट करते हैं कि एक अमरीकी कंपनी सिएना जिसने जांच में भी भाग लिया है, द्वारा प्रस्तुत व्यौरों के अनुसार अमरीका में उनके द्वारा किए गए उत्पादन कार्यकलाप निम्नलिखित तालिका में दिए गए हैं।

क्र.सं	कार्यकलाप	कार्यकलाप का स्थान (अंदर/बाहर/दोनों जगह)
1	अनुसंधान	अमरीका
2	उत्पाद परिकल्पना	अमरीका
3	डिजाइन एवं ड्राइंग	अमरीका
4	प्रौद्योगिकी विकास	अमरीका
5	कार्यचालनात्मकता की परिकल्पना और उसकी समझ	अमरीका
6	उत्पाद का ब्लू प्रिंट तैयार करना	अमरीका
7	संबद्ध साफ्टवेयर का विकास	भारत
8	उत्पाद के प्रोटोटाइप का विकास-हार्डवेयर तथा साफ्टवेयर	अमरीका
9	संघटक की खरीद	अमरीका, चीन जन.गण तथा तीसरे देश
10	सोल्डरिंग तथा ई एम एस कार्यकलाप	अमरीका, चीन जन.गण तथा थाइलैंड, सिंगापुर
11	एकीकरण	अमरीका तथा तीसरे देश
12	टैस्ट जिग तैयार करना	अमरीकी
13	संयोजन	अमरीका तथा तीसरे देश
14	परीक्षण	अमरीका तथा तीसरे देश
15	उत्पाद सहायता एवं बग फिक्स।	अमरीका तथा तीसरे देश

## विचाराधीन उत्पाद का क्षेत्र

35. प्राधिकारी नोट करते हैं कि विचाराधीन उत्पाद ऐसे छी एवं प्रौद्योगिकी के उपयोग द्वारा निर्मित विवार्य द्रांसमेशन उपकरण है। अंतिम ग्राहक की जरूरत को पूरा करते के लिए इसका उत्पादन कई विनिर्देशनों में किया जा सकता है। इसके अलावा, उत्पादन संस्करण/उच्च क्षमता के उपकरण तैयार करना इस उद्योग में निरंतर चलने वाली प्राक्रिया/घटना है। जांच से यह पता चला है कि यद्यपि ऐसे टी एम 64 उपकरण विकसित किए जा रहे हैं ओँ ग्राहकों ने टेलीकॉम नेटवर्क (यद्यपि सीमित रूप में) में इन्हें लगाना शुरू कर दिया है तथापि, जहां तक भारतीय बाजार का संबंध है, ऐसे टी एम 256 जांच अवधि के दौरान विकास के चरण में था। जांच से यह पता चला है कि जांच अवधि के दौरान ऐसे छी ऐसे उपकरणों के निम्नलिखित प्रकारों का या तो उपयोग हो रहा था या उनका विकास किया जा रहा था। प्राधिकारी ने इनमें से कुछ प्रकारों को अलग रखने के बारे में हितबद्ध पार्टियों के तर्कों पर विचार किया और इस पंबंध में निम्नानुसार मत व्यक्त किया :-

क. ऐसे टी एम-1,4,16- इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि इन उत्पादों को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में सही ढंग से शामिल किया गया है।

ख. ऐसे टी एम-64- हितबद्ध पार्टियों ने यह तर्क दिया है कि याचिकाकर्ता ने वाणिज्यिक मात्रा में ऐसे टी एम-64 को नहीं उतारा है। यह भी तर्क दिया गया है कि सबसे बड़ी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के प्रचालक (बी एस एन एल) ने याचिकाकर्ता से ऐसे टी एम-64 की खरीद नहीं की है। अतः प्राधिकारी यह मानते हैं कि ऐसे टी एम-64 निम्नतिरिखित कारणों से विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में सही ढंग से शामिल किया गया है।

- (अ) कंपनी ने ऐसे टी एम-64 का उत्पादन कर भारतीय एवं घरेलू बाजारों में उत्सकी विक्री की है जैसा कि जांच दल के जरिए प्राधिकारी ने सत्यापन किया है।
- (ब) यदि किसी कंपनी ने नियात बाजार में कुछ मात्रा की बिक्री की है तो उस उत्पाद प्रकार की अन्य नहीं रखा जा सकता क्योंकि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित सामान वर्तुले दूर से ली पुष्टि होती है (कप्राधिकारी नोट करते हैं कि नियम 2(घ) के साथ जुड़ा नियम 2 (ख) का तात्पर्य यह है कि घरेलू उत्पाद ने समान वर्तुले दूर सामान किया है। इस बात की अपेक्षा करना एक अस्यक है कि वर्तुले उद्योग को घरेलू बाजार में सामान वर्तुले की विक्री याहिए जो इस वाचिकाकर्ता के परिसरों पर दिए गए गैर के पर सत्यापन करना वाचिकाकर्ता के विवादों में ऐसे टी एम-64 के उत्पादन का पता अल्प अर्थात् छोड़करहेले के दिए गए।)

ग. ऐसे टी एम-256- जांच दल पर नाम अनुदि के दौरान ऐसे टी एम-256 का न तो अन्यात किया जाता है वर्तुले ही घरेलू उद्योग ने आपूर्ति की है। याचिकाकर्ता और विदेशी

उत्पादकों की परिसरों पर की गई जांच से यह पता चला कि एस टी एम-256 का उल्लेख नए किरम के एस डी एच उपकरण के रूप में किया जा सकता है । जांच से यह पता नहीं चला कि यदि एस टी एम-256 का विदेशी उत्पादकों ने निर्यात किया है तो घरेलू उद्योग ने एस टी एम-256 को नहीं उतारा है । वस्तुतः हितबद्ध पार्टियां इस बात से सहमत हैं कि एस टी एम-256 का उपयोग करने हेतु तकनीकी अनुमोदन/अनुमति की प्रणाली देश में मौजूद ही नहीं है । प्राधिकारी ने यह याचिका किया है कि किसी विशेष प्रकार को अलग रखने के दावे को तब तक स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि उसका संगत अवधि के दौरान भारत को निर्यात न किया गया हो व्यौद्धिकी घोषणा जूस समान वस्तु की आपूर्ति न किए जाने के तथ्य को पूर्ण तरह तक नहीं की जा सकती जब तक उस प्रकार का भारत को निर्यात न किया गया हो । प्राधिकारी नोट करते हैं कि एस टी एम-256 के अपर्जन को न्यायोचित ठहराने के लिए कोई आधार नहीं दिया गया है । इलेक्ट्रो अलावा, जांच दल को तेजश्व द्वारा विनिर्मित और बगलौर रिस्थित उनके परिसरों में उपलब्ध हैं एस टी एम-256 उपकरण को दिखाया गया था । तेजस ने यह प्रदर्शित किया कि उसने उत्पाद के विकास हेतु भारी निवेश (\*\*\* करोड रुपए) किया है और यह दावा किया कि इस उपकरण की बिक्री तभी की जा सकती है जब पार्टी उसके लिए ऑर्डर प्रस्तुत करे ।

घ. डिजिटल क्रास कनेक्ट - हितबद्ध पार्टियां ने बार-बार डिजिटल क्रास कनेक्ट को अलग रखने का तर्क दिया । जांच में यह पता चला है कि डिजिटल क्रास कनेक्ट वस्तुतः ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग दूर संचार नेटवर्क में किया जाता है जिससे उच्चस्तरीय संकेतों के बीच पुनः व्यवस्थित तथा अंतर-संबंधित करने के लिए निम्न स्तरीय संकेत प्राप्त होते हैं । डिजिटल क्रास कनेक्ट का उत्पादन एस डी एच प्रौद्योगिकी तथा अन्य प्रौद्योगिकियों में किया जा सकता है । एस डी एच प्रौद्योगिकी का डिजिटल क्रास कनेक्ट उपकरण स्पष्टतः एस डी एच उपकरण है । जांच दल द्वारा सत्यापित रिकॉर्ड से यह सिद्ध होता है कि एस डी एच प्रौद्योगिकी के डिजिटल क्रास कनेक्ट का उत्पादन किया गया है और धारिकाकर्ता ने जांच अवधि के दौरान उसकी आपूर्ति की है । क्षति संबंधी सूचना और क्षति मार्जिन के निर्धारण में शामिल लागत एवं कीमत सूचना में एस डी एच प्रौद्योगिकी के डिजिटल क्रास कनेक्ट का उत्पादन और बिक्री शामिल है । अतः प्राधिकारी यह मानते हैं कि एस डी एच प्रौद्योगिकी का डिजिटल क्रास कनेक्ट सही ढंग से विचाराधीन उत्पाद के दायरे में शामिल है । तथापि, चूंकि डिजिटल क्रास कनेक्ट का उत्पादन अन्य प्रौद्योगिकी में भी होता है, इसलिए वेहद सावधानी के रूप में यह स्पष्ट किया जाता है कि अन्य प्रौद्योगिकियों का डिजिटल क्रास कनेक्ट विचाराधीन उत्पाद और वर्तमान जांच के दायरे में नहीं आता है ।

ड. एस डी एच उपकरणों का एस के डी/सी के डी स्वरूप - हितबद्ध पार्टियों ने व्यापक रूप से यह स्वीकार किया है कि एस डी एच का एस के डी/सी के डी स्वरूप सही ढंग से विचाराधीन उत्पाद के दायरे में आता है । ऊपर उल्लिखित उत्पादन प्रक्रिया से यह देखा जाएगा कि यह उत्पाद कई कारणों, संघटकों का संयोजन है, संयोजन एवं उप संयोजन है । इस बात की प्रबल संभावना है कि उत्पाद की ढुलाई एस के डी/सी के डी स्वरूप में की जाती है । वस्तुतः उत्पाद का बीजक सामान्यतः केवल एस के डी/सी के डी स्वरूप में किया जाता है । उत्पादक "पूर्णतः कार्यचालनात्मक तथा प्रचालनात्मक" एस डी एच उपकरण के लिए

बीजक तैयार नहीं करते हैं। एस के डी/सी के डी स्वरूप से उत्पादन प्रक्रिया अत्यंत कम होती है, संयोजन प्रचालन हेतु केवल सकू ड्राइवर प्रौद्योगिकी की जरूरत होती है। वस्तुतः यह संभव है (और वस्तुतः यह परंपरा व्यापक रूप से अपनाई जाती है) कि सर्वप्रथम आवश्यक जांच आदि सहित पूर्ण उपकरण का उत्पादन किया जाए और तैयार रूप में भेजने के बजाए इसे एस के डी/सी के डी स्वरूप में खंडित करने के बाद भेजा जाए। इस प्रकार ऐसे एस के डी/सी के डी के निर्यात विचाराधीन उत्पाद के ही निर्यात माने जाते हैं। वस्तुतः उत्पाद का पोत परिवहन चीन जन.गण. से इस एस के डी/सी के डी स्वरूप में किया गया है। अतः प्राधिकारी इस बात की पुष्टि करते हैं कि उत्पाद के क्षेत्र में उत्पाद का एस के डी/सी के डी स्वरूप शामिल है।

च. संयोजन और उप संयोजन - चीन जन.गण. और इजराइयल के विभिन्न निर्यातकों के रिकॉर्डों के सत्यापन से यह पता चला कि उपकरण का पोत परिवहन संयोजनों और उप-संयोजनों के रूप में किया जाता है और इनमें से प्रत्येक संयोजनों/ उप संयोजनों की कीमत अलग-अलग निर्धारित की जाती है किसी इकाई के रूप में संयोजनों/ उप संयोजनों के रूप में आयोजित उपकरण विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में आता है।

छ. पापुलेटिड सर्किट बोर्ड/कार्ड - कार्ड/पीसीबी को विनिर्माता द्वारा तैयार की गई डिजाइन के अनुसार पापुलेटिड किया जाता है और तत्पश्चात साफ्टवेयर डालने के अलावा, उन्हें केवल सेल्फ में व्यवस्थित करने और एक सर्किट में समायोजित करने की जरूरत होती है। चूंकि प्रिटेड सर्किट बोर्ड पर विनिर्माता का स्वामित्व होता है, इसलिए ये विचाराधीन उत्पाद के दायरे में आते हैं। तथापि, यह स्पष्ट किया जाता है कि पीसीबी या कार्ड एस डी एच उपकरण से इतर किसी उत्पाद के उत्पादन/संयोजन हेतु नियत होने की स्थिति में वे विचाराधीन उत्पाद के दायरे में नहीं आते हैं। पी सी बी और कार्ड विचाराधीन उत्पाद के दायरे में तभी आते हैं जब ऐसे पीसीबी या कार्ड एस डी एच उपकरण के उत्पादन के लिए हों।

ज. पुर्जे एवं संघटक - हितबद्ध पार्टियों ने पुर्जे और संघटकों को विचाराधीन उत्पाद में शामिल करने का भारी विरोध किया है। हितबद्ध पार्टियों ने अन्य बातों के साथ-साथ यह तर्क दिया है कि (क) पुर्जे/संघटक अलग उत्पाद हैं (2) घरेलू उद्योग ने पर्जे तथा संघटकों की पेशकश नहीं की है। (3) पुर्जे/संघटकों के चरण से उत्पादन काफी अधिक होता है और वस्तुतः यही उत्पादन है। (4) पुर्जे/संघटकों पर पाटनरोधी शुल्क लगाना उचित नहीं है अथवा इससे कार्यान्वयन के चरण पर उत्पीड़न हो सकता है और न्यायोचित न होने पर भी शुल्क वसूली की मांग उठ सकती है। इसके विपरीत घरेलू उद्योग ने इस आधार पर पुर्जे और संघटकों को शामिल करने की मांग की है कि उन्हें अलग रखे जाने से उल्लंघन की बड़ी गुंजाइश बन जाएगी। उन्होंने यह दलील दी है कि "कच्ची सामग्री" अथवा "निविष्टि" के रूप में संघटकों के आयात को संघटक रूप में एस डी एच के आयातों से अलग तथा विशिष्ट रूप में रखा जाना चाहिए (सीमाशुल्क जांच/नियंत्रण/निकासी के बिना आपूर्त आई पी आर सहित)। उन्होंने आगे यह नोट किया है कि घरेलू उद्योग निविष्टि के रूप में संघटकों के आयात के विरुद्ध नहीं है। घरेलू उद्योग चीन के उन्हीं आई पी आर का उपयोग करते हुए संघटकों के

रूप में उत्पाद का आयात करने और तत्पश्चात भारत में उत्पाद का संयोजन करने के खिलाफ है क्योंकि इसे अलग रूप में सतत पाटन माना जाता है ।

झ. प्राधिकारी ने इस तथ्य पर ध्यान दिया है कि घरेलू उद्योग द्वारा पुर्जों और संघटकों का विनिर्माण नहीं किया जाता है क्योंकि पुर्जों और संघटकों का घरेलू उद्योग से प्राधिकारी का सरोकार नहीं है ।

ठ. प्राधिकारी आगे यह नोट करते हैं कि एस डी एच उपकरण में प्रयुक्त पुर्जों और संघटकों का विविध उपयोग होता है और इनका केवल एस डी एच में ही उपयोग नहीं होता है। पुर्जों और संघटकों के उपयोग के ब्यौरों की जानकारी लेने के बाद प्राधिकारी का यह मत है कि अकेले आयात किए जाने की स्थिति में पुर्जों और संघटकों को शामिल किए जाने से समूचा उपभोक्ता टिकाऊ वस्तु उद्योग कठिनाई में पड़ सकता है ।

ठ. अन्य उपकरण के भाग के रूप में एस डी एच उपकरण - प्राधिकारी नोट करते हैं कि विचाराधीन उत्पाद अंततः ब्राड बैंड या सेल्युलर उपकरण का भाग है । ऐसे ब्राड बैंड या सेल्युलर उपकरण के भाग के रूप में एस डी एच उपकरण का आयात किए जाने की प्रबल संभावना है । यदि विचाराधीन उत्पाद के दायरे में ऐसे ब्राउ बैंड या सेल्युलर उपकरण के भाग स्वरूप एस डी एच उपकरण के आयात को शामिल नहीं किया जाता है तो वर्तमान जांच करने की समूची प्रक्रिया और प्रस्तावित उपाय नाकाम हो जाएंगे । इसके अलावा, किसी हितबद्ध पार्टी ने इस आशय का कोई न्यायोचित आधार नहीं दिया है कि ऐसे आयात पर शुल्क क्यों नहीं लिया जाना चाहिए । हितबद्ध पार्टी की एकमात्र चिंता यह हो सकती है कि सीमाशुल्क पत्तन प्राधिकारियों को समूचे ब्राड बैंड या सेल्युलर उपकरण पर पाटनरोधी शुल्क की मांग नहीं करनी चाहिए । अतः यह स्पष्ट किया जाता है कि शुल्क का क्षेत्र केवल ऐसे ब्राड बैंड/सेल्युलर उपकरण में शामिल एस डी एच उपकरण के मूल्य तक सीमित होगा । शुल्क की राशि समूचे उपकरण तक विस्तारित नहीं होगी । आयातकों से आशा है कि वे इस आशय की घोषणा करें और सीमाशुल्क पत्तन प्राधिकारियों से आशा की जाती है कि वे एस डी एच उपकरण के मूल्य का पता लगाने/विभाजन करने में पूर्ण सावधानी बरतें ।

ठ सॉफ्टवेयर - सॉफ्टवेयर विचाराधीन उत्पाद का एक अनिवार्य भाग है क्योंकि उपकरण ऐसे सॉफ्टवेयर के बिना कार्य कर ही नहीं सकता । ऐसे सॉफ्टवेयर को स्वयं उत्पादक द्वारा तैयार किया जा सकता है अथवा उत्पादक इसे अन्य एजेंसियों से तैयार करवा सकता है । यह संभावना है कि ऐसे सॉफ्टवेयर का बीजक उपकरण के भाग के रूप में अथवा अलग से तैयार किया जाए । विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में सॉफ्टवेयर को शामिल करना उचित है और प्राधिकारी इसकी पुष्टि करते हैं ।

ठ बी डब्ल्यू डी एम - कई हितबद्ध पार्टियों ने बी डब्ल्यू डी एम को अलग रखने की मांग की है । बी डब्ल्यू डी एम एक अलग प्रौद्योगिकी वाला ट्रांसमिशन उपकरण है । यह एस डी एच प्रौद्योगिकी उपकरण नहीं है । चूंकि बी डब्ल्यू डी एम एस डी एच प्रौद्योगिकी उपकरण नहीं है, इसलिए यह वर्तमान जांच और प्रस्तावित उपायों में नहीं आता है । तथापि, हितबद्ध

पार्टियों के बार-बार तर्कों और सीमाशुल्क पत्तन प्राधिकारियों द्वारा भविष्य में पाटनरोधी शुल्क की संभावित मांग के दावे को ध्यान में रखते हुए अंतिम जांच परिणाम में इस बात को स्पष्ट करने का प्रस्ताव है कि बी डब्ल्यू डी एम ट्रांसमिशन उपकरण विचाराधीन उत्पाद के दायरे में नहीं आते हैं और उन पर कोई पाटनरोधी शुल्क देय नहीं है ।

36. याचिका, जांच शुरुआत संबंधी अधिसूचना, प्रारंभिक जांच परिणाम, घरेलू उद्योग और विरोधी हितबद्ध पार्टियों के तर्कों को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी यह मानते हैं कि विचाराधीन उत्पाद का क्षेत्र निम्नानुसार है:

“ सिंक्रोनस डिजीटल हाइआर्की ट्रांसमिशन उपकरण, अर्थात् एस टी एम-1, एस टी एम-4, एस टी एम-16, एस टी एम-64, एस टी एम-256 जो संयोजित रूप में, सी के डी, एस के डी रूप म हैं, उसके संयोजन और उप संयोजन अथवा जो आकस्मिक ब्रॉड बैंड/सेल्युलर उपकरण से फिट किए गए हैं । विचाराधीन उत्पाद में एड ड्रॉप मल्टीप्लेक्सर, (ए डी एम), (केवल एस टी एच अनुप्रयोग हेतु), मल्टीप्ल एड ड्रॉप मल्टीप्लेक्सर (एम ए डीएम) तथा डिजीटल क्रॉस-कनेक्ट, (डी एक्स सी) (केवल एस टी एच अनुप्रयोग हेतु), पापुलेटेड सर्किट बोर्ड, (केवल एस टी एच अनुप्रयोग हेतु), और उपकरण अथवा उसके संयोजनों/उप संयोजनों के साथ आयात किए जाने पर उपकरण के भाग के रूप में आयातित पुर्जे/संघटक भी शामिल होंगे । विचाराधीन उत्पाद में इन उपकरणों के अभिन्न भाग और जिसकी खरीद उपकरण के भाग के रूप में या पृथक रूप में की जा सकती है, एस टी एच के लिए नियम साफ्टवेयर भी शामिल होगा । तथापि, एकल आधार पर आयातित संघटक/पुर्जे विचाराधीन उत्पाद के दायरे में नहीं आते हैं । ”

37. सिएना के अनुरोधों के अनुसार वे संघटकों की प्राप्ति चीन जन.गण. से कर रहे हैं और सिएना अमरीका के उत्पादों के लिए विनिर्माण या संयोजन के एक भाग का निष्पादन भी सेनमिना एस सी आई द्वारा चीन जन.गण. में कराया जाता है और ये वीन जन.गण. के मूल के उत्पाद के रूप में पात्र नहीं हैं तथा प्राधिकारी यह मानते हैं कि उनके द्वारा उत्पादित वरतु पर पाटनरोधी शुल्क तभी लागू किया जा सकता है जब वे विचाराधीन उत्पाद की परिभाषा में आते हों और जब भारत में ऐसी वस्तु का आयात जांचाधीन संबद्ध देशों के मूल से किया गया हो या इसका निर्यात किया गया हो ।

### पी सी एन प्रणाली

38. विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन और बिक्री अलग-अलग कई प्रकारों में की जाती है । अलग-अलग प्रकारों का उत्पादन विशिष्ट ग्राहक की जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाता है । सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत के बीच उचित तुलना करने के लिए प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद को ट्रांसमिशन क्षमता, क्रास कनेक्ट क्षमता, ई 1 इंटरफेश, इलैक्ट्रिकल इंटरफेस, आटिकल इंटरफेस, आटिक टाइप आदि जैसे मापदंडों के आधार पर अलग-अलग प्रकारों में विभाजित किया है । प्राधिकारी ने 15 अंकों वाली एक उत्पाद नियंत्रण प्रणाली (पी

सी एन) तैयार की है। सभी हितबद्ध पार्टियों को प्रत्येक पी सी एन के लिए अलग से लागत तथा कीमत सबधी सूचना देने का निर्देश दिया गया था।

39. राचिका का विरोध करने वाली कुछ हितबद्ध पार्टियों ने प्राधिकारी द्वारा विकसित पी सी एन प्रणाली से संबंधित मुद्दे उठाए हैं। यह अनुरोध किया है कि तेजस ने उत्पाद नियंत्रण संख्या (पी सी एन) प्रणाली तैयार कर विचाराधीन उत्पाद में शामिल विभिन्न उपकरणों के निर्देशनों को मानकीकृत करने का प्रयास किया है। उनके अनुसार यद्यपि, पी सी एन मानदंड तैयार कर मापदंडों को मानकीकृत करने का कुछ प्रयास किया गया है, तथापि ऐसे उत्पाद अपनी प्रकृति से मानकीकरण के अनुरूप नहीं हैं क्योंकि वे पूर्णतः अमानकीकृत हैं, प्रत्येक नेटवर्क की जरूरत के अनुरूप तैयार किए जाते हैं, अलग बारंबारता पर कार्य करते हैं, अलग-अलग माड्यूल में होते हैं, जिनमें जोड़-घटा किए जाने से लागत में अंतर आ जाएगा और लागत उपयोग में लाई गई प्रौद्योगिकी, हार्डवेयर तथा साफ्टवेयर की आपसी क्रिया पर निर्भर होती है।

40. इन टिप्पणियों पर ध्यान देते हुए प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि विचाराधीन उत्पाद अनिवार्यतः कई इलैक्ट्रोनिक कार्डों का संयोजन तथा उप संयोजन है। वस्तुतः उत्पादक उत्पाद के एस के डी/सी के डी/कार्ड/उप संयोजन के रूप में बिक्री बीजक तैयार करना चाहते हैं। जांच से यह पता चला है कि समस्त कंपनियां उत्पाद की डिजायन और विकास हेतु समान प्रणाली अपनाती हैं जिसके लिए समान उत्पाद कोडिंग प्रणाली का पालन किया जाता है। विचाराधीन उत्पाद के इस पहलू पर विचार करते हुए प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र को देखते हुए पी सी एन प्रणाली निर्धारित की है और उसकी मंशा विचाराधीन उत्पाद के दायरे को अभिज्ञान योग्य तथा तुलनीय बनाने की थी। ऐसा करते समय प्राधिकारी ने समस्त प्रतिवादी निर्यातकों को यह स्वतंत्रता प्रदान की कि वे पी सी एन प्रणाली को तैयार करने के बारे में कोई अन्य सुझाव दें जो प्राधिकारी द्वारा प्रस्तावित प्रणाली से इतर प्रणाली को न्यायोचित ठहराते हों। इस संबंध में सभी हितबद्ध पार्टियों को अलग-अलग पत्र भेजा गया था। तथापि, जांच में भाग लेने वाले सभी निर्यातकों ने प्राधिकारी द्वारा सुझाई गई पी सी एन पद्धति को स्वीकार कर लिया और उन्होंने उक्त पी सी एन पद्धति के अनुसार आंकड़े प्रस्तुत किए। अतः प्राधिकारी यह मानते हैं कि वर्तमान जांच के लिए अपनाई गई पी सी एन प्रौद्योगिकी सही सिद्ध हुई है और वह समस्त हितबद्ध पार्टियों, खासकर उन प्रतिवादी निर्यातकों के लिए स्वीकार्य बन गई है, जिन्होंने इस पद्धति पर सैद्धांतिक सहमति प्रदान की है और इस पी सी एन पद्धति के आधार पर अपने आंकड़ों का सत्यापन कराया है।

### घरेलू उद्योग का आधार और क्षेत्र

41. विभिन्न हितबद्ध पार्टियों ने निम्नानुसार तर्क दिए हैं :-

- क. याचिकाकर्ता विचाराधीन उत्पाद का स्वयं एक आयातक है।
- ख. नियम 2(ख) के अंतर्गत विवेकाधिकार का उपयोग अलग-अलग पार्टियों के लिए अलग-अलग ढंग से नहीं किया जा सकता।

ग. नियमों में संबद्ध देशों और असंबद्ध देशों से हुए आयातों के बीच कोई अंतर नहीं किया गया है ।

घ. नियमों में आयातों की मात्रा के बारे में कोई संख्यात्मक फार्मूला नहीं दिया गया है ।

ड. याचिकाकर्ता द्वारा थाइलैंड से आयातित वस्तु में ऐसे पुर्जे/संघटक शामिल हो सकते हैं जिन्हें अंततः चीन जन.गण. से प्राप्त किया गया हो और विचाराधीन उत्पाद में पुर्जे/संघटक शामिल होने के कारण याचिकाकर्ता को अपात्र घरेलू उद्योग माना जाना चाहिए ।

42. प्राधिकारी यह मानते हैं कि वर्तमान जांच में विचार और निर्णय हेतु निम्नलिखित मुद्दे उठते हैं ।

(क) क्या तेजस, बी एम सी एल, पृथ्वी और ऐसी अन्य कंपनियों को वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ पाटन कानून के अंतर्गत समान वस्तु का उत्पादक या विनिर्माता माना जा सकता है ।

(ख) क्या तेजस, बी एम सी एल, पृथ्वी तथा ऐसी अन्य कंपनियों को संबद्ध या असंबद्ध देशों से इन कंपनियों द्वारा किए गए आयातों के मद्देनजर नियम 2(ख) के अर्थ के भीतर पात्र या अपात्र घरेलू उद्योग माना जाना चाहिए । इसके अलावा, क्या केवल तीसरे देशों से हुए आयात इस प्रयोजनार्थ संगत हैं अथवा क्या तीसरे देशों से हुए आयात पर नियम 2(ख) के अंतर्गत संभावित अपात्रता मानदंड भी लागू होते हैं ।

43. 15 जुलाई, 1999 से पूर्व नियमावली के नियम 2(ख) में निम्नानुसार उल्लेख था :-

"(ख)"घरेलू उद्योग" का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा उन उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा बनता है, परंतु जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं या वे स्वयं उसके आयातक होते हैं तो ऐसे मामले में ऐसे उत्पादकों को घरेलू उद्योग का भाग नहीं माना जाएगा ।" (जोर दिया गया)

44. इस जांच की शुरूआत के समय नियमावली के नियम 2(ख) का पाठ निम्नानुसार था:

"(ख)"घरेलू उद्योग" का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा उन उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा बनता है, परंतु जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं या वे स्वयं उसके आयातक होते हैं तो ऐसे मामले में ऐसे उत्पादकों को घरेलू उद्योग का भाग नहीं माना जा सकता है ।" (जोर दिया गया)

45. तथापि, जांच की शुरूआत के बाद इस नियम में निम्नानुसार संशोधन किया गया है:

"घरेलू उद्योग" का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा उन उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा बनता है, परंतु जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं या वे स्वयं उसके आयातक होते हैं तो ऐसे मामले में "घरेलू उद्योग" पद का अर्थ केवल शेष उत्पादकों के उल्लेख के रूप में निकाला जाएगा" (जोर दिया गया) ।

46. अतः पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) में यह प्रावधान है कि कुछेक स्थितियों में घरेलू उद्योग का निर्धारण करते समय जो घरेलू उत्पादक निर्यातकों या आयातकों से संबद्ध हैं अथवा वे स्वयं आरोपित पाटित वस्तु के आयातक हैं, उन्हें अलग रखा जा सकता है । चूंकि नियम 2(ख) में "सकता है" शब्द के उपयोग से संदर्भाधीन उत्पादकों के दो प्रकारों का संकेत मिलता है अर्थात् संबद्ध उत्पादक और पाटित आयातों का आयात करने वाले उत्पादक जो घरेलू उद्योग का भाग बनने से स्वतः वंचित नहीं होते हैं । इसके बजाए, जांच प्राधिकारियों की यह सतत पद्धति रही है कि उचितं तथा समान आधारों पर और अंतर्गस्त समस्त विधिक तथा आर्थिक पहलुओं पर ध्यान देते हुए ऐसे उत्पादकों को अलग रखने का निर्णय मामला दर मामला आधार पर लिया जाना चाहिए ।

47. किसी घरेलू उत्पादक को घरेलू उद्योग के क्षेत्र तथा दायरे में शामिल करने या अलग रखने का प्रश्न व्यावहारिक महत्व रखता है क्योंकि प्रश्न यह उठता है कि क्या वे पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) की भावना के अनुसार घरेलू उद्योग के वास्तविक भाग हैं अथवा नहीं । इसका बाद में आवेदन के आधार पर प्रभाव पड़ सकता है अर्थात् क्या उनका (आवेदन को दायर करने वाले अथवा समर्थन करने वाले घरेलू उत्पादकों) उत्पादन पाटनरोधी नियमावली में यथानिर्धारित आनुपातिक रूप से आवश्यक स्तर पर हुआ है क्योंकि निर्यातकों या आयातकों से संबंध रखने के कारण अथवा उनके द्वारा स्वयं पाटित आयात किए जाने के कारण घरेलू उद्योग की परिभाषा से अलग रखे गए घरेलू उत्पादकों के उत्पादन पर कुल घरेलू उत्पादन की गणना करते समय और समर्थक घरेलू उत्पादकों के साथ आवेदक का ऐसे उत्पादन में एक प्रमुख हिस्से का निर्धारण करते समय विचार नहीं किया जाएगा ।

48. प्राधिकारी नोट करते हैं कि नियम 2(ख) में दो बार संशोधन किया गया है । दिनांक 1.1.1995 की स्थिति के अनुसार पाटनरोधी नियमावली में निहित नियम 2(ख) में ऐसी स्थितियों में निर्दिष्ट प्राधिकारी के पास किसी विवेकाधिकार का प्रावधान नहीं था जिनमें एक या अधिक घरेलू उत्पादक ने विचाराधीन उत्पाद का आयात किया है अथवा वह विचाराधीन उत्पाद के किसी आयातक या निर्यातक से संबद्ध हैं । तथापि, डब्ल्यू टी ओ पाटनरोधी करार एवं अन्य जांच प्राधिकारियों के घरेलू कानूनों में ऐसी स्थितियों में जांच प्राधिकारियों को विवेकाधिकार दिया गया है, जिन्हें मामला दर मामला आधार पर लागू किया जाता है । नियम 2(ख) में ऐसी स्थितियों में निर्दिष्ट प्राधिकारी को विवेकाधिकार प्रदान करते हुए सी.शु. अधिसूचना सं. 44/1999 (एन टी) के तहत 15 जुलाई, 1999 से संशोधन किया गया है, जिसे मामला दर मामला आधार पर लागू किया जा सकता है । नियम 2(ख) में हाल में उपर्युक्तानुसार आगे

और संशोधन किया गया है। प्राधिकारी यह मानते हैं कि निम्नलिखित स्थितियों से निपटने के लिए यह विवेकाधिकार जरूरी है।

क. कुछ घरेलू उत्पादक केवल इस वजह से पाटनरोधी आवेदन का समर्थन नहीं करना चाहते कि वे उत्पाद का स्वयं आयात कर रहे हैं अथवा वे उस उत्पाद के आयातक या निर्यातक से संबद्ध हैं। ऐसे घरेलू उत्पादक पाटन के अनुचित व्यवहार के जरिए प्रतिस्पर्धा को समाप्त करने के लिए अन्य घरेलू उत्पादकों का प्रचालन भी बंद करवाना चाहते हैं। प्राधिकारी का विवेकाधिकार निहित करने का एक औचित्य यह है कि प्राधिकारी ऐसी कंपनियों को अलग रख सकें जो पाटनरोधी आवेदन दायर कर पाटन के कारण हुई क्षति के सद्भावनापूर्ण समाधान की मांग करते हुए और पाटन के अनुचित व्यापार व्यवहार के विरुद्ध उचित राहत की मांग करते हुए शेष घरेलू उत्पादकों द्वारा किए गए प्रयास को निष्प्रभावी करना चाहते हैं। यदि ऐसा नहीं है तो शेष घरेलू उत्पादक किसी पाटनरोधी आवेदन को दायर करने के लिए कानून में निर्धारित "आधार संबंधी अपेक्षा" को पूरा करने और पाटन के अनुचित व्यापार व्यवहार के खिलाफ उचित राहत प्राप्त करने के पात्र नहीं हो सकते हैं। संक्षेप में प्राधिकारी यह मानते हैं कि देश में क्षतिकारी पाटर के निवारण हेतु प्राधिकारी को सक्षम बनाने के लिए घरेलू उद्योग के दायरे से कुछेक कंपनियों को अलग रखा जाना जरूरी है।

ख. एक या अधिक घरेलू उत्पादकों द्वारा विचाराधीन उत्पाद का आयात किया गया हो सकता है अथवा उनकी संबद्ध कंपनियों द्वारा एक या अधिक सद्भावी कारणों से विचाराधीन उत्पाद का आयात या निर्यात किया गया हो सकता है। इनमें से कुछ कारण निम्नानुसार हैं:-

- i. अनुषंगी उत्पाद के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा करने के लिए अग्रिम लाइसेंस के तहत किए गए आयात;
- ii. उत्पादन के अस्थायी स्थगन (कई सद्भावी कारणों यथा आगजनी, हड्डताल, प्राकृतिक आपदा आदि की वजह से) के समय किए गए आयात;
- iii. किसी विशेष प्रकार का आयात कर उत्पादन की पूर्ति हेतु किए गए आयात जिसका आवेदक उत्पादन नहीं कर सकता है और जिसका हिस्सा उसके कुल व्यापार प्रचालनों का अत्यंत कम बनता है।
- iv. परीक्षण, अनुसंधान एवं विकास, बीज विपणन प्रयोजनों के लिए किए गए आयात (कम कीमत के आयातों के मुकाबले गुणवत्ता और अन्य मापदंडों की जांच हेतु उत्पाद का आयात)
- v. ऐसे उत्पाद के किसी भाग का आयात जो उत्पाद के विनिर्माण में कोई खास महत्व नहीं रखता है।
- vi. आयात की कुल मात्रा, भारतीय उत्पादन और खपत को ध्यान में रखते हुए आयात की मात्रा बहुत कम है।
- vii. विनिर्माण एवं आयात के बीच कारोबार संतुलन।
- viii. क्या आयात जांचाधीन देशों से हुए हैं।

49. अतः प्राधिकारी का यह मत है कि संशोधित नियमों में उपर्युक्त स्थितियों में प्राधिकारी को विवेकाधिकार प्रदान करने का प्राधिकार है । दूसरे शब्दों में पाटनरोधी नियमों में प्राधिकारी को इसलिए विवेकाधिकार प्रदान करने के लिए संशोधन किया गया है ताकि कुछेक स्थितियों में घरेलू उत्पादक को शामिल किया जा सके और कुछेक स्थितियों में घरेलू उत्पादक को अलग रखा जा सके ।

50. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के रिकॉर्डों के सत्यापन के दौरान उनके द्वारा जांच अवधि में किए गए आयातों के ब्यौरों का भी सत्यापन किया । कपनी द्वारा जारी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार जांच अवधि के दौरान एस टी एम-1, एस टी एम-4, एस टी एम-16 और एस टी एम-64 सहित एस डी एच की बिक्री मात्रा के संबंध में कुल कारोबार \*\*\* करोड़ रु. का रहा है । इसके अलावा, एस ए पी प्रणाली रिकॉर्डों और कंपनी द्वारा रखे गए वित्तीय रिकॉर्डों के सत्यापन से यह पता चलता है कि जिन संघटकों का उपयोग एस डी एच में होता है उनकी कुल संख्या 10795 है, जिनमें से 105 संघटकों की प्राप्ति चीन जन.गण. से की जाती है । चीन के मूल के संघटकों में मुख्यतः 68 वेयर बोर्ड और 5 फैन शामिल हैं । अन्य संघटक यांत्रिक स्वरूप के हैं । तेजस द्वारा विभिन्न लोतों से आयातित संघटकों/पी सी बी का ब्यौरा निम्नानुसार है :-

**क. थाइलैंड-\*\*\* रूपए (\*\*\*%)**

एक ऐसी ई एम एस है जो तेजस द्वारा अभिज्ञात \*\*\* विक्रेताओं से खरीद करती है । जहां से यह माना जाता है कि ई एम एस संघटकों की खरीद करती है । इनमें भारत के \*\*\* विक्रेता अमरीका के \*\*\* विक्रेता, ताइवान के \*\*\* विक्रेता, ई यू के \*\*\* विक्रेता, जापान के \*\*\* विक्रेता, स्विटजरलैंड के \*\*\* विक्रेता, यू के \*\*\* विक्रेता, थाइलैंड के \*\*\* विक्रेता, हांगकांग और कोरिया जन.गण के प्रत्येक \*\*\* विक्रेता, इजराइल के \*\*\* , चीन जन.गण के \*\*\* विक्रेता, कनाटा के \*\*\* विक्रेता, दुबई के \*\*\* विक्रेता और शेष विश्व के \*\*\* विक्रेता शामिल हैं । थाइलैंड से हुए आयातों में शामिल है;

- i. पी सी बी - तेजस द्वारा प्रदत्त डिजाइन के अनुसार संयोजित - \*\*\* रूपए - तेजस द्वारा प्रदत्त खचित साफ्टवेयर शामिल ।
- ii. वेयर बोर्ड- \*\*\* रूपए ।
- iii. कैपेसिटर - \*\*\* रूपए
- iv. कनेक्टर- \*\*\* रूपए
- v. इंडक्टर \*\*\* रूपए
- vi. रेजिस्टर \*\*\* रूपए
- vii. स्टिकर \*\*\* रूपए
- viii. ट्रांसरिसीवर \*\*\* रूपए
- ix. ट्रांसफारमर \*\*\* रूपए
- x. आई सी केबल, वासर, नट, पैकिंग सामग्री जैसी विविध मर्दे \*\*\* रूपए

**ख. भारत से स्थानीय रूप से प्राप्त - \*\*\* रूपए (\*\*\* %) \*\*\* विक्रेताओं से कीत**

- i. ई एम एस से पी सी बी - तेजस द्वारा प्रदत्त डिजाइन के अनुसार संयोजित -\*\*\* रूपए - (56%) तेजस द्वारा प्रदत्त खचित साप्टवेयर शामिल ।
- ii. वेयर बोर्ड- \*\*\* रूपए ।
- iii. कैपेसिटर - \*\*\* रूपए
- iv. कनेक्टर- \*\*\* रूपए
- v. इंडक्टर \*\*\* रूपए
- vi. रेजिस्टर \*\*\* रूपए
- vii. स्टिकर \*\*\* रूपए
- viii. ट्रांसरिसीवर \*\*\* रूपए
- ix. ट्रांसफार्मर \*\*\* रूपए
- x. पैच कार्ड - \*\*\* रूपए
- xi. रैक, चेसेज, फेस प्लेट, ट्रे, आई सी, केबल, वासर, नट, पैकिंग सामग्री जैसी यांत्रिक एवं विधिक मर्दें - \*\*\* रूपए

ग. सिंगापुर- \*\*\* रूपए (iii %) (सिंगापुर में तेजस की एक सहायक कंपनी खरीद कार्यालय के रूप में कार्य कर रही है जो सिंगापुर के \*\*\* विक्रेताओं सहित अनुमोदित विक्रेताओं से खरीद कर रही है)

इन खरीदों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :-

- i. पी सी बी - तेजस द्वारा प्रदत्त डिजाइन के अनुसार संयोजित -\*\*\* रूपए - (कुल कारोबार का \*\*\*%) तेजस द्वारा प्रदत्त खचित साप्टवेयर शामिल ।
- ii. कैपेसिटर - \*\*\* रूपए
- iii. कनेक्टर- \*\*\* रूपए
- iv. इंडक्टर \*\*\* रूपए
- v. रेजिस्टर \*\*\* रूपए
- vi. ट्रांसरिसीवर \*\*\* रूपए
- vii. ट्रांसफार्मर \*\*\* रूपए
- viii. पैच कार्ड - \*\*\* रूपए
- ix. आई सी, केबल, वासर, नट, पैकिंग सामग्री जैसी विधिक मर्दें - \*\*\* रूपए

**घ. चीन जन.गण. - \*\*\* रूपए (\*\*\* %)**

चीन जन.गण. से की गई खरीद का ब्यौरा निम्नानुसार है :-

- i. वेयर बोर्ड- \*\*\* रूपए
- ii. कैपेसिटर - \*\*\* रूपए
- iii. कनेक्टर- \*\*\* रूपए
- iv. इंडक्टर \*\*\* रूपए
- v. ट्रांसफार्मर \*\*\* रूपए
- vi. ट्रांसरिसीवर \*\*\* रूपए
- vii. पैच कार्ड - \*\*\* रूपए
- viii. आई सी, केबल, वासर, नट, पैकिंग सामग्री जैसी विधिक मर्दे - \*\*\* रूपए

#### उ ताइवान-\*\*\* रूपए (\*\*\* %)

ताइवान से की गई खरीद का ब्यौरा निम्नानुसार है :-

- i. कनेक्टर- \*\*\* रूपए
- ii. इंडक्टर \*\*\* रूपए
- iii. ट्रांसफार्मर \*\*\* रूपए
- iv. ट्रांसरिसीवर \*\*\* रूपए
- v. आई सी, केबल, वासर, नट, पैकिंग सामग्री जैसी विधिक मर्दे - \*\*\* रूपए

51. प्राधिकारी नोट करते हैं कि चीन जन.गण. से उक्त कंपनी द्वारा किए गए कल आयातों में से \*\*\*% आयात "कंपनी के कुल कारोबार का \*\*\*%" एकल संधटक के हैं जो विचाराधीन उत्पाद के भाग नहीं हैं और इसीलिए आधार के निर्धारण हेतु प्रासंगिक नहीं हैं। इसके अलावा, प्रतिवादी निर्यातकों के रिकॉर्ड के सत्यापन के दौरान प्राधिकारी को पृथकी तथा वी एम सी एम, दोनों द्वारा चीन जन.गण. से पूर्ण उपकरण के आयात के बारे में सूचना का पता चला। अतः वे पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के क्षेत्र के भीतर घरेलू उद्योग नहीं हैं।

52. इसके अलावा, जांचाधीन देशों से इतर देशों से हुए आयातों के मुद्दे के बारे में प्राधिकारी यह मानते हैं कि जहां उत्पाद का आयात जांचाधीन देशों से नहीं होता है वहां वह "आरोपित पाटित वस्तु" का आयात नहीं माना जाता है। अतः ऐसे आयात से घरेलू उद्योग के रूप में कोई आवेदन दायर करने से ऐसा घरेलू उत्पादक वंचित नहीं होता है। यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि जिन मामलों में घरेलू उत्पादक जांच के अधीन न आने वाले देशों से पर्याप्त मात्रा में आयात कर रहा है, उनमें कारणात्मक संबंध की मौजूदगी अथवा अन्यथा की पुष्टि हेतु यह संगत बन जाता है। यदि तीसरे देशों से हुए आयात की मात्रा काफी अधिक है तो वह अग्रासंगिक बन जाता है। इस बात की आशंका है कि तीसरे देश से हुए ऐसे आयात की मात्रा में पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद वृद्धि हो सकती है।

५०८७ ५०/१०-८१

53. हितबद्ध पार्टियों ने यह तर्क दिया है कि असंबद्ध देशों से किए गए आयात नियम 2(ख) के अंतर्गत असंगत हैं और "आरोपित पार्टित वस्तु" वस्तु से संबंधित है और उसे देश से नहीं जोड़ा जा सकता। प्राधिकारी ने इस संबंध में विभिन्न विधिक प्रावधानों की सावधानीपूर्वक जांच की है और यह माना है कि नियमों के अंतर्गत विभिन्न प्रावधानों में उल्लिखित शब्दावली तथा नियम 2(ख) के अंतर्गत प्रदत्त अपवर्जन के उद्देश्य से यह स्पष्ट हो जाता है कि नियम 2(ख) के अंतर्गत किसी पार्टी को अलग रखने का प्रश्न तभी उठना चाहिए यदि ऐसे आयात जांचाधीन संबद्ध देशों से किए गए हों। प्राधिकारी इस संबंध में नियम 2(ख) के अंतर्गत ऐसे किसी विवेकाधिकार का उपबंध करने वाले उद्देश्य/आशय तथा नियम 2 और 6 के विभिन्न प्रावधानों पर भरोसा करते हैं। नियम 2 और 6 के अंतर्गत पार्टित वस्तु अथवा आरोपित पार्टित वस्तु के सदर्भ स्पष्टतः संबद्ध देशों, ऐसे संबद्ध देशों के उत्पादक तथा ऐसे संबद्ध देशों के उत्पाद के आयातकों के बारे में है। अतः प्राधिकारी यह मानते हैं कि नियम 2(ख) के अंतर्गत घरेलू विनिर्माता को शामिल करने या अलग रखने के प्रयोजनार्थ संबद्ध देशों से जांचाधीन वस्तु का आयात ही प्रासंगिक है।

54. यह तर्क दिया गया है कि नियम 2(ख) अलग-अलग पार्टियों पर अलग ढंग से लागू नहीं किया जा सकता। आगे यह आरोप लगाया गया है कि प्राधिकारी ने तेजस को घरेलू उत्पादक की पात्रता रखने वाला और पृथ्वी तथा वी एम सी एल को घरेलू विनिर्माता की पात्रता न रखने वाला माना है। हितबद्ध विरोधी पार्टियों ने प्रारंभिक निर्धारण का खंडन किया है और यह तर्क दिया है कि जब तेजस और पृथ्वी/वी एम सी एल दोनों ने आयात किया है तो प्राधिकारी ने भेदभावपूर्ण ढंग से नियम 2(ख) में उपलब्ध विवेकाधिकार का उपयोग किया है। विचाराधीन उत्पाद, चीन, भारतीय, तीसरे देशों के अर्थ के बारे में निर्धारण के होते हुए भी भारत, चीन जन.गण. अथवा तीसरे देशों में विनिर्मित वस्तु से यह अर्थ निकाला जाएगा की पृथ्वी और वी एम सी एल भारत में विचाराधीन उत्पाद की घरेलू विनिर्माता नहीं है। अतः प्राधिकारी यह मानते हैं कि नियम 2(ख) में किसी भी हालत में स्वयं आयात करने वाले घरेलू उत्पादकों को शामिल करने या अलग रखने के बारे में किसी एकीकृत निर्णय लेने का प्रावधान नहीं है। प्राधिकारी यह मानते हैं कि ऐसे विवेकाधिकार का उपयोग मामला दर मामला आधार पर करना अपेक्षित है। अलग-अलग पार्टियों, अलग-अलग कारणों से उत्पाद का आयात कर सकती हैं। अलग-अलग पार्टियों द्वारा आयात की मात्रा/सीमा अलग-अलग हो सकती है। नियम 2(ख) के अंतर्गत घरेलू विनिर्माता को शामिल करने या न करने की बात कुछेक कारणों पर आधारित होती है। चूंकि स्वयं कारण पार्टी दर पार्टी अलग-अलग हो सकते हैं, इसलिए विवेकाधिकार के सार्वभौमिक उपयोग को न तो कानून में स्वीकार किया जाता है और न ही ऐसा करना उचित होगा। इस संबंध में प्राधिकारी तथा अन्य जांच प्राधिकारियों की परंपरा से भी प्राधिकारी के विचारों को समर्थन मिलता है।

55. हितबद्ध पार्टियों ने यह तर्क दिया है कि तेजस ने निर्विवाद रूप से ई एम एस की सेवाओं का उपयोग किया है। ऐसी ई एम एस कंपनियां चीन जन.गण. से पुर्जे/संघटकों की खरीद कर सकती हैं, जिनका मूल्य विवेकाधिकार का उपयोग करने में प्राधिकारी द्वारा भरोसेमंद आयात की मात्रा में शामिल नहीं किया गया हो सकता है।

प्राधिकारी नोट करते हैं कि तेजस द्वारा प्रयुक्त सबसे बड़ी ई एम एस सेवा थाइलैंड में है। थाइलैंड में उन्होंने अलग-अलग देशों के \*\*\* विक्रेताओं को अभिज्ञात किया है, जिनसे ये विक्रेता निविष्टियों/संघटकों की प्राप्ति करते हैं। इन \*\*\* विक्रेताओं में से केवल \*\*\* विक्रेता चीन जन.गण. के हैं। इसेक अलावा, इन विक्रेताओं की खरीद एकल संघटकों की होती है जिन्हें "विचाराधीन उत्पाद" के दायरे में नहीं लाया गया है। अतः प्राधिकारी यह मानते हैं कि तेजस की पात्रता का विरोध करने वाली विरोधी हितबद्ध पार्टियों का यह तर्क भी स्वीकार्य नहीं है।

56. यह आरोप लगाया गया है कि यद्यपि, कई अन्य विनिर्माता हैं, तथापि तेजस को पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के क्षेत्र के भीतर कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा रखने वाली कंपनी के रूप में आवश्यक आधार रखने वाला माना गया है। इस संदर्भ में प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि जांच की शुरूआत के बाद आरंभ में पृथ्वी और वी एम सी एल के अलावा, अपने अनुरोधों में पृथ्वी तथा वी एम सी एल दोनों द्वारा रेखांकित तथाकथित कोई अन्य विनिर्माता घरेलू विनिर्माता की हैसियत का दावा करने के लिए आगे नहीं आया है। तथापि, कथनात्मक रूप में इस आशय का दावा करने के अलावा वे अपने विनिर्माण कार्यकलापों के बारे में कोई सूचना देने के लिए आगे नहीं आए। पृथ्वी/वी एम सी एल ने घरेलू उत्पादक अथवा विचाराधीन उत्पाद के आयातक के रूप में निर्धारित प्रपत्र में और निर्धारित ढंग से प्रश्नावली का उत्तर नहीं दायर किया है। प्राधिकारी द्वारा इन कंपनियों को निर्धारित ढंग से और प्रपत्र में सूचना प्रदान करने की सलाह देने के बाद भी इन हितबद्ध पार्टियों ने संगत सूचना प्रदान नहीं है। इन्होंने अन्यथा यह दावा करने के अलावा, अपनी संरचना के बारे में कोई ब्लौरा/आंकड़ा प्रस्तुत नहीं किया कि वे विनिर्माता हैं क्योंकि वे उत्पाद शुल्क का भुगतान भी करते हैं। पूर्व में किए गए उल्लेख के अनुसार इस प्रयोजनार्थ महज उत्पाद शुल्क के भुगतान से "विनिर्माता" का दर्जा प्रदान नहीं किया जा सकता। प्राधिकारी नोट करते हैं कि इन दोनों कंपनियों ने नियम 6(8) के अर्थ के भीतर सहयोग नहीं किया है। प्राधिकारी यह मानते हैं कि यद्यपि, कोई हितबद्ध पार्टी अपना तर्क दे सकती है, तथापि ऐसी हितबद्ध पार्टी के लिए यह अनिवार्य है कि वह प्राधिकारी के अनुरोधानुसार ऐसी सूचना प्रदान करे और सत्यापन हेतु स्वयं को उपस्थित रखे। इन कंपनियों की वास्तविक स्थिति का पता लगाने के इस मामले में की गई समूची प्रक्रिया काफी आसान रही होती, यदि हितबद्ध पार्टियों ने प्राधिकारी द्वारा मांगी गई संगत सूचना प्रदान कर दी होती और उन्होंने मौके पर सत्यापन के लिए स्वयं को प्रस्तुत कर दिया होता। इन हितबद्ध पार्टियों के सुविचारित असहयोग को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी ने इस संबंध में उपलब्ध सामग्री पर भरोसा किया है। रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना से निम्नानुसार पता चलता है।

- i. हितबद्ध पार्टियों ने जांच अवधि की समाप्ति तक एस डी एच उपकरण की बिक्री नहीं है।
- ii. प्राधिकारी ने अनुसंधान, उत्पाद परिकल्पना, डिजाइन व ड्राइंग, प्रौद्योगिकी विकास, उत्पाद परिकल्पना, डिजाइन एवं ड्राइंग, प्रौद्योगिकी विकास, कार्यचालनात्मकता की परिकल्पना एवं समझ, उत्पाद का ब्लू प्रिंट तैयार करने, संबद्ध साफ्टवेयर के

विकास, उत्पाद के प्रोटोटाइप के विकास-हार्डवेयर व साफ्टवेयर, संघटक खरीद, सोल्डरिंग तथा ई एस कार्यकलाप, एकीकरण, टेस्ट जिग की तैयारी, संयोजन, परीक्षण तथा उत्पाद सहायता एवं बग फिक्सेज जैसे कार्यकलापों को अनिवार्य उत्पादन कार्यकलाप के रूप में अभिज्ञात किया । ये हितबद्ध पार्टियां प्राधिकारी द्वारा सूचीबद्ध ये उत्पादन कार्यकलाप नहीं करती हैं, जिनमें वर्तमान मामले में उत्पादन में शामिल कार्यकलाप शामिल हैं । यह सिद्ध नहीं किया गया है कि ये पार्टियां संयोजन प्रचालन भी करती हैं । रिकॉर्ड में इन कंपनियों द्वारा विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन और बिक्री करने का कोई साक्ष्य नहीं है । उत्पाद शुल्क के भुगतान के बार-बार तर्क के बाद भी इन हितबद्ध पार्टियों ने यह सिद्ध नहीं किया है कि उक्त उत्पाद शुल्क का भुगतान एस डी एच उपकरण के बारे में किया गया था । याचिकाकर्ता ने तर्क दिया है कि उक्त उत्पाद शुल्क का भुगतान विभिन्न उत्पादों पर किया गया हो सकता है । इन हितबद्ध पार्टियों ने यह प्रदर्शित करने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है कि उत्पाद शुल्क का भुगतान वस्तुतः विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन और निकासी के लिए किया गया है ।

iii. ये हितबद्ध पार्टियां यह सिद्ध करने में विफल रही हैं कि उन्होंने विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन के लिए अपेक्षित अनुसंधान एवं विकास, संयंत्र एवं उपकरण तथा अन्य सुविधाओं में निवेश किया है । इस संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि केवल विचाराधीन उत्पाद से संबंधित कार्यकलाप प्राधिकारी के लिए संगत हैं । इन हितबद्ध पार्टियों द्वारा किए गए अन्य कार्यकलाप, यदि कोई हों, नितांत अप्रांसंगिक हैं । इस संबंध में यह उल्लेख करना भी प्रासंगिक है कि उनके खुद के रिकॉर्ड के अनुसार वी एस पी एल व पृथ्वी सहित कुछेक हितबद्ध पार्टियों ने डी डब्ल्यू डी एम को "विचाराधीन उत्पाद" माना है । अतः यह सिद्ध नहीं किया गया है कि क्या विनिर्माता की आरोपित स्थिति डी डब्ल्यू डी एम अथवा एस डी एच उपकरण के संभावित उत्पादन व बिक्री की वजह से बनी है । प्राधिकारी नोट करते हैं कि ऐसे मामले में इन कंपनियों ने उत्पादन सुविधाएं स्थापित की हैं और तत्पश्चात डी डब्ल्यू डी एम उपकरण का उत्पादन कर उसकी बिक्री की है । इसलिए वे वर्तमान के प्रयोजनार्थ और वर्तमान विचाराधीन उत्पाद हेतु उत्पादक की हैसियत का दावा करने की पात्र नहीं है ।

57 प्रारंभिक जांच परिणाम जारी होने के बाद फिब्कॉम विचाराधीन उत्पाद का विनिर्माता होने का दावा करते हुए उसने यह दावा किया कि वह विचाराधीन उत्पाद के दायरे में न रखे जाने की स्थिति में संघटकों से संबंधित याचिका का समर्थन करती है । तथापि, उसने विनिर्माता होने के दावे के बारे में प्राधिकारी को कोई आंकड़ा उपलब्ध नहीं कराया है । याचिकाकर्ता ने जांच शुरूआत के पूर्व चरण में याचिका के साथ सी एम ए आई (एसो.), का एक पत्र दायर किया था । सी एम ए आई ने यह उल्लेख किया कि याचिकाकर्ता का भारतीय उत्पादन में एक बड़ा हिस्सा बनता है । जांच की शुरूआत के प्रयोजनार्थ इसे प्रथम दृष्ट्या पर्याप्त साक्ष्य माना गया था ।

58 प्राधिकारी ने प्रारंभिक जांच परिणामों में यह नोट किया कि हितबद्ध पार्टियों द्वारा नार्वे से फेंड सालोमन से संबंधित मामले में पैनल की रिपोर्ट का संदर्भ दिया गया है। प्राधिकारी प्रारंभिक जांच परिणामों में यह नोट करते हैं कि इस मामले के तथ्य वर्तमान मामले के तथ्यों से भिन्न हैं। संदर्भाधीन मामले में ई सी ने इस बात की जांच नहीं की थी कि क्या संबद्ध उत्पाद का उत्पादक न माने गए उत्पादकों द्वारा किए गए कार्यकलाप ऐसे कार्यकलाप हैं जिनहें उत्पादन माना जा सकता है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि डब्ल्यू टी ओ पैनल द्वारा पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 4.1 की दी गई व्याख्या का दायरा इस कार्यवाही में सीमित है। इस संबंध में रिपोर्ट का पैरा 7.115 प्रासंगिक है:

7.115 इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि फ्लेटिड सलमोन इस मामले में ई सी द्वारा अभिज्ञात समान उत्पाद के दायरे में आता है। इस प्रकार अनुच्छेद 4.1 की साधारण भाषा की हमारी व्याख्या के आधार पर हम यह मानते हैं कि ऐसे किसी उद्यम को समान उत्पाद का "उत्पादक" और इस प्रकार घरेलू उद्योग का भाग माना जाना चाहिए जिसने कम से कम पहली बार समान उत्पाद या उसके किसी रूप का उत्पादन किया है।

पाद टिप्पणी 289 में निम्नानुसार उल्लेख है:

289. ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं जिनमें ऐसा कोई उद्यम जिसका उत्पाद समान उत्पाद के दायरे में आता है, इतने कम स्तर पर कार्यकलाप में संलग्न पाया जा सकता है ताकि इस निष्कर्ष को औचित्यपूर्ण ठहराया जा सके कि वह वस्तुतः समान उत्पाद का "उत्पादन" नहीं करता है तथापि, जांच के दौरान घरेलू उद्योग को परिभाषित करते समय केवल फ्लेटिंग कार्यकलाप की मात्रा पर विचार नहीं किया गया था। अतः हमारे समक्ष इस मामले के तथ्यों के संबंध में कोई प्रश्न नहीं है। (जोड़ दिया गया)

59. अतः पैनल ने ऐसी कुछेक परिस्थितियों (पाद टिप्पणी 289 में उल्लिखित) की परिकल्पना की जिसके बारे में पैनल ने यह सहमति व्यक्त की कि वे उत्पाद के "उत्पादक" के रूप में किसी कंपनी पर विचार करने के लिए पर्याप्त नहीं माना जा सकता। तथापि, पैनल ने इस आशय का निर्णय नहीं लिया कि किसी कंपनी को कब घरेलू उत्पादक नहीं माना जा सकता है और कब उसे विचाराधीन उत्पाद का मात्र आयातक माना जा सकता है। पैनल ने इस बात पर भरोसा नहीं किया कि किसी कंपनी का उत्पादक के रूप में उल्लेख करने के लिए पर्याप्त कार्यकलाप क्या है और न ही पैनल ने "उत्पादन" के अर्थ का उल्लेख किया। वर्तमान मामले में विचाराधीन सुर्पष्ट मुद्दा यह है कि उत्पादन किसे कहते हैं और घरेलू उत्पादक किसे माना जा सकता है।

60. उपर्युक्त के मद्देनजर नियम 2(ख) के अंतर्गत घरेलू उद्योग की परिभाषा और रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी यह मानते हैं कि वी एम सी एल और पृथ्वी वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ स्वयं को विचाराधीन उत्पाद का घरेलू उत्पादक सिद्ध करने में

विफल रही हैं । उसके अलावा ये कंपनियां ये सिद्ध करने में भी विफल रही हैं कि उन्हें नियम 2(ख) के अर्थ के भीतर पात्र घरेलू उद्योग माना जाना चाहिए ।

61. जहां तक तेजस का संबंध है, कंपनी द्वारा किए गए आयातों से संबंधित तर्कों को छोड़कर इन कंपनियों द्वारा तेजस को अपात्र घरेलू उद्योग के व्यवहार को न्यायोचित ठहराते हुए कोई अन्य कारण/आधार उपलब्ध नहीं कराया गया है, प्राधिकारी यह मानते हैं कि केवल तीसरे देशों से हुए उत्पाद के आयात वर्तमान प्रयोजनार्थ संगत हैं और इसलिए तेजस द्वारा थाइलैंड से किए गए आयात की वजह से वह घरेलू उद्योग के रूप में विचार किए जाने से वंचित नहीं हो जाती है । प्राधिकारी यह मानते हैं कि कंपनी का प्रमुख कार्यकलाप भारत में विनिर्माण है, जिसमें उत्पादन कार्यकलाप में अनिवार्य अनुसंधान एवं डिजाइन तथा विकास शामिल है । याचिकाकर्ता ने अपने उत्पादन कार्यकलाप में कमी नहीं की है और न ही उसने व्यापार शुरू किया है । याचिकाकर्ता को अलग रखने के बारे में इन हितबद्ध पार्टियों ने कोई न्यायोचित तर्क नहीं दिया है ।

62. रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना के आधार पर प्राधिकारी ने अनंतिम रूप से यह निर्धारित किया कि (क) वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ याचिकाकर्ता के उत्पादन कार्यकलाप उत्पादन हैं (ख) याचिकाकर्ता के आयात ऐसी मात्रा में नहीं हैं जिससे याचिकाकर्ता नियम 2(ख) के दायरे से बाहर हो जाए । (ग) पृथ्वी और वी एम सी एल जैसे अन्य घरेलू आपूर्तिकर्ताओं के आयात ऐसे हैं जिससे नियम 2(ख) के अंतर्गत वे अपात्र घरेलू उत्पादक बन जाते हैं । (घ) याचिकाकर्ता का उत्पादन कुल भारतीय उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा बनता है । इस आधार पर प्राधिकारी अनंतिम रूप से यह निष्कर्ष निकालते हैं कि याचिका में आधार की पूर्ति होती है और याचिकाकर्ता नियमावली के अर्थ के भीतर घरेलू उद्योग है ।

63. मै. तेजस नेटवर्किंग लि. को घरेलू उद्योग मानने के दावे का विरोध करते समय विरोधी हितबद्ध पार्टियों ने यह तर्क दिया कि मै. तेजस नेटवर्किंग लि. को इन तथ्यों के मद्देनज घरेलू उद्योग के रूप में विचार करने की अयोग्य माना जाना चाहिए कि (1) तेजस ने जांच शुरूआत संबंधी अधिसूचना में यथापरिभाषित विचाराधीन उत्पाद के भाग खरूप कुछेक संघटकों का आयात किया है (ख) "घरेलू उद्योग के रूप में पात्रता रखने के लिए घरेलू उत्पादक को "प्रमुख अनुपात" की सीमा तक उत्पाद के विनिर्माण में संलग्न होना चाहिए अर्थात उत्पादक को यह प्रदर्शित करना चाहिए कि वह समस्त आवश्यक पुर्जों, विचाराधीन उत्पाद की सहायक सामग्री और संघटकों का विनिर्माण करता है" (ग) डी जी ए डी ने पृथ्वी और वी एम सी एल को पात्र विनिर्माता नहीं माना है क्योंकि वे निविष्टियों का "पर्याप्त रूपांतरण" नहीं करते हैं (घ) पाटनरोधी नियमावली में "पर्याप्त रूपांतरण" की कोई अवधारणा नहीं है । (ङ) तेजस भी संघटक का आयात करती है फिर भी उसे पात्र घरेलू उद्योग माना जाता है जबकि पृथ्वी और वी एम सी एल को घरेलू उद्योग नहीं माना गया है (च) डी जी ए डी ने यह कहते हुए तेजस के लिए नियमों में ढील दी है कि तेजस ने दोहरे उपयोग के संघटकों का आयात किया है और इस बात पर विचार नहीं किया गया है कि तेजस संघटकों का अनन्य उपयोग करती है अर्थात एस डी एच टेलीकॉम उपकरणों का विनिर्माण किया जाता है । (छ) चीन जन.गण./इजरायल से भिन्न तीसरे देशों से हुए आयात भी आयातक के रूप में माने जाते हैं क्योंकि नियम 2(ख)

के अंतर्गत आयात का देश विशिष्ट नहीं होता है और यदि तेजस चीन, जन.गण. और इजरायल से भिन्न देशों से आयात करती है तो तेजस घरेलू विनिर्माता कहलाने की पात्र नहीं है। (ज) तेजस ने थाइलैंड और मलेशिया से आयात किया है।

64. विधिक प्रावधानों और मामले के तथ्यों की सावधानीपूर्वक जांच करने के बाद प्राधिकारी नोट करते हैं कि रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर मै. तेजस नेटवर्किंग लि. को वर्तमान मामले में घरेलू उद्योग के रूप में विचार करने से अलग रखने का औचित्य नहीं बनता है। विरोधी पार्टियों का यह तर्क इस तथ्य के मद्देनजर सही नहीं है कि किसी कंपनी को उसके द्वारा आयात किए जाने की स्थिति में सामान्यतः अलग रखा जाए कि संबद्ध देशों से तेजस द्वारा किए गए आयात एकल संघटकों के हैं जो विचाराधीन उत्पाद के दायरे से अलग नहीं हैं।

65. प्राधिकारी यह मानते हैं कि पाटनरोधी कानून के प्रयोजनार्थ "विनिर्माण" को आवश्यक मापदंड माने जाने की स्थिति में उत्पाद शुल्क के भुगतान के महत तथ्य से पाटन एवं क्षति के निर्धारण के बारे में कई गलत व्याख्याएं उत्पन्न होंगी क्योंकि :

- i. इसका तात्पर्य यह होगा कि रिटेंगिंग, रिपैकिंग, रिलेबलिंग, माइक्रोनाइजेशन, मैटेलाइजेशन, पुलवराइजेशन आदि जैसे वृद्धिकारी कार्यकलाप भी उत्पादन बन जाएंगे।
- ii. अर्थ निरूपण से ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी जिसमें एक उत्पाद का उत्पादन कई बार किया जा सकता है। उदाहरणार्थ वर्तमान मामले में ई एम एस कंपनियों के रूप में ज्ञात ऐसी कंपनियां हैं जो विशिष्टीकृत इलैक्ट्रोनिक संघटक सोल्डिरिंग कंपनियां हैं जो उनके द्वारा उत्पादित कार्ड की डिजाइनिंग या कार्यचालन के बारे में कोई भी जानकारी रखे बिना कई उद्योगों के लिए ऐसे कार्यकलाप कर रही हैं कि कंपनियां भी उत्पाद शुल्क का भुगतान कर रही हैं। इस व्याख्या का अभिप्राय यह है कि इन कंपनियों को भी एस डी एच विनिर्माता माना जाना चाहिए। अतः तेजस नेटवर्क्स के लिए कार्ड का उत्पादन और आपूर्ति करने वाली ये ई एम एस कंपनियां एस डी एच उपकरण (सी के डी/एस के डी स्थिति में) की विनिर्माता बन जाएंगी और तत्पश्चात तेजस नेटवर्क्स उसी एस डी एच उपकरण की विनिर्माता बन जाएंगी। उत्पादन की गणना दो बार होगी। इसी प्रकार उत्पाद के आयातों की गणना विदेशी उत्पादक के उत्पादन और भारत में आयात के रूप में की जाएंगी और तत्पश्चात उसी उत्पाद की गणना केवल इस वजह से आयातक के उत्पादन और घरेलू बिक्री के रूप में की जाएंगी क्योंकि आयातक ने सी के डी/एस के डी स्थिति में उत्पाद का आयात किया है, उत्पाद का संयोजन किया है और उत्पाद शुल्क के भुगतान के बाद उसकी बिक्री की है। विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में कुछ स्थितियों में पुर्जे व संघटक शामिल होते हैं। इनमें से कुछ पुर्जे व संघटकों का उत्पादन भारत में कुछ अन्य विशिष्टीकृत संघटक विनिर्माताओं द्वारा किया गया हो सकता है। अतः ये संघटक विनिर्माता भी एस डी एच विनिर्माता बन जाएंगे।

iii. उत्पाद की बिक्री करने वाली किसी कंपनी को घरेलू उत्पादक नहीं माना जा सकता। उत्पादक के रूप में माने जाने से पूर्व बजार में किसी उत्पाद की बिक्री करने वाली किसी पार्टी द्वारा पूर्ण किए जाने/पार किए जाने हेतु कुछेक न्यूनतम आरंभिक कार्यकलाप/मानदंड होने चाहिए और ऐसे कार्यकलाप/मानदंड उत्पाद शुल्क का भुगतान नहीं हो सकता। ऐसे कार्यकलाप/मानदंड पर उत्पाद के स्वरूप और उत्पादन प्रक्रिया के आधार पर विचार करना होगा। उदाहरणार्थ आयातित उत्पाद का व्यापार करने वाला कोई व्यक्ति उत्पाद से संबंधित कुछ कार्यकलाप भी कर सकता है। तथापि, ऐसे व्यापारी को पाटनरोधी कानून के अंतर्गत उत्पादक नहीं माना जा सकता भले ही वह उत्पाद शुल्क कानून के अंतर्गत कुछेक उल्लेखनीय कारणों से उत्पाद शुल्क का भुगतान कर रहा हो।

66. प्राधिकारी आगे यह नोट करते हैं कि सी एम ए आई के अलावा, एक अन्य उद्योग एसोसिएशन टीमा ने अपने 3 दिसंबर, 09 के पत्र में घरेलू उद्योग की संरचना की परिभाषा के बारे में याचिकाकर्ता के दृष्टिकोण का समर्थन किया है और प्राधिकारी के अंतरिम निर्णय का समर्थन किया है। यह तथ्य कि किसी अन्य तथाकथित विनिर्माता ने या तो जांच में भाग नहीं लिया है अथवा जिन्होंने भाग लिया है, वे घरेलू उद्योग के लिए निर्धारित प्रपत्र में अपने विनिर्माण कार्यकलापों के बारे में साक्ष्य देने में विफल रहे हैं तथा विस्तृत रूप से चर्चा किए गए अन्य व्यौरों से प्राधिकारी द्वारा निकाले गए इस निष्कर्ष को समर्थन मिलता है कि तेजस पाटनरोधी नियमावली के अर्थ के भीतर "घरेलू उद्योग" है।

जांच की कार्रवाई के बीच में किसी नए निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा कार्यभारत ग्रहण किए जाने की स्थिति में क्या दूसरी सार्वजनिक सुनवाई अनिवार्य/आवश्यक है

67. प्राधिकारी नोट करते हैं कि कानून के अंतर्गत केन्द्र सरकार संयुक्त सचिव से ऊपर के रैक के किसी व्यक्ति को निर्दिष्ट प्राधिकारी नियुक्त कर सकती है। केन्द्र सरकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को ऐसे अन्य व्यक्तियों की सेवाएं उपलब्ध करा सकती हैं और ऐसी अन्य सुविधाएं प्रदान कर सकती हैं जिस वह उचित समझे, जांच की शुरूआत और प्रारंभिक जांच परिणामों को तब अधिसूचित किया गया था जब श्री आर. गोपालन निर्दिष्ट प्राधिकारी थे। सार्वजनिक सुनवाई की अध्यक्षता भी श्री आर. गोपालन ने की थी। बाद में 4 जनवरी, 2010 को केन्द्र सरकार ने मुझे निर्दिष्ट प्राधिकारी नियुक्त कर दिया। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि सार्वजनिक सुनवाई की पूर्व में अध्यक्षता श्री आर. गोपालन ने की थी, कुछेक हितबद्ध पार्टियों ने सार्वजनिक सुनवाई के रूप में एक अन्य सार्वजनिक सुनवाई अथवा व्यक्तिगत सुनवाई करने का अनुरोध किया।

68. इस बात का उल्लेख करना प्रासंगिक है कि उन व्यक्तिगत बैठकों/सुनवाइयों की अनुमति अनुरोध किए जाने पर और न्यायोचित पाए जाने पर प्राधिकारी ने प्रदान की थी। प्राधिकारी ने वर्तमान कार्यवाही के स्वरूप, जांच करने में अपनाई गई प्रक्रिया, इस संबंध में स्थापित परंपरा और सार्वजनिक सुनवाई अथवा सार्वजनिक सुनवाई के रूप में व्यक्तिगत सुनवाई की मांग करने वाली इन हितबद्ध पार्टियों द्वारा प्रस्तुत आधारों को ध्यान में रखते हुए

सार्वजनिक सुनवाई के अनुरोध पर सावधानीपूर्वक विचार किया है। प्राधिकारी यह मानते हैं कि नियम 6 में किसी हितबद्ध पार्टी को लिखित और मौखिक रूप में सूचना प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करने का प्रावधान है। यदि सूचना मौखिक रूप से प्रदान की जाती है तो बाद में उसे लिखित में प्रस्तुत करना अपेक्षित होता है। स्पष्ट तौर पर यह लिखित सूचना ही है जिस पर प्राधिकारी निर्धारण करने के लिए विचार करते हैं। दूसरे शब्दों में यदि किसी पार्टी ने मौखिक रूप से कुछ सूचना प्रदान की है परंतु उसे लिखित में प्रस्तुत नहीं किया है तो प्राधिकारी उस सूचना पर विचार करने से बंचित हो जाते हैं। इसके विपरीत यदि किसी हितबद्ध पार्टी ने कोई अनुरोध किया है, तो प्राधिकारी उस पर विचार करने के लिए बाध्य हैं भले ही वह हितबद्ध पार्टी मौखिक रूप से उसे प्रस्तुत करने में विफल रही हो। वस्तुतः उल्ल्यू टी ओ ए डी ए में इस आशय का स्पष्ट उल्लेख है कि किसी बैठक में भाग लेने के लिए किसी पार्टी पर कोई बाध्यता नहीं होगी और ऐसा करने में विफल रहने की स्थिति में उस पार्टी के मामले में प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगो। इसके अलावा, नियमों में यह निर्धारित नहीं है कि प्राधिकारी को ऐसी किसी सार्वजनिक सुनवाई जिसमें समस्त हितबद्ध पार्टियां मौजूद हों, के रूप में मौखिक रूप से सूचना प्रस्तुत करने हेतु ऐसा अवसर प्रदान किया जाएगा। वस्तुतः उल्ल्यू टी ओ करार में यह स्पष्ट प्रावधान है कि प्राधिकारी अनुरोध किए जाने पर प्रतिकूल हित रखने वाली पार्टियों से मिलने के लिए सभी हितबद्ध पार्टियों को अवसर प्रदान करेंगे ताकि विरोधी विचार प्रस्तुत किए जा सकें और खंडनात्मक तर्क दिए जा सकें। तथापि, किसी भी पार्टी पर बैठक में भाग लेने की बाध्यता नहीं है और न ही ऐसा करने में विफल करने पर उस पार्टी के मामले में भेदभाव किया जा सकता है। इसके अलावा, हितबद्ध पार्टियों को न्यायोचित रूप से अन्य सूचना मौखिक रूप से प्रस्तुत करने का अधिकार भी प्रदान किया गया है। तथापि, प्रदत्त ऐसी मौखिक सूचना पर तभी विचार किया जा सकता है जब उसे बाद में लिखित रूप में प्रस्तुत किया जाए और जांच में भाग लेने वाली अन्य हितबद्ध पार्टियों को उपलब्ध कराया जाए। अतः यह स्पष्ट है कि कोई पार्टी आधिकारिक तौर पर यह मांग नहीं कर सकती कि निर्दिष्ट प्राधिकारी को सार्वजनिक सुनवाई के रूप में मौखिक सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए जिसमें समस्त हितबद्ध पार्टियां उपलब्ध हों। इन परिस्थितियों में कोई हितबद्ध पार्टी सार्वजनिक सुनवाई के जरिए मौखिक रूप से सुने जाने की मांग नहीं कर सकती।

69. इन हितबद्ध पार्टियों द्वारा समय-समय पर और पूर्ववर्ती मौखिक सुनवाई के समय किए गए समस्त अनुरोध मेरे समक्ष प्रस्तुत किए गए थे। मौखिक सुनवाई का अनुरोध करते समय इन हितबद्ध पार्टियों ने ऐसे किसी तथ्य या कारक का उल्लेख नहीं किया है जिससे ऐसी सूचना के प्रस्तुतिकरण हेतु वास्तव में अवसर प्रदान करना जरूरी हो। वस्तुतः सूचना के ऐसे मौखिक प्रस्तुतिकरण के समर्थन में कोई औचित्य नहीं दिया गया है। दूसरे शब्दों में ये हितबद्ध पार्टियां नई सूचना सहित ऐसी कोई सूचना प्रस्तुत करने में असमर्थ रहीं हैं रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं हैं अथवा जिसे मौखिक रूप से प्रस्तुत करने की अन्यथा अपेक्षा है।

70. पूर्वोक्त को ध्यान में रखते हुए मैं यह मानता हूं कि एक अन्य सार्वजनिक सुनवाई आयोजित करना आवश्यक नहीं है न ही कोई अन्य हितबद्ध पार्टी मेरे समक्ष मौखिक रूप से कुछ सूचना प्रस्तुत करने के लिए अपने मामले को पुष्ट करने में समर्थ हुई है। मेरे समक्ष

लिखित में प्रस्तुत सभी साक्ष्यों पर प्रकटन विवरण जारी करते समय विचार किया गया है और प्रकटन विवरण पर की गई टिप्पणियों पर इस अंतिम जांच परिणाम संबंधी दस्तावेज में समुचित कार्रवाई की गई है।

71. कुल मिलाकर वी एम सी एल और पृथ्वी को 19 अप्रैल, 2010 के पत्र के जरिए सार्वजनिक सुनवाई हेतु समय लेने का अवसर प्रदान किया गया था जिसका उन्होंने लाभ नहीं उठाया। इसके अलावा, वी एम सी एल, पृथ्वी तथा अन्य सभी हितबद्ध पार्टियों ने वस्तुतः सीधे अथवा अपने विधिक प्रतिनिधि के जरिए वर्तमान जांच में प्राधिकारी की सहायता करने के लिए नियुक्त अधिकारियों के समक्ष अपने विचार मौखिक रूप से व्यक्त करने के लिए कई अवसरों का लाभ उठाया। विभिन्न हितबद्ध पार्टियों के विधिक प्रतिनिधियों को अधिकारियों द्वारा कई बैठकें करने की स्वीकृति दी गई। वस्तुतः अधिकारियों ने अनुरोधानुसार ऐसा अवसर उदारतापूर्वक प्रदान किया। अधिकारियों के समक्ष मौखिक रूप से अथवा लिखित रूप में किए गए ऐसे समस्त अनुरोध मेरे समक्ष प्रस्तुत किए गए हैं।

### 20 जुलाई, 2010 के पत्र का उत्तर

72. प्राधिकारी ने इस बात पर विचार करते हुए कि पृथ्वी और वी एम सी एल दोनों द्वारा अपने विचारों के समर्थन में कोई पर्याप्त पूरक सूचना प्रदान किए बिना जांच का पुरजोर विरोध किया जा रहा है, इन दोनों हितबद्ध पार्टियों को 20 जुलाई, 2010 को एक पत्र भेजा, जिसमें इन हितबद्ध पार्टियों द्वारा समय-समय पर किए गए विभिन्न दावों के बारे में निविष्टियों कीमांग की गई थी। इसके अलावा, एक पत्र इस मामले से संबंधित पूरक सूचना प्राप्त करने हेतु हुआवी को भी भेजा गया था। प्राधिकारी नोट करते हैं कि जहां हुआवी इंडिया ने प्राधिकारी के विचारार्थ उचित सूचना प्रदान की, वहीं वी एम सी एल और पृथ्वी दोनों का लगातार यह दृष्टिकोण रहा कि प्राधिकारी को सहयोग न किया जाए और कोई संगत पूरक सूचना प्रदान किए बिना एक या दूसरे बहाने से कार्यवाही को बाधिक करने की कोशिश की जाए। उन्होंने जांच के 16वें महीने में सूचना प्राप्त करने के लिए प्राधिकारी की बुधिमत्ता पर भी सवाल उठाया। प्राधिकारी यह मानते हैं कि पाटनरोधी नियमों के अनुसार सिद्ध करने का भार हितबद्ध पार्टियों पर होता है, जिन्हें प्राधिकारी के विचारार्थ समर्थनकारी सत्यापनीय साक्ष्य के साथ संगत सूचना उपलब्ध करानी होती है। नियमों में प्राधिकारी के लिए न तो यह शर्त रखी गई है और न ही उन पर बाध्यता डाली गई है कि वे उस स्थिति में कार्यवाही के अंतिम भाग में किसी हितबद्ध पार्टी से पूरक सूचना/सूचना प्राप्त करें जिसे उन्होंने "संगत सूचना" के रूप में प्राप्त कर लिया है और पार्टियों को पर्याप्त समय प्रदान किया है। 20 जुलाई, का पत्र उन्हें एक अन्य अवसर प्रदान करने के रूप में उपर्युक्त दोनों आयातकों को भेजा गया था ताकि उन्हें अपने दावे की पुष्टि करने के लिए दूसरा मौका दिया जा सके। इसकी पुष्टि करने के बजाए उन्होंने अपने दावे के समर्थन में कोई सूचना/साक्ष्य प्रदान किए बिना अपने अनुरोधों को दोहराया। जहां पृथ्वी ने यह दावा किया कि वे डी डब्ल्यू डी एम (गैर-विचाराधीन उत्पाद) के विनिर्माता हैं वहीं वी एम सी एल ने एक बार फिर विचाराधीन उत्पाद का विनिर्माता होने का दावा किया है और इसके लिए उन्होंने अपने कार्यबल, तुलन पत्र, निविष्टि, आर एंड डी आदि के बारे में व्यौरों द्वारा समर्थित कार्यकलापों से संबंधित कोई सत्यापनीय सूचना नहीं दी है।

दोनों ने उनके द्वारा किए गए आयातों के बारे में भी कोई सूचना नहीं दी है । यद्यपि आयातक प्रश्नावली उनके द्वारा दायर की जानी चाहिए थी, (प्रश्नावली वाणिज्य विभाग की सरकारी वैबसाइट पर उपलब्ध है) । इसके अलावा, उन्होंने यह स्वीकार किया है कि उन्होंने संघटकों का अयात किया है परंतु वे संपूर्ण उपकरण के मुद्दे पर और चीन जन.गण. के एक प्रतिवादी निर्यातक के आंकड़े के सत्यापन के द्वारान प्राधिकारी की जानकारी में आए मुद्दे पर भौन हैं । संक्षेप में प्राधिकारी द्वारा मांगी गई सूचना प्रस्तुत करने के लिए समय बढ़ाने की मांग करने के अलावा मांग, जिसे प्राधिकारी ने स्वीकार भी किया है, पूर्व में समय-समय पर उनके द्वारा किए गए अनुरोधों के अलावा प्राधिकारी को कोई तथ्यप्रक सामग्री प्रदान नहीं की गई है । प्राधिकारी यह मानते हैं कि उनके द्वारा पूर्व में उठाए गए समस्त मुद्दों और 6 अगस्त के अनुरोधों में उठाए गए मुद्दों पर पूर्ववर्ती पैराग्राफों में विचार किया जा चुका है और उन्हें दोहराने की जरूरत नहीं है ।

73. कुछ हितबद्ध पार्टियों ने कई पार्टियों को विचाराधीन उत्पाद के विनिर्माता के रूप में अभिज्ञात किया है । प्राधिकारी ने इन हितबद्ध पार्टियों के दावे की जांच की । यह पाया गया है कि इन हितबद्ध पार्टियों का दावा भारत में ग्राहकों को एस डी एच उत्पाद की आपूर्ति के प्रस्तावों पर आधारित है । प्राधिकारी यह मानते हैं कि किसी कंपनी द्वारा संभावित आपूर्ति के तथ्य से ही यह अर्थ नहीं निकाला जा सकता कि ऐसी कोई कंपनी वस्तुतः उत्पाद की विनिर्माता है । कुछ पार्टियों ने बी एस एन एल, निविदाओं अथवा वैबसाइट सूचना का हवाला दिया है । तथापि, यह नोट किया जाता है कि उक्त सूचना उत्पाद के आपूर्तिकर्ताओं के संबंध में है और इससे इस बात की पुष्टि नहीं होती है कि ये आपूर्तिकर्ता वास्तव में उत्पाद के विनिर्माता हैं ।

### गोपनीयता

74. याचिका का विरोध करने वाली कुछ हितबद्ध पार्टियों ने गोपनीयता के बारे में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं :

- i. वर्तमान कार्रवाई में गोपनीयता के मामले में कथित रूप से अत्यंत अनियमितता थी क्योंकि विभिन्न मुद्दों के बारे में प्रारंभिक जांच परिणामों में खुलासा नहीं किया गया था और उन्हें सूचना को गोपनीय रखने के आधार पर उजागर नहीं किया गया था ।
- ii. आयातों के कीमत प्रभाव की जांच करते समय आयातित उत्पाद की तुलना तेजस द्वारा विनिर्मित एस डी एच ट्रांसमिशन उपकरण के तुलनीय निम्नतर मॉडल के साथ की गई थी । निर्दिष्ट प्राधिकारी ने ऐसी तुलना के ब्यौरे और विश्लेषण का खुलासा नहीं किया है और केवल आयातित उत्पाद की तुलना घरेलू उत्पाद के नयूनतर माडल के साथ करने की बात कहकर कीमत कटौती की पुष्टि की है ।
- iii. घरेलू उत्पादन के निर्धारण हेतु निर्दिष्ट प्राधिकारी ने तेजस द्वारा प्रदत्त उत्पादन के ब्यौरों पर भरोसा किया, जिनके संबंध में यह माना जाता है कि उन्हें विचाराधीन उत्पाद और अन्य उत्पादों के संबंध में वॉयस तथा डाटा रिकॉर्डर पत्रिका में प्रकाशित किया गया है जिनमें उचित समायोजन किया गया है ताकि संगत उत्पाद

के लिए सूचना निर्धारित की जा सके । परंतु सबंधित उत्पाद के बारे में सूचना निर्धारित करने हेतु किए गए समायोजन के ब्यौरे का प्रकटन नहीं किया गया है और उसे गोपनीय रखा गया है ।

iv. उत्तर के अगोपनीय रूपांतरण सहित घरेलू उद्योग से इतर अन्य हितबद्ध पार्टियों द्वारा दिए गए उत्तर को अन्य हितबद्ध पार्टियों को उपलब्ध नहीं कराया गया है ।

v. प्राधिकारी ने बी सी एन ब्यौरे के प्रकटन हेतु चीन की कंपनियों को निर्देश जारी कर भारी गलती की है । इसके विपरीत ऐसी कोई शर्त घरेलू उद्योग के लिए निर्धारित नहीं की गई है । आगे यह अनुरोध किया गया है कि ऐसा निर्देश इन उपबंधों की भावना के प्रतिकूल है ।

vi. ऐसी कुछ सूचना जिसे गोपनीय नहीं रखा जा सकता, उसे घरेलू उद्योग द्वारा गोपनीय रखा गया है । इस आशय का कोई कारण नहीं दिया गया है कि उस सूचना के बारे में गोपनीयता का दावा क्यों किया गया है और जिसकी स्पष्ट अनुमति क्यों दी गई है अथवा जिसका सारांश प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है । यहां तक कि जो सूचना स्वरूप से ही गोपनीय मानी जा सकती है, उसके बारे में कोई उचित सूचीकरण नहीं किया गया है ताकि गोपनीय रूप में प्रस्तुत सूचना की विषय वस्तु की उचित समझ बनाई जा सके । गोपनीयता की अनुमति स्वतः प्रदान नहीं की जा सकती और प्राधिकारी को इस बात का निर्धारण करने में अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए कि क्या गोपनीयता का दावा विधिसम्मत है । यदि आवेदक ऐसी किसी सूचना को प्रकटित करने के इच्छुक नहीं है जिसके बारे में गोपनीयता का दावा नहीं किया जा सकता तो निर्दिष्ट प्राधिकारी को ऐसी समस्त सूचना रद्द कर देनी चाहिए । हमारा प्राधिकारी से अनुरोध है कि वे सर्वप्रथम गोपनीयता के महत्वपूर्ण मुद्दे का निर्णय करें और तत्पश्चात हमें नियमों में की गई अपेक्षानुसार प्रभावी प्रतिनिधित्व करने के लिए अवसर प्रदान करें । हम यह भी अनुरोध करना चाहेंगे कि हमें इस समय घरेलू उद्योग द्वारा दावा की गई अत्यधिक गोपनीयता के मद्देनजर उचित अनुरोध करने से वंचित किया गया है ।

### प्राधिकारी द्वारा जांच

75. प्राधिकारी यह मानते हैं कि गोपनीयता का मुद्दा निम्नलिखित स्थितियों में उत्पन्न हो सकता है -

क. हितबद्ध पार्टियों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना और अन्य हितबद्ध पार्टियों की ओर से उसकी गोपनीयता- प्राधिकारी यह मानते हैं कि किसी हितबद्ध पार्टी द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदत्त सूचना का प्रकटन नियमों के अंतर्गत स्पष्ट प्रावधान के मद्देनजर अन्य हितबद्ध पार्टियों में से भाग लेने वाली अन्य हितबद्ध पार्टियों को नहीं किया जा सकता ।

ख. हितबद्ध पार्टियों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना और उसी पार्टी की ओर से उसकी गोपनीयता- जहां तक स्वयं किसी हितबद्ध पार्टी द्वारा प्रस्तुत सूचना की गोपनीयता का संबंध है, प्राधिकारी ने इस चरण पर हितबद्ध पार्टियों को आंकड़ों का उचित प्रकटन किया है । आंकड़ों का प्रकटन वर्तमान स्तर से पूर्व नहीं किया जा सकता ।

ग. जहां तक इस मुद्दे का संबंध है, घरेलू उद्योग से भिन्न अन्य हितबद्ध पार्टियों द्वारा प्रस्तुत उत्तर का अगोपनीय रूपांतरण अन्य हितबद्ध पार्टियों को उपलब्ध कराने से इंकार किया गया है, सही नहीं है क्योंकि ऐसे समस्त अनुरोध कानून द्वारा अधिदेशित सार्वजनिक फाइल में उपलब्ध हैं और वह आज भी विधिवत सूचीकृत उक्त सार्वजनिक फाइल में उपलब्ध रखे गए हैं।

### सार्वजनिक हित

76. यह अनुरोध किया गया है कि दूर संचार ट्रांसमिशन उपकरणों के पुर्जों और संघटकों का विनिर्माण भारत में नहीं होता है और यह इन मदों के लिए पूर्णतः आयात पर निर्भर है। यह दावा किया गया है कि उद्ग्रहण का तत्काल प्रभाव वी एम सी एल, जो इन मदों का विनिर्माण करती है और जिनकी अंततः आपूर्ति दूरसंचार उद्योग को की जाती है, जैसी वास्तवित विनिर्माता कंपनियों के लिए प्रचालन लागत में भारी वृद्धि के रूप में पड़ेगा। आगे यह आरोप लगाया गया है कि उद्ग्रहण से न केवल भारतीय दूर संचार उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, अपितु आई टी, आई टी ई एस तथ बी पी ओ क्षेत्र, जो वॉयस एवं डाटा ट्रांसमिशन उपकरणों के लिए पूर्णतः दूरसंचार क्षेत्र पर निर्भर है, जैसे अन्य आश्रित क्षेत्रों पर भी प्रभाव पड़ेगा। अतः ऐसे पाटनरोधी शुल्क को लगाए जाने के कारण लागत में होने वाली वृद्धि को घरेलू आयातकों, बी एस एन एल/ एम टी एन एल जैसे दूरसंचार सेवा प्रदाताओं और घरेलू ग्राहकों द्वारा वहन करना होगा। यह भी बताया गया है कि आयात एक आवश्यकता है क्योंकि याचिकाकर्ता कल्पना में भी समूचे भारतीय बाजार की जरूरत की पूर्ति नहीं कर सकता, खासकर जब भारत सरकार का ध्यान भारतीय राष्ट्रीय दूर संचार नीति में किए गए प्रावधान के अनुसार देश में दूरसंचार फुट प्रिंट का विस्तार करने पर टिका हुआ है।

77. प्राधिकारी ने उपर्युक्त अनुरोधों पर ध्यान देते हुए घरेलू उत्पादकों और आयातकों के बीच प्रतिस्पर्धा का समान अवसर प्रदान करने की भूमिका निभाई है। याचिका की जांच करते समय और परिणाम की सिफारिश करते समय प्राधिकारी को पाटनरोधी कानून में निर्धारित कुछेक सिद्धांतों का पालन करना होता है। प्राधिकारी की मंशा न तो आयातों को रोकने की है और न ही किसी हितबद्ध पार्टी की लागत में वृद्धि करने की है, जहां तक भरोसा और परिणाम आंकड़ों पर आधारित है। वर्तमान जांच में समस्त हितबद्ध पार्टियों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों पर भरोसा किया गया है जिनमें से कुछ का सत्यापन भी किया गया है, जहां कहीं हितबद्ध पार्टियों ने प्राधिकारी से उसके सत्यापन की मांग की है। अतः प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि पाटनरोधी कानून के सिद्धांतों और निर्धारित विधिक संरचना के भीतर कार्य करते हुए प्रक्रिया का कोई क्षेत्र अधूरा नहीं रखा गया है। यह भी उल्लेख किया गया है कि याचिकाकर्ता ने यह दावा किया है कि एस डी एच उपकरण की लागत ट्रांसमिशन स्टेशन की कुल लागत में नगण्य होती है। हितबद्ध पार्टियों ने याचिकाकर्ता के इस दावे का खंडन नहीं किया है। जहां तक पुर्जों और संघटकों का संबंध है, जब उनका एकल आधार पर आयात किया जाता है, तब उन्हें विचाराधीन उत्पाद में शामिल नहीं किया जाता है और इसलिए इससे संबंधित तर्क संगत नहीं है।

**सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत तथा पाटन मार्जिन**  
**सामान्य मूल्य**  
**घरेलू उद्योग द्वारा किए गए दावे**

78. आवेदकों ने यह दावा किया है कि चीन गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश है। विस्तृत मूल्यांकन प्रक्रिया, जांच एवं मूल्यांकन करने के बाद किसी देश ने चीन को बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा प्रदान नहीं किया है। उन्होंने आगे यह दावा किया है कि चीन ने भी शामिल होने संबंधी संधि में इस बात पर सहमति व्यक्त की है कि डब्ल्यू टी ओ सदस्य 11 दिसंबर, 2016 के जारी एन एम ई पाटनरोधी कार्य पद्धति का उपयोग कर सकते हैं। पिछले तीन वर्षों में यूरोपीय आयोग तथा अमरीका द्वारा चीन को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश माना गया है। यूरोपीय संघ तथा अमरीका विश्व व्यापार संगठन के सदस्य हैं। भारत में भी निर्दिष्ट प्राधिकारी ने चीन को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश माना है। निर्दिष्ट प्राधिकारी ने 31 मई, 2002 के संशोधन के बाद चीन के खिलाफ शुरू की गई समस्त जांचों में व्यवहारिक रूप से चीन को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश माना है। 4 जनवरी, 2003 के संशोधन के बाद भी निर्दिष्ट प्राधिकारी ने चीन को गैर बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश माना है।

79. आवेदकों ने दावा किया है कि चीन के उत्पादक भारत में संबद्ध वस्तु का पाटन कर रहे हैं। उन्होंने घरेलू बाजार एवं इजराइल में संदत्त और संदेय कीमत के आधार पर इजराइल में सामान्य मूल्य निर्धारित करने का दावा किया है। उन्होंने दावा किया है कि मध्य पूर्व/यूरोपीय क्षेत्र का एक भाग होने के कारण इजराइल के संबंध में विचाराधीन उत्पाद की औसत बिक्री कीमत एशिया में स्थित देशों से उच्चतर होने की संभावना है और इजराइल में वास्तविक सौदा कीमत के संबंध में किसी सूचना के अभाव में बाजार अनुसंधान रिपोर्टों के आधार पर निर्धारित कीमत को सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु स्वीकार किया गया है।

**प्राधिकारी द्वारा जांच**  
**चीन जन.गण.**  
**बाजार अर्थव्यवस्था के दावों की जांच**

80. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पिछले तीन वर्षों में डब्ल्यू टी ओ के अन्य सदस्यों द्वारा की गई पाटनरोधी जांचों में चीन जन.गण. को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश माना गया है; अतः पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 8 (2) के अनुसार चीन जन.गण. को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश माना गया है बशर्ते उपर्युक्त नियमों के अनुसार निर्यातक देश या अलग-अलग निर्यातकों द्वारा उपर्युक्त अनुमान का खंडन किया गया हो।

81. यथासंशोधित पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध 1 के अनुसार गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के अनुमान का उस स्थिति में खंडन किया जा सकता है यदि चीन के निर्यातक (निर्यातकों) द्वारा पैराग्राफ 8 के उप पैरा(3) में विनिर्दिष्ट मानदंडों के आधार पर सूचना और

पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध कराते हैं और उसके विपरीत सिद्ध करते हैं । चीन जन.गण. के संबद्ध वस्तु के निर्यातकों/उत्पादकों के लिए बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी व्यवहार विषयक प्रश्नावली के उत्तर में पैरा 8 के उप पैरा (3) में उल्लिखित आवश्यक सूचना/पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करना अपेक्षित है ताकि निर्दिष्ट प्राधिकारी निम्नलिखित मापदंडों पर विचार कर सकें कि क्या :-

(क) कच्ची सामग्रियों सहित कीमत; लागत और निविष्टि तथा श्रम लागत, उत्पादन, बिक्रियां और निवेश के बारे में चीन जन.गण. में संबंधित फर्मों का निर्णय ऐसे बाजारी संकेतों के अनुसार किया जाता है जिसमें आपूर्ति और मांग परिलक्षित होती है और इस बारे में राज्य का अधिक हस्तक्षेप नहीं होता है और क्या प्रमुख निविष्टियों की लागत में बाजार मूल्य पर्याप्त रूप से प्रदर्शित होते हैं;

(ख) इस प्रकार की फर्मों की उत्पादन लागत और वित्तीय स्थिति विशेषकर परिसंपत्तियों के मूल्यहास, अन्य बड़े खातों, वर्तु विनिमय-व्यापार और ऋणों की प्रतिपूर्ति के माध्यम से भुगतान के संदर्भ में पूर्ववर्ती गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाली प्रणाली से हुई महत्वपूर्ण विकृतियों के अध्यधीन हैं;

(ग) इस प्रकार की फर्में दिवालियापन और संपत्ति कानूनों के अध्यधीन हैं जो फर्मों के प्रचालन की कानूनी निश्चितता और स्थिरता की गारंटी देते हैं; और

(घ) विनिमय दर का परिवर्तन व्याज की दर पर किया जाता है ।

82. प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्राधिकारी द्वारा जारी जांच शरूआत संबंधी सूचना के बाद मै. फाइबर होम टेलीकम्युनिकेशन टेक्नॉलॉजीज लि., मै. जैड टी ई कारपोरेशन, मै. अल्काटेल-लुसेंट शंघाई बैल कंपनी लि., मै. हुआबी टैक्नोलॉजीज कंपनी लि., मै. हेंगज्ञाऊ ई सी आई टेलीकम्युनिकेशन कं. लि. सहित चीन जन.गण के कई उत्पादकों और निर्यातकों ने बाजार अर्थव्यवस्था के दर्जे से संबंधित प्रश्नावली और निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर दिया है तथा गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के अनुमान का खंडन किया है । प्रतिवादी उत्पादकों और निर्यातकों के प्रश्नावली और बाजार अर्थव्यवस्था के उत्तरों की जांच की गई है । चूंकि प्रारंभिक जांच परिणाम के स्तर पर ये उत्तर त्रुटिपूर्ण पाए गए थे, जैसा कि प्रारंभिक जांच परिणाम के दस्तावेज में स्पष्ट उल्लेख किया गया है, इसलिए इन सभी प्रतिवादी निर्यातकों को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाली स्थितियों में प्रचालनरत माना गया था । प्राधिकारी ने प्रारंभिक जांच परिणाम के दस्तावेज में आगे यह स्पष्ट किया था कि बाजार अर्थव्यवस्था के दावे से संबंधित अनुरोधों की जांच प्राधिकारी द्वारा जांच और सत्यापन की कार्रवाई के दौरान विस्तार से की जाएगी और यदि सत्यापन के बाद इन कंपनियों द्वारा एम ई टी मानक को पूरा करने पर जांच की कार्रवाई के दौरान स्थिति की समीक्षा की जाएगी । उपर्युक्त प्रतिवादी निर्यातकों के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था के दावे से जुड़े रिकॉर्ड का सत्यापन किया गया था और अलग-अलग निर्यातकों को विस्तृत सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थीं । सत्यापन से उत्पन्न बाजार अर्थव्यवस्था के दावे की स्थिति का संक्षेप में सारांश निम्नानुसार है :

मे. फाइबर होम टेलीकम्युनिकेशन टेक्नॉलाजीज लि.,

83. (एफ एच आई) (एफ एच टी की ओर से निर्यात करने वाली) तथा फाइबर होम टेक्नॉलाजीज दोनों की शेयरधारिता की प्रणाली से यह पता चलता है कि राज्य के स्वामित्व वाले परिसंपत्ति पर्यवेक्षण एवं प्रशासन आयोग के स्वामित्व वाली बोहान रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट एंड टेलीकम्युनिकेशन (डब्ल्यू आर आई) के इन दोनों कंपनियों में \*\*\* शेयर हैं। एफ एच आई के \*\*\* शेयरधारक हैं अर्थात् एफ एच टी (\*\*\*%) तथा बुहान हांगजिन टेलीकम्युनिकेशन टैक्नोलाजी लि. (डब्ल्यू एच टी टी) (\*\*\*%)। एफ एच टी राज्य के स्वामित्व वाली कंपनी है जिसके \*\*\*% शेयर राज्य के स्वामित्व में हैं और बुहान हांगजिन भी राज्य की स्वामित्व वाली कंपनी है जिसके \*\*\*% शेयर राज्य के स्वामित्व में हैं। इसके अलावा, बोहान रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट एंड टेलीकम्युनिकेशन (डब्ल्यू आर आई) जाहिर तौर पर राज्य के स्वामित्व वाली है। ए ओ ए, के अनुसार निदेशक मंडल में \*\*\* निदेशक हैं, जिनमें \*\*\* अध्यक्ष, \*\*\* उपाध्यक्ष तथा \*\*\* स्वतंत्र निदेशक शामिल हैं। चोटी के \*\*\* शेयरधारकों और निदेशक मंडल की सूची के अनुसार कंपनी में \*\*\* स्वतंत्र निदेशक तथा \*\*\* नियमित निदेशक हैं जिनमें से \*\*\* डब्ल्यू आर आई की ओर से \*\*\* इंस्टीट्यूट आफ पोस्ट एंड टेलीकम्युनिकेशन की ओर से और \*\*\* अन्य शेयरधारकों की ओर से हैं। राज्य की स्वामित्व वाली कंपनी डब्ल्यू आर आई की ओर से \*\*\* निदेशकों ने \*\*, \*\*, \*\*\* तथा \*\*\* के प्रमुख पद धारण किए हुए हैं। श्री \*\*\* एफ एच टी का \*\*\* है जो डब्ल्यू आर आई में \*\*\* भी है और एफ एच आई में भी \*\*\* है। इस पद्धति को ध्यान में रखते हुए इस बात की स्पष्ट पुष्टि हो जाती है कि कंपनी के दैनिक प्रचालनों में राज्य के हस्तक्षेप से इंकार नहीं किया जा सकता और इसलिए प्राधिकारी यह मानते हैं कि कंपनी एन एम ई की स्थितियों में प्रचालन कर रही है। इसके अलावा, कंपनी द्वारा एक भी मानदंड की पूर्ति न किए जाने की स्थिति में कंपनी बाजार अर्थव्यवस्था के दर्जे की पात्र नहीं है। इसलिए, प्राधिकारी ने कंपनी की बाजार अर्थव्यवस्था के दर्जे से संबंधित अन्य पहलुओं की जांच नहीं की है।

मे. जैड टी ई कारपोरेशन

84. कंपनी जैड टी ई कारपोरेशन की स्थापना \*\*\* को की गई थी जिसकी पंजीकृत पूँजी \*\*\* मिलियन आर एम बी थी, पंजीकरण सं. \*\*\* थी और लाइसेंस सं. \*\*\* थी। पूँजी के 9 प्रमुख वितरण/प्रायोजक निम्नानुसार थे :-

1	
2	***
3	***
4	***
5	***
6	***
7	***

8	***
9	***

85. उपर्युक्त में से \*\*\* कंपनी, जिसका आगे \*\*\* के रूप में उल्लेख किया गया है, की संयुक्त रूप से स्थापना \*\*\*, \*\*\* (\*\*\* और \*\*\* द्वारा की गई थी, जिनमें से प्रत्येक के \*\*\* में शेयर \*\*\*%, \*\*\*% और \*\*\*% थे जो अंततः नई कंपनी जैड टी ई कॉर्प में \*\*\*% धारित किए गए थे। उपर्युक्त क्र.सं. 4 पर उल्लिखित कंपनी \*\*\* में \*\*\* थी और शेष \*\*\* थी। \*\*\* प्रमुख शेयरधारक स्टॉक धारिता संरचना अर्थात \*\*\* में \*\*\*, \*\*\* (\*\*\* और \*\*\* दिनांक \*\*\* तक अपरिवर्तित रहती है। इसके अलावा, \*\*\* एक \*\*\* है और \*\*\*, \*\*\* (\*\*\* एक \*\*\* है। यह कंपनी स्टेट साइंश एंड टैक्नोलॉजी कमीशन द्वारा नेशनल टार्च प्लान की हाई टैक्नोलॉजी तथा न्यू टैक्नोलॉजी इंटरप्राइज के अधीन \*\*\*, पुष्टिकृत \*\*\* और पात्र \*\*\*, \*\*\* में से एक है।

86. इसके अलावा, \*\*\* और \*\*\* को छोड़कर \*\*\* जो अभी भी जैड टी ई का प्रमुख शेयरधारक बने हुए हैं, अन्य इक्विटी धारकों ने धीरे-धीरे अपनी धारिता समाप्त कर दी और शीर्षस्थ \*\*\* शेयरधारक चार्ट से अपना नाम हटवा लिया। \*\*\* और अन्य वितरकों/प्रायोजकों ने इस अवधि के दौरान कंपनी स्टॉक की अपनी शेयरधारिता आरंभ में \*\*\* से घटकर \*\*\* कर दी।

87. कंपनी के बोर्ड में \*\*\* निदेशक हैं जिनमें से \*\*\* निदेशक प्रमुख शेयरधारकों में से हैं जो \*\*\* हैं और अन्य शेयरधारक \*\*\* कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन में से हैं और \*\*\* स्वतंत्र निदेशक हैं जो विधि कंपनियों और अन्य विधाओं के संबंधित तकनीकी क्षेत्रों में अधिसूचित हैं। यह देखा गया है कि स्थापना के बाद से ही \*\*\* एक \*\*\* कंपनी है।

88. उपर्युक्त तथ्यों पर विचार करते हुए प्राधिकारी कंपनी को बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा प्रदान करने में असमर्थ हैं और यह मानते हैं कि कंपनी गैर-बाजार अर्थव्यवस्था की स्थिति में प्रचालन कर रही है।

#### मै. अल्काटेल-लूसेंट शंधाई बेल कंपनी लि.

89. कंपनी में शेयरधारिता की मौजूदा संरचना निम्नानुसार है:-

- चेनगन कम्युनिकेशन विलयरिंग एंड शटलमेंट कं. लि., चीन \*\*\*%
- चाइना हुआक्रिसन पोस्ट एंड टेलीकम्युनिकेशंस इकॉनामिक डेवलपमेंट सेंटर \*\*\*%
- अल्काटेल लूसेंट चायना इन्वेस्टमेंट कं. लि., चीन \*\*\*%
- अल्काटेल लूसेंट पार्टीसिपेशंस सिने, फ्रांस \*\*\*%
- अल्काटेल लूसेंट पार्टीसिपेशंस फ्रांस \*\*\*%

90. प्रथम दो चीन के शेयरधारक हैं और अगली तीन कंपनियां अल्काटेल ग्रुप की हैं । अल्काटेल ग्रुप की कुल शेयरधारिता में \*\*\*%+\*\*\* शेयर हैं जबकि शेष शेयरों का स्वामित्व चीन के राज्य स्वामित्व वाले उद्यमों के शेयरधारकों के पास है ।

91. \*\*\* की संयुक्त रूप से स्थापना नेशनल कंप्युटर नेटवर्क एंड इन्फारमेंशन सिक्युरिटी मैनेजमेंट सेंटर ऑफ चायना तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के फर्स्ट सर्विस सेंटर द्वारा की गई थी । चायना हुआजिन पोस्टल एंड टेलीकम्युनिकेशन इकॉनामिक डेवलपमेंट सेंटर ("सेंटर") लोगों के स्वामित्व वाले चायना टेलीकॉम के अधीनस्थ एक उद्यम है ।

92. \*\*\* निदेशक मंडल है, \*\*\* चीन के शेयरधारक हैं और \*\*\* अल्काटेल शेयरधारकों द्वारा नामित हैं । \*\*\* जो \*\*\* है और चीन के शेयरधारक द्वारा नामित है और \*\*\* अल्काटेल शेयरधारक द्वारा नामित है । यह कंपनी अंतर्राष्ट्रीय विनियमों, नियंत्रण एवं प्रकटन अपेक्षाओं के अधीन है ।

93. प्राधिकारी नोट करते हैं कि कंपनी ने सत्यापन के दौरान यह अनुरोध किया कि निर्णय लेने की प्रक्रिया बोर्ड में सरकारी नामितियों द्वारा प्रभावित नहीं की जाती है । तथापि, प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि कंपनी ने अपने अस्तित्व में आने के बाद से ही राज्य विभागों के शेयरधारिता के जरिए काफी सरकारी मौजूदगी स्थापित की है । आगे चल कर सरकारी शेयरधारित की पद्धति \*\*\*% बनी रही जो सरकार के स्वामित्व में है । इस समय निदेशक मंडल में भी राज्य विभागों के \*\*\*% (\*\*\* नामिति) नामिति हैं जिनमें \*\*\* के पास मत देने की शक्ति है । उपर्युक्त को देखते हुए राज्य की इस व्यापक भागीदारी के कारण राज्य के हस्तक्षेप से इंकार नहीं किया जा सकता और प्राधिकारी यह मानते हैं कि कंपनी को बाजार अर्थव्यवरथा का दर्जा प्रदान नहीं किया जा सकता ।

### मै. हुआबी टेक्नोलॉजीज कं. लि.

94. मै. हुआबी टेक्नोलॉजीज के परिसरों में 6-9 अप्रैल, 2010 को मौके पर जांच की गई थी । टिप्पणियां प्रस्तुत करने का असर देते हुए कंपनी को विस्तृत सत्यापन रिपोर्ट जारी की गई थी । चूंकि प्राधिकारी द्वारा जारी सत्यापन रिपोर्ट में यह दर्शाया गया है कि कंपनी की शेयर पूँजी में भारी वृद्धि हुई है, जो निगमन के समय \*\*\* आर एम बी से बढ़कर जांच की अवधि के समय तक \*\*\* मिलियन आर एम बी हो गई है । इसके अलावा, यह दावा किया गया था कि कंपनी का स्वामित्व निगमन के समय \*\*\* प्रकृत व्यक्तियों के पास था । जांच अवधि में स्वामित्व में भारी परिवर्तन हुए । दिनांक \*\*\* के कारोबार लाइसेंस के अनुसार हुआबी टेक्नोलॉजी कंपनी लि. एक सीमित दायित्व वाली कंपनी है जिसमें पूर्ण निवेश \*\*\* ने किया है और इसकी प्रदत्त पूँजी \*\*\* मिलियन आर एम बी थी, जो \*\*\* में बढ़कर \*\*\* मिलियन आर एम बी हो गई और \*\*\* में बढ़कर \*\*\* आर एम बी मिलियन हो गई । \*\*\* कंपनी का विधिक प्रतिनिधि है । संक्षेप में जांच अवधि के दौरान ही प्रदत्त पूँजी \*\*\* बिलियन आर एम बी से बढ़कर \*\*\* बिलियन आर एम बी हो गई । \*\*\* से पूर्व \*\*\* शेयरधारक थे अर्थात \*\*\* धारिता (\*\*\*%) और \*\*\* (\*\*\*%) । \*\*\* के बाद समूची शेयर पूँजी \*\*\* ने धारित की जिसमें से \*\*\* को

शेयर धारक बताया गया था । इस तथ्य पर विचार करते हुए कि कंपनी के स्वामित्व में कई परिवर्तन हुए हैं और शेयर पूँजी में इतनी अधिक वृद्धि हुई है, इसलिए मौके पर सत्यापन शेयर पूँजी में हुए प्रत्येक अभिवर्धन और स्वामित्व संरचना में हुए प्रत्येक परिवर्तन पर केन्द्रित रहा है ।

95. प्राधिकारी इस बात से सहमत हैं कि पूँजी वृद्धि और स्वामित्व संरचना में परिवर्तन निहायत सामान्य कारोबारी परिदृश्य है, तथापि गैर बाजा अर्थव्यवस्था की स्थिति के परिप्रेक्ष्य में विचारार्थ जो मूलभूत मुद्दा उठता है, वह है इस प्रकार निवेशित पूँजी के लिए निधियों का स्रोत, स्वामित्व संरचना में परिवर्तन और पूँजी निवेश के साथ स्वामित्व संरचना की अनुरूपता । निर्यातक निवेश की काफी अधिक राशि हेतु निधियों के स्रोत की पुष्टि नहीं कर सका । यह भी नोट किया जाता है कि निवेशों की भारी राशि \*\*\* और \*\*\* द्वारा जुटाई गई है । प्राधिकारी इस दावे को मानते में असमर्थ हैं कि निर्यातक संगत सूचना प्रदान करने की स्थिति में नहीं था ।

97. सत्यापन रिपोर्ट के उत्तर में निर्यातक ने इस बात पर भारी जोर दिया कि वह अपनी सर्वोत्तम क्षमताओं पर कार्य कर रहा है । प्राधिकारी का ध्यान डब्ल्यू टी ओ करार की ओर भी आकर्षित किया गया है जो ऐसी स्थितियों से संबंधित है जिसमें प्राधिकारी सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना का उपयोग कर सकते हैं । निर्यातक ने यह दलील दी कि उसने अपनी सर्वोत्तम क्षमता पर कार्य किया है और कुछेक दस्तावेज उपलब्ध कराने में विफलता इन दस्तावेजों की पुरातनता रही है और इसलिए उन्हें उपलब्ध कराने में विफलता को निर्यातक के प्रतिकूल नहीं माना जाए । प्राधिकारी इस संबंध में निर्यातक के अनुरोधों को पचा पाने में असमर्थ है और यह मानते हैं कि स्वामित्व संरचना और जिस तरीके से इस अवधि में स्वामित्व में परिवर्तन हुआ है, बाजार अर्थव्यवस्था के दर्जे के निर्धारण हेतु मूलभूत अपेक्षाओं में से एक है । इसके अलावा, किए गए निवेश के स्तर और स्वामित्व संरचना में हुए परिवर्तनों को देखते हुए यह नहीं कहा जा सकता कि उल्लिखित दस्तावेजों का अपरिणामी महत्व है ।

98. उपर्युक्त के मद्देनजर प्राधिकारी निर्यातक को बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा प्रदान करने में असमर्थ हैं और यह मानते हैं कि वह गैर-बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियों में प्रचालन करता है ।

मै. हैंगझाऊ ई सी आई टेलीकम्युनिकेशन कंपनी लि.

99. शुरूआत में चीन की मै. ईस्टन टेलीकम्युनिकेशन कंपनी लि. ("ईस्ट कॉम") और ई सी आई टेलीकॉम लि. इजराइल ("ई सी आई") ने \*\*\* को एक संयुक्त उद्यम पर सहमति व्यक्त की । इस संयुक्त उद्यम से जिस कंपनी का गठन किया जाना था, वह थी हैंगझाऊ ई सी आई टेलीकम्युनिकेशन कंपनी लि. (एच ई टी सी) । संयुक्त उद्यम की पंजीकृत पूँजी \*\*\* मिलियन अम.डॉ. थी ।

100. इस प्रकार ईस्टकॉम के \*\*\*% शेयर और ई सी आई के \*\*\*% शेयर थे । निदेशक मंडल में नियुक्त निदेशक मंडल ईस्टकॉम द्वारा \*\*\* और ई सी आई द्वारा \*\*\* था । ई सी आई का संयुक्त उद्यम में \*\*\* की नियंत्रणकारी हैसियत थी । संयुक्त उद्यम एच ई टी सी मुख्यतः व्यापार कार्यकलाप कर रही थी । उत्पाद एक्स डी एम की खरीद इजरायल से की जाती थी और चीन में मात्र बिक्री की जाती थी । संयुक्त उद्यम विपणन कार्यकलापों के लिए जिम्मेवार था । संयुक्त उद्यम की भंडारण क्षमताएं केवल चीन में थीं । ई सी आई इजरायल द्वारा एच ई टी सी से खरीद करने हेतु इजरायल से बिक्री के लिए अंतरण लागत तय की जाती थी ।

101. \*\*\* में ईस्टकॉम की एक सहायक कंपनी अर्थात् ई ओ टी सी (हैंगझाऊ इस्टर्न आप्टिकल कम्युनिकेशन कंपनी लि.) को ई सी आई ने आगे अधिग्रहण हेतु अभिज्ञात किया । कंपनी ई ओ टी सी ई सी आई के एस डी एच व्यापार के अनुरूप आप्टिक प्रौद्योगिकी का कारोबार कर रही थी । ई सी आई ने ई ओ टी सी की प्रौद्योगिकी की खरीद करने हेतु \*\*\* में सीधे \*\*\* अम.डॉ. का भुगतान किया । एच ई टी सी ने \*\*\* और ई ओ टी सी की अन्य सेवाओं सहित \*\*\* की \*\*\* आर एम बी में खरीद की । इस प्रकार एच ई टी सी ने ई ओ टी सी तथा ई सी आई की \*\*\* में संपूर्ण खरीद कर ली । कंपनी ने इस संबंध में संगत दस्तावेज दिखाए हैं । ई सी आई इजरायलका हिस्सा एच ई टी सी के कुल खातागत मूल्य का बढ़कर \*\*\*% हो गया ।

102. इसके साथ ही ई ओ टी सी की खरीद फरोक्त हो गई, एच ई टी सी बनी रही, ई सी आई संयुक्त उद्यम में \*\*\*% भागीदार बन गई । ईस्टकॉम एच ई टी सी में \*\*\*% भागीदार बनी रही । ईस्ट कॉम के अन्य कार्यकलाप एच ई टी सी में शेयर को छोड़कर (यथावत बने रहे) । \*\*\* में ई सी आई इजरायल ने एच ई टी सी में अपने लघु भागीदार ईस्टकॉम को उसके शेयर का खाता मूल्य अदा कर दिया । इस प्रकार \*\*\* में एच ई टी सी अस्तित्व में तो रही लेकिन ई सी आई इजरायल केवल \*\*\*% स्वामी रही ।

103. उपर्युक्त पर विचार करते हुए प्राधिकारी यह मानते हैं कि कंपनी/उत्पादक ने यह सिद्ध करने के लिए कि वे बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियों में प्रचालन कर रहे हैं और एम ई टी व्यवहार के पात्र हैं, पैरा 8 के उप पैरा (3) में विनिर्दिष्ट मानदंडों के आधार पर सूचना और पर्याप्त साक्ष्य प्रदान किया है ।

### सामान्य मूल्य

#### चीन जन.गण.

मै. फाइबर होम टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज लि., एल्काटेल-लूसेंट शंघाई बेल कंपनी लि.  
तथा मै. हुआवी टेक्नोलॉजीज कं. लि. और जैड टी ई कारपोरेशन

104. इन परिस्थितियों में प्राधिकारी चीन की उपर्युक्त कंपनियों पर नियमावली के अनुबंध-1 का पैरा-8 लागू करने की परिस्थिति में नहीं हैं और उन्हें नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के अनुसार कार्रवाई करनी होगी । इन नियमों के अनुसार चीन में सामान्य मूल्य का निर्धारण निम्नलिखित में से किसी एक के आधा पर किया जा सकता है :

क. बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में कीमत के आधार पर, अथवा  
 ख. बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में परिकलित मूल्य के आधार पर, अथवा  
 ग. ऐसे किसी तीसरे देश से भारत सहित अन्य देशों के लिए कीमत  
 घ. यदि उपर्युक्त विकल्पों के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण नहीं किया जा सकता तो निर्दिष्ट प्राधिकारी उचित लाभ मार्जिन को शामिल करने के लिए विधिवत समायोजित समान उत्पाद के लिए भारत में वास्तव में संदर्भ या संदेय कीमत सहित किसी अन्य उचित आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण कर सकते हैं ।

105. प्राधिकारी ने जांच शुरूआत संबंधी अधिसूचना में यह उल्लेख किया था कि आवेदक ने यह सुझाव दिया है कि संबद्ध वस्तु का उत्पादन और बिक्री अमरीका तथा यूरोप में की जाती है और इन देशों को चीन के लिए प्रतिनिधि देश माना जा सकता है । आवेदक ने इन देशों में उत्पादकों के नाम और पते प्रस्तुत किए थे ।

106. प्राधिकारी नोट करते हैं कि तीसरे देश की लागत और कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु घरेलू बिक्री या तीसरे देश को की गई निर्यात बिक्री तथा तीसरे देश में ऐसे उत्पादकों की उत्पादन लागत के पूर्ण एवं विस्तृत व्यौरे तथा उनका सहयोग अपेक्षित है । चूंकि इन बाजारों में प्रचलित कीमत और लागत के बारे में कोई सूचना प्राप्त नहीं की जा सकती है और चीन की प्रतिवादी कंपनियों ने बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे उचित देश के बारे में कोई दावा नहीं किया है मै. फाईबर होम, मै. अल्काटेल चीन जन.गण. तथा मै. जैड टी ई कारपोरेशन के संबंध में नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के दूसरे परंतुक के अनुसार अन्य उचित आधार पर सामान्य मूल्य का अनन्तिम निर्धारण किया गया । तदनुसार चीन जन.गण. के समस्त निर्यातकों के लिए विचाराधीन उत्पादकों के कारखाना सामान्य मूल्य का परिकलन उपलब्ध तथ्यों के आधार पर किया गया है । एस डी एच उपकरणों के अलग-अलग प्रकारों के लिए पृथक विभिन्न उपकरणों की अंतर्राष्ट्रीय कीमत उपलब्ध न होने के कारण सामान्य मूल्य का परिकलन भाड़े के लिए विधिवत समायोजित घरेलू उद्योग की आयात कीमत के आधार पर समस्त प्रमुख निविष्टियों की वास्तविक भारित औसत कीमत को हिसाब में लेकर किया गया है । सीमाशुल्क के लिए कोई समायोजन नहीं किया गया है क्योंकि एस डी एच हेतु उपकरणों पर शून्य सीमाशुल्क लागू है । यह नोट किया जाता है कि यद्यपि घरेलू उद्योग अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से प्रमुख संघटकों को प्राप्त कर रहा है, तथापि परिवर्तन लागत तथा घरेलू उद्योग के एसजीए व्यय को सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु स्वीकार किया गया है । 5% के उचित लाभ मार्जिन को जोड़ने के बाद सामान्य मूल्य परिकलित किया गया है । गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के अंतर्गत कार्यरत चीन के उत्पादकों द्वारा निर्यातित पी सी एन का भारी औसत सामान्य मूल्य निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है :

कंपनी का नाम	पी सी एन की संख्या	मात्रा (नग)	भारित औसत सामान्य मूल्य (अम.डॉ./नग)
मै. फाईबरहोम टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज	***	***	***

५०८७ ९६/१०- ॥ ॥

लि.			
एल्केटल-लुसोट शोधाई बेल कं. लि.	***	***	***
मै. जैड टी ई कार्पोरेशन .	***	***	***

### मै. हैंगझाऊ ई सी आई टेलीकम्युनिकेशन कं. लि.

107. इस उत्पादक/निर्यातक को बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियों में प्रचालन दर पाया गया था जैसा कि ऊपर विस्तार से स्पष्ट किया गया है। जांच शुरूआत आ उत्तर दायर करते समय उन्होंने परिशिष्ट-1 प्रस्तुत की थी, जिसमें भारत में बेचे गए पी सी एम के अनुरूप घरेलू बाजार में \*\*\* पी सी एन परिवर्तकों की बिक्री करने का दावा किया था। इनके रिकॉर्डों के सत्यापन से यह पता चला कि इन पी सी एन परिवर्तकों की बिक्री घरेलू बाजार में विभिन्न ग्राहकों को \*\*\* अलग-अलग संविदाओं पर की गई है। तथापि, सत्यापन के दौरान इस बात का पता चला कि कई पीसी एन की बिक्री इजरायल में घरेलू बाजार में नहीं की गई थी (विचाराधीन उत्पाद का बीजक इजरायल से तैयार हुआ है) जिसमें ऐसे कुछेक संयोजन/उप संयोजन शामिल थे, जो भारत को निर्यातित पी सी एन में प्रयुक्त वर्तुओं के समान थे। प्रधिकारी नोट करते हैं कि विचाराधीन उत्पाद तैयार, अर्ध तैयार, सी के डी/एस के डी, उप संयोजन होने के कारण और जिस तरीके से उत्पाद का बीजक तैयार किया जा रहा है, एवं इस तथ्य पर विचार करते हुए भी कि सामान्य मूल्य "समान वस्तु" की कीमत है और समनुरूप वस्तु के अभाव में ऐसे अन्य वस्तु पर विचार करना अपेक्षित है, सामान्य मूल्य को एस के डी/सी के डी कीमतों पर विचार करते हुए लेना होगा। ऐसे उप संयोजनों के संबंध में सामान्य मूल्य उस मूल्य के रूप में लिया गया है, जिस पर इन संयोजनों/उप संयोजनों की बिक्री घरेलू बाजार में की गई है। अन्य के लिए उत्पादक/निर्यातक के सत्यापित आंकड़ों के अनुसार उत्पादन लागत सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु ली गई है। तदनुसार सामान्य मूल्य निम्नानुसार निकाला गया है।

कंपनी का नाम	पी सी एन की संख्या	मात्रा (नग)	भारित औरत सामान्य मूल्य (अम.डॉ./नग)
मै. हैंगझाऊ ई सी आई टेलीकम्युनिकेशन कं. लि.	***	***	***

### इजराइल

#### मै. ई सी आई टेलीकॉम लि., इजराइल

108. कंपनी ने सामग्री के बिल के साथ विभिन्न परिशिष्टों में सूचना प्रदान की है जिसकी निर्दिष्ट प्रधिकारी ने जांच की है। प्रधिकारी नोट करते हैं कि भारत को निर्यातित \*\*\* पी सी एन में से केवल \*\*\* नगों की बिक्री घरेलू बाजार में की गई है और \*\*\* की बिक्री तीसरे देशों में की गई है। इस स्थिति की पुष्टि प्रतिवादी निर्यातक के सत्यापन के दौरान करवाई गई थी।

शेष पी सी एन की बिक्री भारतीय बाजार को छोड़कर अन्यत्र नहीं की गई थी । तथापि, सत्यापन के दौरान इस बात का पता चला कि इजरायल के घरेलू बाजार में बेचे न गए कई पी सी एन में ऐसे कुछ संयोजन/उप संयोजन निहित नहीं थे, जो भारत को निर्यातित पी सी एन में प्रयुक्त किए गए थे । प्राधिकारी नोट करते हैं कि विचाराधीन उत्पाद तैयार, अर्ध तैयार, सी के डी/एस के डी, उप संयोजन होने के कारण और जिस तरीके से उत्पाद का बीजक तैयार किया जा रहा है, एवं इस तथ्य पर विचार करते हुए भी कि सामान्य मूल्य "समान वस्तु" की कीमत है और समनुरूप वस्तु के अभाव में ऐसे अन्य वस्तु पर विचार करना अपेक्षित है, सामान्य मूल्य को एस के डी/सी के डी कीमतों पर विचार करते हुए लेना होगा । ऐसे उप संयोजनों के संबंध में सामान्य मूल्य उस मूल्य के रूप में लिया गया है, जिस पर इन संयोजनों/उप संयोजनों की बिक्री घरेलू बाजार में की गई है । अन्य के लिए उत्पादक/निर्यातक के सत्यापित आंकड़ों के अनुसार उत्पादन लागत सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु ली गई है । तदनुसार सामान्य मूल्य निम्नानुसार निकाला गया है ।

कंपनी का नाम	पी सी एन की संख्या	मात्रा (नग)	भारित औसत सामान्य मूल्य (अम.डॉ./नग)
मै. ई सी आई टेलीकॉम लि., इजराइल	***	***	***

### निर्यात कीमत

चीन जन.गण. के प्रतिवादी निर्यातक

मै. एल्केटेल-लुसेंट शंधाई बेल कं. लि., चीन जन.गण.

109. सत्यापित आंकड़ों के अनुसार बीमा, अंतरदेशीय परिवहन, हैंडलिंग प्रभार, विदेशी परिवहन, सीमाशुल्क घोषणा शुल्क, ऋण लागत, बैंक प्रभार एवं पैकिंग लागत (एक अन्य प्रतिवादी निर्यातक के सत्यापित आंकड़ों के अनुसार क्योंकि उसने किसी पैकिंग लागत का दावा नहीं किया था) पर निवल निर्यात कीमत निर्धारित करने के लिए विचार किया गया है । तदनुसार, व्यापार के समान स्तर पर सामान्य मूल्य के साथ तुलना करने के लिए प्रत्येक पी सी एन के संबंध में कारखाना स्तर पर निवल निर्यात कीमत निकाली गई है ।

मै. फाइबरहोम टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज लि.

110. प्राधिकारी के पास दायर उत्तर के अनुसार उन्होंने जांच अवधि में भारत को \*\*\* पी सी एन परिवर्तकों का निर्यात किया है जिनमें \*\*\* नग शामिल हैं । तथापि, प्रतिवादी निर्यातक के रिकार्ड के सत्यापन के दौरान यह पता चला कि उन्होंने जांच अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद के भारत को \*\*\* अलग-अलग पी सी एम परिवर्तकों के \*\*\* सैटों/नगों का निर्यात किया था । प्रत्येक पी सी एम के संबंध में कारखाना निवल निर्यात कीमत के निर्धारण हेतु अंतरदेशीय परिवहन, विदेशी परिवहन तथा ऋण लागत स्थापना पूर्व एवं स्थापना पश्चात सेवा प्रभार/वारंटी एवं पैकिंग लागत पर विचार किया गया है । तदनुसार, व्यापार के समान स्तर पर सामान्य मूल्य के साथ तुलना करने के लिए प्रत्येक पी सी एन के संबंध में कारखाना स्तर पर निवल निर्यात कीमत निकाली गई है ।

मे. हुआबी टैक्नोलॉजीज कं. लि., चीन.जन.गण

111. हुआबी टैक्नोलॉजीज ने कई बार अपने निर्यात बिक्री विवरण में संशोधन किया है । कंपनी ने यह भी तर्क दिया है कि उसके द्वारा अपनाई गई प्रणालियां प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई पी सी एन प्रणाली से भिन्न हैं और यह तर्क दिया कि कंपनी ने निर्यात बिक्री सूचना प्रदान करने में किसी कठिनाई का सामना नहीं किया होता यदि कंपनी ने आंतरिक उत्पाद कोडिंग प्रणाली को अपनाया होता । कंपनी ने कई बार अपने निर्यात बिक्री विवरण को संशोधित किया है, जैसा कि कंपनी को भेजी गई सत्यापन रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है । कंपनी की निर्यात बिक्री सूचना असत्यापित रही है । प्राधिकारी इस तर्क को सवीकार करने में असमर्थ हैं कि प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई उत्पाद कोडिंग प्रणाली अत्यधिक जटिल है, जिससे कंपनी वांछित सूचना प्रदान करने में असमर्थ रही है । वस्तुतः संबद्ध देशों के कई उत्पादकों ने वर्तमान जांच में भाग लिया है और कंपनी द्वारा व्यक्त कठिनाइयों को व्यक्त किए बिना सूचना प्रदान की है । इस बात के होते हुए भी प्राधिकारी ने हितबद्ध पार्टियों को उत्पाद कोडिंग प्रणाली की सूचना देते समय इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया था कि निर्यातक उत्पाद कोडिंग प्रणाली में संशोधन करने अथवा अपनी खुद की प्रणाली का उपयोग करने के लिए स्वतंत्र हैं यदि वे प्राधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रणाली को अपर्याप्त/अनुचित अथवा बोझिल समझते हैं । कुल मिलाकर दोनों आधार पर - प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई उत्पाद कोडिंग प्रणाली और कंपनी द्वारा अपनाई गई उत्पाद कोडिंग प्रणाली के आधार पर सूचना प्रदान करने से निर्यातक किसी भी हालत में वंचित नहीं हुआ है ।

112. विचाराधीन उत्पाद अनिवार्यतः कई इलैक्ट्रोनिक कार्डों का संयोजन और उप संयोजन है । वस्तुतः उत्पादक उत्पाद के एस के डी/सी के डी/कार्ड/उप संयोजनों के संबंध में बिक्री का बीजक तैयार करना चाहते हैं । जांच से यह पता चला है कि सभी कंपनियां उत्पाद की डिजाइन एवं विकास हेतु एक समान प्रणाली का उपयोग करती हैं जिसके लिए कुछ उत्पाद कोडिंग प्रणाली अपनाई जाती है । यह नोट किया जाता है कि कंपनी द्वारा निर्यात बिक्री सूचना में इतना अतिधक संशोधन किया गया है कि जिससे उप संयोजन/कार्ड संरचना में भी अलग-अलग उत्तरों में परिवर्तन कर दिया गया है ।

113. प्राधिकारी के पास दायर उत्तर के अनुसार उन्होंने जांच अवधि के दौरान भारत को \*\*\* पी सी एन परिवर्तकों का निर्यात करने का दावा किया है जिनमें \*\*\* नग शामिल हैं । इनमें से \*\*\* पी सी एन कार्ड थे । इन \*\*\* पी सी एन के संबंध में किसी मात्रा का उल्लेख नहीं किया गया है और इसलिए इन्हें प्रारंभिक निर्धारण हेतु निवल निर्यात कीमत के निर्धारण के प्रयोजनार्थ अलग रखा गया था । ये पी सी एन मूलतः भारत में अलग-अलग ग्राहकों के साथ निष्पादित पी ओ से लिए गए थे । यद्यपि, प्राधिकारी ने सत्यापन दौरे के दौरान अपने आंकड़े सत्यापित करवाने के लिए उन्हें आवश्यक समय दिया, तथापि उनके द्वारा दावा किए गए पी सी एन के ब्यौरों का सत्यापन नहीं किया जा सका क्योंकि उनमें प्राधिकारी द्वारा निर्धारित नामावली के अनुसार प्रत्येक पी सी एन के लिए अभिज्ञात क्षेत्रों में असमानता प्रतीत हुई थी । सत्यापन रिपोर्ट के उत्तर में उन्होंने विसंगति में सुधार करने का दावा करते हुए अद्यतन पी सी

एन के ब्यौरे प्रस्तुत किए और एन ई पी के निर्धारण हेतु उन्हें स्वीकार करने की मांग की । इसके अनुसार, उन्होंने जांच अवधि के दौरान भारत को \*\*\* अलग-अलग पी सी एन परिवर्तकों के \*\*\* सैटों/नगों का निर्यात किया । इसके अलावा, उन्होंने पृथ्वी आदि को ऋण संविदा पर कुछ और पी सी एन का निर्यात करने का भी दावा किया है जिसके बारे में सत्यापन के दौरान वे उचित लेखा उपलब्ध कराने में विफल रहे थे ।

114. उपर्युक्त पर विचार करते हुए प्राधिकारी यह मानते हैं कि उन्हें उचित और पर्याप्त अवसर प्रदान किए जाने के बावजूद भारत को की गई निर्यात बिक्री से संबंधित दावा असत्यापित रहा । अतः प्राधिकारी सबद्ध उत्पादक/निर्यातक के बारे में अलग-अलग पाटन मार्जिन अथवा क्षति मार्जिन के निर्धारण हेतु अलग-अलग निर्यात कीमत और एन ई पी निर्धारित करने में असमर्थ हैं ।

### जैड टी ई कारपोरेशन

115. जहां तक अनंतिम उपायों का संबंध है, अलग-अलग पाटन मार्जिन की उन्हें अनुमति नहीं दी गई थी क्योंकि यह पाया गया था कि उन्होंने अपूर्ण आंकड़े दायर किए हैं । इससे संबंधित ब्यौरे पी एफ दस्तावेज में सूचित किए गए थे । इसके अलावा, पी एफ दस्तावेज में यह बताया गया था कि प्राधिकारी द्वारा इसकी प्राप्ति के बाद यह दृष्टिकोण अपनाया जाएगा कि क्या प्राधिकारी द्वारा नए सिरे से प्रदान किए जाने के लिए प्रस्तावित आंकड़ों को अंतिम निर्धारण हेतु बाद में स्वीकार किया जाएगा । प्रारंभिक जांच परिणाम जारी होने के बाद प्रतिवादी निर्यातक ने भारत को हुए निर्यातों के बारे में आंकड़े प्रस्तुत किए । ये आंकड़े पूर्ण पाए गए, जिन्हें अपूर्ण निर्धारण हेतु प्राधिकारी ने विधिवत स्वीकार किया । प्रस्तुत किए गए संशोधित आंकड़ों के अनुसार सबद्ध निर्यातक/उत्पादक ने जांच अवधि के दौरान भारत को \*\*\* अलग-अलग पी सी एन परिवर्तकों के \*\*\* सैटों/नगों का निर्यात किया है । इसके अलावा, उन्होंने कार्डों के \*\*\* नगों का भी निर्यात किया है । ऋण लागत, अंतरदेशी भाड़े, हैंडलिंग, लदान एवं अनुषंगी व्यय, सीमाशुल्क निकासी, समुद्री भाड़े, बीमा, बैंक प्रभार, पैकिंग प्रभार, वारंटी के लिए सत्यापित समायोजनों पर कारखाना स्तर पर निवल निर्यात कीमत के निर्धारण हेतु विचार किया गया है ।

मै. ई सी आई टेलीकॉम लि. इजराइल के जरिए मै. हांगझोऊ ई सी आई टेलीकम्युनिकेशन कं. लि. चीन जन.गण.

116. सत्यापित आंकड़ों के अनुसार उन्होंने जांच अवधि के दौरान भारत को \*\*\* पी सी एन परिवर्तकों का निर्यात किया है जिनमें \*\*\* नग शामिल हैं । यथा सत्यापित स्वदेशी भाड़े, विदेशी भाड़े, बीमा, भंडारण, वित्तीय लागत/एस जी ए व्यय तथा वारंटी के लिए समायोजनों का दावा किया गया है जिनकी अनुमति कारखाना स्तर पर निवल निर्यात कीमत के निर्धारण हेतु प्रदान की गई है ।

इजराइलमै. ई सी आई टेलीकॉम लि. इजराइल

117. सत्यापित आंकड़ों के अनुसार उन्होंने जांच अवधि के दौरान भारत को \*\*\* पी सी एन परिवर्तकों का निर्यात किया है जिनमें \*\*\* नग शामिल हैं। यथा सत्यापित स्वदेशी भाड़े, विदेशी भाड़े, बीमा, भंडारण, वित्तीय लागत व्यय तथा वारंटी के लिए समायोजनों का दावा किया गया है जिनकी अनुमति कारखाना स्तर पर निवल निर्यात कीमत के निर्धारण हेतु प्रदान की गई है।

पाटन मार्जिन

118. प्राधिकारी ने एस डी एच उपकरणों के विभिन्न प्रकारों की वास्तविक और ऑप्टिकल विशेषताओं में अंतर को स्वीकार किया है और तदनुसार उन्होंने समनुरूपी विनिर्देशनों की तुलना में आयातित एस डी एच उपकरणों की भौतिक एवं ऑप्टिकल विशेषताओं तथा रूपांतरणों पर विचार करने के बाद निर्यात कीमत के साथ सामान्य मूल्य की तुलना की है। प्रत्येक पी सी एन के संबंध में अलग-अलग सामान्य मूल्य तथा निर्यात कीमत के आधार पर तुलना की गई है और तत्पश्चात भारित औसत सामान्य मूल्य की तुलना पाटन मार्जिन के निर्धारण हेतु भारित औसत एन ई पी के साथ की गई है। इस प्रकार निर्धारित पाटन मार्जिन का ब्लौरा निम्नलिखित तालिका में दिया गया है :

कंपनी का नाम	भारित औसत सामान्य मूल्य (अम.डॉ./नग)	भारित औसत निर्यात मूल्य (अम.डॉ./नग)	पाटन मार्जिन (अम.डॉ./नग) (%)
मै. फाइबरहोम टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज लि.	***	***	*** (280-290%)
एल्केटल-लुसेंट शंधाई बेल क. लि.	***	***	*** (40-50%)
मै. हैंगझोऊ ई सी आई टेलीकम्युनिकेशन कं. लि.	***	***	*** (5-15%)
मै. ई सी आई टेलीकॉम लि., इजराइल।	***	***	*** (10-20%)
मै. जैड टी ई कारपोरेशन	**	**	*** (30-40%)
अवशिष्ट - चीन			(280-290%)
अवशिष्ट- इजराइल			(200-210%)

क्षति निर्धारणघरेलू उद्योग द्वारा किए गए सुझाव

119. घरेलू उद्योग ने क्षति के बारे में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं।

(i) ग्राहकों द्वारा विचाराधीन उत्पाद की जरूरत अपने दूरसंचार नेटवर्क के ऑप्टिकल ट्रांसमिशन आधार की स्थापना के लिए होती है। यह उनके लिए पूंजीगत वस्तु

की खरीद होती है। अंतर्रस्त निवेश के भारी मूल्य के कारण ग्राहक खरीद की सुस्थापित प्रणाली का अनुपालन करते हैं।

(ii) बी एस एन एल, एम टी एन एल तथा रेल टेल जैसी कंपनियां खुली निविदा प्रणाली का पालन करती हैं जबकि निजी प्रतिस्पर्धी (यथा भारती, रिलायंस, टाटा कम्प्यूनिकेशन आदि) प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आर ई पी) प्रक्रिया के जरिए बंद निविदा प्रणाली का अनुपालन करते हैं।

(iii) खुली निविदाओं में समस्त आपूर्तिकर्ताओं से मुहरबंद लिफाफों में बोलियां आमंत्रित की जाती हैं, ऐसी बोलियां समस्त भागीदार आपूर्तिकर्ताओं की मौजूदगी में खोली जाती हैं और आपूर्तिकर्ताओं द्वारा उद्धृत कीमतों की सार्वजनिक रूप से घोषणा की जाती है। बंद निविदाओं में ग्राहक भाव दरे आमंत्रित करते हैं, उनकी तुलना करते हैं और तत्पश्चात् सामान्यतः सर्वोत्तम वाणिज्यिक प्रस्ताव (न्यूनतम कीमत, ऋण शर्तें आदि) के आधार पर ऑर्डर प्रदान करते हैं।

(iv) दोनों प्रणलियों में कीमत सौदेबाजी से इंकार नहीं किया जाता है। कीमत का इस प्रकार का नियतन विनिर्दिष्ट मात्रा या अस्थायी मात्रा के लिए हो सकता है। तथापि, वास्तविक पोत लदान, दर संविदा की अवधि (12-14 माह की) के दौरान किया जाता है।

(v) शामिल व्यापार की उच्च मात्रा पर विचार करते हुए याचिकाकर्ता अलग-अलग ग्राहकों की जरूरत का नियमित रूप से पता लगाते हैं और किए गए प्रत्येक प्रस्ताव पर कड़ी निगरानी रखते हैं।

(vi) याचिकाकर्त को ग्राहकों द्वारा की गई खरीद की पूर्ण जानकारी होती है। याचिकाकर्ता को ग्राहकों द्वारा लिए गए खरीद के निर्ण की यथोचित जानकारी होती है।

(vii) याचिकाकर्ता ने नियमित रूप से विकसित इस बाजार आसूचना के आधार पर क्षति अवधि के दौरान प्राप्त किए और गंवाए गए विभिन्न ऑर्डरों के बारे में सूचना समेकित की है।

(viii) विभिन्न इच्छुक आपूर्तिकर्ता अप्रत्यादेय कीमतें उद्धृत करते हैं। इस प्रस्ताव के बाद यद्यपि कीमत में आगे और कमी आने की संभावना होती है, लेकि कीमत में वृद्धि होने की संभावना नहीं होती है।

(ix) घरेलू उद्योग को हुई क्षति का निर्धारण करने के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी को विदेशी उत्पादकों एवं भारतीय उत्पादकों द्वारा किए गए प्रस्तावों पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए। विदेशी आपूर्तिकर्ताओं द्वारा किए गए इन प्रस्तावों के आधार पर क्षति मार्जिन का निर्धारण भी किया जाना चाहिए।

### विरोधी हितबद्ध पार्टियों के विचार/अनुरोध

120 याचिका का विरोध करने वाली हितबद्ध पार्टियों ने क्षति के बारे में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं, जो संक्षेप में निम्नानुसार हैं:-

- i. इस बात का सुझाव देने का काई आधार नहीं है कि अनुच्छेद 3.4 के प्रावधान के तहत ऐसे निर्यातों पर विचार करने पर किसी भी रूप में प्राधिकारी नहीं मिलता है, जिन्हें प्रभावित किए जाने की अपेक्षा अनुसूचित किया गया है ।
- ii. पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन का निर्धारण जांच अवधि के संबंध में ही निर्धारित किया जा सकता है न कि अनुमानों के आधार पर ।
- iii. एस टी एम 64 जैसे एस डी एच ट्रांसमिशन उपकरणों का विनिर्माण याचिकाकर्ता नहीं करते हैं । अतः याचिकाकर्ताओं को हुई खति तभी हो सकती है जब याचिकाकर्ता द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु की मांग सीमित हो । इसके अलावा, याचिकाकर्ता का यह कथन निरर्थक है कि ग्राहक अब एच टी एम 1 की 128 इकाई के बजाए एच टी एम 64 की दो इकाई अथवा एच टी एम 16 की 8 इकाई की खरीद करना चाहते हैं और जिसमें ग्राहक प्रणाली अथवा एस डी एच ट्रांसमिशन उपकरण के उपयोग को समझने की संपूर्ण विफलता प्रदर्शित होती है । स्वीकार न करते हुए यह मानते हुए कि याचिकाकर्ता के अनुरोध में भाव है, प्रश्न यह उठता है कि क्या मात्रा के रूप में संबद्ध वस्तु की मांग में आई पर्याप्त गिरावट नैसर्गिक नहीं होनी चाहिए जबकि उपलब्ध आंकड़े इसके विपरीत स्थिति दर्शाते हैं ।
- iv. वर्ष 2007-08 से लेकर जांच अवधि तक याचिकाकर्ताओं का बाजार हिस्सा 13.5% से अत्यधिक बढ़कर 18.1% हो गया है, यह वृद्धि पूर्णतः संबद्ध देशों के आयातों के कारण हुई है जो वर्ष 2007-08 में 45.19% से घटकर जांच अवधि में 41.32 हो गए हैं ।
- v. भारतीय बाजार की मांग को पूरा करने की क्षमता के संबंध में याचिकाकर्ता के अनुरोध और क्षमता उपयोग का उसके दावे के बारे में किए गए समूचे अनुरोध के अनुसार निर्देशित किया गया है कि इ एम एस विक्रेता जो थाइलैंड और मलेशिया जैसे अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्राधिकारों में स्थित हैं, भारतीय मांग को पूरा करने के लिए अपेक्षित क्षमता रखते हैं । डी जी ए डी के लिए विचार करने हेतु जिस मूल प्रश्न की हम बात करते हैं वह यह है कि क्या याचिकाकर्ताओं को घरेलू उत्पादक मानना संगत है क्योंकि वास्तविक उत्पादन केवल थाइलैंड और मलेशिया में किया जाता है न कि भारत में ।
- vi. आधार वर्ष 2005-06 और पूर्ववर्ती अवधि 2007-08, दोनों की तुलना में उत्पादन और बिक्री में वृद्धि हुई है । याचिकाकर्ता अब यह दावा करता है कि 2006-07 की तुलना में उत्पादन और बिक्री में गिरावट आई है । गिरावट या वृद्धि की पुष्टि करने के लिए अवधियों को स्वेच्छानुसार चुनने की यह नीति औचित्य रहित है ।
- vii. याचिकाकर्ता द्वारा भारी घाटे के दावों का सत्यापन याचिकाकर्ता की वार्षिक रिपोर्ट से नहीं किया गया है ।
- viii. माल सूची के संबंध में याचिकाकर्ता का अनुरोध गलत है ।
- ix. कारणात्मक संबंधों के विश्लेषण के बारे में प्राधिकारी को खपत की पद्धति, प्रौद्योगिकी विकास और तीसरे देशों से हुए आयातों जैसे कि कारकों की जांच करनी चाहिए ।

x. संबद्ध कंपनियों और विदेश स्थित ई एम एस विक्रेताओं से अत्यधिक आयात हुए हैं। यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता को बिक्री करने से पूर्व इन कंपनियों द्वारा लाभ मार्जिन जोड़ा जाएगा। इसके अलावा, संबद्ध कंपनी तेजस कम्युनिकेशन्स पी टी ई लि. से आयात पर्याप्त मात्रा में हुए हैं।

xi. आवेदक उद्योग ने उद्योग के इस खंड में बिक्री के अंतरनिहित स्वरूप को स्वीकार किया है। स्पष्टतः कीमत का निर्धारण मांग और आपूर्ति पर आधारित नहीं होता है। दूसरे शब्दों में पहुंच मूल्य का निविदा प्रक्रिया पर प्रभाव नहीं पड़ता है और इस प्रकार सामान्य मामलों में अपनाई गई कार्य प्रणाली ऐसे मामलों में लागू नहीं होती है। तर्क के अनुसार क्षति के कारक के रूप में उद्योग का संभावित कार्य निष्पादन हर हालत में कानूनन दोषपूर्ण है। इसके अलावा निर्दिष्ट प्राधिकारी हेतु संभावित कार्य निष्पादन के आवेदकों के दावे के समर्थन में ऐसा कोई पुष्टिकरण, तर्कसम्मत सामग्री या आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, जिससे ऐसे दावों के आधार पर निष्कर्ष निकाला जा सके।

xii. प्राधिकारी को याचिकाकर्ता के आरोप के अनुसार एक आकार के संबंध में समूची मात्रा अर्थात् एस टी एम 4 और एस टी एम 16 में परिवर्तन नहीं करना चाहिए और यह अनुरोध किया गया है कि याचिकाकर्ता के उक्त अनुरोध को भी अस्वीकृत कर दिया जाना चाहिए।

xiii. घरेलू बाजार को कोई क्षति नहीं हुई है। वस्तुतः कई संकेतकों से सकारात्मक प्रवृत्ति का पता चलता है।

xiv. चीन के उत्पादकों/निर्यातकों के आयातों के कारण घरेलू उद्योग को कोई वास्तविक क्षति नहीं हुई है अथवा वास्तविक क्षति का खतरा उत्पन्न नहीं हुआ है। आरोपित क्षति मात्र आरोप, अनुमान और परोक्ष संभावना है और इनकी पुष्टि साक्ष्य द्वारा नहीं की गई है।

xv. संबद्ध वस्तु की मांग 100 (2005-06) से बढ़कर 183 (जांच अवधि) हो गई है और घरेलू उद्योग की तदनुरूपी बिक्री उसी अवधि के दौरान बढ़कर 175 हो गई है जिसे काफी कम नहीं कहा जा सकता है।

xvi. चीन के उत्पादक/निर्यातकों ने ऐसी उचित पहुंच कीमत पर भारत को संबद्ध वस्तु का आयात किया है जिससे घरेलू बाजार में संबद्ध वस्तु की कीमत में कटौती नहीं हुई है।

xvii. घरेलू उद्योग का बाजार हिस्से में 2007-08 से जांच अवधि तक वृद्धि हुई है।

xviii. तेजस ने दावा किया है कि वर्तमान वित्तीय आधार पर उसके वित्तीय लाभ घरेलू हानि बन गए हैं। तथापि, यह नोट किया जाता है कि तेजस के वर्तमान आरोपों के बावजूद उसके खुद के आंकड़ों (प्रपत्र IV क) से निर्यात हानि का पता चलता है।

xix. यह विश्लेषण करने के लिए निवेश पर आय कोई उचित सूचकांक नहीं है कि क्या चीन के उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा भारत में संबद्ध वस्तु के आयातकों के कारण घरेलू उद्योग को क्षति हुई है।

xx. यह अनुरोध किया गया है कि विचाराधीन उत्पाद और "समान वस्तु" की परिभाषा न केवल सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु संगत है जिससे पाटन मार्जिन की गणना

की जाती है अपितु घरेलू उद्योग को हुई क्षति के निर्धारण हेतु भी संगत है । किसी पाटनरोधी जांच में यथासंभव शीघ्र समान उत्पाद के मुद्दे पर विचार करना होता है क्योंकि इसका शुलक लगाए जाने सहित कार्रवाई पर स्पष्ट प्रभाव पड़ता है ।

xxi. यह आरोप लगाया गया है कि तेजस द्वारा विनिर्मित अनुषंगी ट्रांसमिशन उत्पादों के बारे में उसके द्वारा प्रदत्त सूचना पर विचाराधीन उत्पाद के व्यापक वर्णन में शामिल पराषंगी ट्रांसमिशन उत्पादों और उपकरणों की अन्य श्रेणियों सहित विचाराधीन उत्पाद में शामिल समूचे उपकरणों से उत्पन्न घरेलू उद्योग को हुई क्षति का आकलन करने के लिए विचार और विश्लेषण किया गया है ।

xxii. समूचा विश्लेषण केवल एस डी एच से संबंधित आंकड़ों पर आधारित है जबकि स्वयं आवेदक उद्योग के अनुसा जांच के क्षेत्र में सहायक सामग्री, संबद्ध साफ्टवेयर, पुर्जे व संघटक, पापुलेटेड पी सी बी, विद्युत आपूर्ति, लेजर, चेसेज, ई आई केबल, पी सी एम केबल, पावर केबल, रैप, वर्क स्टेशन आदि शामिल करना अपेक्षित है ।

### प्राधिकारी द्वारा जांच

121. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के क्षति के दावों के संबंध में हितबद्ध पार्टियों द्वारा व्यक्त विचारों को नोट किया है और क्षति निर्धारण एवं कारणात्मक संबंध के विश्लेषण के प्रयोजनार्थ अनिवार्य कारकों की जांच की है ।

### आयात मात्रा का निर्धारण

122. प्राधिकारी ने गौण स्रोतों से याचिकाकर्ता द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना, डी जी सी आई एंड एस से प्राप्त सूचना, आई बी आई एस से याचिकाकर्ता द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना, प्रतिवादी निर्यातकों एवं आयातकों द्वारा प्रदत्त सूचना की जांच आयात की मात्रा के निर्धारण हेतु की है । जहां तक जांच अवधि का संबंध है, प्राधिकारी ने प्रतिवादी निर्यातकों द्वारा प्रदत्त सूचना पर विचार किया है । पूर्ववर्ती वर्षों के लिए चूंकि किसी भी निर्यातक ने निर्धारित प्रात्र और ढंग से सूचना उपलब्ध नहीं कराई है और अलग-अलग अवधियों के लिए सूचना प्रदान की है इसलिए प्राधिकारी याचिका में निहित सूचना को स्वीकार करने के लिए बाध्य हैं ।

### मांग का निर्धारण,

123. प्राधिकारी ने देश में उत्पाद की मांग या प्रत्यक्ष खपत का निर्धारण घरेलू उत्पादकों की घरेलू बिक्री तथा समरत स्रोतों से हुए आयातों की राशि के रूप में किया है । इस प्रकार निर्धारित मांग निम्नलिखित तालिका में देखी जा सकती है :

	2005-06	2006-07	2007-08	अप्रैल-दिसं. 08 - वार्षिकीकृत	अप्रैल-दिसं. 08	2005-06 की तुलना में जांच अवधि वार्षिकीकृत
<b>नगों के संबंध में</b>						
चीन	***	***	***	***	***	1364%
इजराइल	***	***	***	***	***	35%
संबद्ध देश	***	***	***	***	***	240%
अन्य देश	***	***	***	***	***	151%
भारत में आयात	***	***	***	***	***	186%
उत्पाद शुल्क रिकॉर्डों के अनुसार घरेलू उद्योग की बिक्री	***	***	***	***	***	175%
घरेलू उद्योग के अनुमान के अनुसार अन्य भारतीय उत्पादकों की बिक्री	***	***	***	***	***	
मांग	51,308	118,500	81,186	94,027	70,520	183%
<b>मूल्य के रूप में - लाख रुपए</b>						
चीन	***	***	***	***	***	1159%
इजराइल	***	***	***	***	***	183%
संबद्ध देश	***	***	***	***	***	334%
अन्य देश	***	***	***	***	***	229%
भारत में आयात	***	***	***	***	***	270%
घरेलू उद्योग की बिक्री	***	***	***	***	***	234%
अन्य भारतीय उत्पादकों की अनुमानित बिक्री	***	***	***	***	***	
मांग	50,461	79,829	117,574	132,083	99,062	262%

124. विचाराधीन उत्पाद की मांग में नग एवं मूल्य दोनों रूपों में पर्याप्त वृद्धि प्रदर्शित होती है। घरेलू उद्योग ने आरोप लगाया है कि देश में मांग में पर्याप्त वृद्धि होने के बावजूद वे संबद्ध देशों से हुए पाटन के कारण इसका लाभ नहीं उठा सके हैं। घरेलू उद्योग के इस आरोप की पुष्टि की गई है और इस अवधि के दौरान मांग बढ़कर 42,719 नग/सं. या 816.22 करोड़ रुपए हो गई है तथापि, घरेलू उद्योग की बिक्री बढ़कर केवल 2593 नग/सं. या 18 करोड़ रुपए की हुई है।

### आयात मात्रा तथा बाजार हिस्सा

125. जहां तक पाटित आयातों की मात्रा का संबंध है, निर्दिष्ट प्राधिकारी के लिए इस बात पर विचार करना अपेक्षित होता है कि क्या पाटित आयातों में समग्र रूप में या भारत में उत्पादन या खपत की तुलना में पर्याप्त वृद्धि हुई है। पाटनरोधी नियमावली के नियम के अनुबंध-॥ (ii) में निम्नानुसार उपबंध है:-

“पाटित आयातों की मात्रा की जांच करते समय उक्त प्राधिकारी यह विचार करेंगे कि क्या समग्र रूप से या भारत में उत्पादन और खपत की दृष्टि से पाटित आयातों में भारी वृद्धि हुई है ..... /”

126. संबद्ध देशों से पाटित आयातों की मात्रा का विवरण निम्नलिखित तालिका में दिया गया है :-

	2005-06	2006-07	2007-08	अप्रैल-दिसं. 08 - वार्षिकीकृत	अप्रैल-दिसं. 08
संबद्ध देश	16,159	55,907	36,688	38,856	29,142
अन्य	25,219	38,257	33,520	38,117	28,588
कुल आयात	41,378	94,164	70,208	76,973	57,730
भारतीय उत्पादन	9,930	24,337	10,978	17,053	12,790
भारतीय खपत	51,308	118,500	81,186	94,027	70,520
आयातों का बाजार हिस्सा					
संबद्ध देश	31.49%	47.18%	45.19%	41.32%	41.32%
अन्य	49.15%	32.28%	41.29%	40.54%	40.54%
भारतीय उत्पादन की तुलना में संबद्ध देशों से हुए आयात	162.73%	229.72%	334.20%	229.54%	227.85%

127. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध देशों से हुए आयातों की मात्रा में पर्याप्त वृद्धि हुई है। यह नोट किया जाता है कि यद्यपि, जांच अवधि के दौरान संबद्ध देशों से हुए आयातों की मात्रा (वार्षिकीकृत) (नगों के रूप में आकलित) मात्रा में आधार वर्ष 2005-06 की तुलना में लगभग 140% की वृद्धि हुई है। क्षति अवधि की तुलना में उत्पाद की कुल भारतीय खपत में संबद्ध देशों का हिस्सा 31% से अत्यधिक बढ़कर 41% हो गया है। मात्रा के संबंध में संबद्ध देशों से रामग्र आयात में 2005-06 की तुलना में जांच अवधि के दौरान काफी अधिक लगभग 234% (वार्षिकीकृत) की वृद्धि हुई है।

	2005-06	2006-07	2007-08	अप्रैल-दिसं. 08 - वार्षिकीकृत	अप्रैल-दिसं. 08	2005-06 की तुलना में जांच अवधि वार्षिकीकृत
आयातों की संख्या						
चीन	2,502	9,959	10,056	34,132	25,599	1364%
इजराइल	13,657	45,948	26,632	4,724	3,543	35%
संबद्ध देश	16,159	55,907	36,688	38,856	29,142	240%
अन्य देश	25,219	38,257	33,520	38,117	28,588	151%
कुल आयात	41,378	94,164	70,208	76,973	57,730	186%
आयात मूल्य लाख रु. में						
चीन	2,461	6,717	14,564	28,500	21,400	1159%
इजराइल	13,433	30,989	38,570	24,553	18,414	183%
संबद्ध देश	15,894	37,706	53,134	53,085	39,814	334%

अन्य देश	24,805	25,802	48,545	56,791	42,593	229%
कुल आयात	40,699	63,508	101,679	109,876	82,407	270%
भारतीय उत्पादन						
मात्रा	9,930	24,337	10,978	17,053	12,790	170%
मूल्य लाख रुपए में	9,767	16,414	15,898	22,207	16,655	227%
भारतीय उत्पादन की तुलना में भारतीय देशों से आयात						
मात्रा	163%	230%	334%	228%	228%	141%
मूल्य लाख रुपए में	163%	230%	334%	239%	239%	147%

128. यह देखा गया है कि संबद्ध देशों से हुए आयातों में समग्र रूप में तथा भारत में उत्पादन की तुलना में पर्याप्त वृद्धि हुई है ।

### भारत में खपत की तुलना में आयात

129. भारत में खपत की तुलना में संबद्ध देशों से पाठित आयातों की मात्रा निम्नलिखित तालिका में दी गई है:-

	2005-06	2006-07	2007-08	अप्रैल-दिसं. 08 - वार्षिकीकृत	अप्रैल-दिसं. 08	2005-06 की तुलना में जांच अवधि वार्षिकीकृत
<b>आयातों की संख्या</b>						
चीन	2,502	9,959	10,056	34,132	25,599	1364%
इजराइल	13,657	45,948	26,632	4,724	3,543	35%
संबद्ध देश	16,159	55,907	36,688	38,856	29,142	240%
अन्य देश	25,219	38,257	33,520	38,117	28,588	151%
कुल आयात	41,378	94,164	70,208	76,973	57,730	186%
<b>आयात मूल्य लाख रु. में</b>						
चीन	2,461	6,717	14,564	28,500	21,400	1159%
इजराइल	13,433	30,989	38,570	24,553	18,414	183%
संबद्ध देश	15,894	37,706	53,134	53,085	39,814	334%
अन्य देश	24,805	25,802	48,545	56,791	42,593	229%
कुल आयात	40,699	63,508	101,679	109,876	82,407	270%
<b>भारतीय उत्पादन</b>						
मात्रा	51,308	1,18,500	81,186	94,027	70,520	183%
मूल्य लाख रुपए में	50,461	79,829	117,574	132,083	99,062	262%
<b>भारतीय उत्पादन की तुलना में भारतीय देशों से आयात</b>						
मात्रा	31.49%	47.18%	45.19%	41.32%	41.32%	131%
मूल्य लाख रुपए में	31.50%	47.23%	45.19%	40.19%	40.19%	128%

130. यह देखा जाता है कि संबद्ध देशों से आयात जो वर्ष 2005-06 के दौरान केवल 31.5% थे, वे जांच अधिक में भारत में खपत की तुलना में बढ़कर 41.32% हो गए। प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग पर आयातों का मात्रात्मक प्रभाव प्रतिकूल रहा है।

### आयातों का कीमत प्रभाव

131. जहां तक कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव का संबंध है, प्राधिकारी ने इस बात की जांच की है कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा कीमत में पर्याप्त कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों के प्रभाव से कीमत में अन्यथा पर्याप्त गिरावट आई है अथवा कीमत में होने वाली उस वट्ठि में गिरावट आई है जो अन्यथा पर्याप्त स्तर तक बढ़ गई होती।

132 प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्रत्येक ग्राहक अपनी विनिर्दिष्ट अपेक्षा की पूर्ति हेतु एस डी एच उपकरण की खरीद करता है। एक स्थान पर किसी ग्राहक द्वारा प्रयुक्त एस डी एच उपकरण संबद्ध भौतिक एवं आप्टिकल गुणधर्मों के अनुसार दूसरे स्थानों पर प्रयुक्त एस डी एच उपकरण से अलग हो सकते हैं। इसके मद्देनजर कीमत कटौती के निर्धारण के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा विक्रीत अत्यधिक समान उत्पाद के प्रकार पर विचार किया है और उसकी तुलना आयातित उत्पाद के प्रकार के साथ की है। जहां कहीं कोई समनुरूपी मॉडल नहीं मिला है, वहां प्राधिकारी ने यह सुनिश्चित करने के लिए आयातित उत्पाद की तुलना में कम रूपांतरण वाले मॉडल पर विचार किया है ताकि कीमत कटौती को अधिक न दिखाया जा सके। निर्यातित अलग-अलग पी सी एन के लिए कीमत कटौती का निर्धारण करने के बाद प्राधिकारी ने संबद्ध मात्रा पर विचार करने के बाद प्रतिवादी निर्यातिक के लिए भारित औसत कीमत कटौती निर्धारित की है। यह देखा गया है कि कीमत कटौती मार्जिन काफी अधिक है।

133. इस संबंध में प्राधिकारी ने प्रत्येक मॉडल (पी सी एन) के लिए अलग से कीमत कटौती की जांच की है। जहां कहीं घरेलू उद्योग ने समनुरूपी मॉडल प्रस्तुत नहीं किया है, वहां प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत तुलनीय कम मॉडल पर विचार किया है। यह देखा गया है कि प्रतिवादी निर्यातिकों के लिए आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत उसी उपकरण की बिक्री कीमत से काफी अधिक है, जिसके परिणामस्वरूप कीमत में पर्याप्त कटौती हुई है। वस्तुतः जहां कहीं घरेलू उद्योग ने समनुरूपी मॉडल प्रस्तुत नहीं किया है और तुलना अपेक्षाकृत कम मॉडल के साथ की गई है, वहां यह देखा गया है कि आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम रही है। यद्यपि घरेलू उद्योग ने यह तर्क दिया है कि इन मामलों में बिक्री कीमत में उर्ध्वगामी समायोजन किया जाना चाहिए तथापि, यह देखा गया है कि ऐसे किसी समायोजन के बिना कीमत कटौती का मात्रा अधिक रही है।

134. याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि व्यापार जारी रखने के लिए उसे अपनी कीमत को कम करने के लिए बाध्य होना पड़ा है। परणामतः घरेलू उद्योग अपनी कीमतों को संबद्ध

निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत कम एवं पाटित कीमतों के मद्देनजर न्यायोचित स्तर से भी अधिक स्तर तक धीरे-धीरे कम किया है। याचिकाकर्ता ने यह भी दावा किया है कि परवर्ती ऑर्डरों में उसी उपकरण की आपूर्ति हेतु विदेशी उत्पादकों द्वारा प्रस्तुत कीमतें विगत में प्रस्तुत कीमतों से काफी कम रही हैं। दूसरे शब्दों में समान उपकरणों की आपूर्ति हेतु प्रत्येक परवर्ती कीमत का प्रस्ताव काफी कम कीमत का रहा है। याचिकाकर्ता ने आगे यह तर्क दिया है कि जहां कहीं याचिकाकर्ता ने समान उपकरण के लिए अपने ग्राहकों को प्रत्येक उत्तरवर्ती वर्ष में कम कीमत की पेशकश करने की स्वतः परंपरा अपनाई जाती है, वहां विदेशी उत्पादकों द्वारा प्रस्तावित कीमत में कमी काफी अधिक और तीव्र होती है। बाजार के लघु आकार को देखते हुए (आपूर्तिकर्ताओं की सीमित और ज्ञात संख्या है) याचिकाकर्ता ने आगे यह दावा किया है कि प्रत्येक आपूर्तिकर्ता एवं उपभोक्ता के कार्यकलापों पर सभी संबंधितों द्वारा नजर रखी जानी चाहिए। अतः विदेशी उत्पादकों द्वारा प्रस्तुत कम कीमतों के परिणामस्वरूप न केवल व्यापार में घाटा हुआ है, अपितु उसका घरेलू उद्योग के समस्त परवर्ती प्रस्तावों पर बैंच मार्किंग प्रभाव पड़ा है। इस प्रकार व्यापार में हुए ऐसे घाटे से घरेलू उद्योग को हुई क्षति को एकमात्र इस दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए जहां घरेलू उद्योग को बिक्री का नुकसान हुआ है और उसे ऐसे अन्य कारणों से देखा जाना चाहिए जहां घरेलू उद्योग पाटन से बचने के लिए कीमत कम करने के लिए बाध्य हुआ है।

135. यह निर्धारण करने के लिए कि क्या विचाराधीन उत्पादों के आयातों से विचाराधीन उत्पाद की कीमत का ह्रास या न्यूनीकरण हुआ है, प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग की बिक्री लागत एवं बिक्री मात्रा के रुद्धानां पर विचार किया है। संगत सूचना निम्नलिखित तालिका में दी गई है :

लाख रुपए	2005-06	2006-07	2007-08	अप्रैल-दिसं. 08 - वार्षिकीकृत	अप्रैल-दिसं. 08
बिक्री की लागत	***	***	***	***	***
सूचीबद्ध	100	144	171	294	220
विगत वर्ष की तुलना में वृद्धि		***	***	***	
बिक्री मात्रा	***	***	***	***	***
सूचीबद्ध	100	139	172	234	
विगत वर्ष की तुलना में वृद्धि		***	***	***	

136. यह देखा जाता है कि वर्ष 2006-07 में बिक्री लागत में वृद्धि बिक्री राजस्व में हुई वृद्धि से अधिक रही थी। तत्पश्चात वर्ष 2007-08 में बिक्री लागत में वृद्धि बिक्री राजस्व में हुई वृद्धि से कुछ कम रही थी। तथापि, जांच अवधि में (वार्षिकीकृत) बिक्री राजस्व में वृद्धि बिक्री लागत में हुई वृद्धि से काफी कम रही थी। यद्यपि वर्ष 2007-08 की तुलना में जांच अवधि के दौरान बिक्री राजस्व में केवल 36% की वृद्धि हुई तथापि इस अवधि में बिक्री लागत में 72% की वृद्धि हुई। समग्र आधार पर जहां बिक्री लागत में \*\*\* करोड़ रु. की वृद्धि हुई,

वहीं बिक्री राजस्व में केवल \*\*\* करोड़ रु. की वृद्धि हुई । इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि आयातों के कारण बाजार में घरेलू उद्योग की कीमत का हास/न्यूनीकरण हो रहा था ।

### घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंड

137. नियमावली के अनुबंध-II में यह अपेक्षित है कि क्षति के निर्धारण में ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव की तथ्यपरक जांच शामिल होगी । जहां तक ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव का संबंध है, नियमों में आगे यह उपबंध है, कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में समस्त संगत कारकों और बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्से, उत्पादकता, निवेश पर आय अथवा क्षमता उपयोग में वास्तविक तथा संभावित गिरावट : घरेलू कीमतों, पाटन मार्जिन की मात्रा को प्रभावित करने वाले कारकों; नकद प्रवाह, माल सूची, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि, पूँजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक एवं संभावित नकारात्मक प्रभावों सहित उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले संकेतकों का तथ्यपरक एवं निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होना चाहिए । याचिकाकर्ता ने अनुरोध किया है कि घरेलू उद्योग के निष्पादन के मूल्यांकन से यह पता चलेगा कि घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है । इसके अलावा, नीचे की गई विस्तारित चर्चा के अनुसार वर्तमान स्थिति जारी रहने पर घरेलू उद्योग के समक्ष वास्तविक क्षति होने का खतरा उत्पन्न हो गया है ।

### क्षमता एवं क्षमता उपयोग:

138. याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि इस उद्योग में प्रमुख उत्पादन उत्पाद की डिजाइन एवं विकास के रूप में होता है । विनिर्माण की वास्तविक प्रक्रिया और उसका विस्तार जरूरत के अनुसार परिसर के भीतर या उसके बाहर स्थित हो सकती है । याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि वह संयंत्र एवं मशीनरी में कोई वृद्धि किए बिना समूची भारतीय मांग की पूर्ति कर सकता है । फिर भी इस उद्योग में उत्पादक इलेक्ट्रोनिक विनिर्माण सेवा भागीदारों की क्षमताओं का लाभ उठाते हैं जिन्हें बाद में भारत की अगले 10 वर्षों की जरूरत को पूरा करने के लिए पर्याप्त क्षमताएं हासिल हो जाती हैं । दूसरे शब्दों में क्षमता एवं क्षमता उपयोग को बैद्धिक संपदा तथा आवश्यक डिजाइन एवं विकास कार्य करने एवं वैश्विक आपूर्ति शृंखला का प्रबंधन करने के लिए योग्य कार्मिकों की तैनाती हेतु कंपनी की क्षमता के संदर्भ में देखा जाना चाहिए । इस कारण याचिकाकर्ता के पास भारतीय मांग को पूरा करने की पर्याप्त क्षमता है । इसके मद्देनजर याचिकाकर्ता ने यह दावा किया है कि क्षमता एवं क्षमता उपयोग को वर्तमान मामले में असंगत मापदंड माना जाए ।

139. याचिकाकर्ता ने यह भी दावा किया है कि किसी भी हितबद्ध पार्टी ने इस बात का खंडन नहीं किया है कि जहां तक उत्पादकों द्वारा वैश्विक रूप से मूल अनुसंधान, डिजाइन एवं विकास पर उत्तरोत्तर ध्यान केन्द्रित करने का संबंध है, विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन अत्यंत खास किस्म का है । इसके अलावा, याचिकाकर्ता ने यह दावा किया है कि उत्पादन करने की क्षमता वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में कोई उचित मापदंड नहीं है क्योंकि

विनिर्माता कारकों की संख्या के अनुसार उत्पादन के आंशिक कार्यकलाप बाहर से कराने का निर्णय लेते हैं। प्राधिकारी यह मानते हैं कि याचिकाकर्ता का यह दावा सही है।

### उत्पादन तथा बिक्री मात्रा

140. घरेलू उद्योग के उत्पादन और बिक्री मात्रा में निम्नानुसार घट-बढ़ रही है:

	2005-06	2006-07	2007-08	अप्रैल-दिसं. 08 - वार्षिकीकृत	अप्रैल-दिसं. 08	2005-06 की तुलना में जांच अवधि वार्षिकीकृत
घरेलू उत्पादन (नग)	***	***	***	***	***	***
सूचीबद्ध	100	203	117	175	175	
घरेलू बिक्री (नग)	***	***	***	***	***	***
	100	203	117	175	175	

141. यह देखा जाता है कि क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बिक्री और परिणामी उत्पादन में वृद्धि की प्रवृत्ति प्रदर्शित होती है। याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि यह तीन कारकों की नैसर्गिक परिणति रही थी - (क) याचिकाकर्ता ने अपने नए एस टी एम-1, एस टी एम-4, एस टी एम-16 उत्पादों का उत्पादन एवं बिक्री शुरू की जिससे उसके उत्पादों की रेज बढ़ गई (ख) याचिकाकर्ता ने उच्च प्रौद्योगिकी और समर्थन के कारण अतिरिक्त मात्रा हासिल की है जिसकी भारतीय ग्राहकों ने प्रशंसा की है। (ग) भारत में दूर संचार उपकरणों के बाजार में अभूतपूर्व वृद्धि देखी गई है- जिसका श्रेय दूरसंचार के क्षेत्र में हुई वृद्धि और दूरसंचार क्षेत्र में प्रौद्योगिकी विकास को जाता है। याचिकाकर्ता द्वारा अपनी क्षमताएं एवं कारोबार योजना तैयार करते समय उसके द्वारा परिकल्पित सीमा से अधिक रहा था और इसमें सहायता प्रदान करने के लिए कंपनी में समय-समय पर अतिरिक्त निवेश किए गए थे। वस्तुतः याचिकाकर्ता ने अधिक उच्च स्तर पर प्रचालन की परिकल्पना की थी जो स्तर अब तक प्राप्त हो सका था। याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि वस्तुतः उसका उत्पादन स्तर अब तक सबसे कम रहा है। कम निष्पादन का कारण चीन/इजराइल के आपूर्तिकर्ताओं द्वारा कीमत में पर्याप्त कमी और परिणामतः आयात मात्रा में भारी वृद्धि का रहा है।

142. उत्पादन एवं बिक्री में वृद्धि तथा याचिकाकर्ता के दावों को ध्यान में रखते हुए उत्पादन में वृद्धि की तुलना मांग में वृद्धि के साथ की गई थी। यह देखा गया था कि यद्यपि घरेलू उद्योग के उत्पादन में क्षति अवधि के दौरान वृद्धि हुई है तथापि, विचाराधीन उत्पाद की मांग में वृद्धि उत्पादन में हुई वृद्धि से काफी अधिक रही थी। घरेलू उद्योग ने आरोप लगाया है कि आयातों ने बाजार के पर्याप्त अवसरों पर कब्जा कर लिया है जो घरेलू उद्योग के पास उपलब्ध थे। इस प्रकार प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटन के कारण घरेलू उद्योग के उत्पादन में

५०८७६७१०-१३८

नुकसान हुआ है और घरेलू उद्योग उस सीमा तक उत्पादन को बढ़ाने से वंचित हुआ है, जिसे वह पाटन के अभाव में बढ़ा सकता था ।

### बाजार हिस्सा:

143. याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि इस तथ्य के बावजूद याचिकाकर्ता भारत की सर्वप्रथम ऑप्टिकल नेटवर्किंग उत्पाद कंपनी है, जिसके पास नवीन एवं सृजनकारी पर्याप्त बौद्धिक संपदा है, घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में वृद्धि नहीं हुई है । वस्तुतः इसमें गिरावट आई है । यद्यपि अपने रेंज को बढ़ाकर नए उत्पादों की शुरूआत करके याचिकाकर्ता ने अपना बाजार हिस्सा बढ़ाने की आशा की थी, तथापि बाजार में पाटित आयातों की मौजूदगी के कारण इन वर्षों में याचिकाकर्ता के बाजार हिस्से में गिरावट आई है । घरेलू प्रचालनों के संबंध में घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से का निर्धारण किया गया था । सत्यापित सूचना से निम्नानुसार पता चलता है:

	2005-06	2006-07	2007-08	अप्रैल-दिसं. 08 - वार्षिकीकृत	अप्रैल-दिसं. 08
<b>मांग/ भारत में खपत</b>					
मात्रा	51,308	0	81,186	94,027	70,520
मूल्य लाख रुपए में	50,461	79,829	117,574	132,083	99,062
<b>घरेलू उद्योग की बिक्री</b>					
मात्रा	***	***	***	***	***
सूचीबद्ध	100	203	117	175	131
मूल्य लाख रुपए	***	***	***	***	***
सूचीबद्ध	100	138	172	233	175
<b>घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा</b>					
मात्रा	***	***	***	***	***
सूचीबद्ध	100	88	74	96	96
मूल्य	**	***	***	***	***
सूचीबद्ध	100	87	74	89	89

144. यह देखा जाता है कि आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि के दौरान मात्रा और मूल्य दोनों रूपों में घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में गिरावट आई है ।

### कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक:

145. जैसा कि पूर्व में उल्लेख किया गया है, विदेशी उत्पादकों द्वारा प्रस्तुत की जा रही आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से काफी कम है । आयातित उत्पाद

की कीमत और घरेलू उद्योग की कीमत के बीच पर्याप्त अंतर होने के कारण उपभोक्ताओं ने अपनी मांग के एक भाग की पूर्ति आयातित उत्पाद से करनी शुरू कर दी है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग उन्हीं ग्राहकों को परवर्ती आपूर्तियों में न केवल अपनी कीमत कम करने के लिए बाध्य हुआ है, अपितु बाजार में अन्य ग्राहकों को की गई आपूर्तियों की कीमत में भी कमी की है।

146. घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि चीन के आपूर्तिकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत कीमत में नाटकीय ढंग से गिरावट आई है। विदेशी आपूर्तिकर्ताओं से मिल रही सतत प्रतिस्पर्धा और व्यापार घाटे के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग द्वारा उत्तरवर्ती प्रत्येक प्रस्ताव में अपनी कीमत कम की जा रही है। अतः आयातों का भारतीय बाजार में स्पष्ट तौर पर अत्यंत कीमत हासकारी प्रभाव पड़ा है।

### लाभ/हानि

147. याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि घरेलू बाजार में विचाराधीन उत्पाद की बिक्री और उसके उत्पादन से घरेलू उद्योग द्वारा अर्जित लाभ में क्षति अवधि के दौरान गिरावट आई है। इन वर्षों में लाभ में आई गिरावट इतनी अधिक रही है कि याचिकाकर्ता को अपने घरेलू व्यापार में जांच अवधि के दौरान वित्तीय घाटा हुआ है।

148. अपने घरेलू प्रचालनों के संबंध में घरेलू उद्योग की लाभ/हानि का निर्धारण किया गया था। सत्यापित सूचना से निम्नानुसार पता चलता है। :

	2005-06	2006-07	2007-08	अप्रैल-दिसं. 08 - वार्षिकीकृत	अप्रैल-दिसं. 08
लाभ/हानि/लाख रुपए					
घरेलू	(***)	(***)	(***)	(***)	(***)
सूचीबद्ध	(100)	(207)	(162)	(964)	(723)
वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार	(***)	***	***	(***)	(**)
सूचीबद्ध	(100)	64	165	(14)	(11)
बिक्री मूल्य रु./ लाख					
घरेलू	***	***	***	***	***
सूचीबद्ध	100	138	172	233	175
वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार	***	***	***	***	***
सूचीबद्ध	100	187	302	352	264
बिक्री के % के रूप में लाभ/हानि					
घरेलू	(***)	(***)	(***)	(***)	(***)
सूचीबद्ध	(100)	(149)	(94)	(412)	(412)
वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार	(***%)	***%	***%	(***%)	(***%)
सूचीबद्ध	(100)	34	55	(4)	(4)

149. यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग का बिक्री राजस्व बिक्री लागत से लगातार कम रहा है। इसके परिणामस्वरूप घरेलू प्रचालनों के संबंध में वित्तीय घाटा हुआ है। इसके अलावा, बिक्री राजस्व के प्रतिशत के रूप में घाटा वर्ष 2005-06 में 9.12% से अत्यधिक बढ़कर जांच अवधि में 37.58% हो गया है। इस प्रकार यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग को पर्याप्त वित्तीय घाटा हो रहा था, जिसमें क्षति अवधि के दौरान और अधिक इजाफा हुआ है।

150. चूंकि याचिकाकर्ता के पर्याप्त निर्यात कार्यकलाप हैं, इसलिए वर्ष 2007-08 तक घरेलू तथा निर्यात में संयुक्त प्रचालनों में उसका लाभ सकारात्मक बना रहा। तथापि, घरेलू लाभप्रदता में अत्यधिक गिरावट की परिणति जांच अवधि में कंपनी की समग्र लाभप्रदता में गिरावट के यथ में हुई। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि उसके निर्यात लाभ से इस समय घरेलू घाटे की भरपाई की जा रही है। याचिकाकर्ता ने आगे दावा किया है कि इस आधार पर आगे कोई कंपनी अधिक समय तक प्रचालन नहीं कर सकती। पाटन से घरेलू उद्योग के लिए अत्यंत प्रतिकूल स्थिति उत्पन्न हो गई है।

### निवेश पर आय

151. चूंकि संबद्ध वरतु के उत्पादन में मूल निवेश डिजाइन एवं विकास तथा कुशल/योग्य जनशक्ति के संबंध में भौतिक संपदा में किया जाता है, इसलिए याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि लगाई गई पूँजी पर आय के % के रूप में व्यक्त निवेश पर आय से उस उचित आय का पर्याप्त पता नहीं चलेगा, जितना यह उद्योग आशा करता है। उद्योग ने वैश्विक रूप से सकल मार्जिन के संबंध में लाभप्रदता पर विचार किया है तथा भारत में घरेलू उत्पादकों का सकल मार्जिन उनके वैश्विक प्रतिस्पर्धियों के सकल मार्जिन से काफी कम रहा है।

152. लगाई गई पूँजी पर आय का निर्धारण घरेलू प्रचालनों के संबंध में किया गया है, जो निम्नानुसार है:

रु./लाख	2005-06	2006-07	2007-08	अप्रैल-दिसं. 08
लगाई गई पूँजी - समग्र कंपनी				
निवल स्थायी परिसंपत्ति	***	***	***	***
सूचीबद्ध	100	180	497	346
कार्यशील पूँजी	***	***	***	***
सूचीबद्ध	100	161	249	336
लगाई गई पूँजी	***	***	***	***
सूचीबद्ध	100	162	262	318
ब्याज एवं कर पूर्व लाभ	(***)	***	***	***
सूचीबद्ध	(100)	132	285	55
लगाई गई पूँजी पर आय - %	(***)	***	***	***
सूचीबद्ध	(100)	82	109	16
लगाई गई पूँजी - पी यू सी घरेलू	***	***	***	***

सूचीबद्ध	100	120	149	224
ब्याज एवं कर पूर्व लाभ - पी यू सी घरेलू	(***)	(***)	(***)	(***)
सूचीबद्ध	(100)	(179)	(60)	(910)
लगाई गई पूंजी पर आय - %	(***)	(***)	(***)	(***)
सूचीबद्ध	(100)	(149)	(40)	(406)

153. लगाई गई पूंजी पर आय में प्रवृत्ति के विश्लेषण से यह पता चलता है कि जहां तक घरेलू प्रचालनों का संबंध है, समूची क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग लाभ नहीं कमा सका है। लगाई गई पूंजी पर नकारात्मक आय जोक वर्ष 2005-06 में 100 थी, जांच अवधि में और बढ़कर 400 से अधिक हो गई। समग्र कंपनी के लिए आधार वर्ष में घरेलू उद्योग ने घाटा उठाया है। तथापि, वर्ष 2006-07 एवं 2007-08 के दौरान कंपनी ने लाभ कमाया परंतु जांच अवधि के दौरान लगाई गई पूंजी पर आय में पर्याप्त गिरावट आई जो 2% से भी कम हो गई। निर्यात सहित समस्त प्रचालनों पर कंपनी ने निर्यात प्रचालनों के कारण मुख्य रूप से कुछ लाभ कमाया। इन प्रवृत्तियों से स्पष्टतः यह पता चलता है कि घरेलू उद्योग की लाभप्रदता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

### नकद प्रवाह/लाभ

154. याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि चूंकि घरेलू उद्योग के पर्याप्त घरेलू एवं निर्यात प्रचालन हैं, इसलिए घरेलू उद्योग के नकद प्रवाह की स्थिति से नकद प्रवाह पर पाटन के प्रभाव का पूर्ण रूप से पता नहीं चलता है। अतः घरेलू उद्योग के नकद प्रवाह की स्थिति का निर्धारण कर एवं मूल्यहास से पूर्व लाभ पर विचार करने के बाद किया गया है। यदि देखा जाता है कि घरेलू उद्योग का समूची क्षति अवधि के दौरान नकद प्रवाह ऋणात्मक रहा था। इसके अलावा, जांच अवधि में नकद घाटे में पर्याप्त वृद्धि हुई है।

	2005-06	2006-07	2007-08	जांच अवधि
नकद लाभ - पी यू सी घरेलू	(***)	(***)	(***)	(***)
सूचीबद्ध	(100)	(211)	(158)	(688)

### मालसूची: -

155. याचिकाकर्ता ने दावा किया कि विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन विस्तृत विनिर्देशनों पर आधारित पुष्टिकृत आर्डर लेने के बाद ही किया जाता है और वस्तु को माल सूची में नहीं रखा जाता है। प्राधिकारी यह मानते हैं कि मालसूची घरेलू उद्योग को हुई क्षति दर्शाने वाला मापदंड नहीं है।

4087 40/10-13B

## रोजगार तथा मजदूरी

156. याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि प्रमुख निवेशों में से एक निवेश अनुसंधान एवं विकास के संबंध में बौद्धिक संपदा के विकास में किया जाता है। पूर्व में किए गए उल्लेख के अनुसार याचिकाकर्ता ने देश में अभूतपूर्व दूरसंचार वृद्धि के कारण पर्याप्त बाजारी अवसरों की आशा की थी। इसके अलावा, घरेलू उद्योग अपनी वैश्विक उपस्थिति में सुधार कर रहा है जिसके लिए भी गहन अनुसंधान एवं विकास कार्यकलापों की जरूरत है। इन सबके लिए जनशक्ति में निवेश अपेक्षित होता है। परिणामतः लगाई गई जनशक्ति और घरेलू उद्योग द्वारा संदर्भ परिणामी मजदूरी में इन वर्षों के दौरान वृद्धि हुई है, जैसा कि निम्नलिखित तालिका से देखा जाएगा :

क्र. सं.		2005-06	2006-07	2007-08	अप्रैल-दिसं. 08
1	कर्मचारियों की संख्या				
(क)	अनुसंधान तथा विकास	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	151	247	324
(ख)	अन्य सभी कार्यकलाप	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	139	178	211
(ग)	सकल रोजगार	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	145	215	272
2	मजदूरी				
(क)	अनुसंधान तथा विकास (रु./लाख)	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	181	281	226
(ख)	अन्य सभी कार्यकलाप (रु./लाख)	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	166	271	260
(ग)	सकल रोजगार (रु./लाख)	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	174	276	242

157. याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि रोजगार में कभी करना संभव नहीं है क्योंकि ऐसे किसी प्रयास का तात्पर्य घरेलू उद्योग की स्थायी गिरावट की प्रक्रिया से लगाया जाएगा। विदेशी उत्पादकों की मंशा बिल्कुल साफ है अर्थात् इस प्रमुख उत्पाद खंड में भारतीय उद्योग को समाप्त करना। याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि इस देश में विचाराधीन उत्पाद का उन्होंने विकास किया था और भारत इस उच्च प्रौद्योगिकी वाले उत्पाद की क्षमता और सामर्थ्य रखने वाले विश्व के कुछ चुनिंदा देशों में शामिल हो गया था। भारत में दूरसंचार वृद्धि के कारण विचाराधीन उत्पाद की मांग में भारी वृद्धि हुई है। भारतीय उत्पादक की समाप्ति से न केवल भारत में विदेशी उत्पादकों के लिए भारी बाजार अवसर उपलब्ध होंगे, अपितु विश्व बाजार में उनके लिए प्रतिस्पर्धा भी समाप्त हो जाएगी। अतः वर्तमान पाठन का रोजगार एवं मजदूरी पर अत्यंत प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है क्योंकि भारत मूल्य श्रृंखला में आगे

बढ़ने और प्रौद्योगिकीविदों के सुविज्ञ पूल का सृजन करने का प्रयास कर रहा है जो उच्च मूल्य, बौद्धिक संपदा एवं उत्पादों का उत्पादन कर सकते हैं।

158. याचिकाकर्ता ने आगे दावा किया है कि चीन की सरकार द्वारा अनेक तरीकों से दूरसंचार उपकरण विनिर्माण उद्योग की सहायता की जा रही है जिसमें भारी मात्रा में सुलभ ऋण भी शामिल हैं।

#### उत्पादकता:

159. घरेलू उद्योग की उत्पादकता का आकलन नगों के रूप में व्यक्त प्रति कर्मचारी उत्पादन तथा उत्पादित एस डी एच उपकरणों के मूल्य के संबंध में किया गया है।

क्र.सं.		2005-06	2006-07	2007-08	अप्रैल- दिसं.08
1	प्रति कर्मचारी उत्पादन				
(क)	उपकरणों की संख्या - घरेलू उद्योग	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	140	54	48
(ख)	उपकरणों का मूल्य - घरेलू उद्योग (लाख रुपए)	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	97	81	66

160. यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग की उत्पादकता में सुधार हुआ है। तथापि, उत्पादकता में सुधार के बावजूद कीमत मापदंडों में पर्याप्त गिरावट आई है।

#### निधियों को जुटाने की क्षमता:

161. याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि संयंत्र एवं मशीनरी में निवेश वर्तमान मामले में कोई निर्णायक कारक नहीं है। वस्तुतः इस उद्योग में निधियों की जरूरत नियत परिसंपत्तियों के बजाए कार्यशील पूँजी के कारण अधिक होती है। अतः निधियां जुटाने में इस उद्योग की क्षमता पर घरेलू उद्योग के वर्तमान स्तर की लाभप्रदता के साथ गंभीर प्रभाव पड़ सकता है।

#### क्षति का निर्धारण

162. विभिन्न हितबद्ध पार्टियों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना और की गई जांच को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि सबद्ध आयातों में समग्र रूप में (मात्रा और मूल्य दोनों रूप में) और भारत में उत्पादन तथा खपत की तुलना में वृद्धि हुई है। क्षति अवधि के दौरान आयात कीमत में पर्याप्त गिरावट आई है। आयातों से बाजार में घरेलू उद्योग की कीमत में अत्यधिक कटौती हो रही है। आयातों से बाजार में विचाराधीन उत्पाद की कीमत में

हास हो रहा है। लाभ, बाजार हिस्से तथा निवेश पर आय, नकद प्रवाह, एवं वृद्धि के संबंध में घरेलू उद्योग के निष्पादन में गिरावट आई है। यद्यपि क्षति अवधि के दौरान उत्पादन एवं बिक्री मात्रा में वृद्धि हुई है, तथापि बाजार में अपने उत्पाद की बिक्री करने में घरेलू उद्योग ने व्यापार के पर्याप्त अवसर गंवाए हैं। प्राधिकारी ने क्षमता उपयोग और माल सूची को घरेलू उद्योग को हुई क्षति का संकेतक नहीं माना है। लाभ, निवेश पर आय एवं नकद प्रवाह में गिरावट निर्यात मोर्चा पर निष्पादन में पर्याप्त सुधार आने के कारण आई है। रोजगार, उत्पादकता और मजदूरी में सुधार हुआ है। तथापि, इनमें हुए सुधार से अन्य मापदंडों में गिरावट कम प्रदर्शित हुई है। वर्तमान अवधि के दौरान निष्पादन में आई गिरावट काफी अधिक और वास्तविक रही है।

#### कारणात्मक संबंध और अन्य कारकों का विश्लेषण

163. वास्तविक क्षति की मौजूदगी तथा कीमत कटौती, कम कीमत पर बिक्री एवं कीमत हासकारी तथा न्यूनकारी प्रभावों के संबंध में घरेलू उद्योग की कीमतों पर पाटित आयातों की मात्रा एवं मूल्य संबंधी प्रभावों की जांच करने के बाद प्राधिकारी ने इस बात की भी जांच की है कि क्या भारतीय नियमों एवं पाटनरोधी करार में सूचीबद्ध अन्य सांकेतिक मापदंडों से घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती है। अतः निम्नलिखित मापदंडों की जांच की गई है।

- क) तीसरे देशों से आयात :- जो देश जांचाधीन नहीं है उन देशों से हुए आयात या तो नगण्य हैं, या फिर उनकी कीमत संबद्ध देशों से हुए आयात की कीमत से अधिक है और इसलिए इनका घरेलू उद्योग की कीमत पर प्रभाव नहीं पड़ता है;
- ख) मांग में कमी :- क्षति जांच अवधि के दौरान संबद्ध वस्तु की मांग में पर्याप्त वृद्धि हुई है। अतः मांग में संभावित कमी को घरेलू उद्योग को हुई क्षति का कारण नहीं माना जा सकता।
- ग) खपत की पद्धति: - किसी भी हितबद्ध पार्टी ने खपत की पद्धति में किसी खास परिवर्तन का आरोप नहीं लगाया है।
- घ) प्रतिस्पर्धा की स्थितियां: - यह वस्तु मुक्त रूप से आयात योग्य है। आवेदक संबद्ध वरतु का प्रमुख उत्पादक है और वह घरेलू उत्पादन के लगभग 100% का उत्पादन करता है। अतः घरेलू प्रतिस्पर्धा को घरेलू उद्योग को हुई क्षति का कारण नहीं माना जा सकता। प्राधिकारी की जानकारी में प्रतिस्पर्धा की स्थितियों या व्यापार प्रतिवधात्मक व्यवहारों का कोई अन्य साक्ष्य नहीं लाया गया है।
- ङ) प्रायोगिकी विकास: - प्रायोगिकी में खास परिवर्तन का कोई आरोप नहीं लगाया गया है जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती है।
- च) घरेलू उद्योग का निर्यात निष्पादन: - रिकॉर्ड में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है, जिससे यह पता चल सके कि घरेलू उद्योग के निर्यातों का उसके निष्पादन पर कोई प्रभाव पड़ा है।
- छ) उत्पादकता: - कुल उत्पादन के संबंध में घरेलू उद्योग की उत्पादकता में सुधार हुआ है। अतः इसे घरेलू उद्योग को हुई क्षति का कारण नहीं माना जा सकता।

164. उपर्युक्तानुसार कारणेतर विश्लेषण से यह पता चलता है कि पाटित आयातों से इतर किसी अन्य कारक का घरेलू उद्योग पर प्रभाव नहीं पड़ा है।

### कारणात्मक संबंध को स्थापित करने वाले कारक

165. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के निष्पादन के विश्लेषण से यह पता चलता है कि संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग के निष्पादन में वार्स्तविक गिरावट आई है। अतः निम्नलिखित आधारों पर पाटित आयातों तथा घरेलू उद्योग को हुई क्षति के बीच कारणात्मक संबंध की पुष्टि होती है :

- क. संबद्ध देशों से पाटित आयातों की कीमत और परिणामतः आयातों की पहुंच कीमत में तेजी से गिरावट आई है जिससे कीमत में अत्यधिक कटौती हुई है। इसके प्रत्यक्ष परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग कीमत में कमी किए जाने का कंपनी के लाभ, नकद प्रवाह तथा निवेश पर आय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।
- ख. घरेलू उद्योग द्वारा बिक्री कीमत में कमी किए जाने का कंपनी के लाभ, नकद प्रवाह तथा निवेश पर आय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।
- ग. यद्यपि, घरेलू उद्योग ने आयात कीमत में गिरावट का मुकाबला किया है, तथापि अत्यधिक सकारात्मक कटौती के कारण संबद्ध देशों से आयातों के बाजार हिस्से में वृद्धि हुई है। इसके प्रत्यक्ष परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में गिरावट आई है।
- घ. मांग में वृद्धि और घरेलू उद्योग द्वारा बिक्री कीमत में कमी के बावजूद आयातों की पहुंच कीमत में अत्यधिक कमी के कारण घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में गिरावट आई है। इससे घरेलू उद्योग की वृद्धि अवरुद्ध हुई है।
- ड. विदेशी उत्पादकों द्वारा प्रस्तावित अत्यंत कम कीमतों से घरेलू उद्योग अपने उत्पादन और बिक्री को उस स्तर तक बढ़ाने से वंचित हुआ है, जिस स्तर तक वह पाठन के अभाव में बढ़ा सकता था।

166. प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि घरेलू उद्योग को वार्स्तविक क्षति हुई है और यह क्षति संबद्ध देशों/क्षेत्रों से हुए पाटित आयातों के कारण हुई है।

### क्षति की मात्रा और क्षति मार्जिन

167. प्राधिकारी द्वारा निर्धारित क्षति रहित कीमत की तुलना क्षति मार्जिन के निर्धारण हेतु निर्यातों के पहुंच मूल्य के साथ की गई है। यह तुलना भारत में आयातित मॉडल की क्षति रहित कीमत के निर्धारण द्वारा की गई है। आयातित प्रत्येक मॉडल के लिए अलग-अलग तुलना की गई है और क्षति मार्जिन निर्धारित किया गया है। तत्पश्चात संबद्ध आयात मात्र पर विचार करने के बाद भारित औसत क्षति मार्जिन निर्धारित किया गया है। क्षति मार्जिन की गणना निमानुसार की गई है:

देश	निर्यातक	क्षति मार्जिन रूपरेप्रति नग	क्षति मार्जिन %
चीन जन.गण.	मै. फाइबर होम टेलीकम्प्यूनिकेशन टेक्नोलॉजीज लि.	***	280-290%
	एल्काटेल-लुसेंट शंघाई बेल कंपनी लि.	***	40-50%
	मै. हैंगजाऊ ई सी आई टेलकॉम. कंपनी लि.	***	110-120%
	मै. जैडटीई कार्पोरेशन		30-40%
इंडिया	मै. ई सी आई टेलकॉम. लि., इंडिया	***	2-10%
शेष चीन जन.गण.			280-290%
शेष इंडिया			65-75%

---

## प्रकटीकरण विवरण के बारे में विभिन्न हिंतबद्ध पक्षकारों से प्राप्त टिप्पणियाँ

---

### घरेलू उद्योग

168. प्रकटीकरण विवरण के बारे में घरेलू उद्योग ने अपने उत्तर में निम्नानुसार निवेदन किया है:-

- (i) प्राधिकारी द्वारा उद्गम तथा भारतीय उत्पाद चीन के उत्पाद एवं तीसरे देश के उत्पाद का अर्थ निर्दिष्ट किया जाना चाहिए;
- (ii) ईएमएस का उपयोग “ जॉब वर्क ” में शामिल है, जो कानून के अंतर्गत अनुमत्य है । दरअसल लागत खण्ड में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अथवा कराए गए जॉब वर्क का व्यौरा दिया जाना अपेक्षित है । ईएमएस द्वारा उत्पादन कार्यकलाप उत्पादन में शामिल नहीं है;
- (iii) तेजस ने मलेशिया में किसी ईएमएस कंपनी का उपयोग नहीं किया है;
- (iv) याचिकाकर्ता को वर्तमान याचिका प्रस्तुत करने एवं बनाए रखने का अधिकार है;
- (v) प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा प्रकटीकरण विवरण के बारे में की गई प्रारंभिक टिप्पणियों के आधार पर क्षतिरहित कीमत का पुनःनिर्धारण किया है । पुनःनिर्धारित क्षतिरहित कीमत को घरेलू उद्योग के समक्ष प्रकट किया जाए;
- (vi) घरेलू उद्योग ने आयात से संबंधित कुछ आंकड़े उपलब्ध कराए हैं और दावा किया है कि ईसीआई तथा जैडटीई ने सभी निर्यात सौदों का सही विवरण प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया है;
- (vii) सॉफ्टवेयर, तकनीकी जानकारी तथा लाभ जैसे विषयों पर भी शुल्क संरक्षित किया जाना चाहिए क्योंकि ये उत्पाद के अंतर्गत आते हैं;
- (viii) शुल्क केवल यथामूल्य आधार पर संस्तुत किया जाए ।

### प्राधिकारी द्वारा जाँच

169. प्राधिकारी यह अभिमत व्यक्त करना चाहते हैं कि तेजस घरेलू उद्योग है और आज की तारीख में आई पी आर मुद्दे के संदर्भ में बिना, नियमावली के दायरे के भीतर इसे आवश्यक अधिकार प्राप्त है, क्योंकि तेजस एकमात्र विनिर्माता हैं, जिन्होंने प्राधिकारी को निर्धारित तरीके से आंकड़े उपलब्ध कराए हैं । तेजस एकमात्र विनिर्माता है जिन्होंने प्राधिकारी को निर्धारित तरीके से आंकड़े उपलब्ध कराए हैं । वी एम सी एल तथा पृथ्वी ने घरेलू उत्पादक होने का दावा किया था, जिनमें से एक ने अगस्त, 2010 में जांच के अंतिम चरण के दौरान यह लिखित में स्वीकार किया था कि वह डी डब्ल्यू डी एम का विनिर्माता है जो विचाराधीन उत्पाद के दायरे में शामिल नहीं है और अन्य दावेदार को प्रतिवादी निर्यातक के परिसर में किए गए सत्यापन के दौरान इस उपकरण का आयातक पाया गया था, अतः इसे नियम 2 (ख) के दायरे के अंतर्गत घरेलू उद्योग माने जाने की पात्रता नहीं है । इसके अलावा दोनों में से किसी ने भी प्राधिकारी को सत्यापन योग्य आंकड़े निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत नहीं किए थे । फिब्रुअरी, जिसने अन्य उत्पादक होने का दावा किया है, ने भी कोई सत्यापन योग्य आंकड़े प्रस्तुत नहीं किए, तथा इसने भी पूर्ण उपकरण पर शुल्क लगाने का अनुरोध करते

हुए तेजस का समर्थन किया था। किसी अन्य हितबद्ध पक्षकार ने विनिर्माता होने का दावा प्रस्तुत नहीं किया था और न ही किसी हितबद्ध पक्षकार ने इस मुद्दे पर प्राधिकारी के समक्ष कोई आंकड़े प्रस्तुत किए थे। प्राधिकारी ने क्षतिरहित कीमत का पुनः निर्धारण घरेलू उद्योग द्वारा किए गए निवेदनों के आधार पर किया है। जहाँ तक असूचित सौदों का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि जेड टी ई ने जहाँ इस बात का साक्ष्य उपलब्ध कराया है कि कथित गुमशुदा सौदे विचाराधीन उत्पाद के दायरे में नहीं आते वहीं ई सी आई ने यह साक्ष्य उपलब्ध कराया है कि आयात से संबंधित आंकड़ों में सूचित मात्रा सही नहीं है।

### मै. आरएडी. डाटा कम्यूनिकेशन्स लि. (आरएडी)

170. प्रकटीकरण विवरण पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने उन आरएडी उत्पादों/मॉड्यूलों, जिनके एसटीएम-1 इंटरफेस एसडीएच वातावरण में कार्य नहीं करते, के अपवर्जन का अनुरोध किया है, क्योंकि उनका उपयोग निजी परिसर नेटवर्कों में अथवा रक्षा, रेलवे तथा इनकी यूटिलिटीज के निजी नेटवर्कों में डार्क फाइबर के जरिए डाटा तथा ध्वनि यातायात के परिवहन में किया जाता है। इनमें से अनेक उत्पादों के बारे में बताया जाता है कि ये एसडीएच वातावरण में डाटा/ध्वनि यातायात का पारेषण नहीं करते, क्योंकि इनका उपयोग पारेषण नेटवर्कों के “प्रचालन एवं रखरखाव” हेतु “मॉनीटरिंग/प्रोब” उपकरणों के रूप में किया जाता है। अतः इन उत्पादों/मॉड्यूलों का अंतिम उपयोग एसडीएच ट्रांसमिशन की तरह नहीं है और इन्हें तेजस द्वारा विनिर्मित उत्पादों के “समान उत्पाद” नहीं माना जा सकता। उन्होंने इसी प्रकार के एसटीएम-4 इंटरफेस के अपवर्जन का भी अनुरोध किया है।

### प्राधिकारी द्वारा जाँच

171. प्राधिकारी वर्तमान मामले में विचाराधीन उत्पाद के दायरे को दोहराते हैं और मानते हैं कि अन्य सभी वस्तुएँ जो विचाराधीन उत्पाद के दायरे के अनुरूप नहीं हैं, स्पष्ट रूप से प्रस्तावित उपायों के दायरे के बाहर हैं। हितबद्ध पक्षकारों से अपेक्षा की जाती है कि जिन उत्पादों की संस्थीकृति का अनुरोध किया गया है उनके सही स्वरूप के बारे में अपना दावा सीमाशुल्क पत्तन प्राधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत करें। हालाँकि यह माना जाता है, तथापि यह स्पष्ट किया जाता है कि जिस उत्पाद की संस्थीकृति चाही गई है उस पर पाटनरोधी शुल्क तभी प्रभारित किया जाएगा जब वह विचाराधीन उत्पाद के दायरे के भीतर आता हो। तथापि, प्राधिकारी ने संस्तुत पाटनरोधी शुल्क के दायरे में शामिल करने अथवा उससे बाहर रखे जाने से संबंधित सभी चिंताओं की व्याख्या इस अंतिम जाँच परिणाम दस्तावेज की शुल्क तालिका में एक फुटनोट के रूप में प्रस्तुत की है।

### मै. कैरागोन नेटवर्क्स लि.

172. कैरागोन द्वारा उत्पादित उत्पाद विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर रहेगा, क्योंकि वह विचाराधीन उत्पाद के समान वस्तु नहीं है। उन्होंने यह भी अनुरोध किया है कि प्राधिकारी द्वारा एसटीएम-1 सहित कैरागोन के सभी उत्पादों/मॉड्यूलों को बाहर रखकर जाँच के दायरे में संशोधन

किया जाना चाहिए, ताकि उत्पादों के आयात के दौरान किसी प्रकार के व्याख्यात्मक मुद्दे से बचा जा सके ।

### प्राधिकारी द्वारा जाँच

173. प्राधिकारी इस संबंध में अपनी स्थिति को दोहराते हैं । पाटनरोधी शुल्क उत्पादों पर लागू होता है चाहे उनका उत्पादक कोई भी हो । इसके अलावा, प्राधिकारी यह मानते हैं कि अलग-अलग कंपनियों अथवा उत्पादों, जो विचाराधीन उत्पाद तथा प्रस्तावित शुल्क के दायरे से बाहर हैं, के नामों को निर्दिष्ट करना उचित नहीं होगा । इसके अलावा, किसी निर्यातक पर किसी अन्य उत्पादक द्वारा उत्पादित वस्तुओं, जिन पर पाटनरोधी शुल्क लागू है, का निर्यात करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है । तथापि, प्राधिकारी ने संस्तुत पाटनरोधी शुल्क के दायरे में शामिल करने अथवा उससे बाहर रखे जाने से संबंधित सभी चिंताओं की व्याख्या इस अंतिम जाँच परिणाम दस्तावेज की शुल्क तालिका में एक फुटनोट के रूप में प्रस्तुत की है ।

### फिबकॉम

174. उन्होंने घरेलू विनिर्माता होने के अपने दावे को दोहराया है । प्राधिकारी द्वारा प्रकटीकरण विवरण में उल्लिखित तथ्यों से सहमत होते हुए उन्होंने आयातकों द्वारा पाटनरोधी शुल्क के भुगतान से बचने के लिए विचाराधीन उत्पाद को 8-अंकीय स्तर पर आईटीसी (एचएस) के रूप में परिभाषित करने का अनुरोध किया है ।

### प्राधिकारी द्वारा जाँच

175. प्राधिकारी इस संबंध में अपनी स्थिति को दोहराते हैं । पाटनरोधी शुल्क किसी उत्पाद पर लागू होता है चाहे उसका सीमाशुल्क वर्गीकरण कुछ भी हो । सीमाशुल्क वर्गीकरण का उल्लेख केवल सीमाशुल्क विभाग की सुविधा हेतु किया जाता है और यह उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है जिस पर पाटनरोधी शुल्क लगाया जाना है । पाटनरोधी शुल्क विचाराधीन उत्पाद पर लागू होगा, चाहे आयातक द्वारा सूचित सीमाशुल्क वर्गीकरण कुछ भी हो । इसी प्रकार, पाटनरोधी शुल्क लागू नहीं होगा, यदि उत्पाद का उल्लेख वर्तमान अधिसूचना में उल्लिखित सीमाशुल्क वर्गीकरण के अंतर्गत किया गया है और यह विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर है । तथापि, प्राधिकारी ने संस्तुत पाटनरोधी शुल्क के दायरे में शामिल करने अथवा उससे बाहर रखे जाने से संबंधित सभी चिंताओं की व्याख्या इस अंतिम जाँच परिणाम दस्तावेज की शुल्क तालिका में एक फुटनोट के रूप में प्रस्तुत की है ।

### एसडीएच टेलीकॉम

176. एसडीएच उपकरण पीडीएच उपकरणों के समान नहीं होते । निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा एसडीएच तथा पीडीएच उपकरणों के बीच अंतर का उल्लेख स्पष्ट रूप से किया जाना चाहिए । यदि पाटनरोधी शुल्क का भुगतान किया जाना है तो यह केवल एसडीएच उपकरण पर किया जाना चाहिए न कि पीडीएच उपकरणों पर ।

### प्राधिकारी द्वारा जाँच

177. प्राधिकारी इस संबंध में अपनी स्थिति को दोहराते हैं। पाटनरोधी शुल्क केवल वर्तमान अधिसूचना में यथापरिभाषित विचाराधीन उत्पाद पर लागू होता है। अन्य उत्पाद वैसे भी वर्तमान अधिसूचना में विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर है। तथापि, प्राधिकारी ने संस्तुत पाटनरोधी शुल्क के दायरे में शामिल करने अथवा उससे बाहर रखे जाने से संबंधित सभी चिंताओं की व्याख्या इस अंतिम जाँच परिणाम दस्तावेज की शुल्क तालिका में एक फुटनोट के रूप में प्रस्तुत की है।

### कैरागाँन इजरायल

178. उन्होंने अनुरोध किया है कि वह कुछेक माइक्रोवेब रेडियो टर्मिनलों का निर्यात करते हैं जिनमें एसडीएच ट्रांसमिशन उपकरण के साथ एसटीएम-1 इंटरफेस शामिल हो सकता है। यह दावा किया गया है कि यह इंटरफेस रेडियो तथा एसडीएच उपकरण के बीच संपर्क को समर्थ बनाने हेतु भौतिक माध्यम के रूप में कार्य करता है। इस बात पर भी जोर दिया गया है कि यह महज एक इंटरफेस है और यह किसी भी एसडीएच ट्रांसमिशन उपकरण का कार्य नहीं करता। अतः उन्होंने एसटीएम-1 इंटरफेस सहित कैरागाँन के उत्पादों को बाहर रखते हुए उत्पाद के दायरे में संशोधन करने का अनुरोध किया है।

### प्राधिकारी द्वारा जाँच

179. प्राधिकारी ने संस्तुत पाटनरोधी शुल्क के दायरे में शामिल करने अथवा उससे बाहर रखे जाने से संबंधित सभी चिंताओं की व्याख्या इस अंतिम जाँच परिणाम दस्तावेज की शुल्क तालिका में एक फुटनोट के रूप में प्रस्तुत की है। पाटनरोधी शुल्क केवल वर्तमान अधिसूचना में यथापरिभाषित विचाराधीन उत्पाद पर लागू होता है। अन्य सभी उत्पादों को वर्तमान अधिसूचना में उल्लिखित विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर रखा गया है।

### यूटी स्टारकॉम इंक. (भारत शाखा कार्यालय)

180. उन्होंने निवेदन किया है कि वह निम्नलिखित आधारों पर संबद्ध वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने और प्रकटीकरण विवरण में उल्लिखित निष्कर्षों का विरोध करते हैं।

- (i) तेजस अधिनियम के नियम 2(ख) के अंतर्गत यथापरिभाषित “ घरेलू उद्योग ” की परिभाषा के दायरे में नहीं आता। तेजस द्वारा यह भी सिद्ध किया जाना चाहिए कि वह सभी आवश्यक उप-साधनों, पुर्जों, संघटकों एवं केबलों तथा एसडीएच उपकरण का विनिर्माण करते हैं क्योंकि तेजस इन सभी पुर्जों के आयातक हैं और इनका “ उत्पादन ” नहीं करते, क्योंकि तेजस इन पुर्जों, संघटकों एवं उप-साधनों के 95% का भारत में आयात करते हैं और तेजस द्वारा प्रयुक्त कच्चे माल के 65.58% का आयात किया जा रहा है।

408796)10-140

(ii) निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा यह अपेक्षा की जानी सही नहीं है कि जो हितबद्ध पक्षकार इस जाँच के विरोधी हैं, उनके द्वारा प्रत्येक बात का खण्डन किया जाए। यह तभी होता है जब आवेदक पाटनरोधी नियमावली के नियम 5(1) के अनुसार प्रारम्भिक दायित्व का निर्वहन करता है, तभी प्रतिवादी पक्षकारों पर उसका खण्डन करने का दायित्व आता है।

(iii) संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयात में कथित वृद्धि के कारण स्वदेशी उद्योग के समुख क्षति का कोई जाहिर खत्ता नहीं है। आयातों की मात्रा में केवल वृद्धि होना पाटन को सिद्ध करने का कोई प्रारम्भिक कारक नहीं है और पाटनरोधी शुल्क लागू करने हेतु वास्तविक क्षति की गणना करते समय आवेदक के क्षमता उपयोग, बिक्री की मात्रा, उत्पादन की मात्रा जैसे अन्य आर्थिक मानदण्डों पर भी विचार किया जाना चाहिए। इस संदर्भ में उन्होंने कार्बन ब्लैक मामले का हवाला दिया है जिसमें यह अभिमत व्यक्त किया गया है कि घटती कीमतों पर होने वाले आयातों में वृद्धि तथा विदेशों में स्थापित अतिरिक्त क्षमताएँ आसन्न गंभीर क्षति का सूचक होती हैं।

(iv) प्राधिकारी ने प्रकटीकरण विवरण में अन्य अनेक कारकों को सीधे अस्वीकार कर दिया है जो कारणात्मक संबंध के निर्धारण में प्रासंगिक हैं। निर्दिष्ट प्राधिकारी ने जहाँ यह उल्लेख किया कि घरेलू उद्योग के उत्पादन और बिक्री में वृद्धि हुई है, वहीं घरेलू उद्योग को हुई क्षति के मूल्यांकन में उसे पूर्णतः दरकिनार कर दिया। उन्होंने पाटनरोधी व्यापार करार के अनुच्छेद 3.5 का हवाला दिया है जिसमें यह प्रावधान है कि क्षति एवं उसके कारणात्मक संबंध का निर्धारण करते समय पाटनरोधी शुल्क लागू करने हेतु केवल पाटन की मौजूदगी पर्याप्त नहीं है। इसके अलावा, यह भी निवेदन किया गया है कि प्राधिकारी द्वारा क्षति एवं कारणात्मक संबंध के निर्धारण हेतु प्रासंगिक कारकों पर विचार किया जाना महज एक जाँच सूची दृष्टिकोण युक्त यांत्रिक प्रक्रिया नहीं है, परंतु प्रासंगिक कारकों का एक सार्थक एवं वस्तुनिष्ठ आकलन है, जिसका भारत में किसी स्थापित उद्योग के संदर्भ में ऐसी वस्तु के आयात से क्षति की मौजूदगी एवं उसके परिणाम पर प्रभाव पड़ता है।

(v) जाँच परिणाम में यह विरोधाभास है कि एसडीएच उपकरण की माँग में वृद्धि हो रही है, उत्पादन में वृद्धि हो रही है, बिक्री से आय में भी वृद्धि (जाँच अवधि के दौरान 36%) हो रही है और क्षमता उपयोग में भी वृद्धि हो रही है वहीं घरेलू उद्योग अब भी पाटन और क्षति का आरोप लगा रहा है। प्राधिकारी ने प्रकटीकरण विवरण में उल्लेख किया है कि आयातों की मात्रा वर्ष 2005-06 में 31.55% से बढ़कर जाँच अवधि के दौरान 41.32% हो गई है। तथापि, इस बात को दरकिनार कर दिया गया है कि आयातों की मात्रा वर्ष 2006-07 में 47.18% से घटकर जाँच अवधि के दौरान 41.32% रह गई है। इस प्रकार, इस तरह का विरोध जो एकाधिकार प्राप्त करने के उद्देश्य से गलत आरोपों पर आधारित है और प्रतिस्पर्धा को प्रतिबंधित करना न केवल उपभोक्ता विरोधी तथा प्रतिस्पर्धा विरोधी है बल्कि इससे घरेलू उद्योग द्वारा गठजोड़ को भी बढ़ावा मिलता है।

(vi) याचिकाकर्ता के दावे के विपरीत, उनका उत्पादन वर्ष 2005-06 से 2006-07 और 2007-08 तक उचित दर से बढ़ा है जिसका उल्लेख प्रकटीकरण विवरण में किया गया है। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि घरेलू उद्योग को संबद्ध देशों से एसडीएच उपकरण के आयातों से किसी प्रकार की क्षति नहीं हुई है और इस प्रकार का घरेलू उद्योग को हुई कथित क्षति का कोई कारणात्मक संबंध नहीं है। इस संबंध में उन्होंने ऑफ्रे पेट्रोकैमिकल्स बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी [2006(201) ईएलटी 481 (ट्राई.)] मामले में

माननीय सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर अपीलीय अधिकरण के निर्णय का उल्लेख किया है जिसमें निम्नानुसार अभिमत व्यक्त किया गया है :

“ निर्दिष्ट प्राधिकारी से अन्य बातों के साथ-साथ निर्यात कीमत, सामान्य मूल्य एवं जाँचाधीन वस्तु की पाटन मार्जिन के संदर्भ में तथा इस बात के संदर्भ में कि क्या भारत में कथित वस्तु के आयात से भारत में स्थापित किसी उद्योग को वास्तविक क्षति होती है अथवा होने का खतरा है अथवा भारत में स्थापित किसी उद्योग को वास्तविक नुकसान होता है, अपना जाँच परिणाम प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती है । ”

- (vii) निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा चीन को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश का व्यवहार प्रदान किया गया है जो मनमाने स्वरूप का है । किसी भी अर्थव्यवस्था को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा देने के लिए प्रत्येक मामले में निर्दिष्ट जाँच परिणाम दिए जाने चाहिए । इससे पहले यह व्यवहार प्रदान किया जाना किसी अर्थव्यवस्था को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था का व्यवहार दिए जाने का एकमात्र कारण नहीं हो सकता और यह मान्य नहीं है । इसके अलावा, सामान्य नियम के तौर पर किसी देश पर गैर-बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा चर्चा नहीं किया जा सकता ।
- (viii) समस्त जाँच मनमाने तरीके से संचालित की गई है और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की अनदेखी की गई है, क्योंकि प्रकटीकरण विवरण का उत्तर देने के लिए केवल 24 घण्टे का समय दिया जाना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के घोर उल्लंघन के उदाहरणों में से केवल एक उदाहरण है और इसका विस्तृत ब्यौरा इस मामले की सुनवाई के दौरान प्रस्तुत किया जाएगा ।
- (ix) घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत अधिकाँश आंकड़ों को गोपनीय चिह्नित किया गया है और विद्वान निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा इसे गोपनीय के रूप में स्वीकार किया गया है, जिससे यह स्थिति उत्पन्न हो गई है कि निर्यातक/आयातक घरेलू उद्योग द्वारा किए गए दावे का कारगर तरीके से खण्डन करने में समर्थ नहीं है । पाटनरोधी नियमावली के नियम 7(1) में जहाँ गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करने का प्रावधान है, वहीं इसके नियम 7(2) में किए गए निवेदनों के सार को समझने में अन्य पक्षकारों को समर्थ बनाने हेतु ऐसी सूचना का अगोपनीय सारांश प्रदान किया जाना अधिदेशित है । तथापि, घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत गोपनीय आंकड़ों के अगोपनीय सारांश में तथ्यों/आंकड़ों की कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती अतः वह घरेलू उद्योग के निवेदनों का कारगर उत्तर देने में समर्थ नहीं है ।
- (x) निर्दिष्ट प्राधिकारी ने जहाँ तेजस को “घरेलू उद्योग” की पात्रता प्रदान करने के दावे हेतु सी एम ए आई तथा मेजरमेंट कंट्रोल्स लिंग के पत्रों हेतु स्वीकृति प्रदान की है, केवल सी एम ए आई का पत्र ही रिकॉर्ड में प्रस्तुत किया गया है । तथापि प्रकटीकरण विवरण से यह जाहिर है कि क्या निर्दिष्ट प्राधिकारी ने इसके मिलान हेतु कोई प्रयास किया था, जब स्वयं प्राधिकारी ने यह पाया है कि तेजस द्वारा प्रयुक्त संघटकों में से 65 % से अधिक आयातित हैं ।
- (xi) घरेलू उद्योग ने अपनी याचिका में अन्य बातों के साथ-साथ उल्लेख किया है कि उनके द्वारा किए गए आयातों का ब्यौरा प्रपत्र IV - क में दिया गया है परन्तु उसे गोपनीय के रूप में चिह्नित किया है और उसका अगोपनीय सारांश उपलब्ध नहीं कराया है; और

(xii) निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात की जांच करने अथवा कोई जांच परिणाम दर्ज करने में असफल रहे हैं कि बिक्री, उत्पादन, माल सूची में वृद्धि होने के बावजूद घरेलू उद्योग द्वारा क्षति का आरोप क्यों लगाया गया है।

### प्राधिकारी द्वारा जांच

181. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग के अधिकार, घरेलू उद्योग द्वारा किए गए आयातों तथा पाटनरोधी नियमावली के नियम 2 (ख) के दायरे के भीतर इसके विवेचन से संबंधित मुद्दों का विस्तृत और प्रकटीकरण विवरण एवं वर्तमान जांच परिणाम में दिया गया है। पक्षकार द्वारा कोई नया मुद्दा प्रस्तुत नहीं किया गया है और प्रकटीकरण विवरण में अथवा वर्तमान जांच परिणाम में अन्यत्र विवेचन किए गए मुद्दों का नए सिरे से विवेचन करना आवश्यक नहीं है। जहाँ तक चीन को एक गैर बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश का व्यवहार प्रदान करने का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि नियमावली में इस अवधारणा के खण्डन का प्रावधान है। अतः प्राधिकारी से चीन के उत्पादकों को गैर बाजार अर्थव्यवस्था के अंतर्गत प्रचालित होने का व्यवहार प्रदान करने की अपेक्षा की जाती है, जब तक चीन के उत्पादक बाजार अर्थव्यवस्था दर्ज का दावा सिद्ध नहीं करते हैं।

### सिएना यू एस ए

182. उन्होंने निवेदन किया है कि डी जी ए डी ने घरेलू उद्योग के इस तर्क को स्वीकार कर लिया है कि संबद्ध वरतुओं के उत्पादन में प्रयुक्त मुख्य प्रयास प्रौद्योगिकी का विकास है। संबद्ध वरतुओं के डिजाइन तथा विकास में उत्पादकों द्वारा पर्याप्त अनुसंधान तथा विकास प्रयास किए जाते हैं, संबद्ध वरतुओं के उत्पादन का केन्द्रीय कार्यकलाप प्रौद्योगिकीय विकास, जानकारी, डिजाइन तथा उत्पाद का विकास और संबद्ध वस्तु की उत्पादन प्रक्रिया एवं जिस देश में ऐसी प्रक्रिया प्रयुक्त की जाती है वह उपभोक्ता द्वारा किसी विशिष्ट देश में उत्पादित प्रौद्योगिकी पर विश्वास के रूप में वाणिज्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होती है, अतः प्राधिकारी द्वारा अंतिम जांच परिणाम दस्तावेज में इस बात का उल्लेख करने पर विचार किया जाए कि सिएना द्वारा उत्पादित वरतुओं का पर्याप्त रूपांतरण जांचाधीन संबद्ध देशों में नहीं किया जाता है, अतः ये वस्तुएं चीन जन गण के उद्गम की वस्तुएं नहीं हैं।

### प्राधिकारी द्वारा जांच

183. प्राधिकारी द्वारा उपर्युक्त टिप्पणियों को नोट किया गया है। जहाँ तक आई पी आर हेतु उद्गम देश पर विचार करते हुए उद्गम देश की परिभाषा के मुद्दे का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि दूरसंचार उपकरण से संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय ने दूरसंचार से संबंधित विशेषज्ञता प्राप्त उत्पादों के इस पहलू पर विचार किया था और संबंधित पक्षकारों से टिप्पणियों हेतु इसका प्रचार किया था, तथापि इस मुद्दे पर अभी विचार नहीं किया गया है और इस संबंध में कोई औपचारिक आदेश जारी नहीं किए गए हैं। अतः प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित प्रारम्भिक जांच परिणाम की तर्ज पर वर्तमान जांच हेतु निर्यात के देश और उद्गम के देश को जारी रखा जाएगा।

184. तथापि उपर्युक्त में से किसी बात के होते हुए भी प्राधिकारी यह अभिमत व्यक्त करना चाहते हैं कि तेजस घरेलू उद्योग है आज की तारीख में आई पी आर के मुद्दे के संदर्भ के बिना इसे नियमावली के दायरे के भीतर आवश्यक अधिकार प्राप्त है जो निम्नानुसार है:-

- (i) तेजस एकमात्र विनिर्माता है जिन्होंने प्राधिकारी को निर्धारित तरीके से आंकड़े उपलब्ध कराए हैं ।
- (ii) वी एम सी एल तथा पृथ्वी ने घरेलू उत्पादक होने का दावा किया था, जिनमें से एक ने अगरत, 2010 में जांच के अंतिम चरण के दौरान यह लिखित में स्वीकार किया था कि वह डी डब्ल्यू डी एम का विनिर्माता है जो विचाराधीन उत्पाद के दायरे में शामिल नहीं है और अन्य दावेदार को प्रतिवादी निर्यातक के परिसर में किए गए सत्यापन के दौरान इस उपकरण का आयातक पाया गया था, अतः इसे नियम 2 (ख) के दायरे के अंतर्गत घरेलू उद्योग माने जाने की पात्रता नहीं है । इसके अलावा दोनों में से किसी ने भी प्राधिकारी को सत्यापन योग्य आंकड़े निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत नहीं किए थे ।
- (iii) फिबकॉम, जिसने अन्य उत्पादक होने का दावा किया है, ने भी कोई सत्यापन योग्य आंकड़े प्रस्तुत नहीं किए, तथा इसने भी पूर्ण उपकरण पर शुल्क लगाने का अनुरोध करते हुए तेजस का समर्थन किया था ।
- (iv) किसी अन्य हितबद्ध पक्षकार ने विनिर्माता होने का दावा प्रस्तुत नहीं किया था और न ही किसी हितबद्ध पक्षकार ने इस मुद्दे पर प्राधिकारी के समक्ष कोई आंकड़े प्रस्तुत किए थे ।

184. जहाँ तक आई पी आर हेतु उद्गम देश पर विचार करते हुए उद्गम देश की परिभाषा के मुद्दे का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि दूरसंचार उपकरण से संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय ने दूरसंचार से संबंधित विशेषज्ञता प्राप्त उत्पादों के इस पहलू पर विचार किया था और संबंधित पक्षकारों से टिप्पणियों हेतु इसका प्रयार किया था, तथापि इस मुद्दे पर अभी विचार नहीं किया गया है और इस संबंध में कोई औपचारिक आदेश जारी नहीं किए गए हैं । अतः प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित अन्य जांच परिणामों के तर्ज पर वर्तमान जांच हेतु निर्यात के देश और उद्गम के देश को जारी रखा जाएगा । प्राधिकारी का यह भी अभिमत है कि वर्तमान प्रयोजन हेतु उद्गम एवं निर्यात का अर्थ प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित किया जाना अपेक्षित नहीं है । उद्गम के अर्थ और दायरे को परिभाषित करना भारत सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है ।

#### मै0 हुआवेई टेक्नोलॉजीज कंपनी लिमिटेड, चीन जन गण, एयरसेल लिमिटेड एवं एम आर ओटेक

185. प्रकटीकरण विवरण के उत्तर में मै0 हुआवेई टेक्नोलॉजीज कंपनी लिमिटेड, चीन जन गण ने कहा है कि

- i हुआवेई द्वारा किए गए पूर्ण सहयोग के बावजूद डी जी ए डी द्वारा अन्य पक्षकारों के लिए लागू 280-290 प्रतिशत की पाटन मार्जिन दर को लागू करते हुए हुआवेई को अन्य असहयोगी निर्यातकों के समकक्ष नहीं रखा जाना चाहिए । हुआवेई की निर्यात कीमत को अस्वीकार किए जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी । निर्यात कीमत का ब्यौरा डी जी ए डी को उपलब्ध कराया गया था और निर्यात कीमत में कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया था । परिशिष्ट 2 में सूचित निर्यात कीमत का ब्यौरा संबंधित सहायक दस्तावेजों और

निर्यात से प्राप्त आय के समर्थन में प्रस्तुत बैंक विवरण सहित लेखांकन रिकॉर्डों के अनुसार पाया गया था। सत्यापन के दौरान जब प्राधिकारी ने अलग-अलग दरतावेजों का सत्यापन पी सी एन के विभिन्न उपशीर्षों के साथ किया था तब उसमें कोई गलती नहीं पाई गई थी। सभी दस्तावेज प्रस्तुत आंकड़ों के अनुरूप पाए गए थे। प्रारंभिक जांच परिणाम में कतिपय पी सी एन के समक्ष प्रस्तुत मूल्यों पर, जिनमें मात्रा का व्यौरा नहीं था, नजरअंदाज कर दिया गया था। प्रारंभिक जांच परिणाम के उपरांत हुआवेई ने उन पी सी एन के मूल्यों का पुनः आवंटन अन्य पी सी एन के साथ किया था जिनके साथ मात्राओं का उल्लेख था। सत्यापन के समय मात्रा रहित पी सी एन के संघटकों का पुनः आवंटन मात्रा युक्त पी सी एन के साथ किया गया था। पुनः आवंटन सभी संघटकों को उनकी पी सी एन के मूल्यों के साथ मिलाने के उद्देश्य से किया गया था। ऐसे संशोधनों को निर्यात कीमत में परिवर्तन नहीं कहा जा सकता। दरअसल पुनः आवंटन से पूर्व तथा पश्चात सूचित निर्यात कीमतें एक समान थीं।

ii. चूंकि सत्यापन रिपोर्ट के अनुसरण में कोई अतिरिक्त आंकड़े प्रस्तुत नहीं किए गए तब प्रस्तुत सूचना को डी जी ए डी द्वारा स्वीकार न किए जाने का कोई कारण नहीं था। हुआवेई ने पी सी एन के प्रत्येक उप शीर्ष के उल्लेख प्रयुक्त विवरण की एक पूरी सूची प्रस्तुत की थी। जब पी सी एन के विभिन्न उपशीर्षों के तुलना हेतु हुआवेई के विवरण पर विचार किया गया था तब सूचित पी सी एन तथा संबंधित दस्तावेजों के विवरण में कोई अंतर नहीं पाया गया था।

iii. डब्ल्यू टी ओ के पाटनरोधी करार के अनुबंध II पैराग्राफ 5 के अनुसार यदि प्रस्तुत सूचना सभी प्रकार से उपयुक्त नहीं है, तो उसे अस्वीकार नहीं किया जाएगा क्योंकि हुआवेई ने अपनी सर्वोत्तम योग्यता के अनुसार कार्यवाही की है।

iv. डी जी ए डी द्वारा बहुत पुराने दस्तावेज प्रस्तुत करने पर जोर दिया जाना और पहले से अनुरोध न करना एवं ऐसे दस्तावेजों को प्रस्तुत न किए जाने पर बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा प्रदान करने से इनकार करना अन्यायपूर्ण है।

v. हुआवेई टेक्नोलॉजीज कंपनी (जिन्हें एतद्पश्चात "हुआवेई" कहा गया है) ने विस्तृत साक्ष्य प्रस्तुत किया था जिसमें दर्शाया गया था कि तेजस द्वारा चीन जन गण से अप्रत्यक्ष आयात हेतु थाईलैंड में इसकी अनंत ओई एम विनिर्माण सेलेस्टिका का प्रयोग किया जा रहा है।

vi. तेजस संबद्ध देश से प्रत्यक्ष आयात करने के बजाय थाईलैंड के रास्ते चीन से अप्रत्यक्ष आयात करने के कारण इसका आयातक का दर्जा समाप्त नहीं होता। अतः तेजस को पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 2 (ख) के अंतर्गत घरेलू उद्योग का प्रतिनिधित्व करने की पात्रता नहीं है।

vii. हुआवेई तथा अन्य अनेक हितबद्ध पक्षकारों ने विचाराधीन उत्पाद से संबंधित मुद्दों पर अनन्य विचार-विमर्श हेतु एक सार्वजनिक सुनवाई के आयोजन का अनुरोध किया था। वह यह बताना चाहते थे कि अन्य अनेक उत्पाद जो एस डी एच मानकों के अनुरूप हैं परन्तु तेजस द्वारा उत्पादित एस टी एम - 1 से 16 महीनों से काफी भिन्न हैं, सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा इसमें शामिल किए जाते हैं। इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर सार्वजनिक सुनवाई हेतु बार-बार अनुरोध किए जाने के बावजूद कोई सुनवाई आयोजित नहीं की गई। इस मुद्दे पर कोई नियेदन अथवा प्रति नियेदन का अवसर प्रदान किए बिना डी जी ए डी ने एस टी एम 64, एस टी एम 256, डी एक्स सी, ब्रॉडबैण्ड तथा सेल्युलर उपकरण, जिनमें एस डी एच

उपकरण शामिल होते हैं, एसेम्बलीज तथा सब एसेम्बलीज एवं पॉजुलेटेड सर्किट बोर्ड/कार्डों को विचाराधीन उत्पाद के दायरे में शामिल करने का निर्णय ले लिया । डी जी ए डी का यह निर्णय अत्यंत मनमाना है ।

viii. डी जी ए डी ने प्रकटीकरण विवरण के पैराग्राफ 30(ii) में उल्लेख किया है कि वस्तुओं को उत्पादित माना जाएगा यदि उत्पादन प्रक्रिया में प्रयुक्त निविष्टियों का "उल्लेखनीय रूपांतरण" किया गया है । तथापि डी जी ए डी यह जांच करने में असफल रहा है कि क्या पापुलेटेड सर्किट बोर्डों एवं कार्डों सहित पुर्जों एवं संघटकों, एस डी एच ट्रांसमिशन उपकरण का उत्पादन याचिकाकर्ता द्वारा भारत में किया जाता है ।

ix. डी जी ए डी द्वारा अपनाई गई यह स्थिति भी पूर्णतः त्रुटिपूर्ण है कि मध्यवर्ती अवस्था में प्रसंस्कृत निविष्टियों, जहां उनका कोई उपयोग नहीं है (और जो कोई कार्य नहीं करती) परन्तु अंतिम उत्पाद में उनकी खपत की जाती है, को एक वस्तु नहीं माना जा सकता, याहे उस चरण में वह बिक्री योग्य क्यों न हों ।

x. डी जी ए डी ने लागू पाटनरोधी शुल्क का निर्धारण करते समय सुस्पष्ट उत्पादों तथा एस डी एच ट्रांसमिशन उपकरण के उच्चतर ग्रेडों को भी शामिल कर लिया है जो त्रुटिपूर्ण है । इसके अपवर्जन के कारण निम्नानुसार हैं -

क. एस टी एम 64 - डी जी ए डी का यह निष्कर्ष कि एस टी एम 64 की भारत और विदेशी बाजार में आपूर्ति तेजस ने की है, अत्यंत आपत्तिजनक है । तेजस ने आज की तारीख तक एस टी एम 64 की किसी निविदा प्रक्रिया में भाग नहीं लिया है । डी जी ए डी ने तेजस के झूठे दावे को स्वीकार कर लिया है ।

ख. एस टी एम 256 - आंब्र पेट्रोकेमिकल्स लिलो बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी, 2006 (201) ई एल टी 481 (ट्राई - दिल्ली) मामले में माननीय सीस्टेट का निर्णय कि कोई वस्तु जो किसी देश अथवा भूभाग से भारत में निर्यातित नहीं है, पर पाटनरोधी शुल्क नहीं लगाया जा सकता डी जी ए डी पर बाध्यकारी है, अतः एस टी एम 256 पर कोई पाटनरोधी शुल्क संस्तुत नहीं किया जा सकता । एस टी एम 256 में (i) तकनीकी विशेषताओं (ख) विनिर्माण प्रक्रिया (ग) कार्यों तथा उपयोगों एवं (घ) ग्राहक संकल्पना के आधार पर अंतर किया जा सकता है ।

ग. डिजिटल क्रॉस कनेक्ट अर्थात् डी एक्स सी एक अलग प्रौद्योगिकी है और यह एस डी एच ट्रांसमिशन उपकरणों के एस टी एम - 1 से 256 परिवार से भिन्न है । हुआवेई ने डी एक्स सी तथा एस डी एच ट्रांसमिशन उपकरणों के बीच अंतर का विस्तृत व्यौरा प्रस्तुत किया था जिसमें से किसी पर भी डी जी ए डी ने विचार नहीं किया ।

घ. सी के डी/एस के डी फार्म एवं एसेम्बलीज एंड सब-एसेम्बलीज: डी जी ए डी को यह स्पष्ट करना चाहिए कि एसेम्बलीज/सब-एसेम्बलीज, जिनमें एस डी एच उपकरणों की अनिवार्य विशेषताएं नहीं हैं, पर पाटनरोधी शुल्क लागू नहीं किया जाएगा ।

ड. पी सी बी/कार्ड - तेजस पी सी बी तथा कार्डों का उत्पादन नहीं करता परन्तु पर्याप्त मात्राओं में इनका आयात करता है। इससे संबंधित साक्ष्य डी जी ए डी के समक्ष पहले ही प्रस्तुत किया जा चुका है। अतः पी सी बी तथा कार्डों को विचाराधीन उत्पाद के दायरे में रखना पूर्णतः त्रुटिपूर्ण है।

च. पुर्जे तथा संघटक - चूंकि डी जी ए डी ने स्वीकार किया है कि पुर्जों तथा संघटकों का विनिर्माण "घरेलू उद्योग" द्वारा नहीं किया जाता, अतः पुर्जों/संघटकों/सब-एसेम्बलीज, पी सी बी तथा कार्डों को शामिल किया गया है। पुर्जों/संघटकों तथा एसेम्बलीज/सब एसेम्बलीज/पी सी बी तथा कार्डों के बीच अंतर के स्पष्टीकरण के अभाव में सीमाशुल्क विभाग के प्रशासन में असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी।

छ. उपकरण के भाग के रूप में एस डी एच उपकरण - वित्त मंत्रालय ने सीमाशुल्क अधिसूचना सं 0 132/2009 द्वारा एस डी एच उपकरण युक्त ब्रॉडबैण्ड अथवा सेल्युलर उपकरणों को पाटनरोधी शुल्क के दायरे से बाहर रखा था, जबकि प्रारम्भिक जांच परिणाम में ऐसे उत्पादों को शामिल किया गया था। अतः डी जी ए डी द्वारा इन्हें अंतिम जांच परिणाम में भी बाहर रखा जाना चाहिए।

ज. सॉफ्टवेयर - सॉफ्टवेयर एक सेवा है, न कि कोई वस्तु। डी जी ए डी को सेवाओं पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से अभूतपूर्व कदम नहीं उठाना चाहिए।

xi. दिनांक 30 दिसम्बर, 2009 को किए गए निवेदन में हुआवेई ने उन उत्पादों की एक विस्तृत सूची प्रस्तुत की थी जिन्हें विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए। डी जी ए डी द्वारा इस पर विचार किया जाना चाहिए और इसे वर्तमान शुल्क के दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए।

xii. माननीय अधिकरण ने अनेक मामलों जैसे बीडियोकॉन नर्मदा ग्लास बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी [ 2003 (आई एस आई) ई एल टी (ट्राई-दिल्ली), इंडियन रिफ्रेक्ट्री एसोसिएशन बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी [ 2000 (119) ] ई एल टी ] 150 (ट्राई- दिल्ली) में जिन ग्रेडों का विनिर्माण घरेलू उद्योग द्वारा नहीं किया जाता उन्हें बाहर रखने के पक्ष में निर्णय दिया है। अतः जिन उत्पाद ग्रेडों का विनिर्माण तेजस द्वारा नहीं किया जाता, उन्हें घरेलू उद्योग के दायरे से बाहर रखा जाए।

xiii. डी जी ए डी याचिकाकर्ता की स्थिति के बारे में जांच करते समय यह जांच करने में असफल रहा है कि क्या भारत में तेजस द्वारा सम्बद्ध वस्तुओं का "पर्याप्त रूपांतरण" किया गया था। प्रकटीकरण विवरण के पैराग्राफ 31 में उल्लिखित तेजस द्वारा किए गए कार्यकलाप की सूची से यह सिद्ध नहीं होता कि वारस्तविक उत्पादन तेजस द्वारा किया जाता है अथवा ई एम एस वेण्डरों द्वारा। इस बात का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है कि पृथ्वी तथा वी एम सी के कार्यकलाप तेजस के कार्यकलापों से किस प्रकार भिन्न है।

xiv. डी जी ए डी ने प्रारम्भिक जांच परिणाम के पैराग्राफ 43 में गलत व्यौरा दिया गया है कि तेजस के परिसर की प्रस्तुत जांच की गई थी। सार्वजनिक सुनवाई के दौरान घरेलू उद्योग के सलाहकार ने खुले तौर पर कहा था कि प्राधिकारी ने तेजस के केवल बंगलौर स्थित मुख्यालय का दौरा किया था और उन्होंने संयंत्र का दौरान नहीं किया क्योंकि डी जी ए डी की टीम के दौरे के समय तेजस का कोई संयंत्र नहीं था।

xv. डिजाइन और विकास जैसे "उत्पादन-पूर्व कार्यकलाप" निष्पादित करने से किसी कम्पनी को उत्पादक होने की प्रतीक्षा प्राप्त नहीं होती है। यह अमेरिकी वाणिज्य विभाग/अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आयोग की निरंतर पद्धति रही है।

xvi. नियम 2 (ख) में "विनिर्माण" शब्द का प्रयोग- घरेलू उद्योग की परिमाषा का अर्थ बताया जाना चाहिए। इस शब्द का प्रयोग डब्ल्यू टी ओ पाटनरोधी करार के पाठ के विपरीत है जिसमें भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा दीवान ब्रदर्स बनाम बैंक ऑफ इंडिया, मुम्बई एवं अन्य [ए आई आर 1976 एस सी 1503] में स्वीकार की गई स्थिति डी जी ए डी पर बाध्यकारी है।

xvii. तेजस के 70 प्रतिशत से अधिक शेयर गैर-भारतीयों द्वारा धारित है, इस कारण से भी उसे "घरेलू उद्योग" नहीं माना जा सकता।

xviii. डी जी ए डी ने हुआवेर्ड द्वारा क्षति तथा कारणात्मक संबंध के बारे में दिनांक 4 जनवरी, 2010 के लिखित निवेदन में किए गए विस्तृत निवेदन की जांच नहीं की है।

xix. जांच अवधि को छोड़कर समीक्षाधीन अवधि के दौरान आयात की मात्रा के निर्धारण हेतु "वाईस एंड डेटा" पत्रिका पर विश्वास करना सीस्टेट द्वारा डाई स्टफ मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया बनाम भारत सरकार 2003 (157) ई एल टी 154(ट्राई) मामले में दिए गए बाध्यकारी निर्णय के विरुद्ध है। इसके अलावा, याचिका में प्रस्तुत आयात से संबंधित आंकड़ों में संविदाकृत बिक्री तथा की गई बिक्री को शामिल किया गया है। संविदाकृत बिक्री के कारण कोई क्षति हुई प्रतीत नहीं होती है।

xx. आधार वर्ष 2005-06 और जांच अवधि - अप्रैल-दिसम्बर, 2008 के दौरान आयातों की बिंदुवार तुलना ई सी - ट्यूब्स, डब्ल्यू टी/डी एस 219 के विरुद्ध है जिसमें पैनल ने अभिमत व्यक्त किया था कि क्षति की सार्थक जांच में एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच जांच के स्थान पर क्षति से संबंधित कारकों एवं प्रत्येक सूचक की वारस्तविक मध्यवर्ती प्रवृत्ति का ध्यान रखा जाना चाहिए। मध्यवर्ती प्रवृत्ति में यह देखा गया है कि वर्ष 2007-08 और जांच अवधि के बीच तेजस के बाजार हिस्से में वृद्धि हुई और मांग 47.30 प्रतिशत थी जबकि चीन के निर्यातकों की मांग केवल 16.88 प्रतिशत थी।

xxi. कीमत प्रभाव की जांच करते समय डी जी ए डी द्वारा यह जांच की जानी चाहिए थी कि क्या बिक्री की लागत में हुई बिक्री संबंधित ई एस एस वेडरों, जिन्होंने तेजस के लिए

वास्तविक उत्पादन प्रक्रिया संचालित की थी, द्वारा लाभ की मार्जिन को जोड़ने के कारण हुई थी; क्या तेजस हेतु निर्धारित बिक्री की लागत का निर्धारण तेजस द्वारा वास्तविक रूप से बेचे गए उत्पादों की लागत के आधार पर किया गया था, न कि अन्य उत्पादों की लागत के आधार पर; क्या तेजस द्वारा बाजार हिस्सा प्राप्त करने की असमर्थता उपभोक्ताओं की इस अनोखी मांग को पूरा करने की अक्षमता के कारण थी ।

xxii. हुआवेई द्वारा (1) घरेलू उद्योग की वर्धित लाभप्रदता; (2) उत्पादन/बिक्री एवं बाजार हिस्से में वृद्धि; (3) रोजगार तथा मजदूरी में वृद्धि के संबंध में किए गए लिखित निवेदन पर डी जी ए डी द्वारा विचार नहीं किया गया है । डी जी ए डी ने इस बात की भी जांच नहीं की कि क्या तेजस के पास भारतीय उद्योग की मांगों को पूरा करने की क्षमता मौजूद है ।

xxiii. ई सी - बेड लिनेन, पैराग्राफ सं0 6.154-6.159 में किए गए विवेचन के अनुसार डब्ल्यू टी ओ कानून की यह निर्णित स्थिति है कि जांच एजेंसी द्वारा अनुच्छेद 3.4 में उल्लिखित सूचीबद्ध सभी कारकों की जांच की जानी चाहिए और मेक्सिको - कॉर्न साइरप, पैराग्राफ सं0 7.128 के अनुसार जांच प्राधिकारी के अंतिम निर्धारण में प्रत्येक कारक पर विचार किया जाना चाहिए । तथापि प्रकटीकरण विवरण से ऐसा कोई विचार किया गया प्रतीत नहीं होता ।

### प्राधिकारी द्वारा जांच

186. प्राधिकारी ने निर्यातक को जारी विस्तृत सत्यापन रिपोर्ट, जारी प्रकटीकरण विवरण एवं वर्तमान जांच परिणाम पर विश्वास किया है । इस कंपनी द्वारा उठाए गए मुद्दे पर अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने भी उठाया है और प्रकटीकरण विवरण तथा वर्तमान जांच परिणाम में इनका विवेचन भी अन्यत्र किया गया है । प्राधिकारी हुआवेई टेक्नोलॉजीज द्वारा किए गए निवेदनों को भी नोट करते हैं जिसमें उन्होंने कीमत अभिवचन का प्रस्ताव किया है और निर्यात कीमत, सामान्य मूल्य, पाटन तथा क्षति मार्जिन से संबंधित सूचना उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है ताकि वह समुचित अभिवचन प्रस्तुत कर सकें । प्राधिकारी नोट करते हैं कि सम्बद्ध निर्यातक के लिए निर्यात कीमत का निर्धारण न किए जाने का ब्यौरा प्रकटीकरण विवरण तथा इस जांच परिणाम में स्पष्ट कर दिया गया है तदनुसार संबद्ध निर्यातकों हेतु अलग-अलग पाटन मार्जिन तथा क्षति मार्जिन का निर्धारण करना प्राधिकारी के लिए संभव नहीं है । इसके अलावा, विचाराधीन उत्पाद एक सामान्य समांगी उत्पाद नहीं है बल्कि यह एक जटिल उत्पाद है जिसकी अनेक किस्में हैं । अतः प्राधिकारी का अभिमत है कि उनके द्वारा प्रस्तावित ऐसा कोई अभिवचन प्राप्त करना अव्यवहारिक है; कृपया नियम 15(3) का संदर्भ लें ।

### फाइबरहोम

187. प्रकटीकरण विवरण पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने निम्नानुसार निवेदन किया है:-

क. फाइबरहोम द्वारा निर्यातित पी सी एन तेजस द्वारा विनिर्मित नहीं है तथापि विभिन्न पी सी एन तथा उत्पादों के सामान्य मूल्य की गणना में तेजस के लागत संबंधी आंकड़ों को प्रयुक्त किया गया है ।

ख. सामान्य मूल्य तथा क्षति रहित कीमत के संबंध में अत्यधिक गोपनीयता अपनाई गई है, जो तेजस की वास्तविक लागत से संबंधित आंकड़ों पर आधारित है और इसे गोपनीय नहीं माना जा सकता ।

ग. भारत में उत्पादन लागत चीन में प्रचलित उत्पादन लागत से सर्वथा भिन्न है । तेजस की अनुसंधान एवं विकास लागत अत्यधिक है । प्राधिकारी द्वारा इजराइल अथवा हैंगजाऊ ई सी आई टेलीकम्यूनिकेशन कंपनी लिंग के सामान्य मूल्य को अपनाया जाना चाहिए था क्योंकि चीन जन गण में बाजार अर्थव्यवस्था स्थितियों के अंतर्गत प्रचालित माना जाता है । यदि कुछेक पी सी एन का उत्पादन एवं बिक्री ई सी आई टेलीकॉल लिंग, इजराइल द्वारा नहीं भी की जाती, तब भी प्राधिकारी को सामान्य मूल्य का निर्धारण उसी अवधारणा पर करना चाहिए था । जो उन्होंने उन पी सी एन के सी एन बी की गणना में किया था जिनका उत्पादन तेजस द्वारा नहीं किया जाता ।

घ. पाटनरोधी शुल्क विचाराधीन उत्पाद की जिन किस्मों के आधार पर की जाती है उन्हें अलग-अलग करके किस्म वार आधार पर लगाया जाना चाहिए था ।

ड. क्षति रहित कीमत का निर्धारण गलत है ।

- कच्चे माल की लागत:- जब भारत को निर्यातित सभी पी सी एन तेजस द्वारा विनिर्मित नहीं है, तब उन्हें 522 पी सी एन के संबंध में इस सामग्री के बिलों का पी सी एन वार विस्तृत व्यौरा प्रस्तुत करना चाहिए था । इसके अलावा विभिन्न पी सी एन हेतु विभिन्न कंपनियों हेतु प्रयुक्त पुर्जी और संघटकों में भिन्नता होती है ।
- अनुसंधान एवं विकास लागत: यह ज्ञात नहीं हुआ है कि तेजस द्वारा उत्पादित न किए गए पी सी एन हेतु अनुसंधान एवं विकास लागत का आकलन प्राधिकारी द्वारा किस प्रकार किया गया है ।
- नियोजित निधि से समुचित आय की गणना की विधि पूर्णतः आधारहीन है । प्राधिकारी द्वारा उस अवधि, जिसके दौरान कथित रूप से कोई पाटन नहीं किया गया था, के दौरान तेजस द्वारा नियोजित पूँजी पर वास्तविक रूप से प्राप्त की गई आय की दर को अपनाया जाना चाहिए ।

### प्राधिकारी द्वारा जांच

188. कंपनी द्वारा उठाए गए मुद्दों का, प्रकटन विवरण तथा वर्तमान जांच परिणामों में किसी अन्य स्थान पर समाधान किया गया है। यह स्पष्ट किया गया है कि प्राधिकारी ने निर्यातित पी सी एन हेतु परिकलित सामान्य मूल्य का निर्धारण किया है। इसके प्रयोजनार्थ प्राधिकारी ने निर्यातित उत्पाद प्रकार के गुणधर्मों पर विचार करके पी सी एन का निर्धारण किया है। जहां तक निविष्टियों की कीमतों में अंतर का संबंध है, प्राधिकारी का विचार है कि चीन में प्रवलित निविष्टियों की कीमत को तब तक अपनाया नहीं जा सकता जब तक संबंधित कंपनी को बाजार अर्थव्यवस्था का व्यवहार प्रदान नहीं किया जाए। विभिन्न उत्पाद प्रकारों के लिए विभिन्न शुल्कों के संबंध में प्राधिकारी का मानना है कि उत्पाद प्रकारों में अंतर केवल तुलना (पाटन मार्जिन तथा क्षति मार्जिन के निर्धारण हेतु) के प्रयोजनार्थ ही संगत है। अन्ततः पाटनरोधी शुल्क विचाराधीन उत्पाद पर ही लगाया जाता है। प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग हेतु समुचित लाभ के निर्धारण के लिए आय की इसी दर को अपनाया है जिस पर अन्य जांचों में भी विचार किया गया है। यह आय की उच्चतर दर हेतु घरेलू उद्योग के इस आधार पर किए गए दावे कि वर्तमान उत्पाद में निवेश केवल संयंत्र एवं उपकरण तथा कार्यशील पूँजी तक ही सीमित नहीं है बल्कि इसमें जन शक्ति भी सम्मिलित है जो वर्तमान मागले में उत्पाद के उत्पादन हेतु परिसंपत्ति भी बनती है, के बावजूद किया गया है।

### मै0 जेड टी ई कॉर्पोरेशन, चीन

189. जेड टी ई ने परिशिष्ट 2 ने सभी निर्यात कारोबार को ईमानदारी से सूचित किया है और प्राधिकारी को भ्रमित करने के लिए कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है। हितबद्ध पक्षकार द्वारा सूचित निर्यात सौदे अब एस डी एच यंत्र नहीं बल्कि डी डब्ल्यू डी एम यंत्र हैं और आई टी यू - टी जी 671 तथा आई टी यू - टी जी 680 के अनुसार ओ ए डी एम एक प्रकार का डी डब्ल्यू डी एम यंत्र है।

### प्राधिकारी द्वारा जांच

190. इस संबंध में उनके निवेदनों को यथावत स्वीकार कर लिया गया है और घरेलू उद्योग के दावे के उत्तर में इसका निम्नलिखित पैराओं में उपयुक्त समाधान किया गया है।

बी एम सी एल

191. उनका कथन निम्नानुसार है:-

क. उत्पादन तथा गोपनीयता के अर्थ के संबंध में प्रकटन विवरण, एस सी के निर्णयों के विरोध में है ।

ख. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित कानून के अनुसार वी एम सी एक विनिर्माता है ।

ग. घरेलू उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शिकायतकर्ता के पास कोई विनिर्माण तथा आपूर्ति क्षमताएं मौजूद नहीं हैं । पुर्जों, संघटकों, एसेम्बलीज तथा सब एसेम्बलीज इत्यादि के लिए भारत पूर्णतः आयात पर निर्भर है ।

क. यद्यपि प्रकटन विवरण में पी यू सी को पुनः परिभाषित किया गया है तथापि उसके अनुरूप "घरेलू उद्योग" का पुनर्निर्धारण अथवा उसके परिणामस्वरूप पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध का पुनर्निर्धारण नहीं किया गया है ।

i. एस टी एम 64, एस टी एम 256 तथा डी एक्स सी, एस टी एम 1, एस टी एम 4 तथा एस टी एम 16 के "समान उत्पाद" नहीं हैं ।

ii. डी एक्स सी उपकरण, एस टी एम उपकरणों से पूर्णतः अलग श्रेणी का उपकरण है ।

iii. एस टी एम 64, एस टी एम 256 तथा डी एक्स सी उपकरणों के लिए घरेलू उद्योग के संघटन, पाटन, क्षति, कारणात्मक संबंध इत्यादि का अलग से निर्धारण किए जाने की आवश्यकता है ।

iv. बी एस एन एल, आई टी आई लिओ के पत्रों से यह पता चलता है कि शिकायतकर्ता उद्योग एस टी एम 64, डी एक्स सी उपकरणों का विनिर्माण नहीं कर रहा था ।

v. एस टी एम 256 हेतु केवल क्षमता, जांच उपकरण के विकास में निवेश ही घरेलू उद्योग के निर्धारण के लिए आधार नहीं है ।

vi. एसेम्बलीज तथा सब एसेम्बलीज दोनों तथा पी सी बी को भी, पुर्जों एवं संघटकों की तरह समान व्यवहार प्रदान किया जाता है ।

vii. 'एस टी एम 16 मक्सपोन्डर कार्ड्स' सहित डी डब्ल्यू डी एम के किसी पुर्जों तथा संघटकों, एसेम्बलीज तथा सब एसेम्बलीज इत्यादि को उत्पाद के कार्यक्षेत्र में शामिल नहीं किया जाना चाहिए ।

4087 GI/10-16A

viii. किसी सत्ता को घरेलू उद्योग का एक हिस्सा माना जाए अथवा नहीं इसका निर्धारण करने के लिए "पर्याप्त" परिवर्तन की अवधारणा एक संवैधानिक अपेक्षा नहीं है।

ix. तेजस को संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद के पुर्जों तथा संघटकों का आयातक माना जाना चाहिए।

x. कंपनी ने मांगी गई सभी संगत सूचनाएं उपलब्ध कराई हैं। यह कथन कि कंपनी ने वर्तमान कार्यवाहियों के संबंध में सहयोग नहीं किया है, भ्रामक है।

xi. सार्वजनिक सुनवाई हेतु अनुरोध - पाटनरोधी कार्यवाहियों के संबंध में "विधिवत प्रक्रिया" की अपेक्षा में सुनवाई अपेक्षित होती है और इस प्रकार के अनुरोध को अखीकार नहीं किया जा सकता है। प्राधिकारी द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित निर्धारण संगत आधार को प्रकट किए बिना किया गया है और इसे स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।

क. तेजस ने भारत एवं विदेशों में एस टी एम 64 का उत्पादन एवं बिक्री की है (पृष्ठ 30 पैरा 36 (ख))

ख. तेजस ने वाणिज्यिक मात्राओं में अर्थात बी एस एन एल के लिए भी एस टी एम 64 का उत्पादन प्रदर्शित किया है। [ पृष्ठ 36 पैरा 36 (ख) ]

ग. तेजस ने एस टी एम 256 का विनिर्माण किया है। [ पृष्ठ 36 पैरा 36(ग) ]

घ. जांच अवधि के दौरान तेजस द्वारा एस डी एच प्रौद्योगिकी के डी एक्स सी उपकरण का उत्पादन एवं आपूर्ति की गई है।

ड. टी ई एम ए (एक औद्योगिक एसोसिएशन) का पत्र

### प्राधिकारी द्वारा जांच

192. प्राधिकारी नोट करते हैं कि वी एम सी एल ने हितबद्ध पक्षकार के रूप में अपने दर्जे को स्थापित नहीं किया है। नियम 2 (ग) के अंतर्गत एक हितबद्ध पक्षकार की परिभाषा निम्नानुसार है:-

(ग) "हितबद्ध पक्षकार" में निम्नलिखित शामिल होंगे -

(i) किसी ऐसी वस्तु के निर्यातक अथवा विदेशी उत्पादक अथवा आयातक जो भारत में पाटित किए जाने के कारण जांचाधीन हो अथवा कोई व्यापारी अथवा व्यावसायिक संघ जिसके अधिकांश सदस्य ऐसी वस्तु के उत्पादक निर्यातक अथवा आयातक हों;

(ii) निर्यातक देश की सरकार; तथा

(iii) भारत में समान वस्तु का एक उत्पादक अथवा कोई व्यापार तथा व्यावसायिक एसोसिएशन जिसके अधिकांश सदस्य, भारत में समान वस्तु का उत्पादन करते हों

193. वर्तमान मामले में, कंपनी ने यह निर्धारित नहीं किया है कि वह किस तरह से हितबद्ध पक्षकार है। कंपनी न तो उत्पाद की घरेलू उत्पादक है और न ही आयातक अथवा भारत की कोई उपभोक्ता है। अतः यह मानते हुए कि कंपनी ने हितबद्ध पक्षकार के रूप में अपनी विश्वसनीयता सिद्ध नहीं की है प्राधिकारी ने समय-समय पर कंपनी द्वारा उठाए गए मुद्दों एवं किए गए निवेदनों पर विचार करना उचित समझा है। अपने इस तर्क कि डी एक्स सी तथा एस टी एम भिन्न उत्पाद हैं, के समर्थन में उन्होंने आई आई टी, मुम्बई से एक पत्र के स्वरूप में ताजा साक्ष्य उपलब्ध कराया है। उसमें आगे यह दावा किया गया था कि एस टी एम 1 से 64 लाइन कार्ड हैं जिनका अधिक से अधिक एक परिवहन उपकरण के रूप में उपयोग किया जा सकता है जबकि डी एक्स सी एक अधिक उन्नत प्रौद्योगिकी है जो नेटवर्क के सभी प्रचालनों की आवश्यकताओं के लिए उपयुक्त है। उन्होंने आगे यह दावा किया है कि डी एक्स सी तथा एस टी एम विनिमेय/प्रतिस्थापनीय नहीं है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि उन्हीं साक्ष्यों से यह भी सिद्ध होता है कि डी एक्स सी तथा एस टी एम, दो भिन्न प्रकार के एस डी एम उपकरण हैं। इसके अलावा पत्र में यह भी कहा गया है कि डी एक्स सी केवल एस डी एच के लिए ही विशिष्टीकृत नहीं होना चाहिए जिसका अर्थ यह है कि डी एक्स सी निश्चित रूप से एक एस डी एच उपकरण भी है। प्राधिकारी का मानना है कि केवल इस तथ्य से कि अलग-अलग प्रकारों को विभिन्न विशिष्ट प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाया जाता है, यह तात्पर्य नहीं है कि ये विभिन्न प्रकार, वास्तव में असमान वस्तुएं हैं। निर्विवाद रूप से एस डी एच प्रसारण उपकरण में भी डी एक्स सी मौजूद होता है, इसका उत्पादन तथा विक्री घरेलू उद्योग द्वारा की जाती है और संबद्ध देशों से इसका आयात किया जाता है। इसके अलावा किसी अन्य मामले में किसी और प्रसारण प्रौद्योगिकी का डी एक्स सी विचाराधीन उत्पाद के कार्यक्षेत्र में नहीं आता है।

194. वी जे टी आई, मुम्बई द्वारा जारी पत्र के संबंध में प्राधिकारी ने नोट किया है कि वी जे टी आई के लिए उठाया गया प्रश्न ही अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण है। वी जे टी आई को एस डी एच तथा गैर एस डी एच डी एक्स सी के बीच भेद करने और अंतर बताने के लिए नहीं कहा गया है। इसके अलावा प्रश्न यह नहीं है कि क्या डी एक्स सी और एस टी एम, एस डी एच प्रसारण उपकरण हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त ऐसा प्रतीत होता है कि उत्पाद का कार्यक्षेत्र जिस पर प्राधिकारी द्वारा विचार किया गया है तथा जो किसी पक्षकार द्वारा अपनी राय दिए जाने से पूर्व सबसे आधारभूत अपेक्षित सूचना होती है, भी वी जे टी आई को ज्ञात नहीं है। न ही ऐसा मालूम होता है कि वर्तमान जांच का प्रयोजन, पाटनरोधी जांच में विचार किए जाने हेतु विचाराधीन उत्पाद का कार्यक्षेत्र वी जे टी आई की जानकारी में लाया गया है। ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि वी जे टी आई को यह सूचित किया गया है कि प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद के कार्यक्षेत्र में एस डी एच प्रसारण उपकरणों को शामिल किया है तथा डी एक्स सी तथा एस टी एम समान उत्पाद हैं। इसके बावजूद यह नोट किया गया है कि वी जे टी आई ने केवल यही निष्कर्ष निकाला है कि डी एक्स सी तथा एस टी एम के भिन्न विशिष्ट उपयोग हैं। उन्होंने पाटनरोधी

(उत्पाद विनिर्देशन, विनिर्माण प्रौद्योगिकी तथा प्रक्रिया, कार्य, कीमत निर्धारण इत्यादि जैसे मानदण्डों पर विचार करते हुए) में लागू उत्पाद मानदण्डों के आधार पर डी एक्स सी, एस डी एच संचरण उपकरण एस टी एम एस डी एच संचरण उपकरणों से मूलतः भिन्न हैं।

195. जहां तक एस टी एम 64 का संबंध है प्राधिकारी ने इस बात की पुनः अभिपुष्टि की है कि घरेलू उद्योग ने जांच अवधि के दौरान वास्तव में एस टी एम 64 का उत्पादन एवं बिक्री की है। एस टी एम 256 के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों के तर्क तथा उन पर प्राधिकारी के विचारों का पहले ही प्रकटन विवरण तथा वर्तमान जांच परिणाम में किसी स्थान पर उल्लेख किया गया है। इसके अलावा प्रकटन विवरण हेतु टिप्पणियों के रूप में अतिरिक्त सूचना/साक्ष्य प्रस्तुत करने के संबंध में प्राधिकारी ने नोट किया है कि हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उसे प्रस्तुत करने और प्राधिकारी द्वारा उसकी जांच किए जाने और जांच का परिणाम तैयार करने के लिए एक समय सीमा निर्धारित की गई है। अतः प्राधिकारी का मानना है कि जहां तक वर्तमान कार्यवाहियों का संबंध है, लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के स्वरूप में उनके द्वारा उपलब्ध कराई गई अतिरिक्त सूचना, जो असत्यापित भी है, अर्थीकार्य तथा अग्राह्य हैं।

### ई सी आई तथा हैंगझौऊ ई सी आई

196. प्रकटन विवरण के संबंध में अपनी टिप्पणियों में उन्होंने निम्नानुसार कहा है:-

- i. चूंकि सॉफ्टवेयर एस डी एच उपकरण हेतु महत्वपूर्ण निविष्टियों में से एक है अतः निर्यात कीमत के परिकलन के समय इसका पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए।
- ii. ऐसा प्रतीत होता है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी ने पी सी एन जिन्हें घरेलू बाजार में बेचा गया था हेतु घरेलू माल भाड़ा, करों इत्यादि के लिए समायोजन किए बिना सकल बिक्री कीमत का निर्धारण किया है।
- iii. प्राधिकारी ने 5% के समुचित लाभ पर विचार न करके सहयोगी निर्यातकों को दण्डित किया है, जिस पर अन्यथा ऐसे सहयोगी निर्यातकों के लिए विचार किया जाना था जिन्हें बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार प्रदान नहीं किया गया है।
- iv. प्राधिकारी ने पी सी एन विधि के अनुसार निर्यात कीमत का निर्धारण करने के लिए निर्धारित पद्धति के विपरीत घरेलू बाजार/तीसरे देशों में एसेम्बली/सब एसेम्बली वार बिक्री कीमत को आधार बनाया है।
- v. शेष पी सी एन हेतु सामान्य मूल्य के निर्धारण के संबंध में सामान्य मूल्य के परिकलन हेतु अपनाई जाने वाली विधि, निर्यात कीमत के निर्धारण में असंगत है।
- vi. यह ज्ञात नहीं है कि गैर क्षतिकारी कीमत का परिकलन करते समय घरेलू बाजार में तेजस द्वारा आपूर्त सहायक सामग्रियों की लागत पर विचार किया गया था अथवा नहीं।

vii. निर्यातकों (अर्थात् एव ई टी सी तथा ई सी आई) ने प्रत्येक बार विचाराधीन उत्पाद हेतु मानदण्डों/पद्धतियों ने परिवर्तन किए जाने के बावजूद पूर्ण सहयोग नहीं किया है।

viii. तेजस के पास डी एक्स सी के उत्पादन हेतु अपेक्षित क्षमता केवल 60 जी बी पी एस तक है। 60 जी बी पी एस से अधिक क्षमता वाले डी एक्स सी को शामिल किया जाना त्रुटिपूर्ण है।

ix. बिक्री, उत्पादन, उत्पादकता, रोजगार वेतन में वृद्धि के साथ इस्त्राइल से आयातों में गिरावट के कारण क्षति को स्वीकार करना कठिन है।

x. प्राधिकारी ने अपने प्रकटन विवरण में कोई कारण दिए बिना ई सी आई के लिए क्षति मार्जिन को संशोधित करके 5 - 15% कर दिया है।

xi. निर्यात कीमत का परिकलन करते समय एसेम्बलीज की भारित औसत कीमत पर विचार नहीं किया गया है जबकि सामान्य मूल्य का परिकलन करते समय भारित औसत कीमत का उपयोग किया गया है।

### प्राधिकारी द्वारा जांच

197. जहां तक एक्स डी एम प्रकार का संबंध है एन ई पी तथा एल पी के परिकलन हेतु प्राधिकारी ने एम्बेडेड सॉफ्टवेयर इत्यादि को शामिल करने का अनुरोध स्वीकार कर लिया है। बी जी प्रकार के संबंध में निर्यातक द्वारा इस विषय में किए गए अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि उन्होंने घरेलू बाजार में सॉफ्टवेयर की निःशुल्क बिक्री की है जैसा कि सत्यापन रिपोर्ट में रिकॉर्ड किया गया है। मार्जिनों का निर्धारण करने के लिए केवल घरेलू बिक्री पर लाभ को शामिल करते हुए एन वी के निर्धारण के संबंध में, तथा उसे कारखाना द्वारा रस्तर पर निर्धारित करते हुए उसको समुचित ढंग से शामिल किया गया है। यह स्पष्ट किया गया है कि क्षति रहित कीमत और क्षति मार्जिन के परिकलन में सहायक सामग्रियों को शामिल नहीं किया गया है। चूंकि प्रकटन विवरण के जारी किए जाने के पश्चात यह पाया गया है कि कुछेक तथ्यों को शामिल नहीं किया गया है और कुछ परिकलन संबंधी त्रुटियां भी हैं अतः दूसरा संशोधित प्रकटन विवरण जारी करना आवश्यक हो गया, जिसके कारण घरेलू उद्योग के लिए क्षति रहित कीमत पर पुनर्विचार किया गया था।

### मै0 एल्काटेल -ल्यूसेंट शंघाई बेल कं0 लि0

198. प्रकटन विवरण के उत्तर में उन्होंने निम्नानुसार वक्तव्य दिया है:-

i. "स्वामित्व", बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार, एम ई टी दर्जा प्रदान करने के लिए कंपनी के संगत प्रचालनों के संबंध में उल्लेखनीय राज्य हस्तक्षेप के लिए संगत मानदण्ड नहीं है।

4087 GI/10-16 B

- ii. भारत में आयात कीमतों का उपयोग करना पैरा 7 में परिकल्पित औचित्य के अधिदेश के अनुरूप नहीं है। प्राधिकारी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय कीमतों को पूरी तरह नजरअंदाज किया गया है।
- iii. चूंकि पी सी एन, संघटक, डिजाइन आदि भिन्न-भिन्न हैं अतः घरेलू उद्योग की कीमतों को अपनाना उचित नहीं होगा।
- iv. परिवर्तित विचाराधीन उत्पाद के संदर्भ में, जांच के कार्यक्षेत्र, क्षति विश्लेषण में भी परिवर्तन किया जाना अपेक्षित है।
- v. दिनांक 27/02/2010 की अधिसूचना सं0 18/2010-सीमाशुल्क (एन टी) के नियम 2 (ख) में संशोधन के मद्देनजर आवेदक उद्योग को घरेलू उद्योग माना नहीं जा सकता है।

### प्राधिकारी द्वारा जांच

199. प्राधिकारी नोट करते हैं कि नियमों के अनुसार प्राधिकारी द्वारा यह निर्धारित किया जाना अपेक्षित है कि कच्ची सामग्रियों, प्रौद्योगिकी तथा श्रम लागत, उत्पादन, बिक्री तथा निवेश सहित कीमतों, लागतों तथा निविष्टियों के संबंध में संबंधित फर्मों के निर्णय आपूर्ति तथा मांग को दर्शाने वाले बाजार संकेतकों को दर्शाते हैं और इस संबंध में राज्य द्वारा अत्यधिक हस्तक्षेप नहीं किया गया है। आगे प्राधिकारी नोट करते हैं कि पण्धारकों में से एक जिसके पास महत्वपूर्ण हिस्सा है, राज्य के स्वामित्व अथवा नियंत्रण में है। निर्यातक द्वारा यह स्थापित करना अपेक्षित है कि इन मानदण्डों पर उसके निर्णय राज्य के प्रभाव से स्वतंत्र हैं। निर्यातक यह सिद्ध करने में विफल रहा है कि वह राज्य के हस्तक्षेप से स्वतंत्र है। जैसाकि कहीं उल्लेख किया गया है, प्राधिकारी ने निर्यातक उत्पाद प्रकार के पी सी एन पर विचार करके सामान्य मूल्य का निर्धारण किया है। जहां तक निविष्टि कीमतों का संबंध है प्राधिकारी का मानना है कि घरेलू उद्योग की कीमतों पर विचार करना अनुचित नहीं होगा। प्राधिकारी नोट करते हैं कि नियम 2 (ख) की भाषा में परिवर्तन से, प्राधिकारी द्वारा निर्धारित घरेलू उद्योग के कार्यक्षेत्र के संबंध में जांच परिणाम निष्प्रभावी नहीं होंगे।

### तिरुमला सेवन हिल्स प्रा० लि०

200. कंपनी ने अकेले तथा स्वतंत्र रूप से आयात करते हुए व्यापक प्रकटन विवरण का मूल्यांकन करते हुए तथा विचाराधीन उत्पाद के दायरे में संघटकों/पुर्जों को शामिल न करते हुए आगे यह कहा है कि इससे न केवल भारतीय विनिर्माता को इस अत्यधिक प्रतिस्पर्धी वातावरण में प्रतिस्पर्धी बने रहने में सहायता प्राप्त होगी बल्कि अन्य भारतीय कंपनियों के लिए भी विनिर्माण हेतु अवसर प्राप्त होंगे। उन्होंने यह भी कहा है कि पी यू सी के लिए व्यापक विवरणों के अलग - पी यू सी को और अधिक स्पष्ट बनाने के लिए 8 अंकीय एच एस कोड 85176260 का भी उल्लेख किया जाना चाहिए। उनकी यह भी अपेक्षा है कि पी यू सी से पुर्जों और संघटकों को स्पष्ट रीति से अपवर्जित किया जाए ताकि अधिक पारदर्शिता आ सके और भारतीय सीमाशुल्क में किसी प्रकार की संभ्रान्ति से बचा जा सके। उन्होंने एच डी एच के अतिरिक्त पी डी एच, सी डब्ल्यू डी एम

तथा डी डब्ल्यू डी एम जैसे सभी मल्टीप्लेक्सिंग प्रौद्योगिकी उत्पाद को स्पष्ट रूप से कार्य क्षेत्र से बाहर रखने की मांग की है ताकि भारतीय सीमाशुल्क के लिए स्थिति स्पष्ट हो सके ।

### प्राधिकारी द्वारा जांच

201. प्राधिकारी ने अपने मत को दोहराया है । पाटनरोधी शुल्क को सीमाशुल्क वर्गीकरण, जहां वस्तुओं को स्वीकृति हेतु सूचित किया जाता है, पर ध्यान न देते हुए वर्तमान अधिसूचना में यथापरिभाषित विचाराधीन उत्पाद पर ही लागू किया जाता है । तथापि प्राधिकारी ने शुल्क तालिका की पाद टिप्पणियों के रूप में इन मुद्दों का समाधान किया है ।

### पृथ्वी

202. प्रकटन विवरण के उत्तर में, उन्होंने निम्नलिखित टिप्पणियां प्रस्तुत की हैं :

#### i. सामान्य निवेदन

1. प्राधिकारी ने उत्पादन, गोपनीयता संबंधी मुद्दों के अर्थ जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों के संबंध में कानून के विपरीत कार्य किया है ।

2. एस टी एम 64 तथा डी एक्स सी जो ऐसी मद्दें हैं जिनके संबंध में रिकॉर्ड में यह दर्शाया गया है कि आवेदक के पास उनके लिए विनिर्माण तथा आपूर्ति क्षमताएं नहीं हैं, पर शुल्क लागू करने की सिफारिश करने से व्यापक राष्ट्रीय हित को क्षति पहुँचती है ।

3. प्राधिकारी द्वारा विचाराधीन उत्पाद से डी डब्ल्यू डी एम को हटा दिए जाने के बाद भी डी डब्ल्यू डी एम के आयात पर इस आधार पर पाटनरोधी शुल्क लगाया जा रहा है कि वे विचाराधीन उत्पाद में शामिल हैं ।

#### iii.) विशिष्ट निवेदन

1. वर्तमान कार्यवाहियों के संबंध में असहयोग - प्राधिकारी ने इस बात का गलत निर्धारण किया है कि पृथ्वी ने प्राधिकारी के साथ सहयोग नहीं किया है । प्राधिकारी द्वारा मांगी गई संपूर्ण जानकारी पृथ्वी ने उपलब्ध कराई थी ।

2. सूचना प्रस्तुत न करना - संवैधानिक अपेक्षाओं से इतर सूचना के अतिरिक्त सभी अन्य सूचनाएं प्रस्तुत की गई थीं ।

3. सार्वजनिक सुनवाई - पी यू सी के संबंध में विभिन्न जटिलताओं के आलोक में पुनः सुनवाई करवाने का अनुरोध किया गया था ।

4. विचाराधीन उत्पाद

क. एस टी एम 64, एस टी एम 256 तथा डी एक्स सी, एस टी एम 1, एस टी एम 4 तथा एस टी एम 16 के "समान उत्पाद" नहीं हैं।

i. एस टी एम 64, एस टी एम 256 तथा डी एक्स सी को पी यू सी में शामिल नहीं किया जा सकता है क्योंकि वे आवेदक द्वारा उत्पादित उत्पादों से तकनीकी अथवा वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय नहीं हैं।

ii. डी टी एक्स उपकरण, उपकरणों के प्रयोजन तथा उपयोगों, वार्तविक विशेषताओं, नेटवर्क लोकेशन आदि के आधार पर एस टी एम उपकरणों से भिन्न हैं।

iii. एस टी एम 64, एस टी एम 256 तथा डी एक्स सी उपकरणों के लिए घरेलू उद्योग के संघटन, पाटन, क्षति, कारणात्मक संबंध इत्यादि का अलग से निर्धारण किए जाने की आवश्यकता है।

ख. एस टी एम 64 तथा डी एक्स सी को पी यू सी से अलग किया जाना चाहिए।

i. प्राधिकारी का यह निष्कर्ष कि आवेदक ने एस टी एम 64, डी एक्स सी का उत्पादन शुरू किया है, किरी साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं है। इसके अलावा, इस संबंध में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों पर ध्यान नहीं दिया गया है।

ii. आवेदक जांच अवधि के दौरान एस टी एम 64, डी एक्स सी उपकरणों का विनिर्माण नहीं कर रहे थे।

iii. आवेदक एस टी एम 64, डी एक्स सी हेतु घरेलू उद्योग माने जाने के लिए मानदण्डों को पूरा नहीं करते हैं क्योंकि निर्दिष्ट प्राधिकारी के जांच परिणामों में इसका कोई उल्लेख नहीं है।

ग. एस टी एम 256 को पी यू सी में शामिल नहीं किया जाना चाहिए।

i. देश में एस टी एम 256 का कोई उत्पादन नहीं किया जाता है।

ii. आवेदक एस टी एम 256 के लिए घरेलू उद्योग बनने की योग्यता नहीं रखते हैं। केवल क्षमता, जांच उपकरण के विकास में निवेश से ही घरेलू उद्योग का निर्धारण नहीं किया जा सकता है।

iii. उपर उल्लिखित कारणों से एस टी एम 256 को पी यू सी के कार्यक्षेत्र में शामिल नहीं किया जा सकता है।

घ. एसेम्बलीज, सब एसेम्बलीज तथा पॉप्यूलेटेड सर्किट बोर्ड्स ("पी री बी")

- i. एसेम्बलीज तथा सब एसेम्बलीज को इस तथ्य के बावजूद कि ये उत्पाद पुर्जों तथा संघटकों की प्रकृति के हैं, पी यू सी के एक हिस्से के रूप में बनाए रखा गया है ।
- ii. एसेम्बलीज तथा सब एसेम्बलीज अपने आप में एस डी एच उपकरण नहीं हैं ।

### 5. घरेलू उद्योग

क. यह निर्धारित करने के लिए कि एक सत्ता, विनिर्माता है केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कानून के तहत विनिर्माण की परिभाषा को आधार बनाया जाना चाहिए ।

ख. पृथ्वी एवं अन्य विनिर्माताओं को घरेलू उद्योग न माने जाने का आधार गलत है । यह निर्धारित करने के लिए कि किसी सत्ता को घरेलू उद्योग का एक हिस्सा माना अथवा न माना जाए, "पर्याप्त" परिवर्तन की अवधारणा एक संवैधानिक अपेक्षा नहीं है ।

ग. तेजस को कार्यवाहियां जारी रखने की अनुमति देकर तथा अन्य विनिर्माताओं को घरेलू उद्योग के कार्यक्षेत्र में शामिल न करके आवेदक को अधिमानी व्यवहार प्रदान किया गया है ।

### 6. क्षति विश्लेषण

क. पी यू सी का पुनर्निर्धारण किए जाने की आवश्यकता है क्योंकि आवेदक के पास एस टी एम 64, एस टी एम 256, डी एक्स सी के लिए विनिर्माण क्षमता नहीं है । अतः उन्हें पी यू सी में शामिल नहीं किया जा सकता है ।

ख. तदनुसार, एक नया क्षति विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है और आवेदक द्वारा विनिर्मित उत्पाद के संबंध में इसके परिणामस्वरूप आवेदक को कोई क्षति नहीं होगी ।

### 7. जांच परिणाम, साक्ष्य रहित हैं और उन्हें आधार को प्रकट किए बिना प्रस्तुत किया गया है

क. एस टी एम 64, एस टी एम 256, एस डी एच प्रौद्योगिकी के डी एक्स सी उपकरण के उत्पादन जैसे कुछेक जांच परिणामों के लिए साक्ष्य तथा आधार आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे हैं/किए गए हैं ।

ख. हितबद्ध पक्षकारों को टी ई एम ए के पत्र के विषय में नहीं बताया गया है ।

ग. एन आई पी तथा पाटन मार्जिनों के रेंज के संबंध में भी परिकलनों को निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा उसके संबंध में कोई कारण बताए बिना ही परिवर्तित किया गया था ।

4087 61/10-17A

### प्राधिकारी द्वारा जांच

203. उनके द्वारा उठाए गए मुद्दे अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा भी उठाए गए हैं और इन जांच परिणामों में उनका समुचित समाधान किया गया है। इसके अलावा कंपनी ने हितबद्ध पक्षकार के रूप में अपनी स्थिति को रथापित नहीं किया है। इसके विपरीत प्रकटन विवरण के उत्तर में उपलब्ध कराए गए साक्ष्य से पाटनरोधी नियमों के नियम 2 (ग) के अर्थों के भीतर हितबद्ध पक्ष के रूप में उनकी पात्रता के विषय में संदेह उत्पन्न होता है।

### हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए अन्य सामान्य मुद्दों की जांच

204. उठाए गए कुछेक सामान्य मुद्दों के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस आधार पर कि प्राधिकारी द्वारा हितबद्ध पक्षकारों को संगत सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है, अनेक हितबद्ध पक्षकारों ने प्राधिकारी द्वारा प्रकट किए गए अनेक तथ्यों पर सवाल उठाए हैं। प्राधिकारी इस संबंध में नोट करते हैं कि हालांकि याचिकाकर्ता और हितबद्ध पक्षकार नियम 7 के भीतर गोपनीयता का दावा करने के हकदार हैं, तथापि प्रकटन विवरण अथवा वर्तमान जांच परिणामों में प्राधिकारी द्वारा किए गए प्रकटन भी नियम 7 की अपेक्षाओं के अध्यधीन हैं। अतः तथ्यों को अथवा ऐसे तथ्यों के संबंध में जांच परिणामों को रिकॉर्ड करते समय प्राधिकारी संगत साक्ष्य को प्रकट नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा प्राधिकारी ने प्रकटन विवरण अथवा वर्तमान जांच परिणामों के माध्यम से याचिकाकर्ता अथवा हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत सूचना/साक्ष्य के सार को हितबद्ध पक्षकारों के समक्ष प्रकट किया है और इसी के आधार पर हितबद्ध पक्षकारों को अपने हितों की सुरक्षा करने का अवसर प्राप्त हुआ है।

205. अनेक आर्थिक मानदण्डों, विशेष रूप से मात्रा संबंधी मानदण्डों में सुधार का संदर्भ लेते हुए अनेक हितबद्ध पक्षकारों ने इस बात पर प्रश्न उठाया है कि चूंकि घरेलू उद्योग के निष्पादन में कुछेक मानदण्डों के अनुसार सुधार हुआ है और कुछेक मानदण्डों के अनुसार गिरावट आई है अतः प्राधिकारी द्वारा इस बात की जांच की जानी अपेक्षित है कि क्या कुछेक मानदण्डों के संबंध में घरेलू उद्योग के निष्पादन में गिरावट अन्य मानदण्डों में घरेलू उद्योग के निष्पादन में सुधार से इस सीमा तक अधिक है कि उससे यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि घरेलू उद्योग को क्षति पहुँची है। तथापि यदि कुछेक मानदण्डों में सुधार अन्य मानदण्डों में गिरावट से अधिक है तो प्राधिकारी यह निर्धारित करेंगे कि घरेलू उद्योग को क्षति नहीं पहुँची है। प्राधिकारी ने क्षति का विश्लेषण करने के पश्चात यह नोट किया है कि लाभ, निवेश पर आय तथा नकद लाभों के संदर्भ में घरेलू उद्योग के निष्पादन में वार्तविक गिरावट आई है। अतः केवल एक ही निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि उत्पादन, घरेलू बिक्री इत्यादि जैसे मानदण्डों में सुधार के बावजूद भी घरेलू उद्योग के निष्पादन को वार्तविक क्षति पहुँची है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि समुचित लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से वस्तुओं की बिक्री करने के लिए एक व्यावसायिक उद्यम की स्थापना की गई है। किसी व्यावसायिक उद्यम जिसके उत्पादन एवं बिक्री मात्रा में लगातार अच्छी वृद्धि हो रही है, लेकिन उसके लाभों और निवेश पर आय में इस सीमा तक गिरावट हो रही हो जिससे वह नकारात्मक हो जाए तो उसके निष्पादन को अच्छा नहीं माना जा सकता है। वर्तमान गामले में यद्यपि यह पाया गया कि घरेलू उद्योग के उत्पादन एवं बिक्री में सुधार आया तथापि यह भी पाया गया कि घरेलू उद्योग को वित्तीय हानि, निवेश पर नकारात्मक आय तथा नकारात्मक नकद लाभ हुआ है।

206. प्राधिकारी आगे यह मानते हैं कि सी के डी, एस के डी और उप संयोजन और कुछ नहीं अपितु उत्पाद का प्रकार है जिसका एस डी एच उपकरण में एकीकरण से भिन्न कोई उपयोग नहीं होता है। इनमें विशिष्ट विशेषता, कार्य या उपयोग नहीं होता है। उत्पाद का बीज उपयोग के लिए तैयार तथा एस के डी अथवा उप संयोजन दोनों स्थितियों में तैयार किया जा सकता है जैसा कि प्रतिवादी निर्यातकों के रिकार्ड के सत्यापन के दौरान निर्विवाद सिद्ध किया गया था।

207. चूंकि प्राधिकारी ने एकल संघटकों को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से अलग रखा है इसलिए याचिकार्ता द्वारा ऐसे एकल संघटकों के आयात को आरोपित पाटित उत्पाद का आयात नहीं माना जा सकता।

#### पाटित कीमत पर बेची न गई आयात की मात्रा एवं कीमत

208. संबद्ध वस्तु की आपूर्ति दूसरे देशों को की जा रही है। तथापि, तीसरे देशों से आयात कीमत संबद्ध देशों की तुलना में काफी अधिक है। तीसरे देशों से हुए आयातों के कारण इस चरण पर घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति नहीं हो रही है।

#### मांग में कमी और/खपत की पद्धति में परिवर्तन

209. समूल क्षति अवधि के दौरान संबद्ध वस्तु की मांग में अच्छी वृद्धि हुई है, इसलिए घरेलू उद्योग को क्षति के देश में मांग की कमी से कोई लेना-देना नहीं है। खपत और मांग के आंकड़ों से उत्पाद की खपत पद्धति में किसी परिवर्तन का पता नहीं चलता है और यह घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाने वाला कारक नहीं रहा है।

#### विदेशी तथा घरेलू उत्पादकों के व्यापार प्रतिबंधात्मक व्यवहार और उनके बीच प्रतिस्पर्धा

210. वस्तु मुक्त रूप से आयात योग्य है। आवेदक संबद्ध वस्तु के प्रमुख उत्पादक हैं और अत्यधिक घरेलू उत्पादन और बिक्री करते हैं। प्राधिकारी की जानकारी में प्रतिस्पर्द्धा की स्थितियों अथवा व्यापार प्रतिबंधात्मक व्यवहारों का कोई साक्ष्य नहीं आया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध वस्तु का एक ही बाजार है जहां संबद्ध देशों से पाटित आयात घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु से सीधी प्रतिस्पर्द्धा करते हैं। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि आयातित संबद्ध वस्तु और घरेलू रूप से उत्पादित वस्तु समान वस्तुएं हैं तथा आयातित उत्पाद की बिक्री घरेलू रूप से उत्पादित संबद्ध वस्तु के रूप में समान अनुप्रयोगों/अंतिम उपयोगों की पूर्ति की जाती है।

#### प्रौद्योगिकी विकास

211. उत्पाद की उत्पादन प्रौद्योगिकी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अतः प्रौद्योगिकी विकास क्षति का कारण नहीं है। तथापि, उच्च क्षमता के माडलों का विकास करना इस उद्योग का नियमित परिदृश्य है और दोनों में प्रौद्योगिकी का यह पहलू अपनाया जाता है।

#### निर्यात निष्पादन

212. प्राधिकारी ने निर्यात निष्पादन की सूचना पर अलग से विचार किया है और क्षति विश्लेषण केवल घरेलू बिक्री पर आधारित है।

213. प्राधिकारी की जानकारी में ऐसा कोई अन्य कारक नहीं लाया गया है जिससे घरेलू उद्योग को सीधावित क्षति हो सकती है ।

### कारणात्मक निष्कर्ष

214. जांच का निष्कर्ष निकालते हुए प्राधिकारी यह मानते हैं कि घरेलू उद्योग को क्षति पाटित आयातों के कारण हुई है । प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि:

- i. विदेशी उत्पादकों द्वारा प्रस्तावित कीमत घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तावित कीमत रो कम है । परिणामतः उपभोक्ता पाटित आयातों का सहारा ले रहे हैं ।
- ii. आयातों में वृद्धि के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग अपना बाजार हिस्सा नहीं बढ़ा सका है । घरेलू और आयातित उत्पाद के बीच कीमत में भारी अंतर होने के कारण आयातों द्वारा घरेलू उद्योग की कीमत में ह्रास हो रहा है । परिणामतः घरेलू उद्योग इस अवधि में कीमत कम करने के लिए बाध्य हुआ है ।
- iii. घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तावित कीमत में कमी के परिणामस्वरूप उसकी लाभप्रदता तथा निवेश पर परिणामी आय और नकद प्रवाह अत्यधिक प्रभावित हुए हैं ।

### सिफारिशें

215. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच की शुरुआत कर उसकी सूचना सभी हितबद्ध पक्षकारों को दी गई थी और निर्यातकों, आयातकों एवं अन्य हितबद्ध पार्टियों को पाटन, क्षति एवं कारणात्मक संबंध के पहलू के बारे में सकारात्मक सूचना प्रदान करने का पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था । विनिर्दिष्ट नियमों के अनुसार पाटन, क्षति एवं पाटन तथा घरेलू उद्योग को हुई क्षति के बीच कारणात्मक संबंध के बारे में जांच शुरू एवं संपन्न करने के बाद राकारात्मक पाटन और ऐसे पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को हुई वास्तविक क्षति का निर्धारण करने के बाद प्राधिकारी का यह मत है कि पाटन एवं क्षति को समाप्त करने के लिए अंतिम शुल्क लगाना अपेक्षित है । अतः प्राधिकारी यह आवश्यक समझते हैं और संबद्ध देश रो संबद्ध वस्तु के आयात पर नीचे उल्लिखित प्रपत्र में और तरीके से अंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं ।

216. प्राधिकारी द्वारा अपनाए गए कमतर शुल्क नियम को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी पाटन भार्जिन और क्षति भार्जिन जो भी कम हो, के बाबर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं ताकि घरेलू उद्योग को हुई क्षति समाप्त की जा सके । तदनुरार संबद्ध देशों/क्षेत्रों के मूल की या वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के सभी आयातों पर केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में जारी की जाने वाली अधिसूचना की तारीख से निम्नलिखित तालिका के कालम 8 में उल्लिखित राशि के बाबर पाटनरोधी शुल्क, जो आयातों के सी आई एफ मूल्य का प्रतिशत होगा, लगाने की सिफारिश की जाती है ।

क्र. सं.	उप-शीर्ष	विवरण	उद्गम का देश	निर्यात का देश	उत्पादक	निर्यातक	राशि	माप की इकाई
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
1	851762	"नीचे दी गई टिप्पणी के अनुसार सिंक्रोनस डिजिटल हाइआर्की ट्रांसमिशन उपकरण"	चीन जन. गण.	चीन जन. गण.	मे. फाइबरहोम टेलीम्यूनिकेशन टैक्नोलॉजीज लि.	मे. फाइबरहोम टेलीम्यूनिकेशन टैक्नोलॉजीज लि.	266%	आयातों के सीआईएफ मूल्य का %
2	-वही-	-वही-	चीन जन. गण.	चीन जन. गण.	अल्काटेल-लूसेंट शंघाई बेल कंपनी लि.	अल्काटेल-लूसेंट शंघाई बेल कंपनी लि.	45%	आयातों के सीआईएफ मूल्य का %
3	-वही-	-वही-	चीन जन. गण.	चीन जन. गण.	मे. जैड टी ई कार्पोरेशन	मे. जैड टी ई कार्पोरेशन	36%	आयातों के सीआईएफ मूल्य का %
4	-वही-	-वही-	चीन जन. गण.	चीन जन. गण.	मे. हैंगज्ञाऊ ई सी आई टेलकॉम कंपनी लि., इजराइल लि.	मे. ई सी आई टेलकॉम, इजराइल	7%	आयातों के सीआईएफ मूल्य का %
5	-वही-	-वही-	चीन जन. गण.	चीन जन. गण.	उपर्युक्त क्र. सं. 1,2 व कोई 3 और 4 से इतर कोई अन्य संयोजन	कोई	266%	आयातों के सीआईएफ मूल्य का %
6	-वही-	-वही-	चीन जन. गण.	चीन जन. गण. से इतर कोई	कोई	कोई	266%	आयातों के सीआईएफ मूल्य का %
7	-वही-	-वही-	कोई	चीन जन. गण.	कोई	कोई	266%	आयातों के सीआईएफ मूल्य का %
8	-वही-	-वही-	इजराइल	इजराइल	मे. ई सी आई टेलकॉम लि., इजराइल	मे. ई सी आई टेलकॉम लि., इजराइल	3%	आयातों के सीआईएफ मूल्य का %
9	-वही-	-वही-	इजराइल	इजराइल	उपर्युक्त क्र. सं. 8 से इतर कोई अन्य संयोजन	कोई	70%	आयातों के सीआईएफ मूल्य का %
10	-वही-	-वही-	इजराइल	चीन जन. गण. तथा इजराइल से इतर कोई	कोई	कोई	70%	आयातों के सीआईएफ मूल्य का %
11	-वही-	-वही-	चीन जन. गण. से कोई	इजराइल	कोई	कोई	70%	आयातों के सीआईएफ मूल्य का %

\*\*\*

टिप्पणी 1 विचाराधीन उत्पाद में शामिल होंगे - " सिंक्रोनस डिजीटल हाइआर्की ट्रांसमिशन उपकरण, अर्थात् एस टी एम-1, एस टी एम-4, एस टी एम-16, एस टी एम-64, एस टी एम-256 जो संयोजित रूप में, सी के डी, एस के डी रूप म हैं, उसके संयोजन और उप संयोजन अथवा जो आकस्मिक ब्रॉड बैंड/सेल्युलर उपकरण से फिट किए गए हैं। विचाराधीन उत्पाद में एड ड्रॉप मल्टीप्लेक्सर, (ए डी एम), (केवल एस डी एच अनुप्रयोग हेतु), मल्टीप्ल एड ड्रॉप मल्टीप्लेक्सर (एम ए डीएम) तथा डिजीटल क्रॉस-कनेक्ट, (डी एक्स सी) (केवल एस 4087 GI/10-178

डी एच अनुप्रयोग हेतु), पापुलेटेड सर्किट बोर्ड, (केवल एस डी एच अनुप्रयोग हेतु), और उपकरण अथवा उसके संयोजनों/उप संयोजनों के साथ आयात किए जाने पर उपकरण के भाग के रूप में आयातित पुर्जे/संघटक भी शामिल होंगे। विचाराधीन उत्पाद में इन उपकरणों के अभिन्न भाग और जिसकी खरीद उपकरण के भाग के रूप में या पृथक रूप में की जा सकती है, एस डी एच के लिए नियम साफ्टवेयर भी शामिल होगा। तथापि, एकल आधार पर आयातित संघटक/पुर्जे विचाराधीन उत्पाद के दायरे में नहीं आते हैं।"

टिप्पणी-2 - एस डी एच उपकरण से अनिवार्यतः आप्टिकल फाइबर के जरिए संकेतों का प्रेषण होता है। ऐसा एस डी एच उपकरण से हो सकता है जो विद्युत कॉपर माध्यम या माइक्रो रेडियो तरंगों के जरिए प्रेषण के लिए नियत हो। केवल आप्टिकल फाइबर के जरिए ही आंकड़े प्रेषित करने वाले एस डी एच उपकरण पर पाटनरोधी शुल्क लगाया जाएगा।

टिप्पणी-3 - जब एस डी एच का आयात अंतिम ब्रोड बैंड/सेलुलर उपकरण के भाग के रूप में किया जाएगा तो पाटनरोधी शुल्क आयातों के केवल एस डी एच भाग पर ही संदेय होगा। इसी प्रकार जब अंतिम ब्रोड बैंड/सेलुलर उपकरण का आयात एस डी एच उपकरण के भाग के रूप में किया जाएगा तो पाटनरोधी शुल्क आयातों के केवल एस डी एच भाग पर ही संदेय होगा।

टिप्पणी-4 - पी डी एच, सी उब्ल्यू डी एम, डी डब्ल्यू डी एम, माइक्रोवेव प्रणाली, जीपीओएन, डीएसएलएएम, एम एस ए ए एन, बी आई टी एस, रूटर, पी टी एन, पी डी एस एन, एसजीएसएन, एमजीडब्ल्यू, बीटीएस, बीएससी, एमएससी, ओएनटी, एचएलआर, एचएसएस तथा एसडीएच न देने के कारण एम आर पी और उसका कोई स्वरूप विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर हैं और इसलिए इन पर पाटनरोधी शुल्क लागू नहीं होगा।

टिप्पणी-5 - ऐसे माइक्रोवेव रेडियो टर्मिनल पाटनरोधी शुल्क के भुगतान से बाहर हैं जिनमें एस डी एच ट्रांसमिशन उपकरण के लिए एस डी एम-1 इंटर्लेस हो और जो रेडियो तथा एस डी एच उपकरण के बीच संपर्क स्थापित करने हेतु वास्तविक माध्यम के रूप में कार्य करते हों।

216. उपर्युक्त के अधीन रहते हुए दिनांक 7 सितंबर, 2010 को अधिसूचना द्वारा अधिसूचित अनंतिम जांच परिणामों की एतद्वारा पुष्टि की जाती है।

### आगे की प्रक्रिया

217. इस सिफारिश से उत्पन्न होने वाले केन्द्र सरकार के आदेशों के विरुद्ध कोई अपील अधिनियम के संगत उपबंधों के अनुसार सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क तथा सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण में दायर की जा सकेगी।

218. प्राधिकारी यहां यथाअनुशंसित निश्चयात्मक उपाय को जारी रखने, उनमें संशोधन करने या उन्हें समाप्त करने की आवश्यकता की इस अधिनियम के संगत प्रावधानों और इस संबंध में समय-समय पर जारी सार्वजनिक सूचनाओं के अनुसार समय-समय पर समीक्षा कर सकते हैं। प्राधिकारी द्वारा ऐसी किसी समीक्षा हेतु किसी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा यदि वह किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ निर्धारित समयावधि के अनुसार प्रस्तुत नहीं किया जाता है।

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**  
**(Department of Commerce)**  
**(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)**  
**NOTIFICATION**

New Delhi, the 19th October, 2010

**Final Findings**

**Subject : Anti-Dumping Investigations concerning imports of SDH Equipment originating in or exported from China PR and Israel**

**No. 14/2/2009-DGAD.**—Having regard to the Customs Tariff Act 1975 as amended in 1995 and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti- Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, (hereinafter referred as Rules) 1995 thereof;

**Procedure**

2. The procedure described below has been followed:

- a. The Designated Authority (hereinafter referred to as Authority), received an application filed by M/s Tejas Networks Limited (herein after referred to as the applicant) on behalf of the domestic industry, alleging dumping of Synchronous Digital Hierarchy Transmission Equipment (herein after referred to as SDH equipment or subject goods), originating in or exported from the People's Republic of China and Israel (hereinafter referred to as subject countries) and requested for initiation of anti dumping investigations for levy of anti dumping duties on the subject goods.
- b. The Authority on the basis of sufficient evidence submitted by the applicant on behalf of the domestic industry found it appropriate to initiate the investigations concerning imports of subject goods originating in or exported from China PR and Israel. The authority notified the Embassy of subject countries in New Delhi about the receipt of dumping allegation before proceeding to initiate the investigation in accordance with Rule 5 of the Rules.
- c. The Authority issued a public notice dated 21<sup>st</sup> April 2009 published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating Anti-Dumping investigations concerning imports of the subject goods originating in or exported from the subject countries in accordance with the Rule 5. Sub-Rule 6(1) of the Rules to determine the existence, degree and effect of alleged dumping and injury and to recommend the amount of antidumping duty, which, if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

- d. The Authority forwarded a copy of the public notice to the known exporters (whose names and addresses were made available by the applicant to the authority) and gave them opportunity to make their views known in writing within forty days from the date of the letter in accordance with the Rule 6 and requested them to file questionnaire responses and make their views known in writing within 40 days of the initiation notification.
- e. Copies of the non-confidential version of the petition filed by the domestic industry were made available to the known exporters and the Embassies of the subject countries in accordance with Rules 6 supra.
- f. The Authority forwarded a copy of the public notice to all the known importers (whose names and addresses were made available by the applicant to the authority) of subject goods in India and advised them to make their views known in writing within forty days from the date of issue of the letter in accordance with the Rule 6.
- g. The Embassies/Representatives of the subject countries in New Delhi were informed about the initiation of the investigation in accordance with Rule 6(2) with a request to advise the exporters/producers from their countries/territories to respond to the questionnaire within the prescribed time. A copy of the letter, non confidential version of the petition and exporter questionnaire sent to the exporter was also sent to the Embassies/ of subject countries in India along with a list of known exporters/ producers made available by the petitioner.
- h. A copy of the non-confidential application was also provided to other interested parties, wherever requested.
- i. The Authority sent questionnaire to following known exporters/ producers of the product in subject countries to elicit relevant information to the known exporters from subject countries in accordance with the rule 6.
  - i. Huawei Technologies Co., Ltd
  - ii. Wuhan Research Institute of Post & Telecommunication
  - iii. ZTE Corporation Ltd.
  - iv. Alcatel-Lucent
- j. Following exporters/foreign producers/association of foreign producers have responded to initiation notification and provided information/ submissions:
  - i. ZTE Corporation Ltd.
  - ii. Huawei Technologies Co. Ltd.
  - iii. Shenzhen Huawei Technologies Ltd.
  - iv. Hisilicon Technologies Ltd.
  - v. Fiberhome Telecommunications Technologies Co. Ltd.
  - vi. Wuhan Fiberhome International Technologies Co. Ltd.
  - vii. Hangzhou ECI Telecommunications Co. Ltd.
  - viii. ECI Telecommunications Co. Ltd.
  - ix. Alcatel Lucent Shanghai Bell Co. Ltd.
  - x. CCCME
  - xi. Alcatel-lucent Shanghai Bell Co.,
  - xii. UT Starcom

xiii. Ciena, USA

k. Questionnaire was sent to following importers:

- i. Aircel Limited
- ii. Prithvi Information System
- iii. Dishnet Wireless Limited
- iv. Punjab Communications Limited
- v. Bharati Airtel Limited
- vi. HTL GST
- vii. Bharat Sanchar Nigam Limited
- viii. Huawei India
- ix. Tata Teleservices Limited
- x. ZTE India
- xi. Tata Teleservices (Maharastra) Limited
- xii. ECI India
- xiii. Idea Cellular Limited
- xiv. Alcatel Lucent
- xv. Vodafone Essar Limited
- xvi. Nokia Seimens Networks
- xvii. Railtel Corporation of India Limited
- xviii. Erricson
- xix. Tata Communications
- xx. Himachal Futuristic Communications
- xxi. Reliance Communications Limited
- xxii. ICOMM
- xxiii. Shyam Telelinks

l. Following importers/consumers/association thereof have responded to the Authority and provided information/submissions:

- i. ECI India Pvt. Co. Ltd.
- ii. Huawei India Telecommunications Pvt. Ltd.
- iii. Vodafone Essar Ltd.
- iv. Vuppalamritha Magnetic Components Ltd.
- v. Prithvi Information's Solutions Ltd.
- vi. Huawei Technologies India Pvt. Ltd,
- vii. M/s MRO-TEK Ltd., Banglore
- viii. M/s Juniper Networks Pvt. Ltd., India,
- ix. Aircel Ltd.,
- x. Vodafone Esaar Ltd.,
- xi. Bharti Airtel Ltd.
- xii. ECI Telecom India Pvt. Limited,
- xiii. RAD Data Communications Ltd.
- xiv. Tatatele Service
- xv. BSNL,
- xvi. Tirumala Seven Hills

- m. Request was made to the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) and Central Board of Excise and Customs (CBEC) to arrange details of imports of subject goods for the past three years, including the period of investigations;
- n. The Authority made available non-confidential version of the evidence presented by various interested parties in the form of a public file and kept open for inspection by the interested parties;
- o. Optimum cost of production and cost to make and sell the subject goods in India based on the information furnished by the domestic industry on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) was worked out so as to ascertain whether Anti-Dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to Domestic Industry;
- p. The confidentiality claims of various interested parties in respect of the data submitted by them were examined and duly considered by the Authority. Wherever the Authority was satisfied with regard to claims of confidentiality and where the concerned interested party has provided sufficient non confidential version, the Authority has granted confidentiality to such information provided by interested parties.
- q. The information, which is by nature confidential or which has been provided by an interested party on a confidential basis has been treated as confidential in this Findings document. However, non confidential version of such confidential information has been disclosed to such an extent that the same permits reasonable understanding of the substance of information provided on confidential basis.
- r. Market Economy Treatment (MET) questionnaire was forwarded to all the known exporters and Embassy of China PR. Exporters were informed that authority proposes to examine the claim of the applicant in the light of para 7 and para 8 of Annexure I of Anti Dumping Rules, as amended. The exporters/producers of the subject goods from China PR were therefore requested to furnish necessary information/sufficient evidence as mentioned in sub-paragraph (3) of paragraph 8 to enable the Authority to consider whether market economy treatment be granted to cooperating exporters/producers.
- s. Investigation has been carried out for the period starting 1<sup>st</sup> April -- 31<sup>st</sup> Dec 2008 (9 months – POI). Data for the period 2005-06, 2006-07, 2007-08 and POI has been considered for assessment of injury to the domestic industry.
- t. Authority recorded preliminary finding on 7<sup>th</sup> September 2009, a copy of which was forwarded to all interested parties including Embassies of the subject countries in India. All interested parties were asked to file their comments on preliminary findings.
- u. The Authority held a public hearing on 21.12.09 to hear the interested parties orally, which was attended by representatives of interested parties. The interested parties were advised to file written submissions and were granted permission to file rejoinder to the submissions made by opposing interested parties. The written submissions and rejoinders received from interested parties, to the extent considered relevant, are being considered in this statement. For the purpose, all

interested parties were advised to file their submissions in writing latest by 04<sup>th</sup> Jan 2010 and were permitted to file rejoinder submissions latest by 17<sup>th</sup> Jan 2010.

v. The investigations could not be completed within the prescribed time of one year on account of Court proceedings associated with the case in Hon'ble High Court of Hyderabad and therefore an extension in time for completing the investigation by 20.10.2010 was sought and has been allowed by the Central govt.

w. On the spot verification of the data of the responding exporters who filed their submissions and invited the Authority for verification, were carried out to the extent necessary.

x. In view of large number of participating parties and a number of issues raised by these interested parties, the Authority has first brought out the submissions made by these interested parties. Further, in order to avoid repetition, the Authority has collectively brought out arguments by these interested parties.

y. In accordance with Rule 16 of the Rules supra, the essential facts /basis disclosed to known interested parties and comments received on the same have been considered in Final Findings.

z. \*\*\* in this notification represents information furnished by an interested party on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.

aa. Abbreviations used in this Final Findings Document represents as follows –

SN	Abbreviation	Explanation/meaning
1.	Authority	Designated Authority
2.	Act	Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995
3.	Rules	Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995
4.	PUC	Product under consideration, i.e., SDH Transmission Equipment as defined in the relevant para in this disclosure statement
5.	CKD	Completely knocked down condition
6.	SKD	Semi knocked condition
7.	DA	Designated Authority
8.	DI	Domestic industry
9.	ADA	WTO Agreement on Anti Dumping
10.	SDH	Synchronous Digital Hierarchy Transmission Equipment
11.	Tejas	Tejas Networks Ltd.
12.	VMCL	Vuppalamritha Magnetic Components Ltd
13.	Prithvi	Prithvi Information Solutions Ltd.
14.	BSNL	Bharat Sanchar Nigam Limited

### **Product under consideration and like article**

### **Submissions by Domestic Industry (Tejas) and other Indian producers**

3. Domestic industry made following submissions regarding product under consideration

a. The product under consideration in the present petition is “Synchronous Digital Hierarchy transmission equipment, its accessories, associated

software and its essential parts & components, in assembled, CKD, SKD form or fitted with eventual broadband/cellular equipment".

- b. SDH transmission equipments are also known as multiplexers, Add Drop Multiplexers (ADM), Multiple Add Drop Multiplexer (MADM), digital cross-connects. Populated PCBs, Power supply, Lasers, Chassis and software meant for SDH transmission equipment, etc. consist of essential parts of a SDH transmission equipments and are within the scope of the product under consideration provided the said components are meant for SDH transmission equipment application only.
- c. SDH transmission equipments can be bought either as transmission equipments or forming part of another equipment e.g., broadband and/or cellular (both GSM and CDMA) equipment. SDH transmission equipments forming part of broadband and/or cellular equipments are also within the scope of the product under consideration.
- d. Product under consideration is an assembly of a number of electronic components and/or electronic printed circuit boards, which are designed to perform the specific intended function of multiplexing for combined lower speed signals into high-speed signals for transmission through optical fiber over distances (short or long). Since, among other applications, these are installed at Base Transmission Stations, switch exchanges and other point of presence, SDH equipments installed at different locations may differ in terms of the associated properties.
- e. Different SDH equipment are comparable in term of essential product characteristics including physical and optical, production technology, manufacturing process, R&D Development, software capabilities, functions and usage, etc. Accordingly, various SDH equipments are one like product for the purpose of present investigation.
- f. The product under consideration can be imported either as complete equipment, or in CKD, SKD or even component form. Further, a number of accessories are required for connecting/ installing SDH transmission equipment in the network (E1 cables, PCM cables, power cables, racks, workstations etc.). Software is an integral part of these equipments, which may be bought either as a part of the equipment or separately. These all are also within the scope of the product under consideration.
- g. The product under consideration is classified under Chapter 85 of the Customs Tariff Act, 1975.
- h. The key effort involved in production of subject goods is in the development of technology. Substantial research & development efforts are put in by the producers globally in design & development of the subject goods, the extent of which may be gauged by the fact that about 60% of manpower deployed is in design & development of the product under consideration.
- i. The core of production is in technology, know-how, design and development of the product. The actual process of manufacturing is, in

fact, a much smaller part of the total activity involved in production and supply of subject goods and comprises of complex assembling of a large number of components on a PCB (populated PCBs) and then assembling and testing them as finished products.

- j. The production in the present product is an activity comprising of design and development of complex hardware, embedded software and network management software as well as the final assembly and test of the finished product. The petitioner, producers in subject countries and other global players all undertake combination of all these activities.
- k. The production process can be divided into following:
  - i. research
  - ii. product conceptualization,
  - iii. design & drawing
  - iv. product proto type developments
  - v. development of the technology,
  - vi. conceptualization and understanding of functionality,
  - vii. development of associated software
  - viii. product blue print /prototype development
  - ix. integration,
  - x. testing,
  - xi. assembly,
  - xii. software programming
  - xiii. test jigs,
- l. Any consumer of the product insists on a combination of all the above before placing orders on any party. Further, some of the consumers in India insist on sales & support being extended by someone from India. Therefore, the producers in subject countries have set up their own/related enterprises in India in order to provide sales and support services
- m. Design and development of the subject goods involves significant amount of resources on research and development. The petitioner has developed significant amount of intellectual property over the years. In similar fashion, the foreign producers have also developed significant amount of intellectual property over the years.
- n. The petitioner and major global players in this industry outsource a significant part of component manufacturing to specialized producers (Electronic Contract Manufacturers). These companies, who undertake a significant part of component manufacturing activities, are, however, mere job processors, having no knowledge whatsoever about the technology and design & development involved in the product. These job processors lack the knowledge of intellectual property required in production of the subject goods.
- o. The Indian Rules and WTO Agreement of Anti dumping does not prescribe anything with regard to scope of the product under consideration,

nor has it prescribed the parameters that should be considered for describing/ specifying the product under consideration.

- p. The petitioner researched upon a large number of cases investigation by India, EC and the US in support of its claim of scope of product under consideration. These includes decisions of the US ITC in the matters of Certain Tow-Behind Lawn Groomers and Parts Thereof from China PR, Diamond Sawblades and Parts Thereof From China PR and Korea, Gray Portland Cement and Cement Clinker From Japan, Hand Trucks and Certain Parts Thereof From China PR, Large Newspaper Printing Presses and Components Thereof, Whether Assembled or Unassembled from Japan, Mechanical transfer presses from Japan. Further, petitioner referred to decisions of the EC in the matters of Ironing boards, Steel tube and pipe fittings, Compact Disc Players (CDP).
- q. Domestic industry is entitled to seek relief under the law in respect of “an article” and such article means all its known forms/ species/ types.
- r. “SDH equipment” includes products in its various forms, different names, supplied in different forms. Multiplexers, Add Drop Multiplexers (ADM), Multiple Add Drop Multiplexer (MADM), digital cross-connects are different names of the same product. Populated PCBs, Power supply, Lasers, Chassis and software meant for SDH transmission equipment are various sub-set of the product.
- s. Product can be supplied in assembled form or broken into these various sub-set of the product. An exporter can export either the finished ready to use equipment, or in sub-assembly, cards, CKD/SKD conditions and carry out the remaining operations in India (involving negligible value addition). Further, the product can be produced and supplied in various sizes to meet specific customer requirement.
- t. The way SDH equipment is produced and used and the jurisprudence emerging out of various cases investigated by various investigating Authorities establishes that the scope of the product under consideration is not wide in the present case. Further, inclusion of parts/components is fully justified, considering the production activities relating to the product under consideration.
- u. The petitioner has sought imposition of anti-dumping duties only on parts/ components for SDH application.
- v. The claims of the interested parties for exclusion of various types are not bonafide for the following reasons
  - i. Multiplexors – Petitioner has large scale sale of SDH Multiplex.
  - ii. DWDM multiplexors are not part of present petition and investigations.
- w. As far as scope of the product under consideration is concerned, the only requirement under the law is whether (a) the various types included in the scope of the product under consideration constitute same article; (b) Tejas

is engaged in manufacture of an article which is like article to the product under consideration.

- x. Petitioner has referred to the decision of EC in the matter of fasteners and argued that the fact of no production of some particular component/part of the product does not disqualify a company from seeking protection on the product. The domestic industry should be engaged in production of the product and is not required to be offering parts of the product in the market.
- y. The petitioner has sought inclusion of parts and components as (a) these are specifically designed for production of SDH equipments, (b) these have no other application but for production of the product, (c) production of the product from the stage of parts/components/assemblies/sub-assemblies involves only a screw driver technology and therefore exclusion of these from the scope would imply permitting imports of these at dumped prices, which would lead to continued dumping and injury in spite of imposition of anti dumping duties. It has remained undisputed that the contention of the domestic industry in this regard is incorrect. Domestic industry also raised a question that if anti-dumping duties on product under consideration is justified, why imports of such items should be permitted and why such imports would not cause injury to the domestic industry. Domestic industry has also contended that the Authority can specify that such duty on parts, components, sub-assemblies can be implemented on declaration basis and the same can be specified in the relevant customs notification as well.
- z. DWDM Multiplexors and PDH multiplexors are different products. The Authority may specifically clarify the same to eliminate all doubts unnecessarily created by some interested parties. Further, the Authority may consider such other arguments of opposing parties with regard to appropriate descriptions and clarify the same in the final findings in order to ensure clarity at the time of implementation of the duty.

4. It has been claimed that it is well settled law that the product description remains dispositive and customs classifications are given only for convenience. Merely because import of a product has been reported under a classification specified under an anti dumping duty notification, the same does not imply that anti dumping duty would be charged on the same.

5. With regard to claims of the interested parties to specifically exclude certain products, the domestic industry has claimed as follows –

- i. STM-1, 4, 16 - There is no dispute for inclusion of these types
- ii. STM-64 - The domestic industry has produced and supplied these. The claim is without basis. It has been shown to the officials during the visit that the company produces STM 64 which are also DXC. The mere fact that Tejas did not bid in a specific tender for a specific product type for a specific customer

doesn't mean that the company do not produce the particular product. Non participating in a particular tender does not imply that the company is not manufacturing the particular product.

- iii. STM-256 - There is no requirement so far for STM 256 in India. STM 256 is nothing but SDH equipment. None of the consumers have deployed STM 256 and also there is no approved specification (TEC GR) for STM 256 system, these systems have not been deployed by the telecom operators. A product can be produced only if demand/ requirement for the same exist. It is understood that, none of the telecom operators in India have deployed any STM 256 system and even worldwide only very few telecom operators have deployed STM 256 in their network. Tejas has already made significant R&D investments in developing STM 256 technology and Tejas can provide STM 256 capabilities on its systems, as and when required
- iv. Multiplexers - Multiplexers is a broad term. SDH equipments also have multiplexers. Domestic industry has produced and supplied these. These have been imported in India. The Authority may however clarify that only SDH multiplexers are within the scope of the product under consideration
- v. DWDM - These are not SDH equipments and are beyond the scope of product under consideration. The interested parties have sought this exclusion only to confuse the Authority
- vi. Parts & components of SDH equipments - These cannot be excluded. Argument of domestic industry have been brought out separately

6. It is claimed that the eventual consumers are interchangeably consuming goods supplied by domestic and foreign producers. All major telecom service providers in India like BSNL, Bharti, Aircel are buying Huawei product and Tejas product, and that too for the same network, same application and against the same specification.

7. It is further claimed that Multiplexers or other equipments operating on DWDM technology are not covered under the PUC. Petitioner supplies SDH multiplexer or DXC and it was shown to officers during the visit.

8. Tejas manufactures both SDH products and carrier Ethernet products. Tejas will pay the applicable duty if it will source dual usage components for SDH use and if the same is within the product scope. The petition is only in respect of one article, albeit in its various forms. The rules nowhere prevent inclusion of different forms of an article within the scope of the product under consideration. There may hardly be any investigation conducted so far wherein product under consideration did not have multiple forms.

9. SDH, its accessories, associated software, parts and components, Populated PCB's, Power supply, lasers, Chassis, EI cables, PCM cables, power cables, racks, collectively forms an SDH equipment (excluding work stations). Individually, none of these have any end use. For example - a tube light requires a tube, a choke, a starter and a base. It cannot be said that

each of these four items are different articles, merely because they have their own distinguished character.

9A. The requirements of rule 5 are to be satisfied in respect of product under consideration and not individual forms of the product under consideration. The product under consideration is SDH transmission equipment. When “different technology equipment” is imported with “SDH interfaces” then duties will be not be imposed on full value of “different technology equipment” but only on the parts related with SDH technology.

10. It has been suggested that the Authority may investigate CIENA claim that goods produced by it originated in USA and the IPR is in USA. If goods originated in China PR, anti-dumping duties should apply. If goods are not of Chinese origin, the anti-dumping duties should not apply.

### **Submissions made by FIBCOM**

11. They have claimed to be the domestic manufacturers of the PUC. However, to support their contention, apart from a write up, they have submitted no other information to substantiate their field of activity. In their written submissions, they have stated that it supports the imposition of antidumping duty on “complete SDH equipment” and “populated modules for use in SDH” but has opposed the duty being recommended and levied on components.

### **Submissions by Exporters, Importers and other interested parties**

12. Following opposing parties have advanced their arguments on product under consideration and like article

- a) Huawei Technologies Co. Ltd., China PR,
- b) Huawei Technologies India Pvt. Ltd,
- c) Huawei Telecommunications (India) Pvt. Ltd,
- d) MRO-TEK Ltd., Bangalore (importer),
- e) Juniper Networks Pvt. Ltd., India, Aircel Ltd.,
- f) Vodafone Essar Ltd.,
- g) Bharti Airtel Ltd.,
- h) CCCME,
- i) Prithvi Information Solutions Ltd.,
- j) Vuppalamritha Magnetic Components Ltd.,
- k) ECI telecom Ltd.
- l) Hangzhou ECI Telecommunications Co. Ltd., China PR
- m) ECI Telecom India Pvt. Limited,
- n) RAD Data Communications Ltd.,
- o) Alcatel-lucent Shanghai Bell Co.,
- p) Tatastele Service.,
- q) Fiberhome Telecommunications Technologies, Co. Ltd.,

- r) ZTE Corporation Ltd., China PR,
- s) UT Starcom,
- t) FIBCOM,
- u) Ciena, USA,
- v) BSNL,
- w) Tirumala Seven Hills

13. Submissions made by these interested parties are collectively summarized below.

i. **Product scope is excessive**

- a. Scope of the product under consideration in the present case is excessive.
- b. Product like DWDM, CWDM, microwave radios, base stations, routers etc, are being considered for Anti Dumping Duty by Customs Department and DRI due to lack of clarity, which has led to delay and harassment to telecom consumers. Authority should issue necessary clarification in this regard to avoid delay and harassment.
- c. Product is designed as per TEC guidelines GRs no. GR/SDH-13/01 July 2003, GR-SDH-04/03 Mar 2005, GR/SDH-10/02 Mar 2005, GR-SDH-08/02 Mar 2005 and GR-SDH-07/01 Mar 2005 as stated in the petition. A clarification may kindly be issued that anti dumping duty is applicable only on the products manufactured under these standards of TEC.
- d. Product scope defined in initiation notification is overly broad. There is no rational to include distinctly different goods such as multiplexer in the product scope.
- e. Digital cross connect and add drop cross multiplexers are features of SDH equipment and not SDH equipment. SDH transmission equipment are sophisticated technology, which provides these features.
- f. Some articles such as Base Stations, Microwave, Router & Switches, DWDMs, and CWDMs have interface with SDH products and are not SDH transmission equipments.
- g. DXC technologies are not available in the low-end SDH transmission equipments manufactured by Tejas during the POI, and GR for DXC was also not mentioned in the list of GRs provided by Tejas at Para G of the petition.
- h. The practice all over the world is of restricting the investigation in respect of one article/product only. Customs Act and Anti-dumping Rules use the words “an article”, “any article”, “the article”, “the product”, “a product”, “the product”, “the like product”. Nowhere plurals have been used. Thus any investigation, which covers more than one “like articles”, is ab initio illegal.
- i. Product has been defined very widely without considering the indices like the physical characteristics, degree of commercial interchangeability, functions & end uses, industry specifications, pricing, quality, etc.
- j. The working group under Doha Round has interpreted “product under consideration” and thus DGAD should examine all the relevant factors while determining the scope of the product under consideration.

- k. Based on the PCN provided by the Authority it can be strongly assumed that the extent of Tejas along with supporters is limited to the products ranging from STM-1 to STM-64.
- l. By virtue of widest possible scope of PUC parties are adversely affected by the investigation.

ii. **Customs classification**

- a. Exact customs tariff head 85176260 may kindly be specified in places of present customs tariff head given 851762. Six digit classifications include wide variety of other unrelated products.
- b. The classification of product given is incorrect and misleading.
- c. Para 5 of the PF refers to SDH Transmission Equipment whereas duty table refers to “complete SDH Equipments”. The missing ‘transmission’ word has created confusion, which is evident in customs notification as well.
- d. Imprecise definition has resulted in avoidable harassments and ADD demands by Customs Department, and thereby causing delays in network rollout and inconvenience to telecom customers.
- e. While SDH Multiplexers are classifiable under 8517.62.60, Tejas has deliberately chosen to mislead the DA by giving only 6 digit (8517.62).
- f. As per General Rule of Customs, any product presented in unassembled or disassembled form will be classified as a complete or finished product. Part and components of SDH Equipments cannot in any manner be considered as incomplete or unfinished equipments as per Rule 2(a) of the General Rules of Interpretation. Even in the absence of specific mention that “including in CKD/SKD”, the Indian Customs will apply Rule 2(a).
- g. Six digit code under the duty table has created confusion as the RAD products fall under 8 digit classifications which are 8517.6270/90

iii. **Unjustified inclusion of accessories, parts and components, associated software, populated PCBs, power supply, lasers, chassis and software meant for SDH transmission equipment, etc in product scope: -**

- a. No explanation given of “accessories, associated software and its essential parts and components”. None of the accessories covered in the scope have been specified.
- b. No clear meaning given of associated software.
- c. It is not clear whether parts and components is one word or two words. What are the parts and components and how these are different than accessories.
- d. Initiation notification states “populated PCBs, power supply, lasers, chassis and software meant for SDH transmission equipment, etc.” Scope has been left open ended by using word “etc.” at the end of the list.

- e. There is contradiction regarding inclusion of software within PUC. If the SDH equipment is being imported as a part of equipment such as GSM network, how the export price of SDH equipment will be determined.
- f. Tejas is required to prove that it produces parts and components, which have been sought to be included in PUC.
- g. SDH, its accessories, associated software, parts and components, populated PCB's, power supply, lasers, chassis, EI cables, PCM cables, power cables, racks, workstations etc. are distinct and different articles in terms of name, character and use and cannot be included with the product scope.
- h. Requirements of Rule 5(2) have not been fulfilled as the petition did not contain any data or evidence for accessories, associated software, parts and components, Populated PCB's, Power supply, lasers, Chassis, EI cables, PCM cables, power cables, racks, workstations etc.
- i. Tejas is not in the merchant market of accessories, associated software, parts and components.
- j. There is no DI for parts and components including lasers and receivers. Therefore the same cannot be included under the PUC.
- k. A clarification should be issued for restricting the scope of duty only on parts, components and equipments used in SDH Transmission Technology.

iv. **Product imported as part of equipment/project cannot be subject to duties**

- a. Product under consideration includes certain products, which are not manufactured by the petitioner. It is well accepted principle that unless there is a like product manufactured in the domestic market, there is no question of injury to the domestic industry.
- b. Even though PUC as per PF includes “SDH Equipments forming part of eventual cellular/broadband equipments”, the same are not included in the duty table. As Tejas only assembles low-end traditional SDH Equipments, it has no right to seek duty on cellular/broadband equipments.

v.

**Product not produced by the petitioner cannot be included within the product scope.**

- a. Petitioner is capable of production of only limited technological capacity product, but has sought to include high end equipment through its unsubstantiated claim on injury.
- b. Petitioner has no commercial deployment of STM 64. Therefore, there is no question of the imported goods competing in the market place with the STM 64 of the petitioner.

- c. The definition of PUC should be suitably amended to cover only those equipments which are produced by Tejas, specially in Para 6 of the PF which talks about Multiplexers.
- d. Largest PSU in this sector has also pointed out that Tejas has abstained from bidding for the contracts for STM-64 and DXC products. Thus as per BSNL also, Tejas does not manufacture STM-64, STM-256, and DXC products.
- e. The Authority should define the PUC more accurately and restrictively and should seek specific declaration from Tejas as to the products it actually produces.
- f. PUC has been incorrectly defined to cover SDH transmission equipments not manufactured by Tejas and which are not 'like article' to equipments manufactured by Tejas.
- g. Preliminary Findings at Para 97, BSNL Certificates, Supply certificates of BSNL and certificates of ITI Limited and Bharat Electronics establish that Tejas was engaged in manufacture of STM-1, STM-4 and STM-16 only and not of STM-64 and STM-256:
- h. As Tejas itself has admitted that equipments other than STM-1, STM-4 and STM-16 are to be excluded from the PUC, the scope of PUC needs to be re-determined.
- i. SDH equipments and parts & components that are not being manufactured by Tejas should be excluded from the scope of PUC.
- j. Grades which are not manufactured by Tejas should be excluded from the scope of investigation. ECI's optic based equipments should therefore be excluded, as Tejas does not offer such products.
- k. BSNL has confirmed that Tejas never participated in tenders of STM-64; O-E-O based DXC equipments. Accordingly, this category of SDH and parts and components used to manufacture the same should be kept out of the scope of the PUC.

vi. **Dual use of parts/components difficult to define.**

- a. Tejas is required to explain that what components had been imported, and why they have been treated as having dual use.
- b. ICs inbuilt in the PCBs are specifically designed for SDH Equipments therefore it is difficult to understand how they can have dual use.
- c. It is difficult to draw the distinction that which parts have a dedicated use and which parts have dual use, therefore such a classification is amorphous and ambiguous.
- d. If imports of components are counted only if they have dedicated use for the product, there is a chance of abuse of the provision by Tejas since the dual use imports will not be accounted for.
- e. As has been admitted that some components and parts have alternate use (other than SDH), the imposition of duties would have serious operational issues and would breed litigation and unnecessary cost and consequences to importers and users in India.

- f. Lasers and receivers have multiple uses (beyond SDH) and Indian users are 100% import dependent. There are no alternatives to lasers & receivers.
- g. DGAD should exclude the components which has alternate usage and should include those components which has dedicated use in production of SDH equipments

vii. **Other issues** -

- a. Consumer perception should also be given weight in determination of product under consideration.
- b. There are number of significant differences between Huawei's SDH products and those of Tejas. Huawei produces its own ASIC whereas Tejas does not. For I/Ps Tejas is dependent on FPGA vendor. Their products are like diesel locomotive and steam locomotive engines i.e., both are used for pulling a train but they are not like articles as the difference far exceed the similarities
- c. Tejas has made contradictory arguments. On one hand, it says that foreign producers do R&D in their country and have Indian offices for doing incremental activities only. On the other hand, it claims that foreign producers have opened development centers in India to take advantage of low labor cost in India and IP created by these companies resides in foreign countries.
- d. By the Tejas' own admission (that certain products deserve to be excluded from scope of PUC) during the public hearing, the entire proceedings now deserve to be terminated as aspects like scope of DI, PUC, Dumping Margin, injury analysis will have to be completely re-determined in accordance with the new determination of the PUC.
- e. Because of differences in technology and functionality, different types of SDH Equipments cannot be considered technically or commercially substitutable with each other. Nor are the products of two different manufacturers.
- f. DA has failed to identify whether the imports from the subject countries are similar to Tejas goods, and whether the conditions of competition are also similar to justifying cumulation for injury assessment. Actual users have also placed material on record that Tejas does not have the technologies, which the imported subject goods have.
- g. The product under consideration is SDH transmission equipment. If the company has sold other products, the same in any case not covered under the scope of the product under consideration.
- h. When RAD is importing a “different technology equipment” with “SDH -1 interfaces” then duties will be not be imposed on full value of “different technology equipment” but only on the parts related with SDH-1 technology.
- i. RAD exports some products having STM-1 interface, which are used in Access technology and not in SDH technology. These products do not have same end use as that of SDH Equipments. Most of the RAD products having STM-1 interface don't work in SDH environment, because they are used for carrying data and voice traffic to SDH networks (Access terminals) and not to

build SDH transmission. Thus the scope should be amended to exclude RAD's products, including those with STM-1 interface.

- j. Core Director is undisputedly distinct product in terms of its capability, functionality, technical specification and end use. Technical specifications for Core Director are not covered under those given by Tejas in its Petition. Core Director is placed at a higher level as it assimilates the input data from multiple sources and forwards the same to the network path based on the traffic on a particular path whereas subject goods are placed at lower level.
- k. Ciena is exporting Core Director from USA. Its product is being assembled by a contract manufacturer in China PR as per Ciena specifications and requirements and pursuant to R&D done by Ciena in USA & India.
- l. Majority of value addition in Core Director is the design & development, which is done in USA or in India, and does not originate from China PR. Ciena has been considered as a known American producer of telecom products. Since Ciena's R&D resides in USA, a country other than the subject countries, Core Director should be excluded from the purview of investigation.
- m. Almost 99% of the accessories and parts & components are either imported or locally procured by Tejas, and therefore Tejas cannot be termed as producer of one of the group of PUC.
- n. PUC should be first categorized, and Dumping Margin and Anti Dumping Duty should be assessed and recommended based on these categories, as the DA has done in the case of Cold Rolled Flat Products of Stainless Steel and Lead Acid Batteries

#### **Standing of the petition and scope of the domestic industry**

#### **Submission by the petitioner**

14. Petitioner has advanced following arguments

- a. The petitioner provided information which is adequate and accurate and the same clearly establishes that the petitioner's production constitute a major proportion in Indian production.
- b. Other parties such as VMCL, Prithvi cannot be considered as domestic manufacturers under the rules.
- c. All published information such as Voice and Data, Communications Today confirm that the petitioner is a major producer of the product in the Country and other parties such as VMCL and Prithvi claiming to be domestic manufacturers are not domestic manufacturers at all.
- d. Information of leading Industrial Associations such as CMAI, TEMA etc. also clearly establishes that the petitioner is a majority producer.
- e. Even if companies such as Prithvi, VMCL, Huawei are considered as a producer, they cannot be recognized as an eligible producer under Rule 2(b) in view of the fact that they are largely importing the product under consideration.
- f. The petition is supported by M/s. Measurement & Controls Limited and Coral.

g. Production for the purpose of current product under consideration includes activities such as research, product conceptualization, design & drawing, development of the technology, conceptualization and understanding of functionality, product blue print preparation, development of associated software, product prototype development (hardware and software), component procurement, soldering and EMS activities, integration, preparation of test jigs, assembly, testing, and product support and bug fixes. Unless a company undertakes all these activities, it cannot be recognized as a domestic producer of the product.

h. With regard to imports by Tejas, the petitioner has advanced following arguments –

- (i) The petitioner should be considered as eligible domestic manufacturer to bring the present petition, notwithstanding that supplemental imports of components or sub- assemblies being made by them;
- (ii) The petitioner has provided sufficient details to justify its consideration as a domestic industry under Rule 2(b). These includes (a) bifurcation of materials consumption by Tejas into imported components from China PR, Iseal & third countries (both in direct imports by Tejas or in the sub-assemblies imported by Tejas, (b) research & development costs incurred by Tejas at different stages of production, (c) breakdown of total purchases into domestic & imports, (d) country wise purchases of components & assemblies, (d) break-up of the parts/ components imported from China PR in terms of various items in terms of dual use components and components dedicated in SDH application (which shows that barring printed circuit boards, the parts/components imported from China PR are parts/components which do not have dedicated applications in the product under consideration. The petitioner also claims that even printed circuit boards are produced as per design given by the petitioner),
- (iii) On the basis of verified details, it can be seen that value of Chinese parts/components imported by the petitioner is quite insignificant.

i. Tejas uses services of EMS on job contract basis. This use of EMS services cannot be compared with the manner in which companies such as VMCL/Prithvi are operating. Sub-contracting components or cards manufacturing to specialized agencies (EMS) is substantially different from buying such components or cards from another SDH manufacturer and then assemble the product. Petitioner compared its manufacturing activities with VMCL and Prithvi in terms of parameters such as core business activities of the companies, nature of imported item, reasons for imports, purpose of imports and whether the focus of the company was predominantly on imports of the product or manufacturing in the Country and concluded that companies such VMCL, Prithvi are de-facto working like an agent of Huawei – buying the product in CKD/SKD conditions, using Huawei technology to assemble & test the product and fix bug. VMCL/Prithvi lack technical expertise required for producing SDH equipment and has largely remained an importer of the product.

j. An entity undertaking only incremental activities in India should be considered as ineligible domestic manufacturers, unless such entity (i) is undertaking production

activities in India sufficient enough to constitute substantial transformation of the input into the output, (ii) is not substantially importing the product under consideration and/or are not related to foreign producers of the subject goods from the subject countries, (iii) focus is not on imports with supplemental assembly line or testing operations in India. Various suppliers of SDH equipment in the Indian market can be categorized into two categories – (a) companies who undertake full product life-cycle related expenses, including technology development, research & development and manufacturing in India, and (b) companies who undertake major product related expenses, including technology development, research & development and manufacturing outside India and export finished product either in assembled or CKD/SKD condition to India along with the final assembly/testing instructions.

k. Research & development activities and production – petitioner strongly argued that a company can constitutes producer only if it undertakes sufficient research & development within the Country. Refuting the arguments of other interested parties with regard to research & development, the petitioner has argued that research & development in this industry can be divided into a number of sub-categories, which includes (a) basic research required for production of an equipment having SDH technology, (b) research required to produce a new series of the product (such as STM4, STM16, STM64, STM256), (c) research required for developing a particular model in these series (such as various types of STM4 or STM16), (d) research & development required for mass production of each model. Petitioner further argued that even the accounting standards and income tax authorities do not permit charging of any research & development expense to revenue or capital account. Whether an expenditure incurred on research & development will be charged to revenue account or capitalized would depend on the nature of research carried out by the company. The company provided information from its books of accounts showing (a) bifurcation of total expenses into research design and development expenses and manufacturing expenses including testing and assembly, (b) bifurcation of total research & development expenses into amounts charged into revenue account and amounts capitalized, (c) nature of research where expenses have been capitalized and where the expenses have been charged to revenue account. Further, petitioner compared the various research & development activities done by Tejas, Prthvi, VMCL and Huawei in terms of (a) research in India with IPR resident in India, (b) Design and Development in India, (c) EMS Contract Manufacturing in India and Other Countries, (d) Assembly & Test Procedure, (e) “Specifications Development” in India, (f) Final Assembly & Testing in India, (g) Post Sales “bug fixes /enhancement /upgrades” done in India, (h) Post Sales – Spares Supply/ Technology Support in India and claimed that Prthvi & VMCL merely carry out assembly operations in India and Huawei does most of its Operations outside India.

4087 61/10-20 A

**Meaning of production**

15. Petitioner has argued activities carried out by the company constitute production and activities carried out by other companies such as Prithvi, Huawei and VMCL do not constitute production. Petitioner has advanced number of arguments which are summarized below.

- i. Meaning of production cannot be the same in all products. Production for the purpose of the present investigations shall imply that production activity which results in “production” of the “product under consideration”. Further, product is identifiable in terms of a number of parameters such as product characteristics, production technology, production process, functions & usage, pricing and customs classification. There are several steps/stages involved in the production of SDH equipment which includes conceptualization, preparation of detailed drawings and designs (blueprint).
- ii. Based on operational requirements, Tejas identifies the specific components required and develops various kinds of software elements, which would make such hardware functional with regard to the desired operation. Based on the blueprint for the hardware, and the software developed, a fully functional prototype is produced. This ‘prototype’ contains both the hardware as well as the embedded software necessary for the operation of the equipment and its compatibility with other equipment in the network, as seen through a network management system. Prototype developed by Tejas’ is tested using test specifications and testing software. A fully functional prototype is comprised of chassis, racks, PCB, cables software etc. After testing of SDH prototype instructions are given to EMS for soldering of components on PCB as per Tejas’ requirement. Various software are also provided to the EMS on a carrier media, for carrying out certain assembly line operations principally soldering activities. The soldered non functional PCB’s are supplied by EMS to Tejas manufacturing facility in India as SDH equipment until integrated and tested with Tejas’ customized components such as chassis, racks, cables, software elements. Integration activity is followed by rigorous testing, debugging and quality control. The testing, debugging & reworking activity includes development of special test jigs, test specifications and testing software which is critical in manufacturing process of SDH equipment.
- iii. Anti-Dumping Law does not define as to what would constitute “production” or “manufacture”. The scope of the term “domestic producer” would have to be inferred with reference to the purpose and object of Section 9A of the Act and the Rules made there under. Further, Rules differentiate between domestic industry and domestic manufacturer. Not all domestic producers are domestic industry.
- iv. Definition of “manufacture” under other legislations cannot be imported for the purposes of understanding the scope of domestic industry under dumping law. This principle has been well set out in the recent decision of the Hon’ble Supreme Court in the case of Qazi Noorul HHH Petrol Pump Vs. Deputy Director, ESI Corporation reported in 2009 (240) ELT 481 (SC).

- v. There are numerous statutes, which define the term “manufacture”, “manufacturing process” or “manufacturer”. These include, for example, Factories Act, 1948, Special Economic Zone Act, 2005, Central Excise Act, 1944, Consumer Protection Act, 1986, Beedi and Cigar Workers Act, 1966 and Standard of Weights and Measures Act, 1976, Foreign Trade Policy. The definition of production under these statutes are significantly different, which establishes that merely because a company pays excise duty and is therefore recognized as a producer under Excise Law should also be a treated as a producer for the purpose of the present law as well.
- vi. Under Anti-Dumping Law, the considerations relevant for determining producer would be, factors such as the level of investment in India, technical expertise involved in the activities carried out, extent of value addition in India, employment levels and other costs and activities carried out in India, which result in the production of the article.
- vii. A very significant part of the value of the product is attributable to the software developed in India, which is partially loaded at the stage of assembly by the EMS, partially used for testing, debugging & reworking in India and also provided to users for functioning of SDH network. Development of software also constitutes production of goods.
- viii. The Constitution Bench of the Hon'ble Supreme Court considered whether the term “goods” would include software and, therefore, whether development of software would constitute production of goods.
- ix. Tejas develops software in India, a part of which is provided to the EMS on a carrier media and such activity constitutes production of “goods” by Tejas.
- x. Tejas also carries out substantial activities after the goods are returned from the EMS. At this stage the product is not functional as SDH equipment and is in an intermediate stage of production. Assembly and testing activities done by Tejas using “in house” developed software, test specifications & test procedures. Tejas also develops other SDH software elements like “network management software, element management software, application software etc.” which are necessary for the functioning of the SDH network.
- xi. With regard to the argument that the job worker is also a manufacturer, Tejas has argued that where the entire process is carried out by the job worker, he may acquire the status of manufacturer. However, in a case where only a part of the production activity is outsourced, and substantial activities are carried out by the manufacturer, it cannot be said that the identity as manufacturer of the finished article is lost on account of outsourcing of certain processes.
- xii. The Hon'ble Supreme Court in the case of Shree Ram Vinyl & Chemical Industries Vs. CC, Mumbai reported in 2001 (129) ELT 278 (SC) has held that assembly cannot be equated with the expression manufacture. In the case of United Telecoms Ltd Vs. CC, Bangalore reported in 2009 (241) ELT 380 (T), it has been held mobile phones do not become so, until the software is loaded by the manufacturer. Therefore, whether mere assembly would be manufacture would depend on the facts of each case. Merely because one or two of the processes

involved in the production of the SDH equipment are outsourced, it cannot be said that Tejas is not a producer of SDH equipment

xiii. Under the normal definition of manufacture, the activities carried out by VMCL and Prithvi would not have constituted manufacture, but for the deeming provisions under the Central Excise Act. A deeming provision is to be construed strictly and only for the purpose of the Act in which it is enacted.

xiv. Petitioner provided a comparative of the various activities done by Tejas and Importers. Petitioner argued that production for the purpose of the present product implies activities such as Specification development and designing of Hardware and Software based on research & development carried out, collaborative components development with suppliers, Proto Type Product Development, Development of Network Management Software in India, Development of Element Management Software in India, Development of Test Procedures, Test Specifications and Testing software in India, Product verification w.r.t the specifications and quality of Hardware and Software in India, Complete Verification w.r.t the specifications and quality of the complete SDH proto type (hardware + software combined), Manufacturing of boards, Installation of Software in SDH Hardware, Final Assembly & Testing of the complete SDH box(hardware + software), Post Sales bug fixes”, Post Sales “product features enhancement /upgrades”, Post Sales – Spares Supply/ Technology Support and claimed that Tejas performs all these operations necessary to be considered as a producer, whereas Prithvi, VMCL merely carry out assembly operations in India. Huawei does most of its operations outside India.

xv. In addition Tejas also does rigorous assembly and testing based on the “Test Procedures and Specifications” developed in India by Tejas product design team in India. Other importers like Prithvi and VMCL do not do any technology development or R&D for the subject products and even the final assembly and testing of imported products is done as per specifications given by their foreign technology providers/ manufacturer based in subject countries.

xvi. Tejas has made huge investments to establish customer support and service centers in India. Tejas is capable of doing “installation services, enhancements, bug fixes” for its products within India. By contrast, importers like Prithvi, VMCL don’t have technological capability to do “enhancements”, “bug fixes” capabilities within India and they rely on their foreign technology providers/manufacturers to provide “enhancements” & “bug fixes”. They don’t even have their own “product documentation” (they merely photocopy the one provided by Huawei, including Huawei’s copyrights), which establishes the fact that they are only importers and traders, rather than a domestic producer of SDH.

xvii. Tejas identified various components and their procurement & development in or outside India and argued that taking help of EMS is substantially different from taking help in design & development itself. In case of VMCL and Prithvi, it is de-facto Huawei who is the producer of the product concerned, with assembly operations (if any) left to the VMCL and Prithvi. In case of Tejas, the company is the producer, with soldering operations left to EMS contractors.

xviii. With regard to activities of EMS, petitioner submitted that it is well accepted globally that EMS companies are only a contract manufacturer, with no ownership of product rights, IPR or knowhow, and they are only job-workers, who provide soldering/testing services to electronic products from different industries.

xix. Petitioner has also relied upon USITC consideration of six factors to determine whether a company is a producer of product concern or not. These are

- the extent and source of a firms capital investment;
- the technical expertise involved in U.S. production activity;
- value added to the product in the United States;
- employment levels;
- quantities and types of parts sourced in the United States; and
- any other costs and activities in the United States leading to production of the like product, including where production decisions are made.

xx. Petitioner has also referred to emerging jurisprudence in various books Dumping and Subsidies by M/s. Stranbook & Hooper, The Law and Procedures Governing the Imposition of Anti-dumping and Countervailing Duties in the European Community by M/s. Clive Stanbrook and Philip Bentley, A Handbook on Anti-dumping Investigations by Judith Czako, Johann Human and Jorge Miranda, Cambridge University Press, Antidumping and Countervailing Duty Handbook of the United States International Trade Commission. Petitioner also referred to a number of decisions of the EC, India and US authorities.

#### Submissions by Exporters, Importers and other interested parties

16. Following opposing parties have advanced their arguments on product under consideration and like article

- i. Huawei Technologies Co. Ltd., China PR,
- ii. Huawei Technologies India Pvt. Ltd,
- iii. Huawei Telecommunications (India) Pvt. Ltd,
- iv. MRO-TEK Ltd., Bangalore (importer),
- v. Juniper Networks Pvt. Ltd., India, Aircel Ltd.,
- vi. Vodafone Essar Ltd.,
- vii. Bharti Airtel Ltd.,
- viii. CCCME,
- ix. Prithvi Information Solutions Ltd.,
- x. Vuppalamritha Magnetic Components Ltd.,
- xi. ECI telecom Ltd.
- xii. Hangzhou ECI Telecommunications Co. Ltd., China PR
- xiii. ECI Telecom India Pvt. Limited,
- xiv. RAD Data Communications Ltd.,
- xv. Alcatel-lucent Shanghai Bell Co.,
- xvi. Tatatele Service.,

- xvii. ZTE Corporation Ltd., China PR,
- xviii. UT Starcom,
- xix. FIBCOM,
- xx. Ciena, USA,
- xxi. BSNL,
- xxii. Tirumala Seven Hills
- xxiii. EMS Vendors (Celestica, Smile and Solelectron)
- xxiv. Component Vendors (Arrow , Avnet)

17. Submissions made by these interested parties are collectively summarized below.

- i. Applicant itself is an importer of the subject goods and has no locus of filing the present petition as the applicant gets significant parts of components outsourced to specialized producers called EMS.
- ii. The applicant has been importing subject goods from Celestica, an EMS, which operates through numerous offices in China PR. Since the applicant has itself imported the goods from subject countries, it cannot represent “domestic industry” in this case.
- iii. The applicant’s claim for qualification for “Domestic Industry”, based on the criterion of R&D is defective since R&D is not the sole factor to be used in this regard. Reference is given of paras 7.112, 7.114 and 7.124 of WTO Panel Report WT/DS/337/R. These paras deal with the interpretation of Article 4.1 of the Anti-Dumping Agreement. It has been thereby contended that all categories and group of producers shall be considered as forming domestic industry.
- iv. BSNL also classifies the applicant as an importer.
- v. Petition pertains to some products STM 256, STM 64 and Digital Cross Connects. These are such products which the applicant neither manufactures nor sells. Therefore petitioner also has no Locus.
- vi. The applicant’s claim of having 84.7% share in Indian production during the POI is misleading and incorrect.
- vii. Petitioner has given no proof for its claim that M/s Measurement & Controls Limited supports its petition.
- viii. The ‘letter from undisclosed association’ has wrongly classified MCI, BEL and ITI as Indian Producers. MCI has not even sold single unit of subject goods till date. BEL and ITI work on the same model as HFCL and Prithvi.
- ix. Domestic industry producing the like article has not been properly identified and standing to file the petition has not been established.
- x. Petitioner has made artificial distinction between themselves and other Indian producers. Other producers participated in tenders floated by MTNL and BSNL and won tenders too. However, based on logic given by Tejas, they should be the only producer and only participating company in MTNL, BSNL tenders.
- xi. Winning of MTNL, BSNL tender by a producer itself shows that they are producer of product concern. Determination whether a company is a producer or not based on R&D carried out is absurd and irrelevant for determination for the purpose of Rule 2(b).

- xii. Rule 2(b) defines domestic industry as “the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and activity connected therewith. Tejas does not pass this test.
- xiii. There is no definition of “manufacture” in Indian ADD Rules. Some guidance on scope the term manufacture can be derived from the interpretation of the term by the Supreme Court of India with respect of Section 2(f) of the Excise Tariff Act 1944.
- xiv. Supreme Court stated that as long as a new marketable commodity emerged as a result of the manufacturing activity, a manufacture was deemed to have taken place.
- xv. There is a little distinction between the activities carried out by the petitioners and some of the other members of the domestic industry to whom petitioner classified as importers. Petitioner cannot be defined as domestic industry because of the fact that it sources its components from outside and uses services of contract manufacturing for its production.
- xvi. It is incorrect to claim that only those who have significant R&D activities should be treated as domestic industry. Legal requirement is production and not extent of R&D.
- xvii. There is no whisper in the petition as to which parts and components petitioner produces in India, in absence of which the authority could not have examined whether the petitioner produces all products which are included within the scope of domestic industry.
- xviii. Authority should have sought information with regard to parts and components being imported by the petitioner.
- xix. Tejas, in its petition, provided selected list of Indian producers and has deliberately excluded number of producers (FIBCOM etc.)
- xx. DA's approach of ignoring those engaged in 'incremental activities', is untenable, as 'manufacturer involves any set of activities by which PUC is brought into life'. [BPL India (Supreme Court) and Majestic Auto. (CESTAT) cases relied upon]
- xxi. Rule 2(b) does not require any R&D based classification. It simply uses 'domestic producers engaged in the manufacture of like article and any activity connected therewith'
- xxii. Huawei undertakes huge R&D activities in India.
- xxiii. In view of substantial imports by Tejas, the nature of production activity carried on by Tejas has not been addressed by the petitioner.
- xxiv. Tejas is required to prove that it produces parts and components, which have been sought to be included in PUC whereas it has admitted contrary.
- xxv. Contrary to Para E of the Tejas petition, which says investment in Plant & Machinery is low, Para 68 of PF states that petitioner has made significant investments in manpower as well as plant and equipments.
- xxvi. Tejas is required to explain that what components had been imported, and why they have been treated as having dual use.

xxvii. ICs inbuilt in the PCBs are specifically designed for SDH Equipments therefore it is difficult to understand that how can they have dual use.

xxviii. Without visiting Tejas factory (as admitted during Public Hearing), the Authority could not have come to a conclusion that Tejas has all the required capabilities. Whereas as per Para 43 of PF, the said conclusion has been arrived at after a detailed investigations at petitioner's premises.

xxix. The production process of the petitioner is primarily in Thailand. Even Tejas 2007-08 Annual Report acknowledges the fact.

xxx. A number of SDH equipments have been imported by Tejas. It can also be inferred that Tejas does not even have facility to repair the "imported goods" as some of the entries in this list are described as "repair goods"

xxxi. Part and components are ultimately sourced from China PR, Exports from Thailand shall not be accepted at their face value. [Reference made to DGAD-Rubber Chemicals case].

xxxii. TEMA, which is another leading industry association, in their letter dated 3-Dec-09 has also strongly supported petitioner's stance about the definition of who constitutes domestic industry and their support to the interim decision of the Authority. Clearly traders/assemblers cannot be considered domestic industry.

xxxiii. Tejas claim of having 84.7% share in Indian Production during POI is very doubtful, as Tejas itself has admitted that it commands 16% market share, and as per Voice & Data that of ECI is 30%, of Alcatel is 18%.

xxxiv. Tejas has admitted that it has been importing some components/sub-assemblies from other countries therefore it cannot deny that it has imported the alleged dumped product. and hence it cannot constitute domestic industry.

xxxv. Foreign shareholding in the companies cannot be used as a basis to exclude domestic producers.

xxxvi. While relying upon footnote 289 of WTO Panel Report DS337, DA did not expressly hold that other Indian producers couldn't be considered as Producers.

xxxvii. USITC decision of Colour Television Receivers is based on specific provisions of law of a particular country, are alien standards for India. Even as per six standards referred to in that case Huawei & VMCL are better placed. Furthermore, R&D is not at all a yardstick under the material relied upon nor under Indian Law.

xxxviii. If the conclusion of USITC decision of Colour Television Receivers is relied upon, the other Indian producers should also be considered as part of DI.

\* xxxix. When Indian law on "Domestic Industry" is already present it is unnecessary to apply the alien standards that too which do not deal with AD law at all. The IPR material relied upon by Tejas is merely an opinion of a Private body in US, and has no force of law.

xl. In the Tejas paper-book the reference made to an article "Huawei India Footprint: Milestones", does not support petitioner's case at all, as it makes

evident that Huawei India employs more than 2000 R&D engineers and has invested USD 200 million, and has 7 offices in India.

xlii. Tejas has argued that BSNL does not allow any party to participate in the tender process unless the real manufacturer (OEM) participates. However, this very document reveals that technology transfer is well recognized part of the given market. Further definition of OEM nowhere envisages that OEM alone is manufacturing the entire product.

xliii. As per Supreme Court cases of Delhi Cloth and General Mills and Ujagar Prints, payment of excise duties implies that the entity concerned is engaged in manufacture/production and therefore Petitioner's argument at the Public Hearing that payment of excise duties is not relevant, deserves to be ignored and is clearly meant to obfuscate the issue.

xliv. 60% of Tejas manpower is deployed in R&D which means 40% is involved in Assembling activities of Tejas thus Assembling cannot be treated as 'an activity incidental' to manufacturing of the product.

xlv. Tejas has made contradictory arguments that on one hand it says that foreign producers do R&D in their country and have Indian offices for doing incremental activities only. On the other hand it claims that foreign producers have opened development centers in India to take advantage of low labor cost in India and IP created by these companies resides in foreign countries.

xlii. Coral telecom and TEMA do not get mentioned in PF, hence should not be given opportunity to make submission now.

xlvii. Case referred to Union of India vs Delhi Cloth and General Mills (1963) for defining "Manufacturing" is relied upon, which establishes that the meaning of domestic producer accorded by the Authority is incorrect.

xlviii. 27. 66% of components used by Tejas in STM 1,4, 16 are imported and are not of dual use. Tejas does not have any other production activity apart from using them in SDH.

xlix. Claim of Tejas having 86% of production in India of like article is flawed. Tejas has admitted that cards are assembled outside India and visit to any manufacturing plant will bring this out clearly that cards assembly is the core of manufacturing while testing and R&D are incidental activities.

l. Tejas has classified all other companies as non-manufacturers based on self made matrix. If Tejas argument of IPR owner to be the true manufacturer is accepted, then all producers who do manufacturing by paying royalty will cease to be manufacturer.

li. Tejas has admitted that it imports components then its imports cannot be viewed differently from imports done by VMCL/Prithvi only because Tejas does backward integration activities like R&D. As per Reliance case, it is clear that backward integration activities like R&D cannot be considered necessary to call a company as a manufacturer.

lii. Mere undertaking R&D and having its own production catalogue cannot be termed as manufacturer. Further, producers who have full backward integration alone cannot be treated as producers in India as in case of Reliance Industries.

4087 GI/10-21 A

- liii. The citations and case laws on what constitutes production for the purpose of antidumping duty investigations are misleading and none of the cases referred to would apply.
- liv. The provisions contained in US Law are not contained in Indian Law.
- lv. EMS services are not merely soldering services. Since the applicant exercise full control over EMS in Thailand so they cannot say they don't have a related party in Thailand.
- lvi. Tejas has failed to prove why payment of excise duty doesn't amount to manufacturing.
- lvii. Designated authority should have done polling to grant domestic industry status to Tejas.
- lviii. Since products are custom made, Tejas won't be able to meet entire demand in India.
- lix. Tejas has deliberately left out some Indian producers from the list of domestic industry. Authority cannot selectively apply discretion in the same case.
- lx. Tejas, in its petition, provided selected list of Indian producers and has deliberately excluded number of producers (FIBCOM etc.)
- lxi. DA's approach of ignoring those engaged in 'incremental activities', is untenable, as 'manufacturer involves any set of activities by which PUC is brought into life'. [BPL India (Supreme Court) and Majestic Auto. (CESTAT) cases relied upon]
- lxii. Rule 2(b) does not require any R&D based classification. It simply uses 'domestic producers engaged in the manufacture of like article and any activity connected therewith'.
- lxiii. Tejas is claiming to be the DI when it is a company predominantly owned by third country shareholders, which undertakes production activities through outside EMS does not qualify to be a DI, & which actually imports subject goods.
- lxiv. Commenting on the reliance of Tejas on the definition/meaning of production accorded by the US authorities, the interested parties have argued that when Indian law on "Domestic Industry" is already present, it is unnecessary to apply the alien standards that too which do not deal with AD law at all. The IPR material relied upon by Tejas is merely an opinion of a private body in US, and has no force of law.
- lxv. Reliance by Tejas on an article titled "Huawei India Footprint: Milestones", does not support petitioner's case at all; as it makes evident that Huawei India employs more than 2000 R&D engineers and has invested USD 200 million, and has 7 offices in India.
- lxvi. As per Supreme Court cases of Delhi Cloth and General Mills and Ujagar Prints, payment of excise duties implies that the entity concerned is engaged in manufacture/production and therefore Petitioner's argument that payment of excise duties is not relevant deserves to be ignored and is clearly meant to obfuscate the issue.

lxvii. 60% of Tejas manpower is deployed in R&D which means 40% is involved in assembling activities. Thus assembling cannot be treated merely as 'an activity incidental' to manufacturing of the product.

lxviii. Even though DA has recognized that Tejas is importing from China PR, yet it has chosen to regard it Tejas as domestic industry. Question of the percentage of such imports vis-à-vis total cost of production is extraneous to the Anti Dumping Rules.

lxix. Tejas argued that inclusion is by default but exclusion has to be established. Going by this logic other domestic producers who are making imports deserve to be treated with a similar flexibility as Tejas is seeking for itself

lxx. All the Indian manufacturers including Tejas are dependent upon import in respect of part and components and there is no DI for parts and components

lxxi. There is no determination that whether Tejas constitutes Domestic Industry in respect of each of the articles covered under the PUC.

lxxii. With regards to the issue of "standing" VMCL & other Interested parties have been denied full opportunity

lxxiii. Supreme Court in Reliance Industries vs. DA has held that backward integration of manufacturing process is not relevant for the purpose of determining 'domestic industry'. Therefore research and R&D are irrelevant in this regard.

lxxiv. Consequent to inclusion of parts, components, accessories etc, Prithvi and other similarly situated domestic producers have been illegally excluded from DI.

lxxv. Indian Rules do not lay down a condition of "substantial transformation" for determining whether an entity can be regarded as DI. Assembly of parts and components imported in CKD/ SKD form into fully built up equipment amounts to manufacture. Further, payment of excise duty is an unrebuttable and a definitive proof that manufacture has been carried on. [BPL India, Naren Tulaman cases relied upon.]

lxxvi. Costs related to R&D, IPR ownership in India etc. are irrelevant for purposes of payment of excise duty as well as for determining DI. As per AS-26 by ICAI, development and design expenses ought to be capitalized as assets and do not form part of the costs.

lxxvii. It is evident from list of processes undertaken by Tejas on pages 17 & 18 of Tejas Paper-book, that it is not the actual manufacturer.

lxxviii. If pre-manufacture costs are excluded the imports by Tejas would constitute a very high proportion in its total costs, thus it is clear that Tejas itself is a major importer.

lxxix. Mandatory certification of no self imports or no relationship with exporters/importers was not provided for each of accessories, associated software, parts and components etc.

lxxx. Since Ministry of Finance is presently treating all such producers as producers of SDH, the investigatory arm viz. Ministry of Commerce could not have artificially altered well settled principles of law laid down by the Hon'ble Supreme Court and Central Government.

lxxxi. Tejas is not in the merchant market of accessories, associated software, parts and components.

lxxxii. The DA should disclose the correspondences, if any, to other domestic manufacturers and the basis of its decision to exclude from DI.

lxxxiii. DA has also not recorded reasons in support of exercise of discretion under Rule 2(b) in favour of the Applicant when they were found to be an importers.

lxxxiv. The CMAI letter is undated, unsigned and not on the letterhead. It is surprising to find that the Authority's conclusion is merely based upon CMAI letter and there is no other material placed on record as to what further enquiry was conducted by DAs. None of the supporters were present at the hearing or have till date filed any information.

lxxxv. DA's conclusion that since there are no imports of complete SDH equipments by Tejas, to that extent Rule 2 (b) is not attracted and the petitioner cannot be considered as importer, is legally incorrect specially when Tejas itself is engaged in assembly of parts and components sourced from outside India including China PR

lxxxvi. Scope and definition of Domestic Industry needs to be reassessed by DA as other Indian producers are also engaged in assembly line operations, testing and selling in India, which is similar to Tejas' activities.

**Proceedings before the Hon'ble High Court of Andhra Pradesh at Hyderabad**

18. M/s Vuppalamritha Magnetic Components Ltd. filed a petition being Writ Petition No 22155/09 before the Hon'ble High Court of Andhra Pradesh at Hyderabad seeking a direction or order in the nature of a writ of mandamus declaring the initiation notification dated 21.04.2009 and the preliminary findings dated 07.09.2009 as being illegal, arbitrary and unlawful and consequently, setting aside the same, on a number of grounds. M/s. Prithvi Information Solutions Ltd. and M/s M/s. Tata Teleservices Ltd. filed impleadment application and challenged the notifications. Tejas preferred two SLP against the orders of the Hon'ble High Court. The Authority also preferred an SLP before the Hon'ble Supreme Court. The Authority has carefully considered various arguments raised by the writ petitioner and other parties in these writ petitions and has examined the issues raised by these interested parties in the light of the legal & factual position. The brief of the cases and the arguments raised by the interested parties are given below.

19. Following issues were raised in these Writ Petitions

- i. Prithvi and VMCL argued that request for justice was ignored by DGAD, proceedings are impugned. Though Prithvi and VMCL are one of the largest manufacturers of optical transmission equipments but they were not considered as domestic industry.
- ii. Product under consideration and like article definitions is not right. Product definition is too wide. Several products which were not manufactured by Tejas during POI have also been included within the scope of the product under

consideration. Inclusion of product types such STM64, STM 256, DWDM, DXC, Core Director, etc. have been referred in this regard.

iii. Even STM 1/4/16/64 supplied by Tejas is not the same products as the imported product and there are significant differences between the two.

iv. Duty is imposed on HS Code 851762, which includes DWDM.

v. Product under consideration includes several components and CKD/SKD sets which are not manufactured by Tejas.

vi. Tejas has so defined the product that Prithvi which manufactures other optical transmission product is deliberately left out.

vii. Prithvi and VMCL are manufacturer as per excise and customs data.

viii. BSNL has asked DGAD to terminate the investigations because it results in Tejas monopolizing the market. BSNL has also stated that Tejas has never participated in STM 64 Tender.

ix. Tejas allegation that Huawei dropped prices by more than 50% in a year is wrong.

x. Tejas has monopolistic attitude.

xi. All the manufacturer in India import components and do assembly in India. So by including parts into product scope. Tejas has tried to exclude Prithvi and VMCL from being considered as eligible domestic producer.

xii. Tejas has not provided any documents to prove that they are major producers. Letter given by CMAI is wrong. Credentials of CMAI are doubtful.

xiii. Tejas is not a majority manufacturer and its markets share is just 20% as per ICRA, Gartner and Voice and data.

xiv. Tejas also imports component but is considered as eligible domestic industry while Prithvi and VMCL were not considered as domestic industry. DGAD has relaxed rules for Tejas saying that Tejas has imported dual usage components without considering that Tejas has a dedicated use of components i.e. for manufacturing of SDH Telecom equipments.

xv. Tejas imports from Malaysia and Thailand. Imports from third country (other than China PR/Israel) should also amount to the party being considered as importer, because under rule 2(b) country of imports is not specified. Even if Tejas imported from third countries, Tejas is not eligible to be treated as domestic manufacturer.

xvi. Tejas uses services of EMS. The Authority should check from where these EMS companies import components. It is highly likely that EMS companies import components from China PR.

xvii. A party which is not manufacturing components and importing the same from other countries including China PR cannot ask for duty on components.

xviii. Duty on components with dual usage will create operational problems and confusions.

xix. DGAD has not considered Prithvi and VMCL as eligible manufacturers because they don't do any "substantial transformation" of inputs. No concept of "substantial transformation" exists in Anti Dumping rules.

- xx. DGAD has wrongly considered R&D, EMS contract manufacturing, post sales and bug fixes as part of manufacturing activity. These activities are not relevant to determine an eligible manufacturer.
- xxi. BSNL in their letters to DGAD have stated that Tejas does not qualify as domestic industry and Tejas doesn't manufacture STM 64.
- xxii. Telecom Industry is import dependent since high quality equipments are not available in India. Curb on imports will increase cost for industry. CKD and SKD imports will also affect the industry
- xxiii. DGAD under pretext of confidentiality has suppressed information in preliminary findings thus creating ambiguity and lack of clarity on their approach during preliminary findings.
- xxiv. Contracts are awarded by tendering process and rates are quoted before imports. So no causal links exist between landed value of imports and injury to industry.
- xxv. 9 months POI is against guidelines of anti dumping practice.
- xxvi. Authority has not done separate determination of injury on parts and duty on SDH boxes is applied on parts. This is impermissible under Rule 4(b) and 17(d).
- xxvii. PCN methodology to standardize the product is wrong because by very nature product cannot be standardized.

20. The Hon'ble High Court vide three interim orders dated 21.10.2009, 11.11.2009 and 18.11.2009 in writ petition no. 22155/2009 stayed the anti dumping proceedings at the preliminary stage. Tejas filed SLP No. 32870-32875/2009 before Hon'ble Supreme Court, impugning the aforesaid orders of the Hon'ble High Court. This Hon'ble Supreme Court was pleased to stay the aforesaid impugned orders and direct the Hon'ble High Court to expeditiously hear and dispose of the pending writ petition.

21. The Hon'ble High Court vide order dated 22.01.2010 in WP 22155/2009 set aside the Initiation Notification dated 21.04.2009 and the Preliminary Findings dated 07.09.2009 on, inter-alia, the following grounds

- a. the assumption of jurisdiction by Designated Authority depends on the applicant satisfying that it is a domestic industry as defined under rule 2(b) of the rules and concluding that in the absence of the qualifications as to domestic industry, the assumption of jurisdiction by Designated Authority, initiation of investigation, preliminary findings and final findings would be ex facie without jurisdiction and any investigation would amount to error in the exercise of the jurisdiction.
- b. Rule 2(b), 5(1), 6, 8, 12 and Annexures I and II of the Rules contain no burden on VMCL or on interested parties and that the initial burden is always on Tejas to approve that they constitute domestic industry, that in spite of imports by themselves, they do not constitute importer and that by reason of dumping for the article, they suffered injury; and the Designated Authority cannot expect those manufacturers/ suppliers/ dealers of the same article to prove the negative.

- c. The DA erroneously assumed jurisdiction insofar as Tejas did not fall within the definition of a domestic producer and was really an importer. Further Prithvi and VMCL were importers of SDH equipment in CKD/SKD form from Huawei of China PR, they were also "manufacturers" of SDH equipment because they allegedly "assembled" the equipment and paid excise duties.
- d. Petitioner Tejas was not a "domestic producer" of SDH equipment for purposes of Rule 2(b) of the Anti-Dumping Rules and, therefore, ineligible to file an anti-dumping petition on the ground that it had imported certain components forming part of the Product under Consideration (PUC) as defined in the Initiation Notification. To qualify as a "domestic industry", the domestic producer must be engaged in the manufacture of the product to the extent of a "major proportion", i.e., the producer must show that he manufactures all the necessary parts, accessories and components of the PUC.
- e. VMCL is a manufacturer on the grounds that (a) VMCL is an assessee under Central Excise Act (b) an industry cannot be a manufacturer for levy of central excise and cannot cease to be a manufacturer for the purpose of anti dumping law, (c) mainly because it gets testing software from Huawei and uses its brochure, it does not cease to be a manufacturer, (d) the process involved is certainly manufacturing, (e) in any event, when the impugned preliminary findings and the provisional levy directly affect them, VMCL cannot be denied standing on the ground that they are not manufacturers
- f. The tariff classification under Chapter 85 of the Custom Tariff Act deals SDH under one sub-heading and other multiplexers, optical multiplexer software under different sub-headings and that it is submitted by the counsel that the capacity of SDH equipment differs depending on the specification. It can range from 155 Mbps for STM-1 to 40 Gbps for STM-256. Therefore, the DA while inviting response from interested parties/exporters importers/domestic agencies indicated code table for creating of PCN for SDH equipment for all capacities and other equipment. It only deals with STM-1, STM-4, STM-16 and STM-64. Therefore, from all these materials available, it is not clear as to whether SDH equipments manufactured by VMCL are alike or identical to the products manufactured by Tejas.
- g. DA denied the valuable rights of interested parties and rendered his exercise illegal by permitting Petitioner Tejas to keep certain business proprietary information confidential.

22. Designated Authority vide Special Leave Petition No. 7675 of 2010 (and separately, Tejas Networking Ltd. vide Special Leave Petition No. 7254 of 2010 and Coral Telecom Ltd vide Special Leave petition no. 4589 of 2010), challenged the impugned orders dated 22.01.2010 of Hon'ble High Court of Andhra Pradesh at Hyderabad before the Hon'ble Supreme Court of India. After hearing the parties, the Hon'ble Supreme Court vide its order dated 19.03.2010 was pleased to order as follows:

*"Since these matters involve economic consequence, we are required to expeditiously decide these cases finally as they involve interpretation of Anti-Dumping Laws. The*

*parties are given liberty to mention these matters for a fixed date of hearing after the hearing of Civil Appeal No.3453 of 2002 (Jindal Stainless Limited & anr. Vs. State of Haryana & Ors) by the Constitution Bench is concluded. In the meantime, we direct the importer-companies herein to pay interim duty on the following equipments:*

1. *STM-1*
2. *STM-4 (In SKD, CKD sub assembly and/of parts and components)*
3. *STM-16*
4. *STM-64 and*
5. *STM-256*

*However, it is made clear that DWDM stands excluded from the above list. Subject to above, the impugned judgments of the High Court are stayed.*

*The Designated Authority is directed, however, to proceed with the hearing and adjudication of the matter and pass final orders which will be subject to the decisions in these special leave petitions.”*

23. The Authority notes that interested parties opposing the imposition of ADD including, among others, VMCL, Prithvi and Huawei Technologies India at no point of time provided any information to the Authority either on their manufacturing capacities or imports made by them. Although the onus is always on the interested party to provide verifiable information on claims and counter claims, the Authority, for the sake of clarity, sought information from these interested parties vide letter dated 20<sup>th</sup> July, 2010, specifying a deadline. In response thereto, while strongly opposing the information being called for, VMCL and Prithvi sought extension in time to provide the requested information. The Authority, taking into account the complexity of the case, allowed extension to these two parties for submission of the relevant information. Huawei India however did not seek any extension but submitted information, though belatedly.

24. The information sought by the Authority from these three interested parties is summarized below.

- a. Names, addresses and production of companies in India, who, according to these parties, are producers of SDH equipments;
- b. Justification with verifiable evidence for the arguments that (i) SDH equipment produced and supplied by different parties are different products or otherwise incomparable, (ii) STM-64, STM-256 and DXC are different products and should be excluded, (iii) research & development activities relied upon by the petitioner should be considered as pre-manufacturing activities and should not be basis for defining production.
- c. Details of Research & Development activities, including its nature, carried out by these companies, bifurcating into product under consideration and other products.
- d. Nature of business activities carried out by these companies.
- e. Copies of Annual Reports.

- f. Activities that the company should undertake in order to qualify as a manufacturer as far as the product under consideration are concerned.
- g. Information on activities being carried out by Tejas outside India, particularly with regard to allegations of their ineligibility as a domestic manufacturer.
- h. Difference and similarities between DWDM and SDH Multiplexer.
- i. Justification for exclusion of parts & components and unassembled or disassembled form of the product.

25. The information /submissions made by Prithvi / VMCL and Huawei have been considered in the present Final Findings Document.

26. Apart from these submissions, these interested parties sought a fresh Public Hearing on the grounds that the Authority has changed. Some other parties also sought public or personal hearing. The claims made by these interested parties were therefore examined by the Authority.

27. The Authority has carefully considered the submissions made by these interested parties before the Hon'ble High Court and in their submissions before the Authority during the course of the present investigations. These were appropriately addressed in the disclosure statement as well as in this Final Findings Document.

### **Examination by the Authority**

28. Various submissions made, which are required to be addressed by the Authority can be broadly categorized into following:

- A. Product under Consideration and issues related to it.
- B. Domestic Industry and issues related to its standing, imports by DI etc.
- C. Whether fresh Public Hearing sought by some of the interested parties is mandatory.

### **Product Under Consideration**

29. The Authority stated as follows in the Preliminary Findings with regard to the product under consideration.

*“5. The product under consideration in the present investigation is “Synchronous Digital Hierarchy transmission equipment, its accessories, associated software and its essential parts & components, in assembled, CKD, SKD form or fitted with eventual broadband/cellular equipment”.*

*6. SDH transmission equipments are also known as multiplexers, Add Drop Multiplexers (ADM), Multiple Add Drop Multiplexer (MADM), digital cross-connects. Populated PCBs, Power supply, Lasers, Chassis and software meant for SDH*

*transmission equipment, etc. consist of essential parts of a SDH transmission equipments and are within the scope of the product under consideration provided the said components are meant for SDH transmission equipment application only.*

7. *SDH transmission equipments can be bought either as transmission equipments or forming part of another equipment e.g., broadband and/or cellular (both GSM and CDMA) equipment. SDH transmission equipments forming part of broadband and/or cellular equipment are also within the scope of the product under consideration.*

8. *Product under consideration is essentially an assembly of a number of electronic components and/or electronic printed circuit boards, designed to perform the intended function of multiplexing for combined lower speed signals into high speed signals for transmission through optical fiber over short or long distances. Since, among other applications, these are installed at Base Transmission Stations, switch exchanges and other point of presence, SDH equipments installed at different locations may differ in terms of the associated properties. Different SDH equipment are comparable in term of essential product characteristics including physical and optical, production technology, manufacturing process, R&D Development, software capabilities, functions and usage, etc. Accordingly, various SDH equipments have been regarded as one like product for the purpose of present investigation.*

9. *The product under consideration can be imported either as complete equipment, or in CKD, SKD form. Further, a number of accessories are required for connecting/installing SDH transmission equipment in the network (E1 cables, PCM cables, power cables, racks, workstations etc.). Software is an integral part of these equipments, which may be bought either as a part of the equipment or separately. These all are also within the scope of the product under consideration.*

10. *It is noted that there are a number of components required for production of the product under consideration which have multiple alternate usage. It is therefore, clarified that with regard to the components, the scope of PUC is only such components and parts having a dedicated application with regard to the PUC alone. In other words, the scope of the product under consideration extends to components/parts only if the same have a dedicated use in production of SDH equipment.*

11. *the product under consideration is classified under Chapter 85 of the Customs Tariff Act, 1975. It is further classified under the heading 851762 of schedule-I of Custom Tariff Act as per Indian Trade Classification. The classification is, however, indicative only and is in no way binding on the scope of the present investigation.”*

30. A number of interested parties have disputed the scope of the product under consideration on a number of grounds. The Authority has carefully considered arguments raised by various interested parties supporting or opposing the anti-dumping duties and comes to the following conclusion. A basic issue which arises for consideration in the present

case is the meaning of production. The issue has arisen in view of the peculiarities of the product, production process followed and the nature of activities carried out by companies who are engaged in manufacturing/assembling the product under consideration in India, China PR and third countries. After careful examination of arguments raised by various interested parties, the Authority comes to following conclusion:

- i. It would be appropriate to consider the meaning of production on case by case basis. A universal definition of production would not be appropriate. In fact, different laws and regulations have defined/treated different meaning of production, as is evident from different meaning/interpretation of production under different laws. The Authority holds that the meaning of production is required to be considered having regard to the specific law and regulation, the specific definitions and interpretation given therein and the objective and purpose for which the law has been created. For the purpose of anti-dumping duties, in the present case, for example, it would be grossly inappropriate to hold that a company is a domestic producer merely because it is undertaking certain incremental production activities. In fact, any such interpretation would lead the law becoming inoperable. The Authority, therefore, holds that a company could not be considered as a domestic producer merely because it has paid excise duty. The Authority notes that under excise law, goods are considered to have been produced even if incidental or ancillary activity for the completion of article is conducted including packing or repacking in a unit container or labeling or re-labeling of containers including the declaration or alteration of retail sale price on it or adoption of any other treatment on the goods to render the product marketable to the consumer. However, for the purpose of Anti dumping law, it cannot be said that such production activity are sufficient to constitute production. It will lead to significant multiplicities and double accounting either in imports or in domestic production.
- ii. For the purpose of anti-dumping law, the Authority holds that goods must be considered to have been produced only if the inputs undergo a “substantial transformation” into output. Widely acknowledged practice of the investigating Authorities is to consider parameters such as physical and technical properties, production technology, manufacturing process, plant & equipment, function & uses, pricing, consumer perception and customs classifications in order to consider whether the two articles are same or different. Further, the article may eventually be produced after following a small or long process and might be produced in one or more stages before it is eventually transformed into a form where it can constitute an article produced for the intended purpose. Merely if some inputs have been processed at the intermediate stages, where they have no use (and can perform no functions) but for consumption in the eventual product, the intermediate may not be considered as an article, even if it is saleable at that stage. From this point of view, the Authority holds that production and sale of SDH equipment or assemblies, sub-assemblies which are produced during the production process of making SDH equipment cannot be considered as a distinct product for the present purpose.

iii. The Authority extensively examined the nature of production activities carried out by the petitioner and foreign producers. On the spot verifications was specifically focused, inter-alia, on this aspect. The Authority has considered the argument of various interested parties in this regard. The Authority comes to the following conclusion with regard to what constitutes production and what kind of production activities are required to be included in manufacturing of SDH equipment. The various steps involved in making SDH equipment are as follows:

*Research>> Product Conceptualization>> Design & Drawing>> Development of the technology>> Conceptualization and understanding of functionality>> Product blue print preparation>> Development of associated software>> Product proto type development – Hardware and Software>> Component Procurement>>Populating the Board / Card as per the design>>Soldering and EMS activities>> Integration>> Preparation of Test Jigs>> Assembly>> Testing>> Product Support and Bug fixes.*

iv. It is possible that some of these steps might involve one or more sub-processes which might be carried out independently, or, some of these processes may be integrated by some company.

31. Having regard to the above, the Authority reviewed the scope of the product under consideration as defined in the preliminary findings. The Authority holds as follows with regard to status of various interested parties-

(a) Tejas – The production activities carried out by Tejas are tabulated below.

- a) research
- b) product conceptualization
- c) design & drawing
- d) development of the technology
- e) conceptualization and understanding of functionality
- f) product blue print preparation
- g) development of associated software
- h) product prototype development-hardware and software
- i) component procurement
- j) soldering and EMS activities
- k) integration
- l) preparation of test jigs
- m) assembly
- n) testing
- o) product support and bug fixes

32. Considering the nature of production activity undertaken by Tejas, the Authority holds that Tejas constitutes a domestic manufacturer.

33. As regards Prithvi & VMCL, the production activities carried out by Prithvi & VMCL in India, as available to the Authority based upon source information are assembly, testing and product support and bug fixes. Admittedly, these companies undertake only assembly operations in India, which activity constitutes very insignificant activity. The input does not

undergo a “substantial” transformation into the output. The inputs consumed by the company do not have distinguished character, function/use and are employed for production of the product under consideration.

34. The Authority notes that as per the details furnished by CIENA, a US based company, who have also participated in the investigation, the production activities carried out by them in USA are tabulated below.

SN	Activity	Place of activity (Inside/outside/both)
1	Research	USA
2	Product Conceptualization	USA
3	Design & Drawing	USA
4	Development of the technology	USA
5	Conceptualization and understanding of functionality	USA
6	Product blue print preparation	USA
7	Development of associated software	India
8	Product proto type development – Hardware and Software	USA
9	Component Procurement	USA, China PR and Third countries
10	Soldering and EMS activities	USA , China PR and Thailand, Singapore
11	Integration	USA and Third Countries
12	Preparation of Test Jigs	USA
13	Assembly	USA and Third Countries
14	Testing	USA and Third Countries
15	Product Support and bug fixes	USA and Third Countries

#### Scope of product under consideration –

35. The Authority notes that the product under consideration is essentially transmission equipment using SDH technology. It can be produced in a verity of specifications to meet the eventual customer requirements. Further, evolution of higher version/higher capacity equipment is an ongoing continuous process/phenomena in this industry. The investigation has shown, while STM-64 equipments are already developed and the customers have already started deploying the same in the telecom Networks (even though in a limited way), STM-256 was at development stage during the investigation period as far as Indian market is concerned. The investigation has shown that following types of SDH equipments were either in use or in development during the investigation period. The Authority considered the arguments of the interested parties on exclusion of some of these types and holds as follows in this regard:

- STM-1, 4, 16 – There is no dispute that these products are rightly included within the scope of the product under consideration;
- STM-64 – The interested parties argued that the petitioner has not offered STM-64 in commercial volumes. It has also been argued that largest Public Sector Company

4087 GI/10-22 B

operator (BSNL) has not bought STM-64 from the petitioner. The Authority, however, holds that STM-64 is rightly within the scope of the product under consideration for the reasons –

- (a) The company has produced and sold STM-64 in Indian and overseas markets as was verified by the Authority through its investigating team. ;
- (b) Even if the company has sold some volumes in the export markets, the product type cannot be excluded, as the fact of like article produced by the domestic industry gets established (the Authority notes that rule 2(b) read with 2(d) implies that the domestic industry should have manufactured like article. It is unnecessary to require that the domestic industry should have sold like article in domestic market). On the spot verification conducted at the premises of the petitioner, in fact, showed production of STM-64 in commercial volumes i.e. also for **QUICKTEL**.
- c. STM-256 – Admittedly, STM-256 was neither imported during the investigation period nor supplied by the domestic industry. Investigation conducted at the premises of the petitioner and foreign producers clearly showed that STM-256 can be described as the new generation SDH equipment. The investigation has not shown that if STM-256 was exported by foreign producers, the domestic industry did not offer STM-256. In fact, the interested parties agreed that technical approvals/permissions to deploy SDH-256 are not even in place in the country. The Authority observes that a claim for exclusion of a particular type cannot be entertained unless the same has been exported to India during the relevant period, as the fact of non supply of like article by the domestic industry cannot be established unless the type is exported to India. The Authority holds that no grounds have been made out justifying exclusion of STM-256. Moreover, the investigating team was given access to STM-256 equipment, manufactured by Tejas and available in their premises in Bangalore. Tejas showed that it has made significant investment (Rs. \*\*\*\*\* crores) so far in development of this product and claimed that the equipment could be sold only if some party placed an order for the same.
- d. Digital Cross connects – The interested parties repeatedly argued for exclusion of digital cross connect. The investigation has shown that digital cross connect are actually the equipment used in telecommunications networks, that allows lower-level signals, to be rearranged and interconnected among higher-level signals. Digital cross connect can be produced in SDH technology and other technologies. Digital cross connect equipment of SDH technology is clearly SDH equipment. Record verified by the investigating team establishes that Digital cross connect of SDH technology has been produced and supplied by the petitioner during the investigation period. The cost and price information included in the injury information and injury margin assessment includes the production and sale of digital cross connect of SDH technology. The Authority, therefore, holds that digital cross connect of SDH technology are rightly within the scope of the product under consideration. However, since digital cross connects are produced in other technology as well, it is clarified; as a matter of abundant precaution, that digital cross connect of other technologies are beyond the purview of the product under consideration and present investigations.

- e. SKD/CKD form of SDH equipments – Interested parties largely concede that SKD/CKD form of SDH is rightly within the scope of the product under consideration. As would be seen from the production process elaborated hereinabove, the product is an assembly of a number of cards, components, assemblies and sub-assemblies. It is quite possible that the product is transported in its SKD/CKD form. In fact, the product is in general invoiced in SKD/CKD form only. The producers do not raise invoice for ‘fully functional and operational’ SDH equipment. The production process from SKD/CKD form is a very insignificant assembly line operation requiring only screw driver technology. In fact, it is possible (and in fact is a practice largely adopted) to first produce the complete equipment, including necessary testing etc. and instead of transporting in a finished form, it is dispatched after dismantling in a SKD/CKD form. Exports of such SKD/CKD, thus tantamount to exports of the product under consideration itself. In fact, the product has been shipped from China PR in this SKD/CKD form as well. The Authority, therefore confirms that the scope of the product under consideration includes SKD/CKD form of the product.
- f. Assemblies and Sub-assemblies – the verification of the records of various exporters from China PR and Israel revealed that the Equipment is shipped in the form of assemblies and sub-assemblies and each of these assemblies and sub-assemblies are priced individually. Therefore the equipment imported as a unit or in the form of assemblies / sub-assemblies is within scope of Product under consideration.
- g. Populated Circuit Boards / cards-The cards / PCB's are populated as per the design developed by the manufacturer and thereafter, apart from loading of software, there is only a need to arrange them in a shelf and adjust them to a circuit. Since Populated Circuit Boards are property of the manufacturer, the same are within the scope of Product under consideration. It is however clarified that in case PCB or cards are meant for production/ assembly of a product other than SDH equipment, the same is beyond the scope of the product under consideration. PCB and cards are within the scope of the product under consideration only if such PCB or cards are meant for production of SDH equipment.
- h. Parts and Components- Interested parties have heavily opposed inclusion of parts and components within the scope of the product under consideration. The interested parties have argued, inter-alia, that (i) parts/components are different product, (ii) parts & components have not been offered by domestic industry, (iii) production from the stage of parts/components is quite significant and in fact, constitutes production, (iv) imposition of anti-dumping duties on parts/components is inoperable or may even lead to harassment at the stage of implementation or might lead to demand for collection of duty even when the same may not be justified. The domestic industry on the contrary has sought inclusion of parts and components on the premise that their exclusion will leave a big scope for circumvention. They have pleaded that Imports of components as “raw material” or “inputs” must be distinguished and differentiated with imports of SDH in component form (with IPR being supplied without customs check/control/clearance). They have further submitted that the Domestic industry is not against imports of components as inputs. Domestic industry is against import of

product in the form of components, using the same Chinese IPR and then assembling the product in India as this tantamount to continued dumping in different form.

- i. The Authority, takes note of the fact that parts and components are not manufactured by the Domestic Industry, and the domestic industry for parts and components is not before the Authority.
- j. The Authority further notes that parts and components used in SDH equipment have multiple usages and do not have a dedicated usage in SDH alone. Authority, after going into the details of usage of parts and components is of the view that including parts and components, when imported on a standalone basis is going to put the whole consumer durable industry to hardship. .
- k. SDH equipment as part of another equipment - The Authority notes that the product under consideration eventually forms part of Broadband or Cellular equipment. It is quite possible to import SDH equipment as part of such Broadband or Cellular equipment. If the scope of the product under consideration is not kept to include imports of SDH equipment forming part of such Broadband or Cellular equipment, the entire process of undertaking present investigations and proposed measures can be defeated. Further, no justified grounds have been brought out by any interested party why such import should not be chargeable to duty. The only concern of the interested party may be that the Customs Port Authorities should not demand anti-dumping duties on the entire Broadband or Cellular equipment. It is, therefore, clarified that the scope of the duty shall only be to the extent of the value of SDH equipment included in such Broadband/Cellular equipment. The scope of duty shall not extend to the entire equipment. The importers are expected to declare and the Customs Port Authorities are expected to apply due diligence in ascertain/bifurcating the value of SDH equipment.
- l. Software – Software is an essential part of the product under consideration in as much as the equipment is totally non-functional without such software. Such software can be developed by the producer itself or producer may get the same developed from other agencies. It is possible to invoice such software either as part of the equipment or separately. The scope of the product under consideration rightly includes the software and the Authority confirms the same.
- m. DWDM – Lot of interested parties have sought exclusion of DWDM. DWDM is different technology transmission equipment. It is not SDH technology equipment. Since, DWDM is not a SDH technology equipment, the same was beyond the scope of present investigation and proposed measures. However, in view of repeated arguments of the interested parties and their claim of possible demands of anti-dumping duties in future by Customs Port Authorities, it is proposed to clarify in the final findings that DWDM transmission equipment are beyond the scope of the product under consideration and no anti-dumping duties are payable thereon.
- n. PDH-Is outside the scope of PUC as it does not involve SDH Technology.

36. Having regard to the petition, initiation notification, preliminary findings, arguments raised by the domestic industry and opposing interested parties, the Authority holds that the scope of the product under consideration is as follows:

***“Synchronous Digital Hierarchy transmission equipment, viz. STM-1, STM-4, STM-16, STM-64, STM-256 in assembled, CKD, SKD form, its assemblies and sub-assemblies or fitted with eventual broadband / cellular equipment. Product under consideration will also include Add Drop Multiplexers (ADM) (For SDH Application only), Multiple Add Drop Multiplexers (MADM) (For SDH Application only), and Digital Cross Connect (DXC) (For SDH Application only), Populated Circuit Boards (For SDH Application Only) and parts / components imported as a part of equipment, so long they are imported along with the equipment or its assemblies / sub-assemblies. The Product under consideration will also include Software meant for SDH, which is an integral part of these equipments, which may be bought either as a part of the equipment or separately. However components/ parts imported on a standalone basis are outside the purview of Product under Consideration.”***

37. As per the submissions made by CIENA, they are procuring components from China PR as also some portion of manufacturing or assembly for CIENA USA's products is outsourced and carried out in China PR by Sanmina SCI and the same does not qualify as products originating from China PR. However the Authority holds that goods produced by them shall be subject to AD Duty only if they are covered within the scope of definition of product under consideration and if the imports of such goods into India either originate in or are exported from the subject countries under investigation.

#### **PCN System**

38. The product under consideration is produced and sold in a number of different types. Different types are produced to meet specific customer requirements. In order to ensure fair comparison between normal value and export price, the Authority segregated the product under consideration into different types based on parameters such as transmission capacity; cross connect capacity, E1 interfaces, electrical interfaces, optical interfaces, optics types, etc. The Authority evolved a product control system (PCN) running into 15 digit. All interested parties were directed to provide information on cost & price separately for each PCN.

39. Some of the interested parties, opposing the petition raised issues on PCN system devised by the Authority. It has been submitted that Tejas has attempted to standardize the specifications of the various diverse equipments covered under the PUC by evolving a system of Product Control Number (PCN). According to them, although some attempt at standardization of parameters has been made by evolving the PCN criteria, such products are by their very nature not amenable to standardization as they are completely non-standardized, made to suit the requirements of each network, functioning on a different frequency, contained diverse modules, the addition or deletion of which would lead to wide variation in costs and the costs were dependent on the interplay of technology, hardware and software used etc.

40. The Authority taking note of these comments holds that the product under consideration is essentially an assembly of a number of electronic cards and sub-assemblies. In fact, the producers tend to invoice the sales in terms of SKD/CKD/cards/sub-assemblies of the product. Investigation has shown that all the companies follow some system for design and development of the product, for which some product coding system is followed. Considering this aspect of the PUC, Authority had prescribed a PCN system, considering the scope of PUC and the intent was to bring the scope of the PUC identifiable and comparable. While doing so, the Authority gave liberty to all the responding exporters to come up with any other suggestion on devising the PCN methodology, duly justifying the system, other than the one proposed by the Authority. A communication was individually sent to all the interested parties in this regard. However, all the exporters, who participated in the investigation, chose to accept the PCN methodology suggested by the Authority and submitted data as per the said PCN methodology. Therefore, the Authority holds that the PCN methodology adopted for the present investigation has proved to be correct and reasonably acceptable to all the interested parties, particularly the responding exporters, who in principle agreed to this methodology and got their data verified based upon this PCN methodology.

#### **Standing & scope of the domestic industry**

41. Arguments have been made by various interested parties that –

- a) Petitioner itself is an importer of the product under consideration;
- b) The discretion under rule 2(b) cannot be applied differently for different parties;
- c) The rules do not distinguish between imports from subject countries and non subject countries;
- d) The rules do not prescribe any numerical formula with regard to volume of imports;
- e) The goods imported by the petitioner from Thailand might include parts/components which were eventually sourced from China PR and because the scope of the product under consideration includes parts/components, petitioner should be considered ineligible domestic industry.

42. The Authority considers that following issues arises for consideration and decision in the present investigations –

- (a) Whether Tejas, VMCL, Prithvi and such other companies can be considered as a producer or manufacturer of like article under dumping law for the purpose of the present investigations.
- (b) Whether Tejas, VMCL, Prithvi and such other companies should be considered as eligible or ineligible domestic industry within the meaning of Rule 2(b) in view of imports made by these entities from subject or non subject countries. Further, whether imports from subject countries alone are relevant for the purpose, or

whether imports from third countries also attract possible ineligibility criteria under Rule 2(b).

43. Prior to 15<sup>th</sup> July, 1999, Rule 2(b) of the rules read as follows –

*"(b) "domestic industry" means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in which case such producers shall be deemed not to form part of domestic industry". [Emphasis added]*

44. At the time of the initiation of this investigation, Rule 2(b) of the Rules read as follows:-

*"(b) "domestic industry" means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in which case such producers may be deemed not to form part of domestic industry". [Emphasis added]*

45. However, post initiation, this Rule has been amended as follows:

*"2(b) "domestic industry" means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term 'domestic industry' may be construed as referring to the rest of the producers only" [emphasis added]*

46. Thus, Rule 2(b) of the AD Rules provides that domestic producers which are related to the exporters or importers or which are themselves importers of the allegedly dumped articles may be excluded when determining the domestic industry in certain situations. As the use of the word 'may' in Rule 2(b) suggests, the two types of producers in question, i.e. related producers and producers importing the alleged dumped product, are not automatically excluded from being part of the domestic industry. Rather, it is the consistent practice of the investigating authorities that the exclusion of such producers must be decided on a case-by-case basis, on reasonable and equitable grounds, and by taking into consideration all the legal and economic aspects involved.

47. The question of excluding or including a domestic producer from the ambit and scope of the domestic industry is of practical importance as the question arises whether or not they are really part of the domestic industry in the sense of Rule 2(b) of the AD Rules. This in turn may have an effect on the standing of the application i.e. whether or not their (the domestic producers that have filed or supported the application) production reaches the necessary level of representativeness as stipulated under the AD Rules; as the output of domestic producers, which are excluded from the definition of the domestic industry because of their relationship to exporters or importers; or because of their own dumped imports, will not be taken into consideration while calculating total domestic production and when determining if the applicant along with supporting domestic producers represent a major proportion of such production.

48. The Authority notes that Rule 2(b) has been amended twice. The Rule 2(b) as enshrined in the AD Rules as on 1.1.1995 provided no discretion to the Designated Authority in such situations where one or more domestic producer has imported the product under consideration or is related to an importer or exporter of the product under consideration. However, WTO Agreement on Anti Dumping and domestic laws of other investigating authorities vested discretion to the investigating authorities in such situations, which were to be applied on a case by case basis. Rule 2(b) was amended with effect from 15th July 1999 vide Customs Notification No.44/1999 (N.T.) vesting discretion to the Designated Authority in such situations, which could be applied on case by case basis. Rule 2 (b) has further been amended recently as stated above. The Authority considers that this discretion is necessary to meet situations wherein:-

- A. Some domestic producers may not wish to support an anti-dumping application merely because they themselves are importing the product, or they are related to an importer or exporter of the product. Such domestic producers may even wish to force closure of other domestic producers in order to eliminate competition through unfair practice of dumping. One justification for vesting the discretion in the Authority is to enable the Authority to exclude such entities, who may seek to thwart an attempt by the remaining domestic producers seeking bonafide redressal of injury caused on account of dumping by filing an anti-dumping application and seeking suitable relief against the unfair trade practice of dumping. If it were not so, the remaining domestic producers may not be able to meet the 'standing requirement' as stipulated in the law to file an anti-dumping application and seek suitable remedy against the unfair trade practice of dumping. In short, the Authority considers that there was a need to exclude certain entities from the scope of domestic industry in order to enable the Authority to address injurious dumping in the Country.
- B. One or more of the domestic producers might have imported the product under consideration or their related company might have imported or exported the product under consideration for one or more bona-fide reasons. Some of these reasons are listed below:

- i. imports made under advance license in order to compete in the international market in the downstream product;
- ii. imports made at the time of temporary suspension of production (due to variety of bona-fide reasons, such as fire, strike, natural calamities etc);
- iii. imports made to supplement the product line by importing a particular type which the applicant may not be producing and which might constitute a very small portion of its total business operations;
- iv. imports made for testing, research & development, seed-marketing purposes (imports of the product to test the quality and other parameters when faced with low priced imports );
- v. Imports of the part of the product which does not form the core activity in the manufacturing of the product.
- vi. the volume of imports is low having regard to total volume of imports, Indian production and consumption;
- vii. balance of business between manufacturing and import
- viii. Whether imports are from the countries under investigation

49. Thus, the Authority is of the view that the modified Rule provides discretion to the Authority in the above mentioned situations. In other words, the AD Rules have been amended to provide discretion to the Authority to include a domestic producer in certain situations or to exclude a domestic producer in certain situations.

50. The Authority during verification of the records of the Domestic Industry, also verified the details of imports made by them during POI. As per the annual report issued by the company, total Turn Over in terms of sales of SDH including STM-1, STM-4, STM-16 and STM-64 during POI is to the tune of Rs. \*\*\* Crores. Further verification of the data from SAP system records and financial records maintained by the Company reveals that total number of components which go into an SDH is \*\*\* out of which \*\*\* components are sourced from China PR. The Chinese origin components primarily include \*\*\* Bare Boards and \*\*\* fans. Other components are mechanical in nature. The details of components / PCB's imported from various sources by Tejas are given below:

a. **Thailand- Rs. \*\*\*-(\*\*\*%)**

There is one EMS, who procures from \*\*\* vendors identified by Tejas, where from the EMS are supposed to procure the components. These include \*\*\* vendors from India, \*\*\* vendors from USA, \*\*\* vendors from Taiwan, \*\*\* vendors from EU, \*\*\* vendors from Japan, \*\*\* vendors from Switzerland, \*\*\* vendors from UK, \*\*\* vendors from Thailand, \*\*\* vendors from Hong Kong and Korea RP each, \*\*\* vendors from Israel, \*\*\* from China PR, \*\*\* vendor from Canada, \*\*\* vendor from Dubai, and \*\*\* from rest of the world. Imports from Thailand include:

- i. **PCB-** Assembled as per the design provided by Tejas-Rs. \*\*\* /-Includes embedded software provided by Tejas
- ii. **Bare Boards-Rs.\*\*\*/-**

- iii. **Capacitors- Rs \*\*\*/-**
- iv. **Connectors-Rs. \*\*\*/-**
- v. **Inductors-Rs. \*\*\*/-**
- vi. **Resistors-Rs. \*\*\*/-**
- vii. **Stickers-Rs. \*\*\*/-**
- viii. **Trans Receivers-Rs. \*\*\*/-**
- ix. **Transformers-Rs \*\*\*/-**
- x. **Misc. item like IC's Cables,Washers,Nuts,PackingMaterial-Rs.\*\*\*/-**

**b. Locally from India-Rs. \*\*\* (\*\*\*)-procured from \*\*\*vendors.**

The details of these procurements are as under:

- i. **PCB from EMS-** Assembled as per the design provided by Tejas-Rs. \*\*\*/-  
(\*\*\*)Includes embedded software provided by Tejas
- ii. **Bare Boards-Rs.\*\*\*/-**
- iii. **Capacitors- Rs \*\*\*/-**
- iv. **Connectors-Rs. \*\*\*/-**
- v. **Inductors-Rs. \*\*\*/-**
- vi. **Resistors-Rs. \*\*\*/-**
- vii. **Stickers-Rs. \*\*\*/-**
- viii. **Trans Receivers-Rs. \*\*\*/-**
- ix. **Transformers-Rs \*\*\*/-**
- x. **Patch Cord-Rs \*\*\*/-**
- xi. **Mechanical and Misc. item like Racks, Chassis, Face Plates, Trays, I C's, Cables,Washers,Nuts,PackingMaterial-Rs.\*\*\*/-**

**c. Singapore- Rs. \*\*\* (\*\*\*) (In Singapore Tejas has a subsidiary working as a procurement office, Sourcing from approved vendors including \*\*\* vendors from Singapore)**

The details of these procurements are as under

- i. **PCB -** Assembled as per the design provided by Tejas-Rs. \*\*\*/-(\*\*\*)% of total turnover), Includes embedded software provided by Tejas
- ii. **Capacitors- Rs \*\*\*/-**
- iii. **Connectors-Rs. \*\*\*/-**
- iv. **Inductors-Rs. \*\*\*/-**
- v. **Resistors-Rs. \*\*\*/-**
- vi. **Trans Receivers-Rs. \*\*\*/-**
- vii. **Transformers-Rs \*\*\*/-**
- viii. **Patch Cord-Rs \*\*\*/-**
- ix. **Misc. item like IC's Cables,Washers,Nuts,PackingMaterial-Rs.\*\*\*/-**

**d. China PR-Rs . \*\*\*(% )**

The details of procurements from China PR are as under

- i. **Bare Boards - Rs \*\*\*/-**
- ii. **Capacitors- Rs \*\*\*/-**
- iii. **Connectors-Rs. \*\*\*/-**
- iv. **Inductors-Rs. \*\*\*/-**
- v. **Transformers-Rs \*\*\*/-**
- vi. **Trans Receivers-Rs. \*\*\*/-**
- vii. **Patch Cord-Rs \*\*\*/-**
- viii. **Misc. item like IC's Cables, Washers, Nuts, Packing Material-Rs. \*\*\*/-**

**e. Taiwan Rs. \*\*\*(% )**

The details of procurements from Taiwan are as under

- i. **Connectors-Rs. \*\*\***
- ii. **Inductors-Rs. \*\*\***
- iii. **Transformers-Rs \*\*\***
- iv. **Trans Receivers-Rs. \*\*\***
- v. **Misc. item like IC's Cables, Washers, Nuts, Packing Material-Rs. \*\*\***

51. The Authority notes that imports from China PR, comprising of \*\*\*% of the total imports made by the company (\*\*% of the turnover of the company) are stand alone components, which are no more a part of PUC and therefore not relevant for determination of standing.

52. Further, on the issue imports from the countries other than those under investigation, the Authority holds that where the imports of the product are not from the countries under investigation, the same does not constitute imports of “alleged dumped article”. Such import, therefore, should not prevent such domestic producer from bringing an application as a domestic industry. It is relevant to point out that in case such domestic producer is importing significant volumes from countries not under investigation, the same becomes relevant in establishing existence or otherwise of causal link. If the imports from third countries are insignificant in volume, in any case, the same become irrelevant. It could be feared that such third country import might become significant after imposition of anti-dumping duties.

53. Interested parties have argued that the fact that imports were made from non subject countries is irrelevant under Rule 2(b) and “*alleged dumped article*” relates to article and cannot be linked to the country. The Authority has carefully examined various legal provisions in this regard and holds that terminology in various provisions under rules and the objective of exclusion provided under 2(b) make it abundantly clear that the question of excluding a party under rule 2(b) should arise only if such imports are from subject countries under investigation. The Authority relies upon in this regard on the objective/intent of

providing such a discretion under 2(b) and various provisions under rule 2 and 6. Reference to dumped article or alleged dumped article under rule 2 and 6 is clearly with reference to subject **Country (ies)**, the producer in such subject countries and importers of the product from such subject countries. The Authority thus holds that imports of the article under investigation from subject countries alone are relevant for the purpose of inclusion or exclusion of a domestic manufacturer under rule 2(b).

54. It has been argued that Rule 2(b) cannot be applied differently on different parties. It has further been alleged that the Authority has considered Tejas as eligible domestic producer Prithvi and VMCL as ineligible domestic manufacturers. Interested opposing parties have disputed the preliminary determination and argued that even when both Tejas and Prithvi/VMCL have resorted to imports, the Authority has discriminately applied discretion available in Rule 2(b). Notwithstanding the determination with regard to product under consideration, the meaning of Chinese, Indian and third countries, the meaning of goods manufactured in India, China PR or third countries which leads to a conclusion that Prithvi and VMCL are not domestic manufacturer of the product under consideration in India, the Authority holds that in any case, rule 2(b) does not provide a uniform decision on inclusion or exclusion of domestic producers who are themselves importing the product. The Authority holds that such discretion is required to be exercised on a case by case basis. Different parties might import the product for different reasons. Volume/extent of imports by different parties might be different. Inclusion or exclusion of domestic manufacturer under rule 2(b) is based on certain reasons. Since the reasons themselves might vary from party to party, a universal application of the discretion is neither conceived under the law nor would be appropriate. Practice of the Authority and other Investigating Authorities in this regard also supports this view of the Authority.

55. Interested parties have argued that Tejas has undisputedly used services of EMS. Such EMS companies might have procured parts/components from China PR, value of which might not be included in the volume of imports relied upon by the Authority in applying the discretion. Authority notes that one of the biggest EMS services used by Tejas is in Thailand. In Thailand, they have identified \*\*\* vendors from different countries wherefrom these vendors are to source the inputs / components. Out of these \*\*\* vendors, only \*\*\* are from China PR. Moreover, the procurement by these vendors is stand alone components which are not covered under the scope of "Product under Consideration". The Authority therefore holds that this argument of the opposing interested parties, opposing the eligibility of Tejas, is also not sustainable.

56. It has been alleged that although there are a number of other manufacturers, Tejas has been considered to have the necessary standing of constituting a major proportion of the total domestic production within the scope of Rule 2(b) of AD Rules. In this context, the Authority notes that initially, after the initiation of investigation, apart from Prithvi and VMCL, no other so called manufacturer, as highlighted by both Prithvi and VMCL in their submissions has come forward to claim the status of being a domestic manufacturer. However, apart from making a claim to this effect in a narrative form, they never came up with any information

about their manufacturing activities. Prithvi / VMCL have not filed questionnaire response in the form and manner prescribed, either as a domestic producer or an importer of the product under consideration. Even when the Authority specifically advised these companies to provide information in the form and manner prescribed, these interested parties have preferred not to provide relevant information. Even otherwise they never furnished any details / data about their set up except to claim that they are manufacturers as they also pay excise duty. Mere payment of excise duty cannot give the status of "manufacturer" for the present purpose, as already stated here in before. The Authority notes that these two companies have preferred non cooperation within the meaning of Rule 6(8). The Authority holds that while it is open for an interested party to advance its argument, it is obligatory on the part of such interested party to provide such information as is requested by the Authority and offer itself for verification. The entire exercise undertaken in the instant case in ascertaining actual status of these entities would have been significantly smoothed, had these interested parties provided relevant information demanded by the Authority and offered themselves to spot verification. In view of conscious non cooperation preferred by these interested parties, the Authority has been constrained to rely upon available material in this regard. The information on record has shown as follows –

- i. These interested parties have not sold SDH equipment till the end of the investigation period.
- ii. The Authority identified activities such as research, product conceptualization, design & drawing, development of technology, conceptualization and understanding of functionality, product blue print preparation, development of associated software, product prototype development-hardware and software, component procurement, soldering and EMS activities, integration, preparation of test jigs, assembly, testing and product support and bug fixes as essential production activities. These interested parties do not carry out these production activities listed by the Authority as the activities comprising of production in the present case. It is not established that these parties even carried out assembly operation. There is no evidence on record showing production or sale of the product under consideration by these parties. Even on the repeated argument of payment of excise duty, these interested parties have not established that the said excise duty was paid in respect of SDH equipment. Petitioner argued that the said excise duty might have been paid on different products. These interested parties have not provided evidence to show that the excise duty was indeed paid for production & clearance of the product under consideration.
- iii. These interested parties have failed to establish that they have made investments in research & development, plant & equipment and other facilities required for production of the product under consideration concerned. The Authority notes in this regard that only activities relating to product under consideration alone are relevant to the Authority. Other activities carried out by these interested parties, if any, are entirely irrelevant in this regard. It is also relevant to point out in this regard that on their own accord, some of the interested parties, including VMPL & Prithvi considered DWDM as "product under consideration". It is therefore not

established whether the alleged status of a manufacturer is because of possible production and sale of DWDM or SDH equipment. The Authority notes that in case these companies have set up production facilities and have thereafter produced and sold DWDM equipment, the same cannot entitle them to claim a status of producer for the present purpose and present product under consideration.

57. Subsequent to issue of Preliminary Findings, FIBCOM came up with a claim of being manufacturers of PUC and claimed to support the petition so long as components are placed outside the purview of PUC. They also, however, did not provide any data on their claim to be a manufacturer, to the Authority. Petitioner, at pre-initiation stage had filed a letter from CMAI (Association) along with the petition. CMAI stated that the petitioner account for a major proportion of Indian production. This was considered *prima facie* sufficient evidence for the purpose of initiation of the investigation.

58. Authority noted in the preliminary findings that the reference was made by the interested parties to panel report in the matter concerning Farmed Salmon from Norway. Authority noted in the preliminary findings that the facts of that case are different than those of the present case. In the case under reference, EC had not examined whether or not activity conducted by those producers who were not considered as producers of product concerned was an activity which could constitute production. Authority notes that the interpretation of Article 4.1 of ADA given by the WTO Penal has a limited scope in the present proceedings. The Para 7.115 of the Report are relevant in this regard:

7.115 *There is no dispute that filleted salmon is within the scope of the like product identified by the EC in this case. Thus, based on our interpretation of the plain language of Article 4.1, we consider that any enterprise that produced any form of the like product should be considered, at least in the first instance, a "producer" of the like product, and as such, part of the domestic industry.*

Footnote 289 reads as follows:

289. *There may be circumstances in which an enterprise whose product is within the scope of the like product may be found to have engaged in a level of activity so low as to justify the conclusion that it did not, in fact, "produce" the like product. However, there was no consideration of the degree of activity of filleting-only undertakings in defining the domestic industry during the investigation. Therefore, the question is not before us on the facts of this case. (Emphasis Supplied.)*

59. Panel therefore envisaged some circumstances (as stated in footnote 289), which Panel agreed may not be sufficient to consider an entity as a "producer" of the product. The panel however did not decide when a company may be considered as a domestic producer and when it can be considered as a mere importer of the product under consideration. The Panel did not dwell on what constitutes sufficient activity in order to describe an entity as a

producer. Nor did the Penal describe the meaning of "production". The precise issue under consideration in the present case is what constitutes production and who can be regarded as a domestic producer.

60. In view of the above, having regard to the definition of the domestic industry under Rule 2(b) and information on record, the authority holds that VMCL and Prithvi have failed to establish themselves as domestic producer of the product under consideration for the purpose of present investigations. Further, in any case, these parties have failed to establish that they should be considered as "eligible domestic industry" within the meaning of Rule 2(b).

61. As regards Tejas, barring arguments on imports by the company, no other reasons/grounds have been advanced by these interested parties justifying treatment of Tejas as ineligible domestic industry. The Authority holds that imports of the product from subject countries alone are relevant for the present purpose and therefore imports made by Tejas from Thailand do not disentitle the company from being considered DI. The Authority holds that principal activity of the company is manufacturing in India, which includes essential research and design and development in production activity. The petitioner has not reduced, its own production activity, and has not turned to trading. No justifiable reasons have been advanced by the interested parties warranting exclusion of the petitioner.

62. Based on the information available on record, the Authority provisionally determined that (a) production activities by the petitioner constitutes production for the purpose of the present investigations; (b) imports by the petitioner are not such as to disqualify the petitioner from the scope of Rule 2(b), (c) imports by other domestic suppliers such as Prithvi and VMCL are such as to render them ineligible domestic producers under Rule 2(b), (d) production of the petitioner accounts for a major proportion of total Indian production. On this basis, Authority provisionally concluded that the petition satisfies the standing and the petitioner constitutes domestic industry within the meaning of the Rules.

63. While disputing the claim of M/s Tejas Networking Ltd to treat it as the domestic industry, the opposing interested parties contended that M/s Tejas Networking Ltd should be treated as ineligible for consideration as the domestic industry in view of the facts that (a) Tejas had imported certain components forming part of the product under consideration (PUC) as defined in the Initiation Notification, (b) to qualify as a "domestic industry", the domestic producer must be engaged in the manufacture of the product to the extent of a "major proportion", i.e., the producer must show that he manufactures all the necessary parts, accessories and components of the PUC, (c) DGAD has not considered Prithvi and VMCL as eligible manufacturers because they don't do any "substantial transformation" of inputs, (d) no concept of "Substantial transformation" exists in Anti Dumping rules, (e) Tejas also import component but is considered as eligible domestic industry while Prithvi and VMCL were not considered as domestic industry, (f) DGAD has relaxed rules for Tejas saying that Tejas has imported dual usage components without considering that Tejas has a dedicated use of components i.e. for manufacturing of SDH Telecom equipments, (g) imports from third

countries other than China PR/Israel also amounts to one being considered as importer because under rule 2(b) country of imports is not specified and so even if Tejas imports from countries other than China PR and Israel even then Tejas is not eligible to be called as domestic manufacturer, (h) Tejas imported from Thailand and Malaysia.

64. After careful examination of the legal provisions and facts of the case, the Authority notes that facts on record do not justify exclusion of M/s Tejas Networking Ltd from considering it as the domestic industry in the instant matter. The contention of the opposing parties that a company is ordinarily to be excluded in case it has imported does not hold good in view of the fact that imports made by Tejas from subject countries are essentially standalone components which are now outside the scope of PUC.

65. The Authority holds that that mere fact of payment of excise duty, if considered a barometer of “manufacturing” for the purpose of anti dumping law, would lead to several incorrect interpretations with regard to determination of dumping & injury as

- i. It would imply that even incremental activities such as retagging, repacking, relabeling, micronisation, metallization, pulverization, etc. will also become production.
- ii. The interpretation will lead to a situation where one product could have been produced several times. For instance, in the instance case, there are companies known as EMS companies, who are specialized electronic component soldering companies, doing such activities for a variety of industries, without any knowledge whatsoever with regard to designing or functioning of the card they produce. These companies are also paying excise duty. The interpretation will imply that even these companies should be recognized as SDH manufacturers. Thus, these EMS companies who have produced and supplied the card to Tejas Networks would become the manufacturer of SDH equipment (in CKD/SKD condition) and thereafter Tejas Networks is the manufacturer of the same SDH equipment. The production will be counted twice. Similarly, imports of the product will be counted as production of the foreign producer & import into India and thereafter the very same product will be counted as production & domestic sale of the importer, only because the importer has imported the product in CDK/SKD condition, assembled the product and sold it after payment of excise duty. The scope of the product under consideration includes parts & components in some situations. Some of these parts & components may have been produced by some other specialized component manufacturers in India. Thus, even these component manufacturers would also become SDH manufacturer.
- iii. Every company selling the product cannot be regarded as a domestic producer. There should be certain minimum threshold activity/criteria to be completed/crossed by a party selling a product in the market before it can be regarded as a producer. And such activity/criteria cannot be payment of excise duty. Such

activity/criteria have to be considered on the basis of nature of the product and production process. For example, a person trading in the imported product is also engaged in some activity connected with the product. However, such trader cannot be regarded as a producer under anti dumping law, even if such trader is paying excise duty for some plausible reasons under excise law.

66. The Authority further notes that apart from CMAI, TEMA, which is another industry association, in their letter dated 3-Dec-09 has also supported petitioner's stance about the definition of who constitutes domestic industry and their support to the interim decision of the Authority. The mere fact that **no other so called manufacturer** has either, not participated in the investigation, or those who have participated, have failed to provide any evidence with regard to their manufacturing activities in the Performa prescribed for the domestic industry, and other details elaborately discussed above further support the conclusion drawn by the Authority that Tejas constitutes "Domestic Industry" within the meaning of AD Rules.

**Whether a second Public Hearing is mandatory / necessary if a new Designated Authority assumes charge halfway through the investigation.**

67. The Authority notes that under the law, the Central Govt. may appoint a person not below the rank of Joint Secretary as the Designated Authority. The Central Govt. may provide the designated authority services of such other persons and such other facilities as it deems fit. The investigations were initiated and preliminary findings were notified when Shri R. Gopalan was the Designated Authority. Public hearing was also chaired by Shri R. Gopalan. Subsequently on 4<sup>th</sup> January, 2010, the Central Government appointed me as the Designated Authority. In view of the fact that the public hearing was earlier chaired by Shri R. Gopalan, some interested parties demanded another public hearing or personal hearing in the nature of public hearing.

68. It is relevant to point out in this regard those personal meetings / hearings were granted by the Authority wherever requested and justified. The Authority has carefully considered the request for public hearing having regard to the nature of the current proceedings; the procedure followed in conducting the investigations; established practices in this regard and grounds advanced by these interested parties for seeking public hearing or personal hearing in the nature of public hearing. The Authority holds that Rule 6 provides for an opportunity to an interested party to present information both in writing and orally. If the information is presented orally, it is required to be subsequently reproduced in writing. Clearly it is this written information which alone can be considered by the Authority for making a determination. In other words, if a party has presented some information orally, but the same is not reproduced in writing, the Authority is prevented from considering that information. On the contrary, if an interested party has made some submission, the Authority is obliged to consider the same, even if the interested party fails to present it orally. In fact, the WTO ADA clearly states that there shall be no obligation on any party to attend a meeting, and failure to do so shall not be prejudicial to that party's case. Further, the Rules do

not prescribe that the Authority should provide such opportunity for submitting information orally in the form of a public hearing where all interested parties are present. In fact, the WTO Agreement clearly provides that the Authority shall, on request, provide opportunities for all interested parties to meet those parties with adverse interests, so that opposing views may be presented and rebuttal arguments offered. However, there is no obligation on any party to attend a meeting, nor failure to do so can be prejudicial to that party's case. Further, interested parties have also been given a right, on justification, to present other information orally. However, such oral information provided can be taken into account only in so far as it is subsequently reproduced in writing and made available to other interested parties participating in the investigations. It is thus evident that no party can demand as a matter of right that the Designated Authority should provide opportunity for oral hearing in the form of a public hearing where all interested parties are present. Under the circumstances, in any case, an interested party cannot demand to be heard orally through a public hearing.

69. All submissions made by these interested parties from time to time as also at the time of previous oral hearing have been placed before me. The interested parties, while requesting an oral hearing, have not been able to point out any such fact or factor which indeed requires an opportunity for oral presentation of such information. Indeed no justification has been made out in support of such oral presentation of information. In other words, these interested parties were not able to point out to any such information, including new information, which is not on record or which is otherwise required to be presented orally.

70. In view of the foregoing, I consider that it is not necessary to hold another public hearing. Nor an interested party has been able to establish its case for presenting some information orally before me. All the facts presented to me in writing were considered while issuing the disclosure statement and comments to the disclosure statement are being adequately addressed in this Final Findings Document.

71. Above all, VMCL and Prithvi were given an opportunity to seek an appointment for personal hearing through a communication dated 19<sup>th</sup> April, 2010, which was not been availed by them. Further, VMCL, Prithvi and all other interested parties had and indeed availed, either directly or through their legal representative numerous opportunities to present their views orally before the Officers appointed to assist the Authority in the present investigations. A number of meetings were granted by the Officers to the legal representatives of various interested parties. In fact, the Officers liberally granted such opportunity whenever requested. All such submissions made before the Officers orally or in writing have been placed before me.

#### **Response to the Communication Dated 20<sup>th</sup> July, 2010**

72. The Authority, having considered that both Prithvi and VMCL have been vehemently opposing the investigation without providing any substantial inputs to support their views, sent a communication to both these interested parties on 20<sup>th</sup> July, 2010, seeking inputs on various claims made by these interested parties from time to time. That apart, a

communication was also sent to Huawei seeking inputs relating to this case. The Authority notes that while Huawei India provided reasonable information for consideration by the Authority, both VMCL and Prithvi have continued to have the same attitude of not cooperating with the Authority, but trying to stall the proceedings on one pretext or the other without providing any relevant inputs whatsoever. They went to the extent of questioning the wisdom of the Authority to seek information in the sixteenth month of the investigation. The Authority holds that the onus, under the AD Rules, is on the interested parties to provide relevant information with supportive verifiable evidence for consideration by the Authority. The Rules do not either prescribe or bind the Authority to seek inputs / information from any interested party towards later part of the proceedings, so long as the Authority has received “relevant information” and has provided sufficient time to the parties. The communication dated 20th July was sent to both the above named importers as another opportunity to give them yet another chance to substantiate their claim. Instead of providing the same, they have repeated their earlier submissions without providing any information / evidence to support their claim. While Prithvi has claimed that they are manufacturers of DWDM, (Non-PUC Product), VMCL has claimed to be manufacturers of PUC, once again, without providing any verifiable information on the activities carried out by them supported by the details about their workforce, balance sheet, inputs, R&D etc. Both of them have also not provided any information on imports made by them although an importer’s questionnaire should have been filed by them (Questionnaire is available on the official website of Department of Commerce). Further they have admitted having imported components but have been silent on the issue of complete equipment as well which came to the notice of the Authority during the verification of data of one of the responding exporters from China PR. To sum up, apart from seeking extension in time to file a response to the information sought by the Authority, which was allowed by the Authority, nothing of substance was provided to the Authority except repetition of what had been stated by them earlier from time to time. The Authority holds that all the issues raised by them earlier and repeated in their submissions dated 6<sup>th</sup> August have already been addressed in the paragraphs here-in before and need not be repeated.

73. Some interested parties identified a number of parties as manufacturer of the product under consideration. The Authority examined the claim of these interested parties. It is found that the claim of these interested parties is based on offers for supply of SDH product to the customers in India. The Authority holds that the mere fact of possible supply by a company cannot mean that such a company is indeed a manufacturer of the product. Some parties made reference to the BSNL tenders or website information. It is however noted that the said information is in respect of suppliers of the product and does not establish that these suppliers were indeed manufacturer of the product.

### **Confidentiality**

74. Some of the interested parties opposing the petition made following submissions on confidentiality:

- i. There was alleged material irregularity in the matter of confidentiality in the present proceedings in so much as the preliminary findings with respect to various

issues were not disclosed and were scored out on the purported ground of keeping information confidential.

- ii. While examining the price effect of imports compared with the imported product with comparable lower model of SDH transmission equipment manufactured by Tejas. Designated Authority has not disclosed the details and analysis of such comparison and has on the basis of mere statement that lower model type of domestic product is compared with imported product, sought to establish price undercutting.
- iii. For determination of domestic production, Designated Authority has relied upon production details provided by Tejas which are purported to be published in the Voice and Data Recorder Magazine in respect of PUC and other products and which is appropriately adjusted in order to determine information for the relevant product but the details of adjustment made in order to determine the information in respect of the relevant product is not disclosed and is kept confidential.
- iv. Submissions including Non-Confidential Version of the response made by other interested parties, other than the DI have not been made available to the other interested parties.
- v. The Authority has gravely erred in issuing directions to the Chinese companies for disclosure of PCN details. On the contrary no such stipulation has been prescribed for the DI. It is further submitted that such direction goes against the spirit of these provisions.
- vi. Certain information which could not have been kept confidential has been kept confidential by the Domestic Industry. There are also no reasons provided as to why the information on which confidentiality has been claimed and apparently allowed or is not susceptible to summarization. Even for information which can be considered as confidential, by its very nature, no proper indexation has been done to permit a reasonable understanding of the substance of the information submitted in confidence. Grant of confidentiality cannot be automatic and the Designated Authority must apply its mind to whether confidentiality is validly claimed. If the Applicants are not willing to disclose such information on which confidentiality could not have been claimed, then the Designated Authority and all such information ought to be rejected. We would request the Authority to first decide this important issue of confidentiality, and thereafter provide us an opportunity to make effective representation as envisaged under the Rules. We would also like to submit that we are presently prevented from making appropriate submissions in view of excessive confidentiality claimed by the domestic industry.

#### **Examination by the Authority**

75. The Authority considers that the issue of confidentiality can arise in following situations—

- a. Information filed by interested parties on confidential basis and confidentiality of the same from other interested parties – Authority holds that information provided by an interested party on confidential basis cannot be disclosed to

other interested parties participating in other interested parties in view of express provision under the rules.

- b. Information filed by interested parties on confidential basis and confidentiality of the same from the same party – As regards confidentiality of information provided by an interested party itself, the Authority has adequately disclosed data to the interested parties at this stage. The data could not have been disclosed before the present stage.
- c. On the issue of Submissions that Non-Confidential Version of the response made by other interested parties, other than the DI have not been made available to the other interested parties is denied as all such submissions are made available in Public File mandated by the law and continue to be available in the said Public File duly indexed even today.

### Public Interest

76. It has been submitted that the parts and components of telecom transmission equipments are not manufactured in India and there is clear import dependence for these items. The immediate impact of the levy, it is claimed, would result in a substantial increase in the cost of operations for genuine manufacturing companies like VMCL which manufacture items which are ultimately supplied to the telecommunication industry. It has further been alleged that the levy will not only adversely impact the Indian telecom industry, but also other dependent sectors such as IT,ITES and BPO sector which is wholly dependent upon the telecom sector for its voice and data transmission requirements. Therefore the increase in cost on account of imposition of such Anti-dumping Duty will effectively have to be borne by the domestic importers, telecom service providers like BSNL/ MTNL and by the domestic consumers. It has also been stated that Imports are a necessity as Petitioner cannot by any stretch of imagination supply the needs of the entire Indian market especially with the focus of the Government of India in expanding the telecom footprint in the country as enshrined in India's National Telecom Policy. These are aspects which also need to be borne in mind by the Authority in this investigation.

77. The Authority taking note of the submissions as above has the role to provide a level playing field between the domestic producers and imports. The Authority while examining the petition and recommending the result has to follow certain set principles prescribed in Anti-Dumping Law. The Authority's intention is neither to restrict the imports nor to be a source of increase in cost for any interested parties, so long as the reliance and result is based upon the data. In the present investigation the data supplied by all the interested parties has been relied upon, some of which is also verified, wherever the interested parties invited the Authority for verification of the same. Authority therefore concludes that having worked within the set principles and prescribed legal framework of AD Law, no area of the procedure has been left unattended. It is also pointed out that the petitioner claimed that the cost on account of SDH equipment is insignificant in total cost of a transmission station. The interested parties have not refuted this claim of the petitioner. As regards parts and

4087 GI/10-25A

components, the same when imported on a standalone basis are not included within the scope of PUC and therefore arguments on this score are not relevant.

#### **Normal Value , Export Price and Dumping Margin**

##### **Normal Value**

##### **Claims made by the Domestic Industry**

78. The petitioners have claimed that China PR is a non-market economy. No country has granted market economy country status to China PR after following detailed evaluation procedure, examination and evaluation. They have further claimed that even China PR agreed in the accession treaty that WTO Members could use an NME antidumping methodology through December 11, 2016. China PR has been treated as non-market economy by European Commission and United States in the past three years. European Union and United States are members of World Trade Organization. In India also, the Designated Authority has treated China PR as non-market economy. The Designated Authority has treated China PR as non-market economy in practically all the investigations initiated against China PR after the amendment dated 31st May, 2002. Even after the amendment dated 4th Jan., 2003, the Designated Authority has treated China PR as a non-market economy.

79. Applicants claimed that producers from Israel are dumping subject goods in India. They have claimed to have determined normal value in Israel on the basis of price paid and payable in the domestic market in Israel. They have claimed that Israel being a part of Mid-east / Europe region, the average selling price of PUC is expected to be even higher than those in Asia and in the absence of any information with regard to actual transaction price in Israel, price determined based upon market research reports has been adopted for determination of normal value.

##### **Examination by the Authority**

##### **China PR**

##### **Examination of Market economy claims**

80. The Authority notes that in the past three years, China PR has been treated as a non-market economy country in the anti-dumping investigations by other WTO Members. Therefore, in terms of para 8 (2) of the annexure 1 of AD rules, China PR has been treated as a non-market economy country subject to rebuttal of the above presumption by the exporting country or individual exporters in terms of the above Rules.

81. As per Paragraph 8, Annexure I to the Anti Dumping Rules as amended, the presumption of a non-market economy can be rebutted if the exporter(s) from China PR provides information and sufficient evidence on the basis of the criteria specified in sub paragraph (3) in Paragraph 8 and prove to the contrary. The cooperating exporters/producers of the subject goods from People's Republic of China are required to furnish necessary information/sufficient evidence as mentioned in sub-paragraph (3) of paragraph 8 in response to the Market Economy Treatment questionnaire to enable the Designated Authority to consider the following criteria as to whether:-

- a. The decisions of concerned firms in China PR regarding prices, costs and inputs, including raw materials, cost of technology and labour, output, sales and investment are made in response to market signals reflecting supply and demand and without significant State interference in this regard, and whether costs of major inputs substantially reflect market values;
- b. The production costs and financial situation of such firms are subject to significant distortions carried over from the former non-market economy system, in particular in relation to depreciation of assets, other write-offs, barter trade and payment via compensation of debts;
- c) Such firms are subject to bankruptcy and property laws which guarantee legal certainty and stability for the operation of the firms and
- d) The exchange rate conversions are carried out at the market rate

82. The Authority notes that a number of producers and exporters from China PR including M/S Fibrehome Telecommunication Technologies Ltd., M/S ZTE Corporation, M/s Alcatel-Lucent Shanghai Bell Co. Ltd., M/S Huawei Technologies Co., Ltd., M/S Hangzhou ECI Telecommunication CO. Ltd have responded to the questionnaire pertaining to market economy status and to the exporters' questionnaire, consequent upon the initiation notice issued by the Authority and rebutted the non-market economy presumption. The questionnaire responses and the market economy responses of the responding producers and exporters were examined. Since, at the PF stage, these responses were found deficient, as was elaborately explained in the PF document, all these responding exporters were treated as operating under Non-Market Economy conditions. The Authority had further explained in the PF document that the submissions regarding Market Economy Claim will be examined in detail during the course of investigation and verification by the Authority and the position in this regard will be reviewed during the course of investigation, if, upon verification these companies satisfy the MET norms. The verification of records relating to Market Economy claim was carried out in respect of all the above named responding exporters and detailed verification reports were issued to individual exporters. The position on Market economy claim, arising out of the verification is briefly summed up below:

#### **M/S Fibrehome Telecommunication Technologies Ltd.**

83. Shareholding pattern of both (FHI) (Exporting on behalf of FHT) and FiberHome Technologies reveals that *Wuhan Research Institute of Posts and Telecommunications (WRI)* which is owned by the State Owned Assets Supervision and Administration Commission holds \*\*\* shares in both these Companies. FHI has \*\*\* shareholders namely FHT (\*\*\*%) and WuHan Hongxin Telecommunications Technologies Ltd., (WHTT) (\*\*\*%). FHT is a state owned company with \*\*\*% state owned shares and Wuhan Hongxin is also a state owned company with \*\*\*% state owned shares. Further Wuhan Research Institute of Posts and Telecommunications (WRI) is admittedly state-owned. As per the AOA, Board of Directors shall have \*\*\* Directors including \*\*\* Chairman, \*\*\* Dy. Chairman and \*\*\* independent Directors. As per the list of top \*\*\* shareholders and Board of Directors the

company has \*\*\* independent Directors and \*\*\* regular Directors out of which \*\*\* are on behalf of WRI, \*\*\* on behalf of Institute of Post and Telecommunications and \*\*\* from other shareholders. The \*\*\* Directors on behalf of WRI which is a state owned company are holding the important positions of \*\*\*, \*\*\* \*\*\* and of \*\*\*. Mr. \*\*\* is the \*\*\* of FHT who is also a \*\*\* in WRI and also a \*\*\* in FHI. Considering this pattern, it clearly establishes that state interference in the day to day operations of the Company cannot be ruled out and therefore the Authority holds that the Company is operating under NME conditions. Further, since the company is not entitled for market economy status even if one of the parameters is not satisfied, the Authority has not examined other aspects relating to market economy status of the company.

### **M/S ZTE Corporation**

84. The company ZTE Corporation was established on \*\*\* with registered capital of RMB \*\*\* Million, with Regn. No. \*\*\* and License no \*\*\*. There were nine major contributors/sponsors of the capital as follows:

1	***
2	***
3	***
4	***
5	***
6	***
7	***
8	***
9	***

85. Out of the above, the Company \*\*\* hereinafter referred to as \*\*\* was jointly formed by \*\*\*, \*\*\* (\*\*) and \*\*\* each holding \*\*\*%, \*\*\*% and \*\*\*% share in \*\*\* which ultimately held \*\*\*% in the new company ZTE Corp. The company at serial no 4 above was a \*\*\* in \*\*\* and rest all were \*\*\*. The \*\*\* major shareholders' stock holding structure namely that of \*\*\*, \*\*\* (\*\*) and \*\*\* in \*\*\* stay unchanged since \*\*\*. Further, \*\*\* is a \*\*\*, and \*\*\*, \*\*\* (\*\*) is a \*\*\*. The company \*\*\* is one of \*\*\* \*\*\* confirmed \*\*\* and qualified under the National torch Plan Key High Technology and New Technology Enterprise by the State Science and Technology commission.

86. Also since \*\*\*, except \*\*\* and the \*\*\*, which still remained major share holders of the ZTE, other equity holders gradually liquidated their holdings and delisted from the top \*\*\* share-holder chart. The \*\*\* and other contributors/sponsors reduced its holdings of the company stock from initial \*\*\*% to \*\*\*% during this period.

87. Company has \*\*\* directors on board, out of which \*\*\* directors are from the major share holders that is \*\*\* and other shareholders, \*\*\* are from the company's senior management and \*\*\* are independent directors, notified in their respective technical fields.

from law firms or other disciplines. It has been seen that \*\*\* is the \*\*\* of the company since its inception.

88. Considering the above factors, the Authority is unable to grant market economy status to the company and holds that the Company is operating under non-market economy conditions.

**M/s Alcatel-Lucent Shanghai Bell Co. Ltd.**

89. Presently the structure of the shareholding in the company is as follows:

➤ Changan Communications Clearing and Settlement Co Ltd., China	***%
➤ China Huaxin Posts and Telecommunications Economic Development Centre,	***%
➤ Alcatel Lucent China Investment Co Ltd, China	***%
➤ Alcatel Lucent Participations Chine, France	***%
➤ Alcatel Lucent Participations, France	***%

90. The first two are Chinese Shareholders and the next three entities belonging to the Alcatel Group. Alcatel Group has \*\*\*% plus \*\*\* share in the total shareholding while the remaining shares are owned by the Chinese state owned enterprises shareholders.

91. \*\*\*. were jointly established by the National Computer Network and Information Security Management Center of China and the First Service Center of Ministry of Information Industry. China Hua Xin Postal and Telecommunication Economic Development Center (the "Center"), is an enterprise subordinate to China Telecom and owned by the whole people.

92. There are \*\*\* Board of Directors, \*\*\* by Chinese shareholders, and \*\*\* nominated by Alcatel shareholders. The \*\*\* is \*\*\* and is nominated by Chinese shareholder and \*\*\* is nominated by Alcatel shareholder. The company is subject to International regulations, controls and disclosure requirements.

93. The Authority notes that, the company, during the course of verification submitted that the decision making is not affected or influenced by the government nominees on the Board. However the Authority also notes that the company has, since inception, significant Govt. presence through share holdings by State departments. Over a period of time, the govt. shareholding pattern remained \*\*\*% being Government Owned. Presently, the board of directors also has \*\*\*% (\*\*\* nominees) nominees of State departments including the \*\*\* having a casting vote. In view of the above, with this significant state participation, the state interference cannot be ruled out and therefore the Authority holds that the Company cannot be granted market economy status.

4087 GI/10-25 B

**M/S Huawei Technologies Co., Ltd.**

94. On the spot investigations were conducted at the premises of M/s Huawei Technologies on 6<sup>th</sup>-9<sup>th</sup> April 2010. A detailed verification report was issued to the Company with an opportunity to offer comments thereon. As the verification report issued by the Authority shows that the share capital of the company has undergone substantial increase from RMB \*\*\* at the time of incorporation to RMB \*\*\* million by the time of period of investigation. Further, it was claimed that the company was owned by \*\*\* natural persons at the time of incorporation. The ownership underwent a large number of changes during the period of investigation. As per Business License dated \*\*\*, Huawei Technology Co. Ltd. is a limited liability company, wholly invested by \*\*\* and its paid up capital was RMB \*\*\* Millions, which was increased to RMB \*\*\* Millions in \*\*\* and RMB \*\*\* Millions in \*\*\*. \*\*\* is the legal representative of the Company. In short, during POI itself, the paid-up capital was increased from RMB \*\*\* billion to RMB \*\*\* billion. Prior to \*\*\*, there were \*\*\* shareholders namely \*\*\* Holding (\*\*\*)% and \*\*\* (\*\*\*)%. After \*\*\*, the entire Share Capital was held by \*\*\*, of which \*\*\* were stated to be shareholders. Considering the fact that ownership of the company has undergone so many changes and the share capital has been increased to such a significant extent, on the spot investigation focused on each addition to share capital and each change in the ownership structure.

95. While the Authority appreciates that additions to capital or changes in ownership structures are quite normal business phenomena; particularly in the context of non-market economy situation, the fundamental issue that arises for consideration is the source of funds for the capital so invested, changes in ownership structure and compatibility of ownership structure with capital investments. The exporter could not establish source of funds for fairly large amount of investments. It is also noted that a very large sum of investments have been made by a \*\*\* and the \*\*\*. The source of funds with the \*\*\* or the \*\*\*, however, remains completely unexplained.

96. The exporter pleaded non-availability of a large number of documents stating that the documents were too old and was not required to be permanently stored by the company. The exporter, however, could not show on the basis of statutory requirements in China that the exporter was not required to maintain such records on perpetual basis. Moreover, some of these amounts invested being so large and are by a \*\*\*. The Authority is unable to accept the claim that the exporter was not in a position to provide relevant information.

97. The exporter in its response to verification report heavily stressed that it is acted to the best of its abilities. Kind attention of the Authority has also been drawn to the WTO Agreement which deals with the situations wherein the Authority can apply best available information. The exporter pleaded that it has acted to the best of its abilities and failure to provide certain documents is due to significantly high age of these documents and therefore failure to provide the same should not be held against the exporter. The Authority is unable to appreciate the submissions of the exporter in this regard and considers that ownership structure and the manner in which ownership changed over the period is one of the

fundamental requirements for a determination relating to market economy status. Further, given the level of investments made, and the changes to ownership structure; it cannot be said that the underlying documents are of non-consequential value.

98. In view of the above, the state interference cannot be ruled out and therefore the Authority is unable to grant market economy status to the exporter.

#### **M/S Hangzhou ECI Telecommunication CO. Ltd**

99. In the beginning, M/s Eastern Telecommunications Co. Ltd ("EastCom") of China and ECI Telecom Ltd Israel ("ECI") agreed for a Joint Venture on \*\*\*. The company to be formed out of this Joint Venture was Hangzhou ECI Telecommunication Co Ltd (HETC). The registered capital of the JV was US\$ \*\*\*Million.

100. Eastcom thus had \*\*\*% share and ECI had \*\*\*%. The Board of Directors appointed in the Board of Directors was \*\*\* by Eastcom and \*\*\* by ECI. ECI had their controlling \*\*\* post in the JV. The JV HETC was primarily doing the trading activity. The product XDM was purchased from Israel and simply sold in China. The JV was responsible for marketing activities. The JV had warehousing facilities only in China. ECI Israel fixed the transfer price for selling from Israel to be purchased by HETC.

101. In \*\*\*, a subsidiary of Eastcom namely EOTC (Hangzhou Eastern Optical Communications Co Ltd) was identified by ECI for further acquirement. The company EOTC was in the business of optic technology compatible with the SDH business of ECI. ECI paid US \$ \*\*\* in \*\*\* for purchase of technology to EOTC directly. HETC purchased the \*\*\* including the \*\*\* and other services of EOTC for RMB \*\*\*. Thus, EOTC was totally purchased by HETC and ECI in \*\*\*. The company has shown the relevant documents in this regard. The share of ECI Israel grew to \*\*\*% of the total book value of HETC.

102. With this, EOTC was purchased over, HETC remained, ECI became \*\*\*% partner in the JV, Eastcom remained as \*\*\*% partner in HETC. The other activities of Eastcom (except the share in HETC) remained as usual. In \*\*\*, ECI Israel paid out to their minority partner Eastcom in HETC the book value of their share. In \*\*\*, thus HETC remained there but with ECI Israel only as \*\*\*% owner.

103. Considering the above, the Authority holds that the company / producer has provided information and sufficient evidence on the basis of the criteria specified in sub paragraph (3) in Paragraph 8 to prove that they are operating under Market economy Conditions and are entitled for MET treatment..

#### **Normal Value**

#### **China PR**

#### **M/S Fibrehome Telecommunication Technologies Ltd., Alcatel-Lucent Shanghai Bell Co. Ltd. and M/S Huawei Technologies Co., Ltd. and ZTE corporation**

104. Having concluded upon verification of records of the above named companies that they are operating under Non- Market Economy conditions, the Authority is not in a position

to apply Para 8 of Annexure 1 to the Rules to the above named Chinese companies and has to proceed in accordance with Para 7 of Annexure- I to the Rules. According to these Rules, the normal value in China PR can be determined on any of the following basis:

- a. On the basis of the price in a market economy third country, or
- b. The constructed value in a market economy third country, or
- c. The price from such a third country to other countries, including India.
- d. If the normal value cannot be determined on the basis of the alternatives mentioned above, the Designated Authority may determine the normal value on any other reasonable basis including the price actually paid or payable in India for the like product duly adjusted to include reasonable profit margin.

105. The Authority indicated, in the Initiation Notification, that the applicant has suggested that subject product is produced and sold in USA and Europe and these countries can be treated as surrogate country for China PR. The applicant furnished names and addresses of the producers in these countries.

106. The Authority notes that for determination of normal value based on third country cost and prices, the complete and exhaustive data on domestic sales or third country export sales, as well as cost of production and cooperation of such producers in third country is required. Since no information with regard prices and costs prevalent in these markets could be accessed and also the responding Chinese companies have made no claim with regard to an appropriate market economy third country, the normal value in respect of M/s Fibrehome, M/s Alcatel China PR and M/S ZTE Corporation Ltd. has been worked out on other reasonable basis, in terms of second proviso of Para 7 of Annexure 1 to the Rules. Accordingly, the ex-works Normal Value of the product under consideration for all the above named exporters from China PR has been constructed based on facts available. The Normal Value has been constructed taking into account actual weighted average price of all the major components separately for SDH equipments of different types, based on domestic industry import prices, duly adjusted for freight. No adjustment has been made for Customs Duty since the equipments for SDH are attracting Zero Customs Duty. It is noted that even the domestic industry is sourcing its major components from the international markets. Conversion cost, and SGA expenses of the domestic industry, have been adopted for determination of the normal value. After adding a reasonable profit margin of 5%, normal value has been constructed. The weighted average normal value for the PCNs exported by the Chinese producers working under non-market economy are shown below:

Name of the Company	Nos. of PCN's	Qty (Nos.)	Weighted Normal Value (USD/No.)	Avg. Value
M/S Fibrehome Telecommunication Technologies Ltd.	***	***		***
Alcatel-Lucent Shanghai Bell Co. Ltd.	***	***		***
M/S ZTE Corporation	***	***		***

**M/S Hangzhou ECI Telecommunication CO. Ltd**

107. This producer / exporter were found to be operating under Market economy conditions as elaborately explained above. While filing the response to the initiation, they had submitted an appendix 1, claiming to have sold \*\*\* PCN variants in the domestic market, corresponding to the PCN's sold in India. Verification of records of these revealed that these PCN variants had been sold under \*\*\* different contracts to various customers in the domestic market. It however came to notice during verification that a number of PCN's not sold in the domestic market in Israel (The PUC is invoiced from Israel), did contain some assemblies / sub-assemblies which were the same as used in the PCN's exported to India. The Authority notes that product under consideration being finished, semi finished, CKD/SKD, sub-assemblies, and considering the manner in which the producers are invoicing the product, as also considering the fact that normal value is the price of "LIKE ARTICLE" and in the absence of identical article, another article is required to be considered, normal value has to be taken by considering the SKD/CKD prices. Considering this the Normal value in respect of such sub-assemblies has been taken as the value at which these assemblies / sub-assemblies were sold in the domestic market at ex-factory level. For others, cost of production as per verified data of the producer / exporter plus profit as realized by the exporter on subject goods in the domestic market has been taken for determination of normal value. Accordingly, the normal value has been worked out as under:

Name of the Company	Nos. of PCN's	Qty (Nos.)	Weighted Avg. Normal Value (USD/No.)
M/S Hangzhou ECI Telecommunication Co. Ltd.	***	***	***

**Israel****M/S ECI Telecom Ltd. Israel**

108. The Company has provided information in various appendices, along with Bill of Materials, which has been examined by the Designated Authority. Authority notes that out of \*\*\* PCN are exported to India, only \*\*\* numbers have been sold in domestic market and se\*\*\* to third countries. This position got confirmed during verification of the responding exporter. The rest of the PCN's have not been sold except to Indian market. It however came to notice during verification that a number of PCN's not sold in the domestic market in Israel did contain some assemblies / sub-assemblies which were the same as used in the PCN's exported to India. The Authority notes that product under consideration being finished, semi finished, CKD/SKD, sub-assemblies, and considering the manner in which the producers are invoicing the product, as also considering the fact that normal value is the price of "LIKE ARTICLE" and in the absence of identical article, another article is required to be considered, normal value has to be taken by considering the SKD/CKD prices. Considering this the Normal value in respect of such sub-assemblies has been taken as the value at which these assemblies / sub-assemblies were sold in the domestic market at ex-factory level. For others,

4087 GI/10-26 A

cost of production as per verified data of the producer / exporter plus profit as realized by the exporter on sale of subject goods in the domestic market has been taken for determination of normal value. Accordingly, the normal value has been worked out as under:

Name of the Company	Nos. of PCN's	Qty (Nos.)	Weighted Avg. Value (USD/No.)	Normal
M/S ECI Telecom Ltd, Israel	***	***	***	

### Export Price

#### Responding Exporters from China PR

##### M/s Alcatel-Lucent Shanghai Bell Co. Ltd., China PR

109. As per the verified data, adjustments on account of Insurance, Inland Transportation, Handling Charges, overseas transportation, customs declaration fee, credit cost, bank charges and packing cost(As per verified data of one other responding exporter as they had not claimed any packing cost) have been taken into consideration for determination of net export price. Net export price at ex-factory level in respect of each PCN has been worked out accordingly for comparing the same with the Normal Value at the same level of trade.

##### M/S Fibrehome Telecommunication Technologies Ltd. China PR.

110. As per response filed with the Authority, they have exported \*\*\*PCN Variants to India during POI, comprising of \*\*\* Nos. However during verification of records of the responding exporter it was noticed that they had exported \*\*\* Sets / Nos of \*\*\*different PCN variants of PUC to India during POI. Verified adjustments on account of inland transportation, overseas transportation and credit cost, pre-installation and post-installation service charges / warranty and packing cost have been considered for determination of net export price at ex-factory level in respect of each PCN. Net export price at ex-factory level in respect of each PCN has been worked out accordingly for comparing the same with the Normal Value at the same level of trade.

##### M/S Huawei Technologies Co., Ltd. China PR.

111. Huawei Technologies has revised its export sales statement a number of times. The company also pleaded that the systems followed by the company are different from the PCN system followed by the Authority and argued that the company would have faced no difficulties in providing export sales information had the company followed company's internal product coding systems. The company revised its export sales statement a number of times. As brought out in the verification report sent to the company, the export sales information of the company remained un-verified. The Authority is unable to accept the argument that the product coding system followed by the Authority was too complicated and prevented the company from providing the desired information. Indeed, a number of producers in subject countries have participated in the present investigations and have

provided information without expressing the kind of difficulties expressed by the company. Notwithstanding, the Authority had clearly stated while informing product coding system to the interested parties that the exporters were free to modify product coding system or use their own system, should they find the system proposed by the Authority is insufficient/inadequate or cumbersome. In any case, nothing prevented the exporter from providing information on both the basis – the product coding system followed by the Authority and product coding system followed by the company.

112. The product under consideration is essentially an assembly of a number of electronic cards and sub-assemblies. In fact, the producers tend to invoice the sales in terms of SKD/CKD/cards/sub-assemblies of the product. Investigation has shown that all the companies follow some system for design and development of the product, for which some product coding system is followed. It is noted that the export sales information has been so drastically revised by the company that even sub-assemblies/cards composition has also been altered in different responses.

113. As per response filed with the Authority, they had claimed to have exported \*\*\* PCN Variants to India during POI, comprising of \*\*\* Nos. Out of these \*\*\* PCN's were cards. No quantity had been mentioned in respect of these \*\*\* PCN's and therefore these were excluded for the purpose of determination of NEP for preliminary determination. These PCN's were basically extracted from PO's executed with different customers in India. Although the Authority gave necessary opportunity to them to get their data verified during verification visit, the PCN details claimed by them could not be verified as there appeared mismatch in subfields identified against each PCN as per the nomenclature prescribed by the Authority. This was pointed out to them in the verification report. In response to the verification report, they submitted the updated PCN details, claiming to have corrected the anomaly and sought acceptance of the same for determination of NEP. According to this they had exported \*\*\* sets / nos. of \*\*\* different PCN variants to India during POI. That apart they also claimed to have exported a few more PCN's against loan contract to Prithvi etc. against which they had failed to provide proper accounting during verification.

114. Considering the above, the Authority holds that claim on export sales to India remained unverified in spite of reasonable and adequate opportunity having been provided to them. The Authority is therefore unable to determine individual Export Price and NEP for determination of either individual DM or Injury Margin in respect of the subject producer exporter.

#### **ZTE Corporation**

115. So far as the provisional measures are concerned, individual DM was not allowed to them as it was found that they had filed incomplete data. Details in this regard were reported in PF document. Further it was stated in the PF document that a view as to whether the data proposed to be provided afresh by the company shall be accepted subsequently for final determination shall be taken by the Authority on receipt of the same. The responding

exporter, subsequent to issue of Preliminary Findings submitted fresh data with regard to exports to India. The data was found to be complete and has been duly accepted by the Authority for final determination. As per the revised data submitted, the subject exporter / producer have exported \*\*\* sets / nos. of \*\*\* different PCN variants to India during POI. That apart they had also exported \*\*\* nos. of cards. Verified adjustments on account of credit cost, Inland Freight, Handling, loading and ancillary expenses, customs clearance, ocean freight, insurance, bank charges, packing charges and warranty have been considered for determination of net export price at ex-factory level.

**M/S Hangzhou ECI Telecommunication CO. Ltd China PR through M/S ECI Telecom Ltd. Israel**

116. As per the verified data, they have exported \*\*\* PCN Variants to India during POI, comprising of \*\*\* Nos. Adjustments have been claimed on account of Inland Freight, Overseas Freight, insurance, storage, Finance Cost / SGA Expenses, profit of ECI Israel (related trader in this case) and Warranty etc. as verified have been allowed for determination of Net Export Price at ex-factory level.

**Israel**

**M/S ECI Telecom Ltd. Israel**

117. As per the verified data, they have exported \*\*\* PCN Variants to India during POI, comprising of \*\*\* Nos. Adjustments have been claimed on account of Inland Freight, Overseas Freight, insurance, storage, Finance Cost Expenses and Warranty etc. as verified have been allowed for determination of Net Export Price at ex-factory level.

**Dumping margin**

118. The Authority has recognized differences in physical and optical characteristics of different types of SDH equipment and has accordingly compared normal value with export price by considering the physical and optical characteristic and configurations of SDH equipments imported against identical specifications. The comparison has been made on the basis of Normal value and export price in respect of each PCN separately and weighted average Normal Value has thereafter been compared with the weighted average NEP for determination of Dumping Margins. The dumping margins so determined are detailed in the table below.

Name of the Company	Weighted Normal Value (USD/No.)	Avg. Value (USD/No.)	Weighted Export Value (USD/No.)	Dumping Margin USD/No. (%)
M/S Fibrehome Telecommunication Technologies Ltd.	***	***	***	*** (280-290%)
Alcatel-Lucent Shanghai Bell Co. Ltd.	***	***	***	*** (40-50%)
M/S Hangzhou ECI Telecommunication Co. Ltd	***	***	***	*** (5-15%)
M/S ECI Telecom Ltd., Israel	***	***	***	*** (10-20%)
M/S ZTE Corporation	***	***	***	*** (30-40%)

Residual - China			(280-290%)
Residual – Israel			(200-210%)

### **Injury Determination**

#### **Submissions by the domestic industry**

119. The Domestic Industry has made following submissions on Injury.

- (i) The product under consideration is required by the customers for setting up the optical transmission backbone of their telecom networks. It is capital goods procurement for them. Given the huge value of investments involved, the customers follow a well laid down system of purchase.
- (ii) Companies such as BSNL, MTNL and RailTel, follow a system of open tendering, whereas private players (such as Bharati, Reliance, Tata Communication etc.) follow a system of closed tenders through a Request For Proposal (RFP) process.
- (iii) In open tenders, bids are invited from all suppliers in closed sealed envelopes, such bids are opened in presence of all participating suppliers and prices quoted by suppliers are announced publicly. In closed tenders, the customers invite quotations, compare the same and thereafter normally place orders based on the best commercial offer (lowest price, credit terms etc.).
- (iv) Price negotiation in both the systems is not ruled out. Such price fixation can be for specified volumes or tentative volumes. Actual shipments however take place over the tenure of the rate contract (of 12-24 months).
- (v) Considering high value of business involved, the petitioner regularly tracks requirement of individual customers and very closely monitors each offer made.
- (vi) Petitioner is reasonably well aware of the procurements made by the customers. Petitioner is reasonably well aware of the procurement decision taken by the customers.
- (vii) Petitioner has consolidated information with regard to various orders won and lost over the injury period based on this market intelligence regularly developed.
- (viii) Various intending suppliers quote irrevocable prices. After this offer, while there is a possibility of further price reduction, there is no possibility of increase in the prices.
- (ix) Designated Authority should focus on the offers made by the Foreign Producers and Indian Producers for assessing injury to the domestic industry. The injury margin should also be determined based on these offers made by the foreign suppliers.

#### **Views / Submissions made by opposing interested parties**

120. Interested parties opposing the petition have made submissions on injury which can be summed up as follows:

4087 GI/10-26 B

- i. There is no basis to suggest that the provision of Article 3.4 in any way authorizes the consideration of exports which are scheduled rather than affected.
- ii. A dumping margin and injury margin determination can only be determined with respect to the Period of Investigation and not merely on estimates.
- iii. SDH Transmission Equipments such as STM 64 are not manufactured by the petitioners. Therefore injury faced by the petitioners can only arise out of the limited demand for the subject goods produced by the petitioner. Further the assertion by the petitioner that customers now would prefer to purchase 2 units of STM 64 or 8 units of STM 16 rather than 128 units of STM 1 is preposterous and reflects a complete failure to understand the customer pattern or utilization of SDH Transmission Equipment. Assuming without admitting that the submission of the petitioner actually makes sense, the question needs to be asked whether the significant decline in demand for the subject goods in volume terms should not be a natural corollary where as available data shows quite the contrary.
- iv. There is significant increase in market share of the petitioners from 2007 -08 to POI, from 13.5% to 18.1%. This increase is almost completely at the expense of imports of subject countries which decreased from 45.19% in 2007-08 to 41.32 in POI.
- v. The submission of the petitioner with respect to its capability to cater to the Indian market and capacity utilization has been directed throughout the submission on its claim that EMS vendors, who in turn are primarily based in international jurisdictions such as Thailand and Malaysia, have the requisite capacity to fulfill Indian demand. The basic question that we request the DGAD to address is whether it is relevant to treat the petitioners as domestic producers as the actual production work is carried out only in Thailand and Malaysia and not in India.
- vi. Production and sales have increased compared to both, base year 2005-06 as well as previous period 2007-08. The petitioner now claims sales and production have decline compared to 2006-07. This approach of picking and choosing injury periods to establish a decline or increase is devoid of any reasonable justification.
- vii. Huge claims of losses by the petitioner are not corroborated by the annual reports of the petitioner.
- viii. The submission of the petitioner with respect to inventory is inaccurate.
- ix. On causal link analysis, the Authority should examine factors like pattern of consumption, Development of Technology and imports from third countries.
- x. Significant imports take place from affiliated companies and EMS vendors based abroad. It is quite obvious that a profit margin would be added by these companies prior to sale to the petitioner. Furthermore, imports from the affiliated company Tejas Communications PTE Limited is quite considerable.
- xi. The applicant industry has admitted the inherent nature of the sales in this segment of the industry. Clearly, prices are not determined based on demand and supply. In other words, the landed value has no bearing on the tendering process and hence the methodology adopted in normal cases is not applicable in such cases. In any case potential performance of the Industry as a factor of injury as argued is on the face of it bad in law. Further, there is no substantiation, cogent material or data in support of

applicants claim about potential performance for the Designated Authority to reach conclusions based on such claims.

- xii. Authority should not convert entire volumes in terms of one size say STM-4 and STM-16 as alleged by the Petitioner and it is submitted that the said request by the Petitioner also deserves to be rejected.
- xiii. There is no Injury to the Domestic Market. In fact a lot of indices show a positive trend:
- xiv. There is no material injury or any threat of material injury to the Domestic Industry by the imports of Chinese producers/exporters. The alleged injury is just a mere allegation, conjecture and remote possibility and the same are not substantiated by evidence:
- xv. The demand of the subject goods has as such increased from 100 (2005-06) to 183 (POI) and the corresponding sales of the domestic industry has grown up to 175 during the same period which cannot be said to be significantly low.
- xvi. Chinese producers/exporters imported the subject goods to India at a reasonable landed price which has not caused price undercutting of the subject goods in the Domestic Market
- xvii. The Domestic Industry's market share has increased from the 2007-08 to the POI.
- xviii. Tejas claimed that its export profits are at present financing the domestic losses. However, it is to be noted that despite the Tejas' present allegations, its own data (Proforma IVA) reveals export losses.
- xix. Return on investment is not a proper index to analyze as to whether there has been an injury caused to the Domestic Industry due to imports of the subjects in India by Chinese producers/importers.
- xx. It has been submitted that the definition of PUC and 'like article' is not only relevant for the determination of the normal value, export price which culminates into calculation of dumping margin but also for the assessment of injury to the domestic industry. The issue of like product has to be determined as early as possible in an anti dumping investigation because it clearly has an impact on the proceedings including the imposition of duties.
- xxi. It has been alleged that information provided by Tejas in relation to the low-end transmission products being manufactured by it has been considered and analyzed for arriving at the injury to the domestic industry arising from the entire range of equipments covered under the PUC including the high-end transmission products and other categories of equipments covered within the broad description of PUC.
- xxii. Entire injury analysis is based on data relating to SDH alone whereas according to the applicant industry itself, the scope of investigation seeks to cover accessories, associated software, parts and components, Populated PCB's, Power supply, lasers, Chassis, EI cables, PCM cables, power cables, racks, workstations etc..

### Examination by the Authority

121. The Authority has noted the views expressed by the interested parties in respect of the injury claims of the domestic industry and examined the mandatory factors for the purpose of injury determination and causal link analysis.

#### Assessment of import volumes –

122. The Authority has examined information made available by the petitioner from secondary sources, information received from the DGCI&S, information made available by the petitioner from IBIS, information provided by the responding exporters and importers for assessment of import volumes. The Authority has considered information made available by the responding exporters in so far as POI is considered. For previous years, since none of the exporters have provided information in the form and manner prescribed and has provided information for different periods, the Authority has no other option but to adopt information contained in the petition.

#### Assessment of demand

123. Authority has determined demand or apparent consumption of the product in the Country as the sum of domestic sales of the domestic producers and imports from all sources. The demand so assessed can be seen in following table.

	2005-06	2006-07	2007-08	April-Dec 08 - Annualized	April-Dec 08	POI annualised vis-à-vis 2005- 06
<b>In terms of numbers</b>						
China	***	***	***	***	***	1364%
Israel	***	***	***	***	***	35%
Subject Countries	***	***	***	***	***	240%
Other Countries	***	***	***	***	***	151%
Imports in India	***	***	***	***	***	186%
Sales of Domestic industry	***	***	***	***	***	175%
Sales of Other Indian Producers as estimated by the domestic industry	***	***	***	***	***	
Demand	51308	118,500	81,186	94,027	70,520	183%
<b>In terms of value – Rs. Lacs</b>						
China	***	***	***	***	***	1159%
Israel	***	***	***	***	***	183%
Subject Countries	***	***	***	***	***	334%
Other Countries	***	***	***	***	***	229%
Imports in India	***	***	***	***	***	270%
Sales of Domestic industry	***	***	***	***	***	234%
Estimated Sales of Other Indian Producers	***	***	***	***	***	
Demand	50,461	79,829	117,574	132,083	99,062	262%

124. Demand for the product under consideration has shown significant increase in terms of both numbers and values. Domestic industry alleged that in spite of significant increase in the demand in the country, they are not able to take advantage of the same because of dumping from subject countries. This allegation of the domestic industry is corroborated as much as the demand has gone up by 42,719 pcs / nos or Rs. 816.22 crores, whereas sales of the domestic industry increased by 2593 pcs / nos. or Rs. 108 crores only during the period.

#### **Import volumes and market share**

125. With regard to the volume of the dumped imports, the Designated Authority is required to consider whether there has been a significant increase in dumped imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in India. Annexure-II (ii) of the Anti-dumping rules provides as under: -

*“While examining the volume of dumped imports, the said authority shall consider whether there has been a significant increase in the dumped imports, either in absolute term or relative to production or consumption in India .....”*

126. Volume of dumped imports from the subject countries is given in following table:-

	2005-06	2006-07	2007-08	April-Dec 08 - Annualized	April- Dec 08
Subject Countries	16,159	55,907	36,688	38,856	29,142
Other countries	25,219	38,257	33,520	38,117	28,588
Total Imports	41,378	94,164	70,208	76,973	57,730
Indian Production	9,930	24,337	10,978	17,053	12,790
Indian Consumption	51,308	118,500	81,186	94,027	70,520
Market Share imports					
Subject Countries	31.49%	47.18%	45.19%	41.32%	41.32%
Other countries	49.15%	32.28%	41.29%	40.54%	40.54%
Subject Countries Imports in relation to Indian Production	162.73%	229.72%	334.20%	229.54%	227.85%

127. The Authority notes that the volume of imports from subject countries has increased significantly. It is noted that whereas the volume of imports from subject countries during POI (annualized) (when measured in terms of numbers) increased by about 140% over base year 2005-06. Share of subject countries in total Indian consumption of the product increased significantly from 31% to 41% over the injury period. In terms of value, the absolute imports from subject countries have increased significantly by about 234% during POI (annualized) over 2005-06.

	2005-06	2006-07	2007-08	April-Dec 08 - Annualized	April-Dec 08	POI annualised vis-à-vis 2005-06
In terms of numbers						
China	***	***	***	***	***	1364%
Israel	***	***	***	***	***	35%

4087 GI/10-27A

Subject Countries	***	***	***	***	***	240%
Other Countries	***	***	***	***	***	151%
Imports in India	***	***	***	***	***	186%
Sales of Domestic industry	***	***	***	***	***	175%
Sales of Other Indian Producers as estimated by the domestic industry	***	***	***	***	***	
Demand	51,308	118,500	81,186	94,027	70,520	183%
In terms of value – Rs. Lacs						
China	***	***	***	***	***	1159%
Israel	***	***	***	***	***	183%
Subject Countries	***	***	***	***	***	334%
Other Countries	***	***	***	***	***	229%
Imports in India	***	***	***	***	***	270%
Sales of Domestic industry	***	***	***	***	***	234%
Estimated Sales of Other Indian Producers	***	***	***	***	***	
Demand	50,461	79,829	117,574	132,083	99,062	262%

128. It is seen that there has been significant increase in imports from subject countries both in absolute term as well as in relation to production in India.

### Imports in relation to consumption in India

129. Volume of dumped imports from the subject countries in relation to consumption in India is given in following table:-

	2005-06	2006-07	2007-08	April-Dec 08 - Annualized	April-Dec 08	POI annualised vis-à-vis 2005-06
<b>Imports in Nos.</b>						
China	2,502	9,959	10,056	34,132	25,599	1364%
Israel	13,657	45,948	26,632	4,724	3,543	35%
Subject Countries	16,159	55,907	36,688	38,856	29,142	240%
Other Countries	25,219	38,257	33,520	38,117	28,588	151%
Total Imports	41,378	94,164	70,208	76,973	57,730	186%
<b>Imports in Value Rs./ Lacs</b>						
China	2,461	6,717	14,564	28,500	21,400	1159%
Israel	13,433	30,989	38,570	24,553	18,414	183%
Subject Countries	15,894	37,706	53,134	53,085	39,814	334%
Other Countries	24,805	25,802	48,545	56,791	42,593	229%
Total Imports	40,699	63,508	101,679	109,876	82,407	270%
<b>Indian Consumption</b>						
Volume	51,308	118,500	81,186	94,027	70,520	183%
Value Rs. Lacs	50,461	79,829	117,574	132,083	99,062	262%
<b>Subject Countries Imports in relation to Indian Consumption</b>						
Volume	31.49%	47.18%	45.19%	41.32%	41.32%	131%
Value Rs. Lacs	31.50%	47.23%	45.19%	40.19%	40.19%	128%

130. It is seen that imports from subject countries which were only 31.5% during 2005-06 went up to 41.32 % in POI in relation to consumption in India. Authority notes that volume impact of the imports on the domestic industry has been adverse.

### **Price effect of imports**

131. With regard to the effect of the dumped imports on prices, the Authority examined whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree.

132. The Authority notes that each consumer procures SDH equipment meeting its specific requirement. SDH equipment used by a consumer at one station might differ from SDH equipment used at other stations in terms of associated physical and optical properties. In view of the same, for the purpose of assessment of price undercutting, the Authority has considered most closely resembling product type sold by domestic industry and compared the same with imported product type. Wherever there are no identical models, the Authority has considered a model having lower configuration than the imported product in order to ensure that price undercutting was not overstated. After determining price undercutting for individual PCN exported, the Authority has determined weighted average price undercutting for the responding exporter after considering associated volumes. It is seen that the price-undercutting margin are quite significant.

133. In this regard, Authority examined price undercutting separately for each model (PCN). Wherever the domestic industry has not offered identical model, the Authority has considered comparable lower model offered by the domestic industry. It is seen that the landed price of imports for the responding exporters are significantly lower than the selling price of the same equipment offered by the domestic industry, resulting in significant price undercutting. In fact, wherever the domestic industry has not offered identical model and comparison has been made with comparable lower model, it is seen that the landed price of imports are lower than the selling price of the domestic industry. While the domestic industry argued that its selling prices must be adjusted upwards in these cases, it is observed that the extent of price undercutting was significant even without such an adjustment.

134. Petitioner claimed that it has been forced to lower its prices in order to continue to get business. Resultantly, the domestic industry has been gradually lowering its prices, far beyond justified levels in view of low & dumped prices offered by the subject exporters. Petitioner also claimed that the prices offered by the foreign producers for supply of the same equipment in subsequent orders have been materially lower than the prices offered in the past. In other words, each successive price offer for supply of the same equipments has been at materially lower prices. Petitioner further argued that whereas the petitioner suo-moto, follows a practice of offering lower prices each successive year to its clients for the same

equipment, the price reduction offered by the foreign producers are too significant and too steep. Given the small size of the market [there is limited and known number of suppliers], petitioner further claimed that activities of each of the supplier and consumer get tracked by all concerned. Therefore, low prices offered by the Foreign Producers not only result in loss of business in that account, but also, the same has benchmarking impact on all subsequent offers that the domestic industry makes. Thus, injury to the domestic industry from such loss of business must be seen not only in one account where the domestic industry loses sales, the same must be seen in all other accounts where the domestic industry thereafter is forced to reduce the prices to prevent the dumping.

135. In order to determine whether imports for the product under consideration are suppressing or depressing the prices of product under consideration, the Authority considered the trends in cost of sales and sales revenue for the domestic industry. The relevant information is given below:

Rs. Lacs	2005-06	2006-07	2007-08	April-Dec 08 - Annualized	April-Dec 08	POI annualised vis- à-vis 2005-06
Cost of sales	***	***	***	***	***	***
Index	100	144	171	294	294	
Increase over previous year		***	***	***		
Sales revenue	***	***	***	***	***	***
Index	100	139	172	234	234	
Increase over previous year		***	***	***		

136. It is seen that the increase in cost of sales in 2006-07 was higher than increase in sales revenue. Thereafter, in 2007-08, the increase in cost of sales was slightly lower than increase in sales revenue. However, in period of investigation (annualized), increase in the sales revenue was far lower than increase in cost of sales. Whereas sales revenue increased only by 36% during POI over 2007-08, cost of sales increased by 72% over the period. On overall basis, whereas cost of sales increased by Rs. \*\*\* crores, the sales revenue increased only by Rs. \*\*\* crores. It is thus clear that imports were suppressing/depressing the price of domestic industry in the market.

#### **Economic parameters of the domestic industry**

137. Annexure II to the Rules requires that a determination of injury shall involve an objective examination of the consequent impact of these imports on domestic producers of such products. With regard to consequent impact of these imports on domestic producers of such products, the Rules further provide that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry should include an objective and unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on

investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments. Petitioner submits that examination of performance of the domestic industry would reveal that the domestic industry has suffered material injury. Further, the domestic industry is threatened with material injury, should the present condition continue, as discussed in detail here in under.

### Capacity and capacity utilization:

138. Petitioner claimed, core of production in this industry is in design and development of the product. The actual process of manufacturing and extent thereof can be in house or outsourced depending on requirement. The petitioner claimed that it can meet the entire Indian demand without any addition to plant and machinery, since producers in this industry leverage the capacities of Electronic Manufacturing Services partners, who in turn have enough capacities to meet the next 10 years requirements of India. In other words, capacity and capacity utilization must be seen in terms of intellectual property and ability of the company to deploy qualified personnel to carry out necessary design and development and manage its global supply chain. On this account, the petitioner has sufficient capacity to meet the Indian demand. In view of the same, petitioner claimed that capacity and capacity utilization may be considered irrelevant parameter in the present case.

139. Petitioner also claimed and no interested parties disputed that production of the product under consideration is extremely peculiar in as much as producers globally are increasingly concentrating on basic research, design & development. Further, petitioner claimed that capacity to produce is not an appropriate parameter in the fact and circumstances of the present case as the manufacturers decide to outsource part production activity depending on a number of factors. Authority holds that petitioners claim on this score is correct.

### Production and sales volumes

140. Production and sales volumes of the domestic industry moved as shown below:

	2005-06	2006-07	2007-08	April-Dec 08 - Annualized	April-Dec 08	POI annualized vis-à-vis 2005-06
Domestic Production (Nos.)	***	***	***	***	***	***
Indexed	100	203	117	175	175	
Domestic Sales (Nos.)	***	***	***	***	***	***
	100	203	117	175	175	

141. It is seen that domestic sales and consequently production of the domestic industry shows increasing trend over the injury period. Petitioner claimed that this was a natural outcome of three factors -(a) petitioner commenced production & sale of its new STM-1, STM-4, STM-16 and STM-64 products that enhance the range of its products (b) petitioner

4087 GI/10-27 B

has gained additional volumes due to superior technology and support that is appreciated by Indian customers (c) the market for telecommunication equipment in India has seen unprecedented growth in India - thanks to the telecommunication boom and the technological development in telecommunication sector. This was more than envisaged by the petitioner while setting up its facilities and its business plan, and additional investments were made in the company from time to time to support this. In fact, petitioner had envisaged much higher level of operation that could be achieved so far. Petitioner claimed that its production levels in fact have been lower than what it should have been. The reason for sub-optimal performance is the significant reduction in prices by Chinese/Israel suppliers and consequently substantial increase in the import volumes.

142. In view of increase in production & sales and claims of the petitioner, the increase in production was compared with increase in demand. It was seen that even when production of the domestic industry has increased over the injury period, increase in the demand of the product under consideration was far higher than the increase in production. The domestic industry had alleged that imports have taken over significant market opportunities that were available to the domestic industry. The authority thus holds that production of the domestic industry has suffered because of dumping in as much as the domestic industry has been prevented from increasing production to the extent it should have had in the absence of dumping.

#### **Market Share:**

143. Petitioner has claimed, despite the fact that the petitioner is India's first optical networking product company which is innovating and creating significant Intellectual property, the market share of domestic industry has not increased. The same has, in fact, declined. Whereas the petitioner had expected to increase its market share by introduction of new products to expand its range, the market share of the petitioner has declined over the years because of presence of dumped imports in the market. Market share of the domestic industry was determined in respect of its domestic operations. The verified information showed as follows:

	2005-06	2006-07	2007-08	April-Dec 08 - Annualized	April-Dec 08
<b>Demand/ Consumption in India</b>					
Volume	51,308	1,18,500	81,186	94,027	70,520
Value Rs. Lacs	50,461	79,829	117,574	132,083	99,062
<b>Sales of Domestic industry</b>					
Volume	***	***	***	***	***
Indexed	100	203	117	175	175
Value Rs. Lacs	***	***	***	***	***
Indexed	100	138	172	233	233
<b>Market Share of Domestic industry</b>					
Volume	***	***	***	***	***

Indexed	100	88	74	96	96
Value	***	***	***	***	***
	100	87	74	89	89

144. It is seen that the market share of domestic industry has come down during period of investigation both in terms of volume and value in comparison to the base year.

#### **Factors affecting prices:**

145. As stated before, landed price of imports being offered by Foreign Producers are significantly below the selling price of the domestic industry. As a result of significant price difference between the imported product price and domestic industry price, consumers have switched over part of their demand to the imported product. Further, the domestic industry has been forced to reduce its prices not only in subsequent supplies to the same customer, but also supplies to other customers in the market as well.

146. The domestic industry claimed, there is dramatic decline in the prices offered by Chinese suppliers. As a result of continued competition from foreign suppliers and loss of business, the domestic industry has been lowering its prices with every successive offer. The imports are therefore, clearly having significant price depressing effect in the Indian market.

#### **Profit/Loss**

147. Petitioner claimed that profits earned by the domestic industry from production and sale of the product under consideration in the domestic market declined over the injury period. So significant has been decline in the profits over the years that the petitioner has suffered financial losses during the POI in its domestic business.

148. Profit/loss of the domestic industry was determined in respect of its domestic operations. The verified information showed as follows:

	2005-06	2006-07	2007-08	April-Dec 08 - Annualized	April-Dec 08
Profit/Loss Rs./ Lacs					
Domestic	(***)	(***)	(***)	(***)	(***)
Indexed	(100)	(207)	(162)	(964)	(723)
As per annual report	(***)	***	***	(***)	(**)
Indexed	(100)	64	165	(14)	(11)
Sales Value Rs./ Lacs					
Domestic	***	***	***	***	***
Indexed	100	138	172	233	175
As per annual report	***	***	***	***	***
Indexed	100	187	302	352	264
Profit/Loss as % of Sales					
Domestic	(***)	(***)	(***)	(***)	(***)
Indexed	(100)	(149)	(94)	(412)	(412)

As per annual report	(****%)	****%	***%	(****%)	(****%)
Indexed	(100)	34	55	(4)	(4)

149. It is seen that the sales revenue of the domestic industry remained consistently below the cost of sales resulting in financial losses in respect of domestic operations. Further, loss has in percentage of sales revenue increased substantially from 9.12% in 2005-06 to 37.58% in the period of investigation. It is thus seen that the domestic industry was suffering significant financial losses, which increased significantly over the injury period.

150. Since the petitioner has significant export activities, its profits in combined operations in domestic and exports continued to be positive till 2007-08. However, significant decline in its domestic profitability has resulted in decline in the overall profitability of the company in the POI. Petitioner claimed that its exports are reasonably profitable and are at present financing the domestic losses. Petitioner further claimed that no company can survive in the long run on such basis. Dumping has created very adverse position for the domestic industry.

### **Return on Investments**

151. Since basic investments in production of the subject goods is in intellectual property in terms of design and development and skilled/qualified man power, petitioner claimed that the return on investment expressed as a percentage of return on capital employed would not adequately reflect the reasonable returns that this industry can expect. Globally the industry considers profitability in terms of gross margins and the gross margins of the domestic producers in India are significantly lower than the gross margins for their global peers.

152. Return on capital employed was determined in respect of its domestic operations showed as follows:

Rs./Lacs	2005-06	2006-07	2007-08	April-Dec 08
<b>Capital Employed – Company as a whole</b>				
Net Fixed Assets	***	***	***	***
Indexed	100	180	497	346
Working capital	***	***	***	***
Indexed	100	161	249	336
Capital Employed	***	***	***	***
Indexed	100	162	262	318
Profit before interest and tax	(***)	***	***	***
Indexed	(100)	132	285	55
Return on capital employed - %	(***)	***	***	***
Indexed	(100)	82	109	16
<b>Capital Employed – PUC Domestic</b>				
Indexed	100	120	149	224
Profit before interest and tax PUC	(***)	(***)	(***)	(***)

domestic				
Indexed	(100)	(179)	(60)	(910)
Return on capital employed - %	(***)	(***)	(***)	(***)
Indexed	(100)	(149)	(40)	(406)

153. The analysis of trend in return on capital employed showed that the domestic industry has not been able to earn profits throughout the injury period so far as domestic operations are concerned. The negative return on capital employed, which was 100 in 2005-06 deteriorated further to over 400 in POI. For the company as a whole, the domestic industry in the base year made losses. However during 2006-07 and 2007-08, the company earned profits but during POI, the return on capital employed declined significantly to the level of less than 2%. The company on its all operations including exports earned some returns mainly due to export operations. These trends show that the profitability of the domestic industry and return on investments has suffered adversely.

#### Cash flow/profit

154. Petitioner claimed that since the domestic industry has significant domestic and export operations, cash flow situation of the domestic industry for all its operations is not reflective of the impact of dumping on cash flow. Therefore, cash profits situation of the domestic industry have been ascertained considering profit before taxes and depreciation. It is seen that domestic industry had negative cash flow throughout the injury period. Further, the cash loss increased substantially in the investigation period.

	2005-06	2006-07	2007-08	POI
Cash Profit – PUC domestic	(***)	(***)	(***)	(***)
Indexed	(100)	(211)	(158)	(688)

#### Inventories: -

155. Petitioner claimed that the product under consideration is produced only after taking firm order based on detailed specifications and these goods are not kept in inventories. Authority holds that inventories are not a parameter reflecting injury to the domestic industry.

#### Employment and Wages

156. Petitioner claimed, one of the major investments is in development of intellectual property in terms of research and development. As stated before, petitioner had anticipated significant market opportunity because of the unprecedented telecommunication boom in the Country. Further, the domestic industry is improving its global presence, which also calls for intensified research & development activities. All this required investment in manpower. Resultantly, manpower deployed and consequently wages paid by the domestic industry has increased over the years, as would be seen from the table below.

4087 GI/10-28 A

SN		2005-06	2006-07	2007-08	April-Dec 08
1	Number of employees				
(a)	Research & development	***	***	***	***
	Indexed	100	151	247	324
(b)	All other activities	***	***	***	***
	Indexed	100	139	178	211
(c)	Gross employment	***	***	***	***
	Indexed	100	145	215	272
2	Wages				
(a)	Research & development (Rs./Lacs)	***	***	***	***
	Indexed	100	181	281	226
(b)	All other activities (Rs./Lacs)	***	***	***	***
	Indexed	100	166	271	260
(c)	Gross employment (Rs./Lacs)	***	***	***	***
	Indexed	100	174	276	242

157. Petitioner claimed that it is not possible to reduce the employment, as any such effort would imply a process of permanent decline of the domestic industry. The intent of the foreign producers is very clear – to eliminate Indian industry in this important product segment. The petitioner claimed that the product under consideration was developed by them in this Country and India joined select few countries in the world having capability and capacity to produce this high technology product. The Telecom growth in India has created a huge demand for the product under consideration. Elimination of Indian Producer can provide not only huge market opportunity to the foreign producers in India, but also would eliminate competition to them in global market. Present dumping is therefore likely to have very significant adverse impact on employment and wages, as India is trying to move up the value chain and create a talent pool of technologists who can create high-value, intellectually property and products.

158. Petitioner further claimed that the Govt. of China was supporting its telecom equipment manufacturing industry in a variety of ways, which includes huge soft loans.

#### Productivity:

159. Productivity of the domestic industry has been measured in terms of production per employee, expressed in number and value of SDH equipments produced.

SN		2005-06	2006-07	2007-08	April-Dec08
1	Production per employee				
(a)	Number of equipment Domestic Industry	***	***	***	***
	Indexed	100	140	54	48
(b)	Value of equipment Domestic Industry( Rs./Lacs)	***	***	***	***
	Indexed	100	97	81	66

160. It is seen that the productivity of the domestic industry has improved. In spite of improvement in productivity, however, price parameters have deteriorated significantly.

#### **Ability to raise funds:**

161. Petitioner claimed that investments in plant and machinery are not a critical factor in the present case. In fact, funds requirements in this industry are more on account of working capital than in fixed assets. Ability of this industry to raise funds may, therefore, seriously be affected with the present level profitability of the domestic industry.

#### **Assessment on Injury**

162. Having regard to the information made available by various interested parties and investigation conducted, the Authority concludes that subject imports have increased in absolute terms (both in volume & value) and in relation to production & consumption in India. There is significant decline in the import price over the injury period. Imports are significantly undercutting the prices of the domestic industry in the market. Imports are depressing the prices of the product under consideration in the market. Performance of the domestic industry deteriorated in terms of profits, market share, and return on investment, cash flow, and growth. Even though volume of production and sales increased over the injury period, the domestic industry lost significant business opportunities to sell their products in the market. Authority has considered capacity utilization and inventories is not indicator of injury to the domestic industry. Decline in profits, return on investments and cash flow is in spite of significantly improved performance on export front. Employment, productivity and wages have improved. However, the improvement therein far outweighs the deterioration in other parameters. The deterioration in the performance during the current period is quite significant and material.

#### **Causal link and Analysis of other factors**

163. Having examined the existence of material injury and volume and price effects of dumped imports on the prices of the domestic in terms of its price undercutting, price underselling and price suppression, and depression effects the Authority has also examined whether other indicative parameters listed under the Indian Rules and Agreement on Anti Dumping could have contributed to injury to the domestic industry. Therefore, the following parameters have been examined:

- a) Imports from Third Countries: - Imports from countries not under investigation are either insignificant or at prices higher than the import prices from the subject countries and therefore, do not affect the prices in the domestic industry;
- b) Contraction in Demand: - Demand for the subject goods have increased substantially during the injury examination period. Therefore, possible contraction in demand cannot be attributed to the injury to the domestic industry.

- c) Pattern of consumption: - No significant change in the pattern of consumption has been alleged by any interested party.
- d) Conditions of competition: - The goods are freely importable. The applicant is the major producers of the subject goods and account for almost 100% of the domestic production. Therefore, domestic competition could not be attributed to the injury to the domestic industry. No other evidence of conditions of competition or trade restrictive practices has been brought to the knowledge of the Authority.
- e) Developments in technology: - There is no allegation of significant changes in technology which could have caused injury to the domestic industry.
- f) Export performance of the domestic industry: - There is no evidence on record to show that exports of the DI have any impact on its performance considered hereinabove.
- g) Productivity: - Productivity of the domestic industry has improved in terms of total output. Therefore, this cannot be attributed to the injury of the domestic industry.

164. The non-attribution analysis as above shows that no other factor other than the dumped imports has affected the domestic industry.

#### **Factors establishing causal link**

165. Analysis of the performance of the domestic industry over the injury period shows that the performance of the domestic industry has materially deteriorated due to dumped imports from subject countries. Therefore, the causal links between dumped imports and the injury to the domestic industry is established on the following grounds:

- a. The dumped import prices and consequently the landed price of imports from the subject countries steeply declined, resulting in significant price undercutting. As a direct consequence, the domestic industry was forced to reduce the prices.
- b. Reduction in the selling prices by the domestic industry adversely affected the profits, cash flow and return on investments of the company.
- c. Even though the domestic industry responded to decline in import prices, significant positive price undercutting resulted in increase in market share of imports from the subject countries. As a direct consequence, market share of the domestic industry declined.
- d. In spite of increase in demand and reduction in selling prices by the domestic industry, market share of the domestic industry declined due to significant reduction in landed price of imports. This retarded the growth of the domestic industry.
- e. The significantly low prices being offered by the foreign producers have prevented the domestic industry from increasing its production and sales to the level it could have in the absence of dumping.

166. The Authority concludes that the domestic industry suffered material injury and the injury have been caused by the dumped imports from the subject countries/territories.

**Magnitude of Injury and injury margin**

167. The non-injurious price determined by the Authority has been compared with the landed value of the exports for determination of injury margin. The comparison has been done by determining the non injurious price for the model imported in India. Separate comparison has been done and injury margin determined for each model imported. Thereafter, the weighted average injury margin has been determined considering the associated import volumes. The injury margins have been worked out as follows:

Country	Exporter	Injury Margin Rs Per PCN	Injury Margin %
China PR	M/S Fibrehome Telecommunication Technologies Ltd.	***	280-290%
	Alcatel-Lucent Shanghai Bell Co. Ltd.	***	40-50%
	M/S Hangzhou ECI Telecommunication Co. Ltd	***	110-120%
	M/S ZTE Corporation	***	30-40%
Israel	M/S ECI Telecom Ltd., Israel	***	2-10%
Residual—China PR		***	280-290%
Residual - Israel		***	65-75%

**Comments Received from Various Interested parties to the disclosure statement.****Domestic Industry**

168. Domestic Industry in their submissions in response to the disclosure statement has stated as under

- i. The Authority should specify meaning of origin and what constitutes Indian product, Chinese product or third country product;
- ii. Use of EMS constitutes “job work”, which is very much permissible under the law. In fact, the costing section requires details of job work done or got done by the domestic industry. Production activity by EMS does not constitute production;
- iii. Tejas has not utilized any EMS company in Malaysia
- iv. Petitioner has standing to bring and maintain the present petition;
- v. The Authority has re-determined non injurious price based on preliminary comments to disclosure statement given by the domestic industry. The re-determined non injurious price may be disclosed to the domestic industry;
- vi. The domestic industry has provided some import data and claimed that ECI and ZTE have not truthfully disclosed all of their export transactions to the Authority.
- vii. Duty should be recommended on software, technical know-how and profit element as well, as these constitute product;
- viii. Duty may be recommended on ad-valorem basis only;

4081/61/10-28 B

**Examination by the Authority**

169. Authority seeks to hold that Tejas is the Domestic Industry and has necessary standing within the scope of the Rules, without a reference to the IPR issue, as of now because Tejas is the only manufacturer who provided data in manner prescribed, to the Authority. There were claims of being domestic producers by VMCL and Prithvi, one of whom, at the fag end of the investigation in August, 2010, admitted in writing that they are into manufacture of DWDM, not included under PUC, and the other claimant was found to be an importer of the equipment during the course of verification carried out at the premises of the responding exporters and therefore not eligible to be considered as DI within the scope of Rule 2(b). Moreover, no verifiable data, whatsoever, in the manner prescribed, was presented to the Authority by either of the two, FIBCOM, the claimant to be another producer, also did not provide any verifiable data, although they came in support of Tejas seeking imposition of duty of complete equipment and no other interested came forward to claim to be the manufacturer, nor did any other interested party provide any data on this score to the Authority. The Authority has re-determined non injurious price based on the submissions made by the domestic industry. As regards unreported transactions, the Authority notes that while ZTE provided evidence that the alleged missing transactions are not within the scope of the product under consideration; ECI also provided evidence that the volumes reported in the import data were not correct.

**M/S RAD Data Communications Ltd (RAD).**

170. Commenting on the disclosure statement they have sought exclusion of those RAD products/modules having STM-1 interface don't work in SDH environment, because they are used to carry data and voice traffic over dark fiber, in private campus networks or private networks of Defense, Railways, and Utilities. Many of these products are stated not to transmit data/voice traffic in SDH environment, because they are used only as 'monitoring/probe' devices for 'Operations and Maintenance' of Transmission Networks. Therefore these products/modules do not have the same end use of SDH Transmissions and cannot be considered as "like products" to those manufactured by Tejas. They have also sought exclusion of similar STM-4 interfaces.

**Examination by the Authority**

171. The Authority reiterates the scope of the product under consideration in the present case and holds that all other goods which do not conform to the scope of the product under consideration are clearly beyond the scope of the proposed measures. The interested parties are expected to establish their claims before the customs port authorities with regard to exact nature of the product sought to be cleared. While it is well understood, it is clarified that anti dumping duty is chargeable only if the product sought to be cleared falls within the scope of the product under consideration. The Authority has however addressed all the concerns on inclusions and exclusions from the purview of recommended AD Duty in the form of a footnote to the Duty Table of this Final Findings Document.

**M/s Ceragon Networks Limited**

172. The product produced by Ceragon shall be outside the scope of the product under consideration as it is not like article with the product under consideration. They have also submitted that Designated Authority should amend the scope of the investigation by clearly excluding Ceragon's products/modules including STM -1 so as to avoid any kind of interpretational issues during the imports of the products.

**Examination by the Authority**

173. The Authority reiterates its position. Anti dumping duty applies on the product regardless of the producer. Further, Authority considers that it would not be appropriate to specify names of the individual companies or products which are outside the scope of the product under consideration and proposed duties. Moreover, nothing prevents an exporter to export goods produced by some other producer attracting anti dumping duty. The Authority has however addressed all the concerns on inclusions and exclusions from the purview of recommended AD Duty in the form of a footnote to the Duty Table of this Final Findings Document.

**Fibcom**

174. They have re-iterated their claim to be domestic manufacturers. While agreeing with the facts brought out by the Authority in the disclosure statement, they have sought describing the PUC in terms of ITC (HS) at 8 digit level to avoid circumvention on payment of AD Duty by the importers.

**Examination by the Authority**

175. The Authority reiterates its position. Anti dumping duty applies on the product regardless of customs classification. Customs classifications have been mentioned only for customs convenience and are not binding on the scope of the product liable to anti dumping duty. Anti Dumping duty shall apply on the product under consideration regardless of the customs classification reported by the importer. Similarly, anti dumping duty will not apply even if a product has been reported under the customs classification mentioned in the present notification if the product sought to be imported falls beyond the scope of the product under consideration. The Authority has however addressed all the concerns on inclusions and exclusions from the purview of recommended AD Duty in the form of a footnote to the Duty Table of this Final Findings Document.

**ANDA Telecom**

176. SDH equipments are not similar to PDH equipments. The of Designating Authorities should be clearly mentioning the difference between SDH and PDH equipments, If any antidumping duty is payable it should only on SDH equipment not on PDH equipments

**Examination by the Authority**

177. The Authority reiterates its position. Anti dumping duty applies only on product under consideration as defined in the present notification. All other products are in any case beyond the scope of the product under consideration of the present notification. The Authority has addressed all the concerns on inclusions and exclusions from the purview of recommended AD Duty in the form of a footnote to the Duty Table of this Final Findings Document.

**Ceragon Israel**

178. They have pleaded that Ceragon exports some Microwave Radio Terminals which could have an STM-1 interface to the SDH transmission equipment. This interface claimed to act as a physical media to enable the connectivity between the radio and the SDH equipment. It has been emphasized that this is merely an interface, and does not perform any of SDH transmission equipment requirements. Thus they have sought to amend scope to exclude Ceragon's products, including those with STM-1 interface.

**Examination by the Authority**

179. The Authority has addressed all the concerns on inclusions and exclusions from the purview of recommended AD Duty in the form of a footnote to the Duty Table of this Final Findings Document. Anti dumping duty applies only on product under consideration as defined in the present notification. All other products are in any case beyond the scope of the product under consideration of the present notification.

**UT Starcom Inc. (India Branch Office)**

180. They have submitted that They oppose imposition of antidumping duty on the Subject Goods and contest finding in the Disclosure Statement on the following grounds::

- i. Tejas does not fall under the ambit of the definition of "Domestic Industry" as defined under Rule 2 (b) of The Act Tejas must also prove that they manufacture all necessary accessories, parts, components and cables and SDH Equipment, considering that Tejas is an importer of these parts and does not "produce" them as Tejas imports 95% of these parts, components and accessories into India, 65.58% of raw material utilised by Tejas being imported.
- ii. It is wrong on part of the Designated Authority to expect the interested parties opposing such investigation to prove otherwise. It is only when the applicant discharges the initial burden in terms of Rule 5(1) of the Anti Dumping Rules onus would then shift to the responding parties to prove their case.
- iii. There is no apparent threat of injury faced by the indigenous industry due to alleged surge of import of the Subject Goods from the Subject Countries. A mere increase in volume of imports is not the primary factor for establishing dumping and proper importance should also be given to other economic parameters such as capacity

utilization, volume of sales, volume of production of the applicant in the investigations to calculate actual injury for levy of anti dumping duty. In this regard they have drawn reference is drawn to Carbon Black case , wherein it has been held that increased imports entering at declining prices coupled with the fact that surplus capacities were set up abroad is an indicator of imminent serious injury.

- iv. The Authority in the Disclosure Statement has out rightly rejected various other factors which are also relevant for determining the causal relationship. The Designated Authority while observing that production and sales of the Domestic Industry has increased completely ignored it while evaluating extent of injury to the Domestic Industry. They have referred to Article 3.5 of the Anti Dumping Trade Agreement which provides that while determining injury and causal link thereof mere existence of dumping is not sufficient to impose anti dumping duty. Furthermore it has also been submitted that the consideration of the relevant factors for determining injury and causal link by the Designated Authority, should not be a mere mechanical exercise with a check-list approach, but, a meaningful and objective assessment of relevant factors having bearing on existence and consequences of injury by import of such article in the context of any established industry in India.
- v. There is contradictions in the findings that while demand of SDH Equipment is increasing, production is increasing, sales revenue is also increasing (36% during POI) and capacity utilization is also increasing, still the Domestic Industry is alleging dumping and injury. The Authority in the Disclosure Statement has mentioned that volume of imports has increased from 31.55 in 2005-06 to 41.32% during POI however, very conveniently ignoring the same data which shows that volume of imports has also gone down from 47.18% in 2006-07 to 41.32% during the period of investigation. Thus this kind of proposition is based on false allegations by a single motive of gaining monopoly and restricting competition is not only anti consumer, anti competition but also encourages cartelization by the Domestic Industry.
- vi. Contrary to claims of the Petitioners, their production has increased at a reasonable rate during the period 2005-06 to 2006-07 to 2007-08 which is also corroborated in the Disclosure Statement. Thus, it is evident that the Domestic Industry is not facing any injury from imports of SDH Equipment from the Subject Countries and thus there exists no causal link of alleged injury to the Domestic Industry. In this regard they have placed reliance on the decision of the Hon'ble Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in the case of **Andhra Petrochemicals Vs. Designated Authority** [2006 (201) E.L.T. 481 (Tri.)] wherein it has been held:

*“The designated authority is required to give a final finding, inter alia, as to the export price, normal value and the margin of dumping of the article under investigation and as to whether import of the said article into India causes or threatens material injury to any industry established in India or materially retards the establishment of any industry in India.”*

- vii. Treatment of China as a non market economy country by the Designated Authority is rather arbitrary in nature. To treat any economy as non market economy specific

4087 GI/10-29 A

findings has to be given in each case. Past treatment cannot be the sole reason for treating any economy as non market economy is not tenable. Further non market economy status cannot be fastened to any country as a general rule.

viii. The entire investigation is being conducted in an arbitrary manner and without having regards to the principles of natural justices as giving bare 24 hours to submit response to the Disclosure Statement, lists out some instances of the gross violations of principles of natural justices, further details of which would be submitted during the course of hearing in the matter:

ix. Most of the data submitted by the Domestic Industry has been marked confidential and accepted by the learned Designated Authority as such, leading to a situation that exporter/ importers are not able to make an effective rebuttal of claim made by the Domestic Industry. While Rule 7(1) of the Anti Dumping Rules provides for submissions of information on confidential basis, Rule 7(2) thereof mandates for providing non confidential summary of such information to enable the other parties to understand substance of submissions. However the non confidential summary of confidential data submitted by the Domestic Industry does not give any understanding of the facts/ data and hence they are not able to make an effective response to the submissions of the Domestic Industry

x. While the Designated Authority consented to the letter by CMAI and Measurement Controls Limited for claim made by Tejas to qualify as “domestic industry”, only letter by CMAI is placed on record. However it is apparent from the Disclosure Statement, whether the Designated Authority has made any efforts to corroborate the same when Authority itself found that more than 65% of components used by Tejas is imported

xi. The Domestic Industry in the Petition mentioned that inter-alia details of exports made by them are available in Performa IV-A, but marked the same as confidential and non confidential summary thereof had not been provided, and

xii. The Designated Authority failed to cause investigations or record any findings as to why in spite of increase in sales, production, inventory the Domestic Industry is alleging injury.

### **Examination By the Authority**

181. Authority notes that the issues relating to standing of the domestic industry, imports by domestic industry as also addressing the same within the scope of Rule 2(b) of the AD Rules has elaborately been taken care of in detail in the disclosure statement and present findings. No new issues have been brought out by the party and the issues addressed in the disclosure statement or the present findings elsewhere need not be addressed afresh. With regard to treatment of China as a non market economy country, the Authority notes that the Rules provides for rebuttable presumption. Therefore, the Authority is required to treat Chinese producers as operating in non market economy, unless a responding Chinese producer establishes its claim of market economy status.

**CIENA USA**

182. They have submitted that considering that DGAD has admitted the plea of Domestic Industry that the key effort involved in production of subject goods is in the development of technology. Substantial research & development efforts are put in by the producers in design & development of the subject goods, the core activity in the production of the subject good is development of technology, know-how, design and development of the product and the production process of subject good and the country in which such process is carried out is of significant commercial importance in terms of the reliance placed by consumer on the technology produced in certain specific country, Authority may consider to mention in Final Findings document that that the substantial transformation goods produced by CIENA is not carried out in the subject countries under investigation and, therefore, the goods do not originate from China PR.”

**Examination by the Authority**

183. Authority takes note of the comments as above. As far as the issue of defining the country of origin by taking into account the country of origin for IPR, Authority notes that although the Administrative Ministry for Telecom Equipment was considering this aspect for specialized products relating to Telecom and had publicized the same for comments from all concerned, the issue had not been firmed up as yet as no formal orders to this effect have been issued. Therefore, the Country of Export and Country of Origin for the present investigation will continue to be in line with Preliminary findings notified by the Authority.

184. However, irrespective of the above, Authority seeks to hold that Tejas is the Domestic Industry and has necessary standing within the scope of the Rules, without a reference to the IPR issue, as of now, as under.

- i. Tejas is the only manufacturer who provided data in manner prescribed, to the Authority.
- ii. There were claims of being domestic producers by VMCL and Prithvi, one of whom, at the fag end of the investigation in August, 2010, admitted in writing that they are into manufacture of DWDM, not included under PUC, and the other claimant was found to be an importer of the equipment during the course of verification carried out at the premises of the responding exporters and therefore not eligible to be considered as DI within the scope of Rule 2(b). Moreover, no verifiable data, whatsoever, in the manner prescribed, was presented to the Authority by either of the two.
- iii. FIBCOM, the claimant to be another producer, also did not provide any verifiable data, although they came in support of Tejas seeking imposition of duty of complete equipment.
- iv. No other interested came forward to claim to be the manufacturer, nor did any other interested party provide any data on this score to the Authority.

M/s Huawei Technologies Co., Ltd, China PR , Aircel Ltd. and MRO Tech

185. Responding to the disclosure statement, M/s Huawei Technologies Co., Ltd, China PR

- i. DGAD should not have treated Huawei on par with other non-cooperating exporters by applying the all others rate of dumping margin of 280 - 290% despite all the cooperation extended by Huawei. There was no warrant to discard the export price of Huawei. Export price details were made available to DGAD and there was no change whatsoever in the export price. Export price details reported in Appendix 2 were found to be tallying with the relevant supporting documents and accounting records including bank statements in support of realization of export proceeds. During the verification, when the authority verified the individual documents with the various sub-fields of the PCNs, no mistake was ever found. All the documents matched with the data presented. In the preliminary findings, the values reported against certain PCNs without quantities had been ignored. After the preliminary findings, Huawei had reallocated the values of those PCNs to other PCNs that had quantities. At the time of verification, the components in PCNs without quantities were also reallocated to those PCNs with quantities. The re-allocations were made in order to match all components with their values in the PCNs. Such modifications did not amount to changing the export price. In fact, the export prices before and after the reallocation remained the same.
- ii. Since no additional data was submitted pursuant to the verification report, there was no reason why DGAD could not accept the submitted information. Huawei had given a complete list of description that it had used to for denoting every sub-field of the PCN. When the description used by Huawei was considered for comparing the various sub-fields of the PCN, there was no difference in the description between the PCNs reported and the underlying documents.
- iii. In terms of paragraph 5 of Annex II of the WTO ADA, even if the information provided is not ideal in all respects, it shall not be disregarded as Huawei has acted to the best of its abilities.
- iv. Insistence of the DGAD on production of extremely old documents, not requested before hand and refusal to grant MET status on the failure to produce such documents was unjustified.
- v. Huawei Technologies Co., Ltd (hereinafter “Huawei”) provided detailed evidence which showed that Tejas was using its exclusive OEM manufacturer Celestica in Thailand as a front to engage in indirect imports from China PR.
- vi. Tejas does not cease to be an importer merely because it indirectly imports from China via Thailand instead of engaging in direct imports from the subject country. Therefore, Tejas does not qualify to represent the Domestic Industry under paragraph 2(b) of the Antidumping Rules, 1995.
- vii. Huawei and a number of other interested parties sought a public hearing to exclusively discuss the issues relating to the product under consideration. They wanted to highlight that a number of products that comply with SDH standards are

sought to be included by customs authorities though they are significantly different from the STM 1 to 16 machines manufactured by Tejas. Despite repeated requests to hold a public hearing on this crucial issue, no hearing was held. Without providing an opportunity to address submissions or counter-submission on the issue, DGAD has decided to summarily include STM 64, STM 256, DXCs, broadband and cellular equipments which incorporate SDH equipments, assemblies & sub-assemblies and populated circuit boards/cards within the scope of the PUC. The decision of the DGAD is highly arbitrary.

- viii. DGAD in paragraph 30(ii) of the Disclosure Statement has stated that the goods are produced only if the inputs deployed in the production process undergo a “substantial transformation”. However, DGAD failed to examine whether parts & components including populated circuits boards and cards, SDH Transmission Equipment are produced in India by the petitioner.
- ix. The position adopted by the DGAD that inputs processed at an intermediate stages, where they had no use (and could perform no functions) but for consumption in the eventual product, could not be considered as an article even if saleable at that stage, is completely faulty.
- x. DGAD has erroneously included distinct products and higher grades of SDH Transmission Equipment not produced by Tejas, while determining the applicable anti-dumping duty. Reasons for exclusion are provided below:
  - i. STM 64 – The finding of the DGAD that Tejas has supplied STM - 64 in India and overseas market is highly questionable. Tejas has not participated in any tender process for STM 64 till date. DGAD has accepted the false claims of Tejas.
  - ii. STM 256 – The decision of Hon'ble CESTAT in *Andhra Petrochemicals Ltd Vs Designated Authority, 2006 (201) ELT 481 (Tri-Del)* that an article which is not an article exported from any country or territory to India cannot be subjected to anti-dumping duty is binding on DGAD and no antidumping duty can be recommended on STM 256. STM 256 is distinguishable on the basis of (a) technical characteristics (b) manufacturing process (c) functions & uses and (d) customer perceptions.
  - iii. Digital Cross Connects - DXCs represent a separate technology and are distinguishable from STM 1 to 256 family of SDH Transmission Equipments. Huawei submitted detailed differences between DXC and SDH Transmission Equipments, none of which was considered by DGAD.
  - iv. CKD/SKD form and assemblies & sub-assemblies – DGAD should clarify that assemblies /sub-assemblies not having the essential character of SDH equipments shall not be subject to anti-dumping duty.
  - v. PCB/Cards - Tejas does not produce PCBs and cards but imports them in substantial quantities. Evidence to this effect has already been furnished to the DGAD. Inclusion of PCBs and cards within the PUC is therefore completely erroneous.
  - vi. Parts & components – Since DGAD has acknowledged that parts & components are not manufactured by the “Domestic Industry” DGAD should issue a clarification to exclude parts & components. While excluding parts &

components, assemblies/sub-assemblies, PCBs and cards have been included. In the absence of a clarification as to the distinction between parts/components and the assemblies/subassemblies/PCBs and cards, it will create chaos in the customs administration.

- vii. SDH equipment as part of equipment – Ministry of Finance vides Customs Notification Non 132/2009 had excluded broadband or cellular equipments which incorporate SDH equipments from the scope of anti-dumping duty, despite inclusion of such products in the Preliminary Finding. Therefore, DGAD should exclude the same from final findings also.
- viii. Software – Software is a service and not a good. DGAD should not take an internationally unprecedeted step of imposing anti-dumping duty on a service.
- xi. Vide submission dated December 30, 2009; Huawei has submitted a detailed list of products which should be excluded from the scope of the PUC. The same may kindly be considered by the DGAD and excluded from the scope of the present levy.
- xii. The Hon'ble Tribunal in a plethora of cases such as *Videocon Narmada Glass Vs Designated Authority* [2003(151) ELT 80(Tri-Del)], *Indian Refractory Associations Vs Designated Authority* [2000 (119) ELT 319 (Tribunal)] and *Magnet Users Association Vs Designated Authority* [2003 (157) ELT 150 (Tri- Del)] has ruled in favour of excluding grades not manufactured by the Domestic Industry. Therefore, product grades not manufactured by Tejas should be excluded from the scope of the Domestic Industry.
- xiii. DGAD in examining the locus standi of the petitioner has failed to examine whether “substantial transformation” of the subject goods are carried out by Tejas in India. The list of activities carried out by Tejas as provided in paragraph 31 of the Disclosure Statement does not establish whether actual production is carried out by Tejas or by EMS vendors. No explanation has been provided as to how the activities carried out by Prithvi & VMC are different from that of Tejas.
- xiv. DGAD has made a false statement in paragraph 43 of Preliminary Finding that detailed investigation was carried out at the premises of Tejas. During the public hearing, the counsel for the domestic industry openly stated that the authority visited only the head office of Tejas at Bangalore and they did not visit the plant at all for the reason that Tejas did not have any plant at all at the time of visit by DGAD Team.
- xv. Performance of “pre-production activities” like design and development cannot qualify a company as a producer. This is a consistent practice of US Department of Commerce/ International Trade Commission
- xvi. The use of the term “manufacture” in Rule 2(b) – Definition of Domestic Industry - has to be given meaning. The use of the term is a deviation from the text of the WTO ADA which uses the term “production” with the purpose of aligning the Rules with India jurisprudence. The position of law as acknowledged by the Supreme Court of India in *Diwan Bros vs Central Bank of India, Bombay and Ors* [AIR 1976 SC 1503] is binding on DGAD.
- xvii. More than 70% of the shares of Tejas are held by non-Indians and for this reason also, they cannot be treated as ‘domestic industry’.

- xviii. DGAD has not examined the detailed submissions made by Huawei on injury and causal link in its Written Submission dated January 4, 2010.
- xix. Reliance on “Voice & Data” magazine to determine import volume for the period under review, except the POI was in clear violation to the binding decision of CESTAT in *Dye Stuff Manufacturers Assn of India v GOI 2003 (157) ELT 154 (Tri)*. Additionally, import data submitted in the petition comprised sales contracted as well as sales effected. No injury could be deemed to have been caused through contracted sales.
- xx. Point to point comparison i.e. comparison of the imports during base year 2005-06 with POI – April – December, 2008 was in clear violation of *EC-Tubes*, WT/DS219 where the panel had held that a meaningful examination of injury must take into account the actual intervening trends in each of the injury factors and indices rather than just a comparison of the end points. Intervening trends indicate that between 2007-08 and the POI, market share of Tejas in increased demand was 47.30% while that of Chinese exporters was only 16.88%.
- xxi. In examining the price effect, DGAD should have examined whether increase in cost of sales was a result of the profit margin added by related EMS vendors who carried out the actual production process for Tejas; whether the cost of sales determined for Tejas was on the basis of the cost incurred on products actually sold by Tejas and not other products; whether inability of Tejas to gain market share flowed from the incapability of meeting the unique demands of the customer.
- xxii. Submissions of Huawei on (1) Enhanced profitability of the Domestic Industry ; (2) Increase in production/sales & market share; (3) Increase in Employment & Wages presented in the Written Submission have not been considered by the DGAD. DGAD has not even examined whether Tejas had the capacity to meet the demands of the Indian industry.
- xxiii. It is a settled position of WTO law, as elucidated *EC - Bed Linen*, paragraph 6.154 - 6.159, that all the listed factors mentioned in Article 3.4 must be examined by the investigating agency and *Mexico – Corn Syrup*, paragraph 7.128 that consideration of each of the factors must be apparent in the final determination of the investigating authority. No such consideration is however apparent from the disclosure statement.

### **Examination by the Authority**

186. The Authority relies upon elaborate verification report issued to the exporter, disclosure statement issued and the present findings. Issues raised by the company have also been raised by other interested parties and have already been addressed elsewhere in the disclosure statement and present findings. The Authority also takes note of the submissions made by Huawei Technologies, proposing a price undertaking and seeking information on export price, normal value, dumping and injury margins so as to enable them to submit a suitable undertaking. The Authority notes that the details about non-determination of export price in respect of the subject exporter have already been explained in the disclosure statement as well as in these findings. Consequently it has also not been possible for the Authority to determine the individual DM and IM for the subject exporter. Moreover, the

product under consideration is not a simple homogeneous product but a complex one with a number of variants. Therefore the Authority holds that such an undertaking, proposed by them is impractical; Rule 15(3)) refers.

### **Fibrehome**

187. While commenting on the disclosure statement, they have stated as under

- a. PCN's exported by Fibrehome are not manufactured by Tejas. How cost data of Tejas has been used for working out Normal Value for different PCN and products.
- b. Excessive confidentiality has been adopted in respect of Normal Value and Non-injurious Price which is not based on actual cost data of Tejas and cannot be treated confidential.
- c. Cost of production in India is entirely different from prevailing in China. R&D cost is very high for Tejas. Authority should have adopted Normal Value as prevailed in Israel or Hangzhou ECI Telecommunication Co. Ltd, considered as operating under Market Economy conditions in China PR. In case some of the PCN are not produced and sold by ECI Telecom Ltd. Israel, the Authority should have resorted to Normal Value based on the same assumption as has been adopted while working out the CNV for those PCN which are not produced by Tejas.
- d. Anti Dumping Duty should be imposed type-wise by segregating the PUC into the types they are sold.
- e. Non-injurious Price determination is incorrect
  - Raw Material Cost:- when all the PCN exported into India have not been manufactured by Tejas, they could not have provided PCN wise detailed Bills of Material on 522 PCN. Further parts and components used for different PCN by different companies may differ.
  - Research & Development Cost: How Authority has assessed the R&D cost for PCN not produced by Tejas is not known.
  - Reasonable Return on Capital Employed methodology is totally baseless. Authority should adopt the rate of return on capital employed actually earned by Tejas during the period when there was no allegation of dumping.

### **Examination by Authority**

188. Issues raised by the company have already been addressed elsewhere in the disclosure statement and present findings. It is clarified that the Authority has constructed normal value for the exported PCN. For the purpose, the Authority has established PCN by considering the properties of the exported product type. As regards difference in the prices of inputs, the Authority holds that the prices of inputs prevailing in China cannot be adopted unless the company concerned has been given market economy treatment. As regards separate duty on different product type, Authority holds that the difference in product types is relevant only for

the purpose of comparison (for determining dumping margin and injury margin). Eventual anti dumping duty has to be on the product under consideration. The Authority has adopted the same rate of return for determining reasonable profit for the domestic industry as has been considered in other investigations. This is despite the claim of the domestic industry for higher rate of return on the grounds that the investment in the present product is not limited to plant & equipment and working capital, but extends to manpower, which also constitutes assets for the production of the product in the present case.

### **M/s ZTE Corporation, China**

189. ZTE has truthfully reported all exports transactions in Appendix 2 and nothing has been concealed to mislead the Authority. Rather the export transactions reported by the interested party now are not SDH devices but DWDM devices and according to ITU-T G.671 and ITU-T G.680, OADM is one form of DWDM device.

### **Examination by the Authority**

190. Their submissions on this score have been accepted on its face value and suitably addressed in response to the claim of the DI on this score in paras herein before.

### **VMCL**

191. They have stated as under

- a. The disclosure statement is in contravention to SC decisions as regards what constitutes production and confidentiality.
- b. VMC is a manufacturer as per the law declared by the Hon'ble Supreme Court
- c. Complainant has no manufacturing and supply capabilities to address the needs of the domestic users. For the import of parts, components, assemblies, sub-assemblies, etc., India is wholly dependent on import.
- d. While the PUC has been redefined in disclosure statement there has been no corresponding re-determination of the 'domestic industry' or consequent re-determination to the dumping, injury and causal link.
  - i. STM 64, STM 256 and DXC are not 'like products' to STM 1, STM 4 and STM 16.
  - ii. DXC equipment is altogether a different category of equipment than the STM equipments.
  - iii. Constitution of the domestic industry, dumping, injury, causal link, etc. needs to be separately determined for STM 64, STM 256 and DXC equipments.
  - iv. In the light of the letters by BSNL, ITI Ltd, it emerges that the complainant industry was not engaged in the manufacture of STM 64, DXC equipments.
  - v. Mere investment in capacity, development of test equipment, etc. for STM 256 is not the thresholds for determining the domestic industry.
  - vi. Both assemblies and sub-assemblies as also PCBs have like treatment as has been afforded to parts and components.

4087 GI/10-3D

- vii. No parts and components, assemblies & subassemblies, etc. of DWDM equipments including 'STM 16 Muxponder cards' should be included in the scope of the product.
- viii. Concept of "substantial" transformation is not a statutory requirement to determine whether or not an entity can be regarded as part of the domestic industry.
- ix. Tejas should be considered to be importer of parts and components of PUC from the subject countries.
- x. The company has provided all the relevant information called. The statement that the company has not extended co-operation in relation to the present proceedings is fallacious.
- xi. Request for public hearing - the "due process" requirement in relation to the Anti-dumping proceedings requires hearing and such request cannot be denied. Following determination proposed to be made by the Authority are without disclosing the relevant basis and should be rejected.
  - a. Tejas has produced and sold STM 64 in India and overseas [Pg. 30 Para 36 (b)]
  - b. Tejas has shown production of STM 64 in commercial volumes i.e. also for BSNL [Pg. 30 Para 36 (b)]
  - c. Tejas has manufactured STM 256 [Pg. 30 Para 36 (c)]
  - d. DXC equipment of SDH technology has been produced and supplied by Tejas during the investigation period.
  - e. Letter of TEMA (an industry association)

#### **Examination by Authority**

192. Authority notes that VMCL has not established its status as an interested party. Under Rule 2(c), an interested party is defined as follows

- (c) "interested party" includes -
  - (i) an exporter or a foreign producer or the importer of an article subject to investigation for being dumped in India, or a trader or business association a majority of the members of which are producers, exporters or importers of such an article;
  - (ii) the government of the exporting country; and
  - (iii) a producer of the like article in India or a trade and business association a majority of the members of which produce the like article in India;

193. In the instant case, the company has not established how it constitutes an interested party. The company is neither a domestic producer of the product, nor an importer nor a consumer in India. Thus, while holding that the company has not been able to establish its credentials as an interested party, the Authority has considered it appropriate to take cognizance of the issues raised by the company and submissions made from time to time. They have furnished fresh evidence in the form of a letter from IIT, Mumbai, in support of its contention that DXC and STM are different products. It further claimed that STM 1 to 64 are

line cards and at best can be used as a transport equipment, whereas DXC is a much more advanced technology suiting the needs of network wide operations. They have further claimed that DXC and STM are not interchangeable / substitutable. The Authority notes that the very same evidence admits that DXC and STM are two different types of SDH equipment. Further, the letter admits that DXC need not be specific to just SDH, which implies that DXC is certainly an SDH equipment as well. The Authority holds that the mere fact that different types are deployed for different specific end applications does not imply that such different types are indeed dislike articles. Undisputedly, SDH transmission equipments also have DXC; the same have been produced & sold by the domestic industry, and imported from subject countries. Further, DXC of other transmission technology in any case are beyond the scope of the product under consideration.

194. As regards letter issued by VJTI, Mumbai, the Authority notes that the query raised onto VJTI itself was incomplete and incorrect. VJTI has not been asked to distinguish and differentiate between SDH and non SDH DXC. Further, the query is not on whether DXC and STM can be SDH transmission equipment. Moreover, the scope of the product under consideration as considered by the Authority, which is most fundamental information required by any party before giving opinion does not appear to have been made known to VJTI. Nor the purpose of the present investigations, scope of product under consideration as can be considered in anti dumping investigations appears to have been brought to the knowledge of VJTI. It does not appear that VJTI has been informed that the Authority has considered the scope of the product under consideration as SDH transmission equipments and in that case whether DXC & STM of SDH technology constitute one product. Notwithstanding, it is noted that VJTI has only concluded that DXC and STM have different specific end application. They have not concluded that DXC SDH transmission equipments are fundamentally different from STM SDH transmission equipments on the basis of product criteria applied in anti dumping (considering parameters such as product characteristics, manufacturing technology & process, function, pricing, etc.)

195. As regards STM64, the Authority reconfirms that the domestic industry has in fact produced and sold STM64 during the investigation period. As regards STM256, the arguments of the interested parties and position of the Authority thereon has already been brought in the disclosure statement and the elsewhere in the present findings. Further with regard to submission of the additional information / evidence in the form of comments to the disclosure statement, the Authority notes that there is a deadline prescribed for interested parties to submit the same and for the Authority to examine it and conclude the investigation. The Authority therefore holds that additional information furnished by them in the form of Auditor's report etc. which also remains un-verified, is un-acceptable and inadmissible so far as the present proceedings are concerned.

**ECI and Hangzhou ECI**

196. In their comments to the disclosure statement they have stated as under:

- i. Software being one of the crucial inputs in SDH equipment should be given full effect while calculating export price.
- ii. It appears that the Designated Authority has taken the gross selling price without making adjustments for domestic freight, taxes etc. for PCN's which were sold in the Domestic Market.
- iii. Authority has penalized the cooperating exporters by not considering a reasonable profit of 5% which has otherwise been considered for the cooperating exporters who have been denied market economy treatment.
- iv. Authority has taken assembly/sub-assembly wise selling price in the domestic market / third countries contrary to the method followed in arriving at the export price as per the PCN methodology.
- v. With regard to the determination of the normal value for the remaining PCN's, the methodology adopted in calculating the normal value is inconsistent with the determination of the export price.
- vi. It is not known whether the costs of accessories supplied by Tejas in the domestic market have been considered while computing the Non-Injurious Price.
- vii. Exporters (i.e. HETC and ECI) have fully cooperated even when each time the parameters / methodologies for the Product under Consideration were modified.
- viii. Tejas had the requisite capability to produce DXC only up to 60 GBPS. Inclusion of DXC's exceeding 60 GBPS is erroneous.
- ix. It is hard to accept injury with rise in sales, production, productivity, employment, wages coupled with a fall in imports from Israel.
- x. Authority in its disclosure statement without offering any reasons revised the injury margin to 5-15% for ECI

While calculating the export price, the weighted average price of assemblies has been ignored whereas while calculating the normal value a weighted average price has been used.

**Examination by the Authority**

197. Authority has accepted the submissions of including embedded software etc. for calculation of NEP and LP so far as XDM variant is concerned. As regards BG variant, the submissions on this score made by the exporter cannot be accepted as they have sold software in the domestic market free of cost as has been recorded in the verification report. Regarding determination of NV by including profit on domestic sales alone, as also taking the same at ex-factory level, the same has suitably been incorporated while working out the margins. It is clarified that accessories have not been included in the calculations of non injurious price and injury margin. The non injurious price for the domestic industry had to be revisited as some omissions and calculation errors came to notice after issue of disclosure statement necessitating issue of a second revised disclosure statement.

**M/s Alcatel-Lucent Shanghai Bell Co. Ltd.**

198. Responding to the disclosure statement, they have stated as under:

- i. “Ownership” is not relevant criterion to determine grant of Market Economy Treatment, significant state interference with regard to operations of the company being relevant to granting MET status.
- ii. Using the import prices in India would not be in accordance with the mandate of reasonability as envisaged under para 7. International prices have been completely ignored by the Authority.
- iii. Since the PCN’s are different, components are different, design is different etc., the adoption of Domestic Industry prices would not be appropriate.
- iv. Change in the product under consideration or scope of investigation, the injury analysis is also required to be carried with reference to changed product under consideration.
- v. Applicant Industry could not have been treated as Domestic Industry in view of the amendment in Rule 2(b) vide notification No. 18/2010-Customs (NT) dated 27.02.2010.

**Examination by the Authority.**

199. The Authority notes that the Rules require the Authority to determine whether the decisions of the concerned firms regarding prices, costs and inputs, including raw materials, cost of technology and labour, output, sales and investment, are made in response to market signals reflecting supply and demand and without significant State interference in this regard. The Authority further notes that one of the shareholders, holding very significant share, is State owned or controlled, the exporter is required to establish that its decisions on these stated parameters are independent of the State. The exporter has not been able to establish such independence from the State interference. Moreover as already recorded in the Disclosure Statement and these findings, the state interference cannot be ruled out under the circumstances. As stated elsewhere, the Authority has determined normal value by considering the PCN of the exported product type. As regards input prices, the Authority holds that it would not be inappropriate to consider the domestic industry prices. The Authority notes that the change in the definition of Rule 2(b) does not vitiate the finding on scope of the domestic industry arrived by the Authority.

**Tirumala Seven Hills P Ltd**

200. The company, appreciating exhaustive disclosure and exclusion of components/ parts from the product under consideration while imported on standalone and independently has further stated that this will, not only help the Indian manufacture to remain competitive in this cut through competitive environment but will open doors to other Indian companies to get in to the manufacturing. They have also stated that apart from exhaustive details for PUC – 8 digit HS code 8517 62 60 should also be mentioned to bring more clarity to PUC. They also want that a clear exclusion should also be made for parts and components from PUC to bring more clarity and to avoid any confusion at Indian customs. They have also sought a clear

*H087 GI/10-31*

exclusion of all multiplexing technology product like PDH, CWDM and DWDM other than SDH should also be made for better understanding of Indian customs.

#### **Examination by the Authority**

201. The Authority reiterates its position. Anti dumping duty applies only on product under consideration as defined in the present notification, regardless of customs classification where the goods have been reported for clearance. However, the Authority has addressed these issues in the form of footnotes to the duty table.

#### **PRITHVI**

202. Responding to the disclosure statement, they have submitted following comments:

##### *i. General Submissions*

1. The Authority has acted contrary to law on critical aspects like what constitutes production, confidentiality issues etc.
2. Damage is caused to the larger national interest by recommending imposition of duty on STM 64 and DXC which are items in relation to which the evidence on record shows that the Applicant does not have the manufacturing and supply capacities.
3. Irrespective of exclusion of DWDMs from the PUC by the Authority, anti dumping duties are being imposed on the import of DWDMs on the ground that the same is also covered under the PUC.

##### *ii. Specific Submissions*

1. Non cooperation as regards present proceedings - Authority has erred in concluding that Prithvi has not cooperated with the Authority. All the information sought by the Authority was provided by Prithvi.
2. Non submission of Information - Except the information which was beyond the statutory requirements, all other information was submitted.
3. Public hearing- Request for conducting Fresh Hearing in light of various complexities relating to PUC was ignored.
4. Product under Consideration
  - a. *STM 64, STM 256 and DXC are not 'like products' to STM 1, STM 4 and STM 16*
    - i. STM 64, STM 256 and DXC cannot be included in the PUC as they are not technically or commercially substitutable to the products that are produced by the Applicant.

- ii. DTX Equipments are different from STM Equipment on the basis of the purpose and applications of the equipments, physical characteristics, network location, technology supported, etc.
- iii. Constitution of the domestic industry, dumping, injury, causal link, etc. needs to be separately determined for STM 64, STM 256 and DXC equipments.

b. *STM 64 & DXC should be excluded from PUC*

- i. Finding of the Authority that Applicant has undertaken the production of STM 64, DXC is unsubstantiated with any evidences. Further, the evidences submitted by the interested parties in this regard are ignored.
- ii. Applicant was not engaged in the manufacture of STM 64, DXC equipments during the POI.
- iii. Applicant does not meet the standing qualification for being recognized as Domestic Industry for STM 64, DXC as the same is absent in the findings of the Designated Authority.

c. *STM 256 should be excluded from the PUC*

- i. There is no production of STM 256 in the country.
- ii. Applicant does not qualify to be the Domestic Industry for STM 256. Mere investment in capacity, development of test equipment, etc. does not determine Domestic Industry.
- iii. For the aforementioned reasons, STM 256 cannot be included within the scope of PUC.

d. *Assemblies, Sub- assemblies and Populated Circuit Boards ("PCB")*

- i. Assemblies and sub-assemblies have been retained as part of the PUC, despite the fact that these products are in the nature of parts and components.
- ii. Assemblies and sub-assemblies do not by itself constitute the SDH Equipment.

## 5. Domestic Industry

- a. Definition of manufacture under the Central Excise law should be the basis to determine whether an entity is a manufacturer.
- b. Prithvi and other manufacturers have been wrongly excluded from being considered as Domestic Industry. The concept of "substantial" transformation is not a statutory requirement to determine whether or not an entity can be regarded as part of the domestic industry.

c. Preferential treatment has been accorded to the Applicant by allowing Tejas to maintain the proceedings and excluding other manufacturers from the purview of domestic industry.

**6. Injury Analysis**

a. Redetermination of the PUC is required as the Applicant does not have the manufacturing capabilities for STM 64, STM 256, DXC, etc the same cannot be covered under the PUC.

b. Accordingly, fresh injury analysis will be required, and then the same will not result in any injury to the Applicant in respect of the products manufactured by it.

**7. Findings are without evidence and without disclosing the basis**

a. Evidence and basis for certain findings i.e., production of STM 64, STM 256, DXC equipment of SDH Technology are/have been produced by the Applicant;

b. Letter of TEMA are not disclosed to the interested parties.

c. The calculations in relation to the NIP and also the range of dumping margins were modified by the Designated Authority without providing any reasons for the same.

**Examination by the Authority**

203. The issues raised by them have also been raised by the other interested parties and have been addressed appropriately in these findings. Further the Company has not established its status as interested party. On the contrary the evidence provided in response to the disclosure statement raises doubts on their eligibility as interested party within the meaning of Rule 2(c) of Ad Rules.

**Examination of other common issues raised by interested parties.**

204. As regards some of the common issues raised, the Authority notes that, a number of interested parties have disputed a number of facts disclosed by the Authority on the ground that the relevant evidence has not been disclosed to the interested parties by the Authority. The Authority notes in this regard that while the petitioner and interested parties are entitled to claim confidentiality under Rule 7, the disclosures by the Authority either in the disclosure statement or in the present findings is also subject to the requirements of Rule 7. Therefore, while recording the facts or the findings on such facts, the Authority cannot disclose the relevant evidence. Moreover, the Authority has disclosed to the interested parties substance of the information/evidence provided by the petitioner or interested parties through the disclosure statement or the present findings and the interested parties have got an opportunity to defend their interests on the basis of the same.

205. Referring to improvements in a number of the economic parameters, more particularly in volume parameters, a number of interested parties have disputed that the domestic industry has suffered injury. The Authority holds since performance of the domestic industry has improved in respect of some parameters and deteriorated in respect of other parameters, the Authority is required to consider whether deterioration in performance of the domestic industry in respect of some parameters outweigh the improvement in performance of other parameters to such an extent that it must be concluded that the domestic industry has suffered injury. If, however, the improvements in some parameters outweigh the deterioration in other parameters, the Authority must conclude that the domestic industry has not suffered injury. The Authority, after analyzing the injury notes that the performance of the domestic industry has materially deteriorated in terms of profits, return on investment and cash profits. Thus only conclusion that can be drawn is that the performance of the domestic industry has suffered materially, notwithstanding improvements in parameters such as production, domestic sales, etc. The Authority notes that a business enterprise is set up for selling the goods with the objective of earning reasonable profits. It cannot be said that performance of a business enterprise whose production & sales volumes are improving leap & bound is good, if its profits and return on investment deteriorate to such an extent that the same becomes negative. In the present case, while it is found that production and sales of the domestic industry improved, it is also found that the domestic industry has suffered financial losses, negative return on investment and negative cash profits.

206. The Authority further holds that CKD, SKD and sub-assemblies are nothing but form of the product, having no use other than into integration into SDH equipment. These do not have distinct character, function or use. The product can be invoiced both in finished ready to use condition and in SKD or sub-assemblies condition, as was established beyond doubt during verification of the records of the responding exporters.

207. Since the Authority has excluded standalone components from the scope of the product under consideration, imports of such standalone components by the petitioner, in any case, do not constitute imports of alleged dumped product.

#### **Volume and Prices of imports not sold at the dumped prices**

208. The subject goods are being supplied from other countries as well. The import prices from third countries are, however, significantly higher than the subject countries. Imports from third countries are not causing material injury to the domestic industry at this stage.

#### **Contraction in demand and / or change in pattern of consumption**

209. Demand for the subject goods shows a healthy growth during the entire injury investigation period and therefore, the injury to the domestic industry has nothing to do with the lack of demand in the country. The data on consumption and demand does not show any change in the pattern of consumption of the product and has not been a factor causing injury to the domestic industry.

**Trade restrictive practice and competition between the foreign and domestic producers**

210. The goods are freely importable. The applicants are the major producers of the subject goods and account for significant domestic production and sales. No evidence of conditions of competition or trade restrictive practices has come to the knowledge of the Authority. The Authority notes that there is a single market for the subject goods where dumped imports from subject countries compete directly with the subject goods produced by domestic industry. The Authority also notes that the imported subject goods and domestically produced goods are like articles and the imported product is sold to meet the similar applications/ end uses as domestically produced subject goods.

**Development of Technology**

211. Technology for production of the product has not undergone any change. Developments in technology are, therefore, not a factor of injury. However development of models of higher capability is a regular phenomenon in this industry and both follow this aspect of the technology.

**Export performance**

212. Information on export performance has been considered by the Authority separately and injury analysis is based on domestic sales alone.

213. No other factor, which could have possibly caused injury to the domestic industry, has been brought to the knowledge of Authority.

**Conclusion on Causation**

214. Concluding the investigation, the Authority holds that injury is caused to the domestic industry by dumped imports. The Authority concludes that:,

- i. The prices offered by the foreign producers are lower than the prices offered by the domestic industry. Resultantly the consumers are increasingly switching over to dumped imports.
- ii. As a result of increase in imports, the domestic industry is being prevented from improving its market share. The imports are depressing the prices of the domestic industry as a result of significant price difference between domestic and imported product. Consequently the domestic industry has been forced to reduce the prices over the period.
- iii. As a result of reduction in prices offered by the domestic industry, its profitability and consequently return on investments & cash flow materially suffered.

### Recommendations

215. The Authority notes that the investigation was initiated and notified to all interested parties and adequate opportunity was given to the exporters, importers and other interested parties to provide positive information on the aspect of dumping, injury and causal link. Having initiated and conducted an investigation into dumping, injury and causal links between dumping and injury to the domestic industry in terms of the Rules laid down and having established positive dumping margin as well as material injury to the domestic industry caused by such dumped imports, the Authority is of the view that imposition of final duty is required to offset dumping and injury. Therefore, the Authority considers it necessary and recommends imposition of final anti-dumping duty on imports of subject goods from the subject countries in the form and manner described hereunder.

216. Having regard to the lesser duty rule followed by the authority, the Authority recommends imposition of anti-dumping duty equal to the lesser of margin of dumping and margin of injury, so as to remove the injury to the domestic industry. Accordingly, antidumping duty as indicated in Col 8 of the duty table below, which shall be as a percentage of CIF value of imports, is recommended to be imposed from the date of notification, to be issued in this regard by the Central Government, on all imports of subject goods originating in or exported from the subject countries/territories.

S. No	Sub. Heading	Description	Country Of origin	Country of Export	Producer	Exporter	Amount	Unit of Mea- sure- ment
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
1	851762 & 851770	**“Synchronous Digital Hierarchy transmission equipment” as per notes below	China PR	China PR	M/S Fibrehome Telecommunication Technologies Ltd.	M/S Fibrehome Telecommunication Technologies Ltd.	266%	% of CIF Value of Imports
2	-DO-	-DO-	China PR	China PR	Alcatel-Lucent Shanghai Bell Co. Ltd.	Alcatel-Lucent Shanghai Bell Co. Ltd.	45%	% of CIF Value of Imports
3	-DO-	-DO-	China PR	China PR	M/S ZTE Corporation	M/S ZTE Corporation	36%	% of CIF Value of Imports
4	-DO-	-DO-	China PR	China PR	M/S Hangzhou ECI Telecommunication Co. Ltd.	M/S ECI Telecom Ltd., Israel	7%	% of CIF Value of Imports
5	-DO-	-DO-	China PR	China PR	Any other combination than as at Sl. 1,2	Any	266%	% of CIF Value of Imports

					3 and 4above			
6	-DO-	-DO-	China PR	Any other than China PR	Any	Any	266%	% of CIF Value of Imports
7	-DO-	-DO-	Any	China PR	Any	Any	266%	% of CIF Value of Imports
8	-DO-	-DO-	Israel	Israel	M/S Telecom Israel	ECI Ltd.,	M/S ECI Telecom Ltd., Israel	3% % of CIF Value of Imports
9	-DO-	-DO-	Israel	Israel	Any other than combination as at Sl.No. 8 above	Any	70%	% of CIF Value of Imports
10	-DO-	-DO-	Israel	Any other than China PR and Israel	Any	Any	70%	% of CIF Value of Imports
11	-DO-	-DO-	Any other than China PR	Israel	Any	Any	70%	% of CIF Value of Imports

**\*\*Note 1.** The product under consideration will include "Synchronous Digital Hierarchy transmission equipment, viz. STM-1, STM-4, STM-16, STM-64, STM-256 in assembled, CKD, SKD form, its assemblies and sub-assemblies or fitted with eventual broadband / cellular equipment. Product under consideration will also include Add Drop Multiplexers (ADM) (For SDH Application only), Multiple Add Drop Multiplexers (MADM) (For SDH Application only), and Digital Cross Connect (DXC) (For SDH Application only), Populated Circuit Boards (For SDH Application Only) and parts / components imported as a part of equipment, so long they are imported along with the equipment or its assemblies / sub-assemblies. The Product under consideration will also include Software meant for SDH, which is an integral part of these equipments, which may be bought either as a part of the equipment or separately. However components/ parts imported on a standalone basis are outside the purview of Product under Consideration

**\*\*Note 2.** SDH Equipment essentially transmits signals through the medium of Optical Fibre. There may be SDH equipment meant for transmission through electrical Copper Medium or Microwave Radio Medium. The SDH Equipment transmitting the data through optical fibre alone shall be subject to levy of antidumping duty.

**\*\*Note 3.** When SDH is imported as a part of eventual broadband / cellular equipment, the AD Duty shall be payable only on the SDH portion of the imports. Similarly when eventual Broadband / Cellular equipment is imported as a part of the SDH equipment, the AD Duty shall be payable only on the SDH portion of the imports.

**\*\*Note 4** PDH, CWDM, DWDM, Microwave systems, GPON ,DSLAM, MSAN, BITS, Routers, PTN, PDSN, SGSN, MGW, BTS, BSC, MSC, ONT, HLR, HSS and MRP being non-SDH in any of its form are outside the scope of PUC and therefore not subject to levy of AD Duty.

**\*\*Note 5.** Microwave Radio Terminals which could have an STM-1 interface to the SDH transmission equipment and act as a physical media to enable the connectivity between the radio and the SDH equipment are outside the purview of payment of AD Duty

216. Subject to the above the provisional findings, notified vide notification dated 7<sup>th</sup> September, 2010, are hereby confirmed

**Further Procedures**

217. An appeal against the orders of the Central Government that may arise out of this recommendation shall lie before the Customs, Excise and Service tax Appellate Tribunal in accordance with the relevant provisions of the Act.

218. The Authority may review the need for continuation, modification or termination of the definitive measure as recommended herein from time to time as per the relevant provisions of the Act and public notices issued in this respect from time to time. No request for such a review shall be entertained by the Authority unless the same is filed by an interested party as per the time limit stipulated for this purpose.

P. K. CHAUDHERY, Designated Authority